राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 98

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 16 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

22 तक पहुंचा पंकज आडवाणी का विश्व खिताब का संग्रह

>> 14

सरोकार

पेशेंट पोर्टल के जरिए कोलंबिया से होगा गरीबों का इलाज

साहिबगंज : झारखंड के आइटी विशेषज्ञ देवेश मिश्र कोलंबिया में आइटी विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने पेशेंट पोर्टल नाम का एक मोबाइल एप तैयार किया। इस एप के जरिए कोलंबिया के डॉक्टर भारत में मरीजों को मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श दे सकते हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

नानक नगरी में देखिए गुरु जी का 99 शहरों का सफर

कपूरथला : सिख पंथ के लिए आस्था का केंद्र सुल्तानपुर लोधी एक और मामले में खास होने जा रहा है। यहां गोलाकार आकृति की चार मंजिल की इमारत बनाई जा रही है, जहां गुरुनानक देव के 99 शहरों के सफर का दर्शन किया जा सकेगा। (पेज-11)

इमरान को सता रहा भारत से हार का डर

हौसले पस्त ▸ परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाक पीएम बोले, जंग हुई तो हार जाएंगे

कहा, कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच है परमाणु युद्ध का खतरा

इस्लामाबाद, एजेंसियां : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर परमाणु युद्ध होने की आशंका एक बार फिर जताई है। हालांकि अब उन्हें हार का डर सताने लगा है। उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में भारत से हार जाएगा।

अल जजीरा टीवी चैनल को रविवार को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी परमाणु युद्ध शुरू नहीं करेगा। खुद को युद्ध विरोधी बताते हुए दावा किया कि जंग के नतीजे घातक हो सकते हैं। बोले-वियतनाम, इराक को ही देख लीजिए युद्ध के कारण कहीं अधिक गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जानते हैं कि दो परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच परंपरागत युद्ध शुरू होता है तो वह परमाणु युद्ध पर आकर खत्म हो सकता है। मोदी सरकार से हैरान-परेशान पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान परंपरागत युद्ध में पड़ता है तो वह भारत से लड़ाई हार भी सकता है।

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। एएफपी

अगर एक देश के पास दो ही विकल्प हों-या तो हथियार डाल दे या आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ता रहे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। जब एक परमाणु संपन्न देश अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र से संपर्क साधा है। इसीलिए हम हर अंतरराष्ट्रीय फोरम पर अपील कर रहे हैं कि वह अभी इस मामले में दखल दें। अन्यथा कश्मीर मामला भीषण विनाश का कारण बन सकता है। यह मामला भारतीय उपमहाद्वीप के परे चला जाएगा।

सीमा पर गोलाबारी को लेकर भारत ने पाक को चेताया

नई दिल्ली : दुनिया के सामने न्यूक्लियर ब्लैक मेल की प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशों के बीच भारत ने पाकिस्तान को संघर्षविराम उल्लंघन और सीमा पार से हो रही घुसपैठ को लेकर आगाह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिना किसी कारण के हो रही सीमा पार की गोलाबारी पर भारत गंभीर है। (पेज-6)

मोदी सरकार पाक को आर्थिक रूप से तबाह करने के एजेंडे पर :

पाकिस्तानी पीएम ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत से बातचीत के कई प्रयास किए, लेकिन मतभेद दूर नहीं हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अब पाकिस्तान को एफएटीएफ (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की काली सूची में डालने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ की काली सूची में डाला गया तो फिर पाक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। वह हमें आर्थिक रूप से तबाह करने पर लगे हुए हैं। तभी हमें अहसास हुआ कि यह सरकार (मोदी सरकार) पाकिस्तान को बर्बादी की ओर ढकेलने का एजेंडा लेकर आई है।

370 हटने के बाद भारत से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता : उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत सरकार से बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इमरान ने भारत पर आरोप लगाया कि कश्मीर को अवैध तरीके से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मजबूत देशों अमेरिका, चीन और रूस आदि का सहारा लेना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण तक नियंत्रण रेखा मार्च टाला : इमरान खान ने भारत से लगी नियंत्रण रेखा तक होने वाला मार्च फिलहाल टाल दिया है। वह 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाले अपने संबोधन में कश्मीर मुद्दा उठाएंगे। इसलिए इमरान ने कुछ पाकिस्तानी राजनीतिक दलों और धार्मिक दलों से कहकर भारतीय सीमा तक पूर्व निर्धारित मार्च कुछ समय के लिए रोक दिया है। विगत शुक्रवार को इमरान ने कहा था कि ज्यादातर लोग एलओसी तक मार्च करके प्रदर्शन करना चाहते हैं।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तीन मंदिरों में तोड़फोड़

▸ ईश निंदा के आरोप में हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआइआर दर्ज

▸ उपद्रवियों में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले मौलवी मियां मिठू के समर्थक भी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रविवार को तीन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआइआर दर्ज किए जाने के बाद यह हंगामा हुआ है। मंदिरों के अलावा स्कूल और अल्पसंख्यक हिंदुओं की अन्य संपत्तियों में भी तोड़फोड की गई है। उपद्रवियों में सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने वाले मौलवी पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिठू के समर्थक भी शामिल थे।

घोटकी जिले के सिंध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक छात्र के पिता अब्दुल अजीज राजपूत ने ईश निंदा का मामला दर्ज कराया है। अजीज ने दावा किया कि प्रिंसिपल ने उसके सामने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। केस दर्ज होते ही भीड़ हिंसा पर उतर आई और एक हिंदू मंदिर और सिंध पब्लिक स्कूल में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। प्रिंसिपल के नहीं मिलने पर उपद्रवी और बेकाबू हो गए। मीरपुर मथेलो और अदिलपुर समेत घोटकी के आस-पास के इलाकों में भी उपद्रव हुआ। बाद में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि आरोपित नोतन मल को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने यह भी दावा कि घोटकी में हालात को तुरंत काबू कर लिया गया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता रमेश कुमार वंकवानी ने कहा कि मामले की जांच हैदराबाद के डिप्टी इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है। वंकवानी पाकिस्तान हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। वंकवानी ने भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने तीन मंदिरों, स्कूल और हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। उन्होंने पुलिस से दंगाइयों के खिलाफ केस दर्ज करने का अनुरोध भी किया।

इससे पहले, हिंसा भड़कने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हिंसा का वीडियो साझा करते हुए सरकार से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मानवाधिकार आयोग ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। मंदिरों और स्कूलों में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के खिलाफ सुनवाई आज

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के संबंध में विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वैधता को चुनौती और राज्य में लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों के मामले भी शामिल हैं।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

आंध्र प्रदेश में नाव गोदावरी नदी में पलटी, 12 की मौत

अमरावती : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में नाव हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग लापता हैं। 60 सैलानियों और चालक दल के सदस्यों से भरी नाव गोदावरी नदी में पलट गई। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

हांगकांग में फिर चले आंसू गैस के गोले और पेट्रोल बम

रायटर : हांगकांग में रविवार को लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर टकराव हुआ। स्वायत्त क्षेत्र के विधानमंडल भवन और केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोका तो टकराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार छोड़ी तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और पेट्रोल बम चलाए।

स्पोर्ट्स ▸ पृष्ठ 14

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी-20 मैच धुला

धर्मशाला : टी-20 विश्व कप 2020 की तैयारी को लेकर धर्मशाला में सीरीज का पहला मैच खेलने की भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों की उम्मीदों पर मौसम ने पानी फेर दिया। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को मोहाली में होगा। धर्मशाला में रविवार दोपहर करीब एक बजे पानी बरसना शुरू हुआ, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी छा गई।

उत्तर भारतीयों की योग्यता पर सवाल उठाने पर घिरे गंगवार

जागरण संवाददाता, बरेली

▸ केंद्रीय मंत्री ने कहा था, जो कंपनियां नौकरी देने आतीं हैं, उन्हें उनके मुताबिक युवा नहीं मिल पाते

उत्तर भारतीय युवाओं में कौशल की कमी की बात कहकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस महासचिव ने ट्वीट किया कि मंत्री का यह बयान उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाला है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए ट्वीट किया कि मंत्री माफी मांगें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बयान को युवाओं का मनोबल तोड़ने वाला बताया।

मोदी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर शनिवार को गंगवार ने बरेली में प्रेस वार्ता की थी। देश में मंदी और नौकरी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि नौकरियों की कमी नहीं है। उत्तर भारत में जो कंपनियां भर्ती के लिए आती हैं, उनमें से कुछ के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके काम के अनुसार गुणवत्ता नहीं मिल पाती। हम युवाओं को उस लायक बनाने पर काम कर रहे हैं। रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की लंबी सूची के बाबत तर्क दिया कि बड़ी संख्या में पंजीकृत युवा अच्छी नौकरी हासिल कर चुके हैं। उससे भी बेहतर मौके पाने की तलाश में वे

संतोष गंगवार फाइल फोटो

अपना पंजीकरण निरस्त नहीं कराते। इसलिए सूची लंबी है।

प्रियंका बोलीं, ये नहीं चलेगा : कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि 'मंत्रीजी, पांच साल से ज्यादा समय से आपकी सरकार है। नौकरियां पैदा नहीं हुईं। जो नौकरियां थीं वो सरकार द्वारा लाई आर्थिक मंदी के चलते छिन रही हैं। नौजवान रास्ता देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छा करे। आप उत्तर भारतीयों का अपमान करके बच निकलना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा।' जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि गंगवार के इस वक्तव्य से उत्तर भारत के युवाओं की परेशानी और बढ़ेगी। गंगवार जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह के वक्तव्य से परहेज करना चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्रियों के हास्यास्पद बयानों के बाद उत्तर भारतीयों की बेरोजगारी दूर करने के बजाय यह कहना कि रोजगार की कमी नहीं बल्कि योग्यता की कमी है, अति-शर्मनाक है।

रविवार को ऐसे दी सफाई

मैंने उत्तर भारतीयों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो मेरे सामने प्रमाण लाए। मैंने गुणवत्ता ठीक करने की बात की थी।

(ग्वालियर से दिल्ली लौटते वक्त फोन पर हुई बातचीत के अनुसार)

महंगा पड़ेगा खुले में कचरा जलाना, होगी जेल

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▸ पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण ने दिए निर्देश, दिल्ली समेत चार राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछी बैठक की तारीख

इस बार सर्दियों में खुले में कचरा जलाया तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, उनसे पूछा है कि सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी पर बैठक कब बुलाई जा सकती है।

वायु प्रदूषण के लिहाज से 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक का समय दिल्ली-एनसीआर में सर्वाधिक चिंताजनक होता है। हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिमी या पश्चिमी होने के कारण उसमें नमी की मात्रा काफी अधिक हो जाती है। ऐसे में प्रदूषक कण उड़ नहीं पाते और वातावरण में जमने लगते हैं। इस मौसम में अगर प्रदूषण बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जाए तो परिस्थितियां गैस चैंबर में बदलने लगती हैं। दिल्ली-एनसीआर ने 2016 और 2017 लगातार दो साल इस स्थिति का सामना किया है। 2018 में गैस चैंबर वाले हालात भले ही नहीं बने, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपातकालीन स्थिति अवश्य बन गई थी। इस साल समय रहते तैयारी शुरू कर दी गई है। सर्दियों में चोरी छिपे खुले में कचरा जलाने की घटनाएं खूब होती हैं। रात के अंधेरे में औद्योगिक कचरे, रबड़ और प्लास्टिक में आग लगाई जाती है। बीते वर्ष ईपीसीए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की टीमों ने ऐसे अनेक मामले पकड़े थे और पांच हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी ठोका था। इस बार ईपीसीए ने सख्ती जताते हुए ऐसा करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने का निर्णय लिया है।

प्रतीकात्मक

> प्रदूषण से जंग में सख्ती बहुत जरूरी हो गई है। हालांकि नोएडा में पहले भी ऐसे कुछ मामलों में कार्रवाई की गई है, लेकिन अब समूचे दिल्ली-एनसीआर में सख्ती से कार्रवाई होगी। जल्द ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य सचिवों के साथ सारी तैयारी पर बैठक भी की जाएगी।
>
> -भूरेलाल, अध्यक्ष, ईपीसीए

बताया जाता है कि ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने दिल्ली-एनसीआर में शामिल शहरों वाले चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्हें स्थानीय निकायों को इसके लिए निर्देश जारी करने को कहा गया है कि 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक की अवधि में दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू रहेगा। अगर कोई भी खुले में कचरा, रबड़ या प्लास्टिक जलाता हुए पाया जाए तो सार्वजनिक स्थल पर गड़बड़ी फैलाने या जनता के लिए परेशानी उत्पन्न करने के जुर्म में धारा 133 के तहत न केवल उस के खिलाफ मामला दर्ज हो बल्कि जेल की हवा भी खिलाई जाए। पत्र में कहा गया है कि सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए उनका क्या एक्शन प्लान है, इस पर ईपीसीए की टीम उन्हीं के गृहक्षेत्र में आकर बैठक करना चाहती है, तारीख तय करके इसकी सूचना दें।

गंगा की अविरल धारा में अब बाधा नहीं बनेंगे बांध

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

व्यवसायिक हितों के चलते ई-फ्लो के नियमानुसार गंगा में पानी न छोड़ने वाली मौजूदा हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने मौजूदा हाइड्रोपावर परियोजनाओं को ई-फ्लो नियमों का पालन करने के लिए 8 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया था लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिसंबर 2019 कर दिया है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसका मतलब यह है कि गंगा नदी पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव तक गंगा नदी पर स्थित सिंचाई परियोजनाओं सहित सभी बांधों को 15 दिसंबर 2019 से ई-फ्लो के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सरकार ने यह कदम केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी) की निगरानी और एक विशेषज्ञ दल की उस जांच रिपोर्ट के बाद उठाया है जिसमें कहा गया था कि कई मौजूदा जल विद्युत परियोजनाएं अपने व्यवसायिक हितों के चलते गंगा में जरूरी मात्रा में पानी नहीं छोड़ रही हैं। एक सितंबर 2019 को **दैनिक जागरण** ने यह खबर प्रकाशित करते हुए बताया था कि मौजूदा कंपनियां ई-फ्लो के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। सरकार ने 9 अक्टूबर 2018 को ई-फ्लो के नियमों की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत जिन परियोजनाओं में मानकों का पालन करते हुए जल छोड़ने की संरचना नहीं है, उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा ताकि वे संरचना में जरूरी बदलाव कर सकें।

ई-फ्लो की मौजूदा संरचना में बदलाव की जरूरत नहीं पेज>>7

अरैमको ने भारत में तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने का भरोसा दिलाया

रियाद : यमन के हाउती विद्रोहियों के ड्रोन हमले का शिकार हुई सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको ने भारत में तेल आपूर्ति प्रभावित नहीं होने का भरोसा दिलाया है। सूत्रों के अनुसार, अरैमको ने एक भारतीय रिफाइनरी को बताया कि हमले के कारण तेल आपूर्ति पर तत्काल कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरैमको की अबकैक स्थित ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी और खुरैश स्थित बड़ी ऑयल फील्ड को शनिवार को ईरान समर्थित यमन के हाउती विद्रोहियों ने ड्रोन से निशाना बनाया था। (पेज-13)

श्रीनगर में दिखे 24 आतंकी, बड़ी वारदात की फिराक में

राज्य ब्यूरो, जम्मू

श्रीनगर में बड़ी वारदात की फिराक में 24 से अधिक आतंकी दाखिल हुए हैं। दहशतगर्द व्यापारियों को धमका रहे हैं कि दुकानें बंद रखें, वर्ना जान से मार देंगे। यही वजह है कि अभी तक बाजार पूरी तरह से नहीं खुले हैं। वहीं, आतंकियों की मौजूदगी की सूचनाओं से सुरक्षा एजेंसियों से लेकर राज्य प्रशासन तक सकते में है। ज्ञात हो, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर के हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने पाबंदियों को लगभग हटा दिया है। वहीं, श्रीनगर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर के डाउन टाउन में कुछ आतंकियों को घूमते देखा गया है। आतंकी लाल चौक, राजबाग, जवाहर नगर समेत कई क्षेत्रों में व्यापारियों को दुकानें न खोलने के लिए धमका रहे हैं। आतंकी वारदात करने के अलावा हालात खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

आतंकरोधी ऑपरेशन ढीले पड़े : एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पांच अगस्त के बाद आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन ढीले पड़े हैं। एक महीने से सिर्फ दो ही मुठभेड़ हुई हैं। इनमें एक 20 अगस्त को बारामुला और दूसरी नौ सितंबर को सोपोर में हुई है। प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी नागरिक की हिंसा में मौत न हो। आतंकी वारदात के दौरान कई बार हिंसा होने की आशंका बनी रहती है। श्रीनगर शहर को साल 2012 में आतंकवाद मुक्त करार दे दिया था। शोपियां के आतंकवादग्रस्त क्षेत्र में बीते शनिवार को आतंकियों ने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप को जलाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी आतंकियों के होने की संभावना से इन्कार नहीं किया है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि आतंकी सरेआम घूम रहे हैं। वहीं, सूत्रों का कहना है कि दो दर्जन आतंकवादी श्रीनगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखे गए हैं।

मोदी का जलवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कायम है, लोकप्रियता का आलम उन्हें मिले उपहारों की नीलामी को देखकर हो जाता है

500 रुपये के गमछे की 11 करोड़ की बोली

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▸ प्रधानमंत्री को मिले 2772 उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शुरू, नमामि गंगे के लिए निधि जुटाना है मकसद

▸ पीएसएलवी-सी7 के धातु से बने मॉडल की कीमत लगी एक करोड़

▸ कीमत तय करने में बरती गई पूरी पारदर्शिता, सीबीआइसी की ली गई मदद

अति महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के लिए निधि जुटाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले एक साल में मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी शनिवार को शुरू हुई। पीएम की लोकप्रियता का आलम यह है कि इन उपहारों के लिए लोग हैरान कर देने वाली बोली लगा रहे हैं। अंगवस्त्रम (गमछा या अंगोछा) की बोली 11 करोड़ रुपये लगी है तो पीएसएलवी-सी7 के धातु से बने मॉडल की कीमत एक करोड़ रुपये पहुंच गई। अंगवस्त्रम का मूल्य 500 रुपये और पीएसएलवी-सी7 की कीमत दो हजार रुपये रखी गई थी।

पहले कार्यकाल में मिले उपहारों की भी हुई थी नीलामी : इन उपहारों की नीलामी 3 अक्टूबर तक इंफारमेटिक्स सेंटर (एनआइसी) की वेबसाइट https://pmmementos.gov.in/pmmementos/#/ पर की जाएगी। पीएम के तौर पर मोदी के पहले कार्यकाल में मिले उपहारों की नीलामी 27 जनवरी से 9 फरवरी 2019 तक चली थी। 4000 से अधिक उपहारों की नीलामी से मिला पूरा धन नमामि गंगे परियोजना को अर्पित किया गया था। तब सबसे अधिक बोली लकड़ी से बनी बाइक पर पांच लाख रुपये लगी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिले पीएसएलवी का मॉडल, इसकी एक करोड़ रुपये बोली लगाई गई है। जागरण

बोली लगाने से पहले देख भी सकते हैं स्मृति चिह्नों को : पिछली बार लोगों ने ऑनलाइन के साथ नीलामी स्थल इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में जाकर बोली लगाई थी। मगर इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। एनजीएमए में जाकर इन स्मृति चिह्नों को देखा भी जा सकता है। रविवार को ही 100 से अधिक लोग इन्हें देखने पहुंचे। इस बार नीलामी के लिए कुल 2772 उपहार रखे गए हैं जो पीएम को देश में अलग-अलग स्थानों पर प्रवास के दौरान या दिल्ली में देश-विदेश के अतिथियों से मुलाकात में भेंट में मिले।

इस बार सबसे कम कीमत गणेश जी की छोटी सी मूर्ति की रखी गई है, जो 200 रुपये है। अधिकतम कीमत का उपहार 2.5 लाख रुपये का है। इनकी कीमत तय करने में पारदर्शिता का खयाल भी रखा गया है। इसमें कला विशेषज्ञों के साथ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) का सहयोग भी लिया गया है। नीलामी में गाय-बछड़े की धातु की प्रतिकृति की बोली 51 लाख रुपये लगी है। इसके साथ-साथ अंगवस्त्रम व पीएसएलवी-सी7 को बोली प्रक्रिया से हटा लिया गया है। नीलामी प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक फिलहाल बोलियों की जांच की जा रही है। अगर इन्हें संदिग्ध पाया गया तो इन उपहारों की नए सिरे से बोली लगेगी। नीलामी पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है।

1102 गाड़ियां जब्त की गई हैं एक सितंबर से 12 सितंबर तक यातायात नियम का पालन नहीं करने पर। इस दौरान 3168 लोगों के चालान काटे गए हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर 2019

अस्पतालों में खाली बेड की सूचना होगी ऑनलाइन

सुविधा ▸ दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेल्थ मिशन के साथ मिलकर ऑनलाइन प्लेटफार्म कर रहा तैयार

अभी सरकारी अस्पतालों में जगह के बारे में नहीं मिल पाती है जानकारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं होने के कारण अक्सर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर गंभीर मरीजों को जरूरत के वक्त आइसीयू में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पाता। अस्पताल में भले ही वेंटिलेटर खाली हो फिर भी मरीज को यह कहकर दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है कि वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग स्टेट हेल्थ मिशन के साथ मिलकर ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध बेड व वेंटिलेटर की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। इस सुविधा के शुरू होने पर मरीजों को वेंटिलेटर उपलब्ध कराने से इन्कार करना आसान नहीं होगा क्योंकि तीमारदार भी ऑनलाइन यह देख सकेंगे कि अस्पतालों के किस विभाग में कितने आइसीयू बेड हैं, उनमें से कितने के साथ वेंटिलेटर हैं।

कुछ माह पहले कई अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराने और तीमारदारों द्वारा अंबु बैग के सहारे मरीजों को सांस देने के मामले सामने आए थे। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था। तब अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अधिकारी कहते हैं कि इसके मद्देनजर ही ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

वैसे निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए आरक्षित बेड की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने की पहले से व्यवस्था है। इसमें जनरल वार्ड के बेड के अलावा आइसीयू बेड की स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अनुसार निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए कुल 148 क्रिटिकल केयर बेड उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर 46 हैं जिनमें से 21 खाली हैं। अक्सर ऐसी ही स्थिति होती है। फिर भी सरकारी अस्पतालों में मरीज वेंटिलेटर के लिए दर-दर भटकने को मजबूर होते हैं।

डेंगू से निपटने के लिए सड़कों पर उतरी सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। इस दौरान यह भी पता लगाया गया कि लोग डेंगू से बचने के लिए अपने घरों का निरीक्षण कर रहे हैं या नहीं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्रिकेटर कपिल देव, गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री तापसी पन्नू सहित कई बड़ी हस्तियों ने लोगों से अपील की है।

अभियान के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में सहयोगियों को अभियान में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया था। इसके तहत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने क्षेत्र के मानस अपार्टमेंट, मयूर विहार फेज-एक के आचार्य निकेतन और पांडव नगर में निवासियों के छोटे समूहों के साथ मुलाकात की। सिसोदिया ने अभियान को लेकर लोगों से बात की और उनसे कहा कि यह ऐसा अभियान है जो मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चला रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पश्चिम विहार में निवासियों के घरों पर जाकर देखा। उन्होंने निवासियों को समझाया कि हमारे घरों के अंदर कूलर और एसी के साफ पानी से डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बल्लीमारान में स्थानीय निवासियों के एक समूह के साथ डेंगू मच्छर के बारे में जानकारी के साथ पर्चों का वितरण कराया। डेंगू को रोकने के लिए निवासियों को सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने लोगों को सूचनात्मक सामग्री बांटी। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम और गोपाल राय ने भी अभियान के तहत शहर के कुछ हिस्सों का दौरा किया।

डेंगू के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को मयूर विहार और पांडव नगर में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लोगों को जागरूक किया। सौजन्य : दिल्ली सरकार

पार्टी के विधायक भी घर से निकले

डेंगू जागरूकता के लिए पार्टी ने दिल्ली में दो सौ से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें विधायकों और पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र में लोग को जागरूक किया। विधायक प्रमिला टोकस ने मोहम्मदपुर गांव व आरके पुरम सेक्टर ।के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के लोगों से मिलीं। उनसे अपने घरों का निरीक्षण करने और प्रोत्साहित करने के लिए तस्वीरें ट्वीट करने को कहा। विधायक गिरीश सोनी ने मादीपुर क्षेत्र, विधायक राजेश गुप्ता ने नीमड़ी कॉलोनी वार्ड व कल्याणपुरी के निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के एससी-एसटी विंग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने भी सुबह अपने घर के निरीक्षण की तस्वीरें ट्विटर पर साझा कीं।

कस्टम बांड का मालिक विदेशी शराब की तस्करी में गिरफ्तार

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

▸ उसका कर्मचारी और शराब खरीदना वाला भी पकड़ा गया

▸ अर्जेंटीना और चिली की बनीं शराब की 20 पेटियां की गईं बरामद

देश और विदेश में बनी शराब की तस्करी में अब तक शराब माफिया और उनके कारिंदों के पकड़े जाने की बात सामने आती रही है, लेकिन रविवार को विदेशी शराब की तस्करी में कस्टम बांड के मालिक को ही गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी विभाग का दावा है कि देश में पहली बार शराब तस्करी में कस्टम बांड के मालिक की गिरफ्तारी हुई है।

आबकारी विभाग में तैनात एसीपी आलोक कुमार के मुताबिक गिरफ्तार किया गया कस्टम बांड का मालिक अमित अग्रवाल (44) सफदरजंग इंक्लेव में रहता है। विभाग ने उसके कर्मचारी भूपेश (नई बस्ती, आनंद पर्वत) व अवैध रूप से विदेशी शराब खरीदने वाले हरचरण सिंह (राजौरी गार्डन) को भी गिरफ्तार किया है। हरचरण शराब को पंजाबी बाग व मॉडल टाउन में रहने वाले अमीर लोगों, फार्म हाउस, बार, क्लब व रेस्टोरेंट आदि में आपूर्ति करता था।

अधिक मुनाफे के चक्कर में तस्करी : रविवार सुबह पांच बजे आबकारी विभाग को सूचना मिली कि अमित अग्रवाल का कर्मचारी भूपेश विदेशी शराब लेकर अवैध रूप से हरचरण सिंह को आपूर्ति करने पश्चिम दिल्ली जा रहा है। विभाग की टीम ने सुबह करीब आठ बजे रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास भूपेश व हरचरण को दबोच लिया। भूपेश उस समय अमित की रिट्ज कार से शराब निकालकर हरचरण को सौंप रहा था। कार की डिग्गी से अर्जेंटीना और चिली निर्मित शराब की 20 पेटियां बरामद हुईं। बरामद शराब की कीमत तीन लाख बताई जा रही है। पूछताछ में भूपेश ने बताया कि वह अमित अग्रवाल के कहने पर लोगों को विदेशी शराब आपूर्ति करने का धंधा कर रहा था। इसके बाद अमित को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कस्टम बांड मालिक अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपने विश्वास पात्र कर्मचारियों के जरिये तस्करी करवाते हैं।

कस्टम बांड के पास आती है विदेशी शराब

भारत में बनी शराब विभिन्न कंपनियों से बनकर पहले एक्साइज बांड में आती है। वहां से अधिकृत ठेके, बार, रेस्टोरेंट आदि में आपूर्ति की जाती है। इसी तरह विदेशों में बनी शराब कस्टम बांड के पास आती है। वहां से एक्साइज व कस्टम की अनुमित के बाद विदेशी शराब ठेके व अन्य जगहों पर आपूर्ति की जाती है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली में चार-पांच कस्टम बांड हैं, जो विदेशों से शराब मंगवाकर दिल्ली में आपूर्ति करते हैं। कस्टम बांड का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लोगों को करीब 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

रद होगा लाइसेंस

बांड मालिक अमित का करीब 500 करोड़ का सालाना टर्न ओवर बताया जा रहा है। अब उसके लाइसेंस को रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

गांधी जयंती पर कांग्रेस राजीव भवन से निकालेगी पदयात्रा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में प्रदेश कांग्रेस दो अक्टूबर को महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष का एक साल पूरा होने पर पदयात्रा निकालेगी। यह पदयात्रा सुबह साढ़े नौ बजे राजीव भवन से शुरू होकर राजघाट स्थित गांधी समाधि पर 11 बजे खत्म होगी। आयोजन को लेकर रविवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको ने प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की।

चाको ने दिल्ली के सभी पूर्व सांसदों, पूर्व मंत्रियों, जिला अध्यक्षों और पार्टी के प्रमुख नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यों दो अक्टूबर को पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित पदयात्रा को राष्ट्रीय आयोजन माना जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। चाको ने सभी जिला अध्यक्षों से अपील की कि वे अपने-अपने जिलों से अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। वे ब्लॉक कांग्रेस समितियों से भी अधिकाधिक कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए कहें।

इस दौरान उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को प्रदेश महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल और अन्य फ्रंटल संगठनों का समर्थन लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए कहा। चाको ने बैठक में बताया कि एआइसीसी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की पदयात्रा को केंद्रीय कार्यक्रम बनाना है और राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करना है। इस बैठक में तीनों कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ, देवेंद्र यादव व राजेश लिलोठिया, पूर्व सांसद रमेश कुमार, कृष्णा तीरथ व उदित राज, डॉ. नरेंद्र नाथ, डॉ एके वालिया आदि मौजूद थे।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में पीसी चाको। सौजन्य : कांग्रेस

'अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर केंद्र का देंगे साथ'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आर्थिक सुस्ती को दूर करने में उनकी सरकार केंद्र को पूरा सहयोग देगी। अगर जल्द अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी तो इसका असर राजस्व को जुटाने पर पड़ सकता है। कर संग्रहण कम हो सकता है। वह एनडीएमसी कंवेंशन सेंटर में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) की ओर से आयोजित व्यापारी व उद्यमी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सीटीआइ के तीन साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 27 उद्यमी, व्यापारी, समाजसेवी व महिला कारोबारियों को नवरत्न के सम्मान से भी नवाजा गया। यह सम्मान मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ ही उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के साथ महाशय धर्मपाल की मौजूदगी में दिए गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी व्यापारी वर्ग से आते हैं। उन्हें पता है कि किस तरह व्यापारी को ग्राहक, स्टॉकिस्ट, नेता, अधिकारी समेत अन्य से संतुलन बैठाकर चलना पड़ता है। इसलिए जब वह सत्ता में आए तो सबसे पहले व्यापारियों के रास्ते में आ रही समस्याओं को खत्म करने में लग गए। छापेमारी के राज को सबसे पहले बंद कराया। इसके बाद वैट दरों में कटौती की। इसी तरह बिजली, पानी मुफ्त कराया। अब महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त होने जा रही है। इसका फायदा व्यापारी वर्ग को भी मिलेगा।

केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है। उम्मीद है कि इसमें जल्द ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो भी कदम उठाएगी राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि 2013 से अब तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं। जबकि पहले 2010 से 2013 के बीच 100 फीसद दरें बढ़ी थीं। सीटीआइ के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि सीलिंग, जीएसटी समेत व्यापारियों और उद्यमियों की हर समस्या को लेकर सीटीआइ अपने स्थापना के बाद इन तीन वर्षों में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के पास गई और रास्ता निकलवाया। यहां तक कि मुद्दों को लेकर सड़क तक पर उतरे।

एडीएमसी कंवेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल को सम्मानित करते सीटीआइ के पदाधिकारी और अन्य। सीएम ने व्यापारियों के हित में किए कार्यों को गिनाया। जागरण

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को जल्द लागू करने की तैयारी

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जल्द लागू होने जा रही है। विकास विभाग ने कैबिनेट नोट तैयार कर सरकार के पास भेज दिया है। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। योजना के तहत किसानों को उनकी फसल की लागत से 50 फीसद ज्यादा दाम दिया जाएगा। जो कि गेहूं के लिए तकरीबन 2,616 रुपये और धान के लिए 2,667 रुपये प्रति क्विंटल होता है।

दिल्ली सरकार इस योजना के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने जा रही है। प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गेहूं के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित एमएसपी से 776 रुपये और धान के लिए 897 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा है। दिल्ली सरकार यह बात साफ कर चुकी है कि दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में उत्पादन लागत ज्यादा है। इसे देखते हुए सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है। इसके आधार पर एमएसपी निर्धारित किया गया है।

20 हजार किसान परिवारों को फायदा : दिल्ली में 20 हजार किसान परिवार हैं। आप सरकार इस माह के अंत तक इस योजना को लागू करने के पक्ष में है। तैयार किए गए कैबिनेट नोट के अनुसार, इस योजना के लागू होने से सरकार पर 96.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए ये चीजें जरूरी

- लाभ लेने वाला किसान दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की खुद की जमीन होनी चाहिए।
- लाभ उसी को मिलेगा जो अपनी जमीन पर नियमित खेती करता हो।
- किसी बैंक में उसका खाता और दिल्ली के पते पर बना आधार कार्ड होना चाहिए।
- किसान के पास उसकी जमीन के पूरे दस्तावेज हों।
- निवास प्रमाण पत्र और दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र।

गाजियाबाद में यादव-गुर्जरों में बवाल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

▸ मंदिर में पंचायत के बाद पथराव और फायरिंग, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़

▸ यति नरसिंहानंद समेत 100 के खिलाफ रिपोर्ट की गई दर्ज

रोडरेज को लेकर यादव-गुर्जर समाज के लोगों में जातीय टकराव बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को डासना देवी मंदिर में दोनों पक्षों की पंचायत हुई। पुलिस व पीएसी पहले से ही तैनात थी, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही दोनों गुट भिड़ गए। पथराव और तोड़फोड़ के साथ फायरिंग भी की गई। बवाल के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। देर शाम डासना चौकी प्रभारी ने मसूरी थाने में मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद व उनके सहयोगी अनिल यादव समेत 100 लोगों के खिलाफ बलवा, धमकी देने, तोड़फोड़ करने और बिना अनुमति आयोजन करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया है।

मंदिर में 10-15 लोगों की मीटिंग होनी थी, जिसके लिए पुलिस और दो प्लाटून पीएसी मंदिर में लगाई गई थी। मगर बैठक में पहुंच गए 250 से अधिक लोग। इसके बाद भी पंचायत होने दी गई और सुबह साढ़े 10 बजे मंदिर से बाहर आते ही जमकर बवाल शुरू हो गया।

गले मिलकर विवाद निपटाया : बवाल के बाद लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुर्जर इकला गांव पहुंचे और यादव मंदिर में रुके। शाम को इकला गांव में विधायक, महंत, यतेंद्र नागर व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों समाज के लोग एक-दूसरे के गले मिले।

यह है पूरा मामला : 24 अगस्त की शाम बम्हैटा निवासी गौतम सिंह और अच्छेजा निवासी चिराग गुर्जर की गाड़ियां टकरा गई थीं। चिराग ने चार-पांच साथियों को मौके पर बुला मारपीट की थी, जिसमें सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने थाने पर समझौता कर लिया, लेकिन कुछ दिन पूर्व फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की जाने लगीं। इनमें लिखा कि यादव जाति के लोग गुर्जरों को जाति पूछ-पूछकर पीट रहे हैं। मसूरी में 13 सितंबर को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के बिना ही दोनों पक्षों ने पंचायत की और इसी दिन बम्हैटा में गुर्जर लिखी काले रंग की स्कॉर्पियो कार तोड़ दी।

डासना स्थित देवी मंदिर के पास हंगामे के दौरान कार का शीशा तोड़ता युवक। वीडियो ग्रैब

दिसंबर तक आएंगी 975 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लखनऊ स्थित टाटा मोटर्स के संयंत्र का निरीक्षण कर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली लौट आए हैं। टाटा कंपनी ने मंत्री को भरोसा दिया है कि दिसंबर तक दिल्ली में बसें उपलब्ध करा दी जाएंगी।

गहलोत दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और अन्य अधिकारियों की एक टीम के साथ 13 सितंबर को लखनऊ गए थे। परिवहन मंत्री ने वहां स्टैंडर्ड-फ्लोर क्लस्टर बसों की स्थिति की जांच की। क्लस्टर योजना के तहत कुल एक हजार स्टैंडर्ड फ्लोर साइज की बसें कंपनी से ली जानी हैं। इनमें से 25 बसें चलाई जा चुकी हैं और 975 बसें अभी आनी हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त में विशेषताओं से लैस 1,000 स्टैंडर्ड-फ्लोर बसों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई थी। मंत्री यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बसें सही समय पर आ जाएं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक इन बसों को सड़कों उतार देने का है। पूर्व योजना के तहत 15 सितंबर तक शहर में 125 बसें आने वाली थीं, जो नहीं आ सकीं। देरी को लेकर लेकर गहलोत ने टाटा मोटर्स के लखनऊ में लगे संयंत्र का निरीक्षण करने की योजना बनाई थी।

आखिरी दिन उमड़ी पुस्तक प्रेमियों की भीड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रगति मैदान में आयोजित पांच दिवसीय 25वें पुस्तक मेले का रविवार को समापन हो गया। किताबों के कुंभ में आखिरी दिन भी पुस्तक प्रेमियों ने खूब डुबकी लगाई। समापन दिवस पर पाठकों को पुस्तकों की खरीद पर काफी छूट भी मिली। अधिकतर विक्रेताओं खासकर अंग्रेजी के स्टॉलों पर 20 से लेकर 70 फीसद तक की छूट दी जा रही थी, जिस कारण यहां पाठकों की भीड़ ज्यादा रही। हिंदी की पुस्तकों पर भी 10 से 20 फीसद तक छूट मिल रही थी, जिसका किताब प्रेमियों ने लाभ उठाया। स्टेशनरी का सामान भी सस्ता कर दिया गया था।

मौसम में रविवार को बदलाव होता रहा। कभी हल्की और कभी रिमझिम बारिश भी हुई। तब भी हर उम्र के पुस्तक प्रेमियों की भीड़ पुस्तक मेले में दिखी। भारतीय प्रकाशक संघ (एफआइपी) के मुताबिक, नौ दिन के स्थान पर पांच दिन का मेला अच्छा प्रयोग रहा। संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार मित्तल और कोषाध्यक्ष नवीन गुप्ता ने बताया कि 2020 में आयोजित होने वाला दिल्ली पुस्तक मेला अब तक सबसे बड़ा मेला होगा क्योंकि तब तक प्रगति मैदान का नवीनीकरण भी पूरा हो जाएगा।

मेले के आखिरी दिन भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (आइटीपीओ) के महाप्रबंधक अभिषेक वर्मा ने कहा कि पुस्तक मेलों में पाठकों की भीड़ देखकर लगता है कि डिजिटल युग में भी पुस्तकों की महत्ता बरकरार है। आज भी हर उम्र के लोग पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं। इस दौरान मेले में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रकाशकों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने मेले के सफल आयोजन पर प्रकाशकों को बधाई देते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि अगले वर्ष दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन इससे भी ज्यादा भव्य होगा। पुरस्कारों में हिंदी भाषा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रकाशन विभाग को स्वर्ण पदक, सम्यक प्रकाशन को रजत पदक और गीता प्रेस को कांस्य पदक दिया गया। अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आर्य पब्लिशिंग कंपनी बुक्स को स्वर्ण पदक, जयको पब्लिशिंग हाउस को रजत पदक एवं ओसवाल बुक्स को कांस्य पदक दिया गया।

प्रगति मैदान में आयोजित पुस्तक मेले में पुस्तकों का अवलोकन करते लोग। जागरण

योजना पूरी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम के निजी महल का संरक्षण कार्य किया पूरा, भ्रमण के लिए लोगों के लिए खुला

मुमताज महल के निजी महल में लौटी रौनक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के लाल किला स्थित निजी महल का संरक्षण कार्य पूरा करा दिया है। अब भ्रमण करने के उद्देश्य से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। संरक्षण कार्य 112 साल के बाद कराया गया है। इससे पहले 1907 में संरक्षण कार्य कराया गया था। इसमें 1919 से संग्रहालय चल रहा था। फरवरी में इसके संरक्षण के लिए काम शुरू किया गया था।

लाल किले के दक्षिणी और पूर्वी कोने में स्थित यह महल सबसे खूबसूरत था। इसे शाहजहां के रंगमहल के करीब बनाया गया था। इसे मुमताज महल की पसंद के अनुसार सजाया गया था। दीवारों और फर्श पर बेहतरीन नक्काशी की गई थी। बताया जाता है कि 1857 में जब अंग्रेजों ने लाल किला पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने यहां बहुत तोड़फोड़ की। इसके बाद इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों को कैद कर रखा जाने लगा। बाद में जब देश की राजधानी को दिल्ली लाए जाने की योजना बनी तो लाल किला को फिर से ठीक किया जाने लगा। इस महल में भी 1907 के करीब कुछ संरक्षण कार्य कराया गया। अब भी इस महल की कुछ दीवारों पर चित्रकारी मौजूद है और कुछ स्थानों पर कांच का काम दिखाई दे जाता है। शाम के समय यह महल अब रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है।

लाल किला स्थित मुमताज महल। जागरण

मुमताज महल से जुड़ी कुछ बातें

- मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था।
- मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था।
- 14 साल की उम्र में मुमताज महल की सगाई शाहजहां के साथ हुई। दोनों की मुलाकात एक बाजार में हुई थी।
- सगाई के पांच साल बाद 10 मई 1612 को शाहजहां से मुमताज का निकाह हुआ।
- मुमताज महल शाहजहां की तीसरी और पसंदीदा बेगम थीं।
- मुमताज महल बहुत अच्छी शतरंज खिलाड़ी थीं, वह शाहजहां से भी अच्छा खेलती थीं।
- 19 साल में उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें से सात की कम उम्र में ही मौत हो गई।
- मुमताज महल का निधन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 17 जून 1631 को बेटी गौहारा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ। मुमताज महल को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था।
- मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाने का फैसला किया। इसके निर्माण में 22 साल लगे।
- बाद में बुरहानपुर के जैनाबाद से मुमताज महल के जनाजे को एक विशाल जुलूस के साथ आगरा ले जाया गया और ताजमहल के गर्भगृह में दफना दिया गया। बताया जाता है कि उस जुलूस पर उस समय आठ करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

'सभ्य कपड़े' पहनने के फरमान का छात्राओं ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ हिंदूराव मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में रह रही छात्राओं के लिए जारी किया गया अजीबो-गरीब निर्देश

▸ छात्राओं में रोष, शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, निगमायुक्त ने अनभिज्ञता जाहिर की

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले हिंदूराव मेडिकल कालेज की छात्राओं के लिए अजीबो-गरीब फरमान जारी किए जाने को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल, कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एमबीबीएस की छात्राओं को छात्रावास व मेडिकल कालेज में शालीन कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। अगर छात्राओं ने दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अलावा उन्हें छात्रावास से निकाला भी जा सकता है।

कॉलेज प्रशासन के इस फरमान के बाद छात्राएं विरोध कर रही हैं। साथ ही इसके खिलाफ उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि कोई भी छात्र-छात्रा खुलकर सामने नहीं आ रहा। एक छात्रा ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि प्रशासन कैसे तय कर सकता है कि हम कैसे कपड़े पहनें। यह पिछड़ी सोच को दर्शाता है। इससे छात्राओं में रोष है।

छात्राओं का कहना है कि प्रशासन को इस नोटिस को वापस लेना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। छात्रावास में करीब 250 विद्यार्थी हैं, जिनमें 50 फीसद छात्राएं हैं। हालांकि इस मामले में निगमायुक्त वर्षा जोशी का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं हैं। वह इस मामले को देखेंगी। इसके बात ही वह इस बारे में कुछ कह सकेंगी।

184 क्लास रूम को डिजिटल स्वरूप दिया गया है ओडिशा में। ये क्लास रूम कुल नौ केंद्रीय विद्यालयों में स्थित हैं। पूरी परियोजना में कुल चार करोड़ रुपये की लागत आई है। माना जा रहा है कि इससे 12 हजार से अधिक छात्रों को लाभ होगा।

कांग्रेस में बाहरियों के लिए कूलिंग पीरियड

नई नीति ▶ दूसरे दलों से आए नेताओं को पांच साल बाद ही मिल सकेगा कोई अहम पद

संगठन के सभी स्तरों पर निष्ठावान नेताओं को पार्टी में मिलेगी तवज्जो

संजय मिश्र, नई दिल्ली

सोनिया गांधी

राहुल गांधी फाइल फोटो

अच्छे दिनों में साथ और बुरे दिनों में घात के हालत से रूबरू हो रही कांग्रेस बाहर से आए नेताओं को अब संगठन में अहम जिम्मेदारी देने से परहेज करेगी। इस लिहाज से पार्टी ने बाहर से आने वाले नेताओं को पांच साल तक पद नहीं देने की अपनी पुरानी नीति पर अमल को तवज्जो देने का फैसला किया है। कांग्रेस के शीर्ष संगठन के साथ कुछ राज्यों के संगठन में होने वाले बदलाव में पार्टी हाईकमान निष्ठावान नेताओं को वरीयता देते हुए कार्यकर्ताओं को इस आशय का संदेश देने की कोशिश करेगा।

लोकसभा चुनाव के पहले से ही नेताओं के पार्टी छोड़ने के लगातार जारी सिलसिले को थामने की रणनीति के तहत कांग्रेस नेतृत्व ने 'बाहरी नेताओं' की बजाय पार्टी के प्रति वफादार रहे नेताओं-कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी देने का संदेश देगी। दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को तत्काल मौका दिए जाने को लेकर विगत में कांग्रेस वैसे तो समय-समय पर पांच साल के 'कूलिंग पीरियड' की बात कहती रही है मगर इस पर अमल शायद ही हुआ हो। लेकिन लोकसभा के चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय ही नहीं राज्य स्तर पर कांग्रेस नेताओं ने जिस गति से पार्टी छोड़ी है वह नेतृत्व के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सोनिया गांधी की बीते गुरुवार प्रदेश अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में नेताओं के पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर चर्चा हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ऐसे लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया है।

खासकर महाराष्ट्र में अभी चुनाव से पहले कांग्रेस के दर्जनों बड़े नेता भाजपा या शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसीलिए पार्टी हाईकमान ने सभी राज्यों के प्रभारी महासचिवों और प्रदेश इकाईयों को अपने-अपने स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी देने के मामले में पांच साल के कूलिंग पीरियड की नीति का ख्याल रखने को कहा है। वैसे पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहने वालों को ईनाम मिलने का संदेश देने के लिए कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाइयों से कहा है। 2004, 2009 और 2014 की लोकसभा और इस दौरान राज्यसभा में पार्टी के सांसद रहे उन नेताओं की सूची कांग्रेस नेतृत्व ने मांगी है जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संगठन के पुनर्गठन में पार्टी के प्रति वफादार ऐसे नेताओं को मौका दिया जाएगा।

राजनीतिक संकट के इस दौर में पार्टी के भीतर इस बात का बखूबी अहसास किया जा रहा कि बाहरी नेताओं को एक सीमा से ज्यादा तवज्जो देने से कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हुआ है। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला या फिर महाराष्ट्र में नारायण राणे का उदाहरण देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि दोनों सत्ता का लाभ उठाने के लिए कांग्रेस में रहे मगर जब संघर्ष का समय आया तो पार्टी छोड़ने में देर नहीं की। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत की दहलीज से मामूली अंतर से दूर रह गई और वाघेला ने इस नुकसान में अपनी भूमिका निभाई। पार्टी सूत्रों ने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले नेताओं को तुरंत कोई पद नहीं दिया जाना इसीलिए भी जरूरी है कि मौकापरस्त लोगों को भी संदेश दिया जा सके। अभी हाल में राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं संजय सिंह और भुवनेश्वर कालिता का उदाहरण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि दोनों को पार्टी ने सब कुछ दिया। लेकिन जब पार्टी के लिए कुछ करने की बारी आई तो दोनों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इसीलिए कांग्रेस के संगठन में किए जा रहे बदलावों में सोनिया गांधी ऐसे नेताओं को तरजीह दे रही हैं जो सुख-दुख में पार्टी के साथ रहे हैं। हरियाणा में कुमारी सैलजा, झारखंड में रामेश्वर उरांव और एकनाथ खड़से को मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना यही दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश में मंत्रियों और अफसरों का इम्तिहान, योगी उड़नदस्ता

राजीव दीक्षित, लखनऊ

लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 'मंथन-2' ● आइआइएम लखनऊ में हुई सरकार के मंत्रियों और अफसरों की परीक्षा, समूहों के बीच परीक्षक के तौर पर घूमकर टीम की थाह लेते रहे मुख्यमंत्री

लखनऊ में रविवार को आइआइएम में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 'मंथन-2' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने प्रबंधन का पाठ पढ़ा। एएनआइ

रविवार सुबह नौ बजे हैं। छुट्टी का दिन होने के बावजूद भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) लखनऊ के बोधिगृह-द्वितीय भवन की पहली मंजिल पर हलचल है। यहां परीक्षा कक्ष के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा सीटिंग प्लान पर निगाहें दौड़ा रहे योगी सरकार के दो कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री और मुकुट बिहारी वर्मा यह ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉल के अंदर उन्हें किस टेबल पर बैठना है। इस बीच सरकार के मंत्रियों और मुख्य सचिव समेत शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की जमात हॉल के अंदर समूहवार लगीं 11 राउंड टेबलों पर अपने-अपने नामों की तख्तियां देख नियत स्थान पर बैठ चुकी है। बैचमेट आइएएस अफसरों के बीच हंसी-ठट्ठा, धौल-धप्पा भी चल रहा है और मंत्रियों के बीच सलाम-दुआ भी।

आइआइएम लखनऊ की निदेशक प्रो. अर्चना शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हॉल में दाखिल होते ही यह सुनगुन खामोशी में तब्दील हो जाती है। कार्डलेस माइक लिए प्रो.अर्चना मंत्रियों को एक परिस्थिति विशेष के बारे में बताती हैं। जिस विषम परिस्थिति का वह जिक्र कर रही हैं, उसका मजमून परीक्षा हाल में बैठे मंत्रियों, अफसरों को दिए जा चुके कागज पर भी लिखा है। मुख्यमंत्री आहिस्ता से मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी वाली राउंड टेबल के साथ लगी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कागज का टुकड़ा उठाकर मंद-मंद मुस्कुराते हुए उसे पढ़ने लगते हैं तो अब तक रिलैक्स्ड नजर आ रहे मुख्य सचिव अंगुली से चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए गंभीर मुद्रा अख्तियार कर कागज में खो जाते हैं। मुख्यमंत्री के उठकर जाते ही मुख्य सचिव अंगुलियों में कलम फंसाए टेबल पर बैठे समूह के सदस्यों को कुछ बताने लगते हैं। चर्चा में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर, अपर मुख्य सचिव अनीता भटनागर जैन, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह भी शामिल होते हैं। चेहरों से तनाव बर्फ की मानिंद पिघलता है और फिर हंसी की फुहार छूटती है।

नर्वस दिखे श्रम राज्य मंत्री : योगी उठकर दूसरी राउंड टेबल पर पहुंचते हैं तो प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन राजन शुक्ला हड़बड़ा कर उठते हैं और बगल की कुर्सी पर रखा बैग झट से उठाकर मुख्यमंत्री को स्थान देते हैं। योगी के बैठते ही श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मन्नूलाल कोरी एड़ियां उचका कर पंजों के बल पर पैर ऊपर नीचे हिलाने लगते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर है कि वे नर्वस महसूस कर रहे हैं। योगी ने माहौल में तनाव भांपा, टेबल के उस पार बैठे उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से कुछ चुटकी ली और चल दिए।

हड़बड़ाए मंत्री तो सीएम ने सहज किया : योगी का अगला पड़ाव वह राउंड टेबल थी जिसके चारों ओर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता, प्रमुख सचिव परिवहन अरविंद कुमार व अन्य बैठे थे। मुख्यमंत्री के आते ही सभी सतर्क हो गए और उनका अभिवादन किया। इस समूह के सदस्यों से संक्षिप्त परामर्श के बाद योगी उस टेबल पर पहुंचे जिस पर कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक और चेतन चौहान बैठे थे। पीछे से आए मुख्यमंत्री की बगल में मौजूदगी को भांपकर स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल अचकचा गए लेकिन योगी ने कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सहज किया। प्रमुख सचिव सिंचाई टी. वेंकटेश ने मुख्यमंत्री को कुछ बताया और फिर वह आगे बढ़ गए।

योगी के जाते ही मंत्री ने पिया पानी : फिर योगी उस टेबल पर गए जिस पर समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता समेत अन्य बैठे थे। योगी के पहुंचते ही इस समूह के सदस्यों के बीच चल रही गपशप थमी और माहौल में संजीदगी छा गई। समूह से संक्षिप्त चर्चा कर योगी आगे बढ़े, तब जाकर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ.सतीश द्विवेदी ने निश्चिंतता के भाव के साथ सामने रखे तांबे की वाटर बॉटल से गिलास में पानी उड़ेला और सूखे गले को तर किया।

सुरक्षाकर्मियों में भी रहा कौतूहल : अंदर चल रही इस अजब-गजब परीक्षा को लेकर हॉल के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों में भी कौतूहल था। कार्यक्रम शुरू होने के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे एक सुरक्षाकर्मी ने हॉल के दरवाजे पर लगे शीशे से भीतर झांकने के बाद पहले से तैनात सहयोगी से पूछा कि अंदर क्या हो रहा है? सहयोगी ने विलंबित लय वाले पुरबिया लहजे में बताया कि 'मंत्री और अफसर लोग परीक्षा दे रहे हैं न।' 'लेकिन मुख्यमंत्री जी तो हॉल में टहल रहे हैं?' पहले ने फिर सवाल किया तो सहयोगी सुरक्षाकर्मी ने स्थिति स्पष्ट की 'मुख्यमंत्री जी तो उड़नदस्ता हैं न।'

आकाश से गिरे, रेगिस्तान में अटके : प्रशिक्षणार्थी मंत्रियों और अफसरों को इस परीक्षा में एक विषम परिस्थिति से रूबरू कराया गया ताकि उनका आकलन किया जा सके। उन्हें बताया गया कि आप एक हवाई जहाज पर सवार हैं जो रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान दुर्घटना में पायलट और दो क्रू मेंबर घायल हो जाते हैं। विमान में आपके पास पानी, नमक की टैबलेट, पैराशूट, ओवरकोट, रेनकोट, चश्मा, चाकू, जानवरों की किताब, पिस्टल, दर्पण समेत कुल 15 वस्तुएं हैं। जान बचाने के लिए समूह को विमान से बाहर निकलना है तो इनमें से इनमें से किन-किन वस्तुओं का प्राथमिकता के आधार पर चयन करेंगे। प्रत्येक कार्यसमूह को संगठित रूप से और उसके हर सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर अपनी प्राथमिकताएं लिखकर बतानी थीं। सदस्यों के व्यक्तिगत और समूह के सामूहिक उत्तर के आधार पर टीम की कार्यसाधकता और समन्वय के आधार पर अंक दिए जाने थे।

न्यूज गैलरी

शरद पवार ने पाकिस्तान की तारीफों के बांधे पुल

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने रविवार को कहा कि यहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ अन्याय हो रहा है और वह नाखुश हैं। लेकिन यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति समझे बगैर सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पड़ोसी देश में जाने पर उनका वहां बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। उन्होंने बताया कि वह कई दफा पाकिस्तान जा चुके हैं। पाकिस्तानी मानते हैं कि अगर वह अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत नहीं जा सकते तो वह एक भारतीय के साथ अपने रिश्तेदारों जैसा ही बर्ताव करते हैं। (एएनआइ)

82 पूर्व सांसदों ने अब तक नहीं खाली किए बंगले

नई दिल्ली : लोकसभा समिति की कड़ी चेतावनी के बावजूद 82 पूर्व सांसदों ने अब तक लुटियन जोन में आवंटित आधिकारिक बंगलों को खाली नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार संबंधित सांसदों के खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत तौर पर रहने वालों से खाली करवाना) कानून के तहत कार्रवाई पर विचार कर रही है। सीआर पाटिल की अध्यक्षता वाली लोकसभा की आवास समिति ने 19 अगस्त को करीब 200 पूर्व सांसदों को एक सप्ताह के भीतर बंगला खाली करने का आदेश दिया था। समिति ने यह भी कहा था कि तीन दिनों के भीतर इन बंगलों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सूत्रों ने बताया, 82 पूर्व सांसदों ने अब तक बंगले खाली नहीं किए हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2014 में तत्कालीन सांसदों को आवंटित बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। पूर्व सांसदों द्वारा बंगला न खाली किए जाने से नवनिर्वाचित सांसदों को अभी अस्थायी आवास में रहना पड़ रहा है। (प्रेट्र)

मदनी-भागवत की मुलाकात को उलमा का समर्थन

बरेली : जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघ चालक मोहन भागवत की मुलाकात का बरेलवी मसलक के उलमा ने भी समर्थन किया है। दरगाह आला हजरत पर उर्स-ए-नूरी में भाग लेने पहुंचे मुंबई रजा अकादमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने शनिवार को कहा कि इस मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। पिछले कुछ समय से नफरत का दायरा बढ़ रहा है, उसे मिटाने के लिए संवाद और नजदीकियां जरूरी हैं।

सरकार वाट्सएप पर संदेशों के स्रोत जानने की मांग पर अडिग

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने दिया वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार वाट्सएप पर भेजे जाने वाले संदेशों के स्रोत तक पहुंचने की मांग पर अडिग है, जबकि फेसबुक ने संदेशों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव किया है।

संदेशों के स्रोत की पहचान का मुद्दा लंबे समय से सरकार और वाट्सएप के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। फेसबुक की कंपनी वाट्सएप संदेश डालने वाले मूल व्यक्ति की पहचान बताने की सरकार की मांग को मानने से अभी इन्कार करती आ रही है। उसका कहना है कि ऐसा करने से गोपनीयता तथा शुरू से लेकर अंत तक संदेश के इनक्रिप्शन की उसकी नीति प्रभावित होगी।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि फेसबुक के उपाध्यक्ष (वैश्विक मामले एवं संवाद) निक क्लेग ने पिछले सप्ताह केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्लेग ने संदेशों के मूल स्रोत का पूरा सुराग देने के मुद्दे पर कुछ वैकल्पिक सुझाव दिए हैं। उन्होंने मेटा डाटा (पारिभाषिक डेटा) और मशीन इंटेलीजेंस के इस्तेमाल के साथ ही कानूनी एजेंसियों को वाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंकेज का लाभ देने का विकल्प दिया।

गोपनीयता को लेकर प्रतिबद्ध : फेसबुक के प्रवक्ता ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, 'फेसबुक भारत में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखती है। निक की इस सप्ताह हुई बैठक से हमें हमारे हर एप में सुरक्षा एवं गोपनीयता को लेकर हमारी प्रतिबद्धता पर बातचीत का अवसर मिला। हमें यह भी समझने को मिला कि हम इन साझा लक्ष्यों को पाने में भारत सरकार के साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं।' वाट्सएप से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि संदेशों के इनक्रिप्टेड होने की वजह से कंपनी भी इन्हें पढ़ नहीं सकती है।

सूचना की वैध मांग मानने को बाध्य : क्लेग ने गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ 12 सितंबर को मुलाकात की। उन्होंने दोहराया कि वाट्सएप भारत सरकार द्वारा सूचना की वैध मांग को मानने के लिए बाध्य है। हालांकि उन्होंने कहा कि आदान-प्रदान किए गए संदेशों को पढ़ पाना संभव नहीं है। क्लेग ने कहा कि कंपनी सिग्नल और मेटा डाटा प्रदान कर सकती है, यह बता सकती है कि किसे कॉल किया गया और कितनी देर बात की गई। भारत में वाट्सएप के 40 करोड़ और फेसबुक के 32.8 करोड़ यूजर हैं।

राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू से कहा था, सिर्फ हिंदू लॉ क्यों

माला दीक्षित, नई दिल्ली

फिर चर्चा में यूसीसी

- हिंदू कोड बिल पर स्पष्ट रूप से कहा था, सबके लिए समान नागरिक संहिता लाओ
- हिंदू कोड बिल पर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच मचा था घमासान

डॉ राजेंद्र प्रसाद व पं. जवाहर लाल नेहरू। (आर्काइव से)

सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की तरफदारी करते हुए कहा था कि यद्यपि 1956 में हिंदू लॉ कोडीफाई हो गया, लेकिन पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। ऐसी ही बात भारत के पहले राष्ट्रपति डाक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से कही थी।

राष्ट्रपति डॉ. प्रसाद ने सिर्फ हिंदू लॉ को कानून में पिरोने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर मौजूदा कानून अपर्याप्त और आपत्तिजनक है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की जाती। सिर्फ एक समुदाय को ही कानूनी दखलंदाजी के लिए क्यों चुना गया? तत्कालीन राष्ट्रपति के कहने के बावजूद न तो तब सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए कदम उठाया, न उसके बाद कभी प्रयास हुए। 1951 में सिर्फ हिंदुओं के लिए हिन्दू कोड बिल लाने पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच काफी घमासान मचा था। दोनों ओर से पत्राचार हुए थे, बात अधिकारों तक पहुंची और अंत में अटार्नी जनरल की राय ली गई तब मामला शांत हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 सितंबर के फैसले में कहा है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में इस उम्मीद से अनुच्छेद 44 जोड़ा था कि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करेगी लेकिन आज तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। शुरुआत से मामले पर निगाह डालें तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान भले ही संविधान में शामिल कर दिया गया हो लेकिन संविधान लागू होने के बाद वह सरकार की प्राथमिकता मे नहीं रहा।

951 में हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाई करने की कोशिश शुरू हुई और नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लाई जिसका तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कड़ा विरोध किया था। उस समय की स्थिति की झलक इस मसले पर पहले राष्ट्रपति डाक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार को देखने से मिलती है। 14 सितंबर 1951 को राष्ट्रपति प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरु को पत्र लिखा था जिसमे सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाने का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए क्यों लाए जा रहे हैं बाकी समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहें। अगर मौजूदा कानून अपर्याप्त और आपत्तिजनक है तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की जाती सिर्फ एक समुदाय को ही कानूनी दखलंदाजी के लिए क्यों चुना गया।

उन्होंने कहा था कि वह बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे। उन्होंने नेहरू को यह पत्र 15 सितंबर को भेजा था। नेहरू ने उसी दिन उन्हें उसका जवाब भी भेज दिया जिसमें कहा कि आपने बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर परखने की जो बात कही है वह गंभीर मुद्दा है। इससे राष्ट्रपति और सरकार व संसद के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। संसद द्वारा पास बिल के खिलाफ जाने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। डाक्टर प्रसाद ने नेहरू को 18 सितंबर को फिर पत्र लिखा जिसमें उन्होंने संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियां गिनाई साथ ही यह भी कहा कि वह मामले में टकराव की स्थिति नहीं लाना चाहेंगे। इसके बाद मामले पर अटार्नी जनरल एमसी सीतलवाड़ की राय ली गई। सीतलवाड़ ने 21 सितंबर 1951 को दी गई राय में कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से चलेंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। इससे पता चलता है कि उस वक्त भी समान नागरिक संहिता पर चर्चा चल कर रह गई थी और आज भी मामला चर्चा तक ही सीमित है।

विशेषज्ञों ने कहा, समान नागरिक संहिता पर वार्ता शुरू करे सरकार

नई दिल्ली, आइएएनएस : समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विधि विशेषज्ञों ने कहा है कि केंद्र सरकार को इसके उपायों पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कानून प्रणाली को कारगर बनाने के लिए इसे अहम बताया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा लंबे सयम से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करती रही हैं। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। हालांकि, एक साल पहले ही केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले विधि आयोग ने इसे गैरजरूरी और अवांछित करार दिया था। वरिष्ठ वकील और संविधान के जानकारी राकेश द्विवेदी ने कहा कि असल मुद्दा यह है कि क्या धर्म के आधार पर विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानून बनाने की छूट दी जा सकती है? संविधान में तो इसकी मनाही है। उन्होंने कहा कि समान धार्मिक संहिता नहीं समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और सभी विवाहों का पंजीकरण होना चाहिए। लिंग का भेदभाव किए बिना विरासत का बंटवारा किया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील विकास सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सरकार को कार्रवाई करनी है। सरकार को समान नागरिक संहिता पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगर कोई धर्म महिलाओं को पुरुषों के आधा मानता है तो ऐसी व्यवस्था को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के खिलाफ सुनवाई आज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वैधता को चुनौती और विभिन्न प्रतिबंधों के मामले भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मूल मामला पहले ही पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा जा चुका है। इस मामले पर अक्टूबर में सुनवाई होनी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। उन्होंने घाटी में रह रहे अपने परिजनों का हाल-चाल जाने के लिए अदालत से अपने गृह राज्य में जाने की अनुमति मांगी है। इस मामले की सुनवाई भी यही पीठ सोमवार को करेगी। कांग्रेस नेता ने राज्य की सामाजिक स्थिति जानने के लिए भी सर्वोच्च अदालत से मंजूरी मांगी है। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वह दो बार वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हवाई अड्डे से ही प्रशासन ने उन्हें वापस लौटा दिया था।

सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी ने भी राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के खिलाफ याचिका दायर की है। बाल अधिकार कार्यकर्ता एनाक्षी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में अवैध तरीके से बच्चों को बंधक बनाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की याचिका पर भी होगी सुनवाई

राज्यसभा सदस्य और एमडीएमके के संस्थापक वाइको की याचिका की भी सोमवार को ही सुनवाई होनी है। इसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को उपस्थित करने का केंद्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश देने की अपील की है। वाइको ने कहा है कि प्रशासन को फारुक को 15 सितंबर को चेन्नई भेजने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के जन्मदिन पर एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे।

हाल ही में माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी थी, ताकि वह अपनी पार्टी के बीमार सहयोगी मुहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात कर सकें। यह याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें तारिगामी से मिलने के लिए कश्मीर जाने की पहले ही इजाजत दे दी थी। अदालत ने लेकिन उनकी यात्रा पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा था कि वह वापस लौटकर इस संबंध में रिपोर्ट दें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

हाईटेक आयुर्वेद

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड बनाने की दिशा में सरकार

ग्रिड से जुड़ेंगे सभी आयुष चिकित्सा केंद्र और प्रयोगशालाएं, मरीजों के लक्षण और उसके इलाज में दवाओं के असर पर रखी जाएगी नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अब हाईटेक होने जा रही है। इसके लिए देश के सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्रों और प्रयोगशालाओं को एक राष्ट्रीय आयुष ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। सरकार की कोशिश आयुर्वेदिक दवाओं से उपचार और उससे रोगियों को होने वाले लाभ का डाटा तैयार करना है, ताकि भविष्य में और बेहतर आयुर्वेदिक दवाओं का विकास किया जा सके। इसके साथ ही विभिन्न रोगों की रोकथाम में कारगर साबित होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय आयुष ग्रिड बनाने के लिए आयुष मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता भी हो गया है।

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड में आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज पर पूरी निगरानी का प्रबंध किया जा रहा है। इसके तहत मरीज के लक्षणों से लेकर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं और बाद में उनके प्रभाव का पूरा ब्यौरा आयुष ग्रिड में दर्ज होगा। इससे साफ-साफ पता चल सकेगा कि कौन सी आयुर्वेदिक दवा किस मर्ज को ठीक करने में कारगर साबित हो रही है। आयुष ग्रिड से प्रयोगशालाओं को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि इसमें

काम कर रहे वैज्ञानिक खुद दवाओं का असर देख सकें। इससे उन्हें भविष्य में बेहतर आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड के आयुर्वेदिक चिकित्सा पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। मरीजों और आयुर्वेद से इलाज का बड़ा डाटा मौजूद होने के बाद आयुर्वेद को वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार्य बनाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही विभिन्न बीमारियों के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल में भी एकरूपता आएगी। ग्रिड से जुड़े डॉक्टर इलाज में दवाओं के फायदे के अनुसार मरीजों को इस्तेमाल की सलाह दे सकते हैं। दरअसल सरकार ने पूरे देश में 12,500 आयुष केंद्र स्थापित करने का एलान किया है। इनमें से 4000 केंद्र इस साल के अंत तक शुरू जाएंगे। इन केंद्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति से मरीजों का इलाज होगा, जिनमें आयुर्वेद प्रमुख है।

दरअसल पिछले कुछ सालों में देश की चोटी की प्रयोगशालाओं में उच्च कोटि की आयुर्वेदिक दवाओं का विकास किया गया है। संबंधित रोगों के इलाज में इन दवाओं ने बाजार में अहम जगह भी बना ली है। लेकिन रोगियों पर प्रभाव का वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध न होने के कारण वैश्विक बाजार में इनकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही है।

उदाहरण के तौर पर सीएसआइआर ने डायबटीज के इलाज के लिए 'बीजीआर- 34' तैयार की है तो रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले डीआरडीओ ने किडनी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए 'नीरी-केएफटी'

18 जिलों के 102 प्रखंडों की 896 पंचातयों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है बिहार में। जिन प्रखंडों और उनके अंतर्गत आने वाली पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है वहां इस बार औसत से 30 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर 2019

संघ, शाह और सीएम की कसौटी पर टिकट का दारोमदार

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा का रण

विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हरियाणा में टिकट के लिए सबसे अधिक मारामारी सत्तारूढ़ भाजपा में मची है। चुनाव की तारीखों में जैसे-जैसे देरी हो रही है, वैसे-वैसे टिकट के लिए लॉबिंग बढ़ रही है। मौजूदा विधायक, दूसरे दलों से आए पूर्व विधायक और काडर बेस कार्यकर्ता अपनी दावेदारी जता रहे हैं। भाजपा ने फिलहाल त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। टिकट के दावेदारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कसौटी पर परखा जा रहा है, जिसमें पास होने वाले दावेदारों को ही टिकट मिलेंगे। 25 सितंबर के बाद टिकटों की घोषणा संभव है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली के बाद भाजपा ने राज्यभर में महा जनसंपर्क अभियान चलाया था। इसके बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 व 17 सितंबर को दो दिन हरियाणा के प्रवास पर रहेंगे। 16 को कुरुक्षेत्र व 17 को झज्जर में कार्यक्रम होंगे। भाजपा ने 16 सितंबर को रादौर में पिछड़ा वर्ग और 17 सितंबर को खरखौदा में दलित सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान टिकटों के बढ़ते दावेदारों के चलते भाजपा ने त्रिस्तरीय सर्वे शुरू कराया है। एक सर्वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की टीम कर रही है, जबकि दूसरा सर्वे आरएसएस द्वारा कराया जा रहा है। तीसरा सर्वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से हो रहा है। जिन दावेदारों के नाम इन तीनों सर्वे में मेल खाएंगे, उनके टिकट लगभग तय हैं। इससे इतर उन्हीं नेताओं को टिकट मिलेंगे, जो जीतने की स्थिति में होंगे तथा जातीय समीकरणों में फिट बैठेंगे।

विपक्ष के विधायकों के हलकों में भाजपा की पैनी निगाह : भाजपा की निगाह उन विधानसभा क्षेत्रों पर अधिक है, जहां विपक्ष के विधायक चुनाव जीतकर आए थे। उदाहरण के लिए कलायत से आजाद विधायक जय प्रकाश जेपी के कांग्रेस में शामिल होने की स्थिति में यहां भाजपा किसी काडर बेस दमदार नेता को चुनाव मैदान में उतारेगी। भाजपा में यहां हरियाणा पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी के सदस्य डॉ. सुखदेव कुंडू और राज्यसभा सदस्य समर्थक धर्मपाल शर्मा प्रमुख दावेदार हैं। पिहोवा में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भारत भूषण भारती को आगे किया जा सकता है। भाजपा का पूरा जोर फिलहाल उन हलकों में जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश पर है, जहां विपक्ष का कब्जा रहा है। 2014 में 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 विधायक भाजपा के चुनकर आए थे, जो जींद उपचुनाव जीतने के बाद 48 हो गए। दूसरे दलों के 10 विधायक विधानसभा की सदस्यता छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

▸ हरियाणा भाजपा में टिकट के लिए सबसे अधिक मारामारी

2014 के चुनाव में भाजपा ने बदले थे 67 टिकट

मिशन 75 पार का लक्ष्य हासिल करने में जुटी भाजपा इस बार अपने कई चेहरे बदल सकती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अधिकतर पुराने चेहरे बदल डाले थे। 2009 के चुनावी रण में ताल ठोंक चुके 67 पुराने उम्मीदवारों को भाजपा ने 2014 में टिकट नहीं दिए थे, सिर्फ 23 पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया था। 2014 के चुनाव में नए चेहरे-मोहरों में 27 उम्मीदवार दूसरे दलों से आए नेता बने थे। पार्टी ने 22 युवाओं और 15 महिलाओं को टिकट दिए थे। 25 जाट, 17 अनुसूचित जाति, 16 ओबीसी, दो मुस्लिम, नौ ब्राह्मण, आठ पंजाबी, आठ वैश्य, दो सिख और तीन अन्य जातियों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। इस बार भी टिकटों में बदलाव की पूरी संभावना है।

प्रदेश कांग्रेस में बढ़ रहा दिग्गजों में टकराव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में दिग्गजों का टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संगठन में बदलाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक अलग बैठकें करते थे, अब यह काम निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर और उनके समर्थक कर रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस आधा दर्जन गुटों में बंटी हुई है। अशोक तंवर की प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी के बाद कुमारी सैलजा व हुड्डा ने हाथ मिला लिए और दोनों फील्ड में उतर पड़े हैं, लेकिन किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर और रणदीप सुरजेवाला अभी खुलकर हुड्डा के मंच पर नहीं आए हैं। सुरजेवाला कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना है। वह पिछले काफी दिनों से जिलों में अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि, कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से हटाई गईं किरण चौधरी के घर जाकर हुड्डा ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, लेकिन किरण अभी तक उनके मंच पर नहीं पहुंची हैं।

हरियाणा में भी लागू होगा एनआरसी : मनोहर लाल

जागरण संवाददाता, पंचकूला

मनोहर लाल फाइल

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर देशभर में मचे घमासान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि असम की तरह हरियाणा में भी इसे लागू किया जाएगा। सरकार परिवार पहचान पत्र पर तेजी से कार्य कर रही है। इसके आंकड़ों का उपयोग एनआरसी में भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम दिन रविवार को राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एचएस भल्ला से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष में किए गए कार्यों की जानकारी देने के साथ वे प्रबुद्ध लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं। अच्छे सुझावों को अपने संकल्प पत्र में शामिल भी कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में कानून आयोग के गठन करने पर भी विचार किया जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए अलग से एक स्वैच्छिक विभाग का गठन किया जाएगा। विकास कार्यों का ऑडिट समाज के प्रबुद्ध लोगों से हो, इसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम लागू किया जाएगा जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, अध्यापकों, इंजीनियर या किसी अन्य प्रकार की विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली विभूतियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ कानून बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें बदलने की भी आवश्यकता है। वन विभाग का पीएलपी एक्ट में भी बदलाव जरूरी है। हालांकि राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया है।

पंजाब उपचुनाव में भाजपा व शिअद की अग्निपरीक्षा

चुनौती ▸ दोनों पार्टियों को अपने-अपने मजबूत किले में लड़ना होगा कांग्रेस से

फगवाड़ा में भाजपा तो जलालाबाद में शिअद का रहा है दबदबा

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

▸ विधानसभा की चार सीटों पर उपचुनाव की जमीन तैयार

▸ मुकेरियां में भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार होती रही है मजबूत टक्कर

पंजाब में विधानसभा की चार सीटों पर उपचुनाव की जमीन तैयार है। यह चुनाव भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि आम तौर पर उपचुनाव हमेशा ही सरकार के हक में जाते हैं। मुकेरियां विधानसभा हलके को छोड़ दिया जाए, तो दाखा और जलालाबाद में शिअद का मजबूत गढ़ है। वहीं, फगवाड़ा में भाजपा लगातार तीन बार से जीत का स्वाद चखती आ रही है। मुकेरियां में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार मजबूत टक्कर होती रही है। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा और शिअद को कांग्रेस सरकार से सीधी टक्कर मिलना तय है।

क्या लोकसभा जैसा प्रदर्शन कर पाएगी भाजपा : भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकेरियां और फगवाड़ा में लोकसभा जैसा प्रदर्शन कर पाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले भारी बहुमत मिला था। भाजपा के प्रत्याशी सोम प्रकाश अब केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनकी भी कड़ी परीक्षा होगी। उन पर उपचुनाव में अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने का दबाव होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेरियां में भाजपा प्रत्याशी सोम प्रकाश को 74,913 वोट पड़े थे, जबकि फगवाड़ा में उन्हें 44,436 वोट मिले थे। वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी को मुकेरियां में 37,207 और फगवाड़ा में 39,290 वोट पड़े थे। मुकेरियां और फगवाड़ा की सीट पर हमेशा भाजपा ही चुनाव लड़ती रही है।

जलालाबाद के किले को बचाना चुनौती : जलालाबाद शिरोमणि अकाली दल का पिछले चार चुनाव से मजबूत किला है। 2007 में शिअद से शेर सिंह घुबाया चुनाव लड़ कर जीते थे, जिसके बाद उन्होंने सुखबीर बादल के लिए यह सीट खाली कर दी थी। अकाली दल की सत्ता में रहते हुए सुखबीर बादल ने उपचुनाव जीता। इसके बाद 2012 व 2017 में लगातार दो जीत हासिल की। शिअद के अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र होने के कारण जहां कांग्रेस के समक्ष इस विधानसभा को जीतने का खासा दबाव रहेगा। वहीं, उससे अधिक दबाव शिअद को अपना किला बचाने को लेकर है। इसी साल हुए हुए लोकसभा चुनाव में सुखबीर बादल को जलालाबाद में 88,857 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी शेर सिंह घुबाया को 57,944 वोट हासिल हुए थे। वे शिअद छोड़ कांग्रेस में चले गए थे। ऐसे में इस सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों पर खासा दबाव है। कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बादलों के लिए लचीला रुख अपनाने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि पंजाब में लगातार गिर रहे ग्राफ को रोकने के लिए शिअद को हर हाल में इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। वहीं, लुधियाना की दाखा सीट पारंपरिक रूप से शिअद के कब्जे में रही है। पिछले पांच चुनाव में शिअद इस सीट पर तीन बार विजयी रहा, जबकि एक बार कांग्रेस व 2017 में आम आदमी पार्टी के एचएस फूलका विजयी रहे। ऐसे में पारंपरिक सीट को बचाना भी अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती होगी।

सबकी सहमति से ही होगा जदयू से गठबंधन पर फैसला : रघुवंश

रघुवंश प्रसाद सिंह फाइल

राज्य ब्यूरो, पटना : राजद के साथ जदयू के अंदरखाने बातचीत चलते रहने का दावा करने वाले राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह रविवार को भी सफाई दी। राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया और राज्यपाल फागू चौहान को संवैधानिक मर्यादा की नसीहत दी। जदयू के बयान से पीछे हटते हुए उन्होंने कहा कि जनतंत्र में बोलने की आजादी है। मैं जो महसूस करता हूं, उसे बोलता हूं। निर्णय लेना पार्टी का काम है। पार्टी जो फैसला करेगी, उसे मानूंगा।

राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रघुवंश ने कहा कि हमारी पार्टी में बोलने पर रोक नहीं है, लेकिन फैसला सबकी सहमति से होता है। एक कार्यक्रम में राज्यपाल के शिरकत करने के मसले पर सिंह ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जातीय सम्मेलनों में जाने से बचना चाहिए। फागू चौहान ने राज्यपाल के पद का जातीय नजरिए से इस्तेमाल किया। राज्यपाल पद की मर्यादा होती है। वह सबके होते हैं। किसी एक के नहीं।

दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों की सुनवाई को बनेंगी 1,023 विशेष अदालतें

▸ 389 विशेष त्वरित अदालतें सिर्फ पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की करेंगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : महिला व बाल यौन अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए केंद्र सरकार 1,023 विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना करेगी। देशभर की विभिन्न अदालतों में फिलहाल महिला व बाल यौन अपराधों से संबंधित 1.66 लाख मुकदमे लंबित हैं।

केंद्रीय कानून मंत्रालय के तहत न्याय विभाग की तरफ से तैयार किए एक प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रत्येक विशेष अदालत से हर साल कम से कम ऐसे 165 मामलों के निपटारे की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, इनमें से 389 अदालतें खासतौर से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करेंगी। बाकी 634 अदालतें दुष्कर्म या पॉक्सो कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगी।

प्रस्ताव में कहा गया है, 'उम्मीद है कि प्रत्येक विशेष त्वरित अदालत हर तिमाही में 41-42 मामलों का और साल में कम से कम 165 मामलों का निपटारा करेगी।' विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, देश की विभिन्न अदालतों में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के 1,66,882 मामले लंबित हैं। 389 जिलों में पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों की संख्या 100 से अधिक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इनमें से प्रत्येक जिले में एक विशेष पॉक्सो अदालत होनी चाहिए। इन अदालतों में किसी दूसरे मामले की सुनवाई नहीं होगी।

दो अक्टूबर से होगी अदालतों की स्थापना की शुरुआत

कानून मंत्रालय कह चुका है कि इन विशेष अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया दो अक्टूबर से शुरू होगी। न्याय विभाग ने इन 1,023 अदालतों की स्थापना के लिए कुल 767.25 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय सहयोग के रूप में एक साल के लिए 474 करोड़ रुपये निर्भया फंड से दिए जाएंगे।

भट्ट का आरोप, रमन, मोहले और भोजवानी थे नान घोटाले के मास्टरमाइंड

नईदुनिया, रायपुर : नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के पूर्व प्रबंधक और घोटाले के आरोपित शिवशंकर भट्ट ने रविवार को पत्रकारवार्ता कर कोर्ट में दिए शपथपत्र की बातों को दोहराया। उन्होंने कहा कि 3600 करोड़ का नान नहीं, बल्कि खाद्यान्न घोटाला हुआ है। इस घोटाले में खाद्य विभाग, मार्कफेड के लोग भी शामिल थे। केवल चावल ही नहीं, बाकी खाद्यान्न चना, दाल, नमक, केरोसिन, गैस की धांधली की गई। भट्ट का आरोप है कि इस पूरे घोटाले के मास्टर माइंड पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले और नान के पूर्व अध्यक्ष लीलाराम भोजवानी हैं। इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन खाद्य सचिव, वित्त सचिव की संलिप्तता की भी बात कही है।

भट्ट ने रविवार को प्रेस क्लब के सभागार में पत्रकारवार्ता की। उनके मुताबिक, खाद्य विभाग के कुछ अधिकारियों पर रमन, मोहले और भोजवानी ने एक ही परिवार के तीन-चार राशन कार्ड बनाने का दबाव बनाया। यह काम नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। अतिरिक्त बनवाए गए 21 लाख राशन कार्ड के हिसाब से अक्टूबर-नवंबर 2013 में खाद्यान्न का भंडारण कराया गया, लेकिन इसमें से कम मात्रा में ही कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न का वितरण कराया। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फंड में राशि देने और अपनी जेबें भरने के लिए बचे हुए खाद्यान्न को खुले बाजार में बिकवाया। भट्ट का यह भी आरोप है कि इस मामले में रमन ने मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री पद का भी पूरा उपयोग किया।

इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा हुए कांग्रेसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पूर्व मंत्री सुभाष गोयल समेत कई नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ

▸ निर्दलीय विधायक जयप्रकाश (जेपी) भी कांग्रेस में शामिल

विधानसभा चुनाव से पूर्व हरियाणा में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना तेज हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, हांसी से इनेलो के पूर्व विधायक सुभाष गोयल, कालका से पूर्व विधायक व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी सहित पूर्व मंत्री जसविंद्र सिंह संधू के बेटे गगनजोत सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश (जेपी) ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।

रविवार सायं कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के हरियाणा प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद ने इन नेताओं के पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मौके पर मौजूद थे। राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल इनेलो में टूट के बाद पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और नेताओं का दूसरे दलों में जाने का सिलसिला लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गया था। पार्टी के अब तक दस विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनेलो के चार विधायक नवगठित जननायक जनता पार्टी में हैं। 2014 में इनेलो के कुल 19 विधायक जीते थे, इनमें दो विधायकों जींद के हरीचंद मिढ्डा और पिहोवा के जसविंद्र सिंह संधू का निधन हो गया था। इनेलो में अब तीन विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला, ओमप्रकाश व वेद नारंग ही हैं।

टिकट की गारंटी पर कांग्रेस का थामा है दामन

लोकसभा चुनाव के बाद अशोक अरोड़ा ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन टिकट की गारंटी नहीं मिलने के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। अब कांग्रेस से इन सभी को टिकट का आश्वासन मिला है। तीन बार सांसद रह चुके कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश पिछले पांच साल से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जमे हुए हैं। जेपी जींद उपचुनाव में भी कांग्रेस से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे।

आइएफएस अधिकारी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराई मुआवजे की रकम

किशोर जोशी, नैनीताल

▸ हाई कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने दिया था संजीव चतुर्वेदी को मुआवजा

▸ पीएम को लिखा पत्र- जनता के पैसे का इस्तेमाल बदले की कार्रवाई में न हो

संजीव चतुर्वेदी फाइल

भारतीय वन सेवा के चर्चित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से मुआवजे के रूप में मिली 25 हजार की धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें इसके लिए धन्यवाद पत्र भेजा है। राहत कोष में भेजी गई रकम के साथ चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी भेजा था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जनता के पैसे का इस्तेमाल बदले की कार्रवाई में नहीं किया जाना चाहिए।

बता दें कि पिछले साल अगस्त में एसीआर में जीरो अंकन के मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने संजीव के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्र के रवैये को प्रतिशोधात्मक बताते हुए 25 हजार जुर्माना लगा दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई, लेकिन केंद्र द्वारा जुर्माने की राशि नहीं दिए जाने पर संजीव ने फिर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसी साल जुलाई में केंद्र ने इस धनराशि का भुगतान संजीव को कर दिया था। इसके बाद उन्होंने यह धनराशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दी थी। इस पर अब पीएमओ ने चतुर्वेदी के पत्र के जवाब में जुर्माने में मिली धनराशि दान देने के लिए आभार प्रकट किया है।

काम की आजादी की पैरोकारी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में संजीव चतुर्वेदी यह भी लिखा था कि प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे इस मुकदमे में खर्च धनराशि तथा जुर्माने की राशि की वसूली की जानी चाहिए थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई न करते हुए जनता के पैसे से मुआवजा की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है, जो कि उनकी समझ से परे है। पीएम को भेजे पत्र में उन्होंने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को काम करने की आजादी और सुरक्षा का भाव देने की बात कही थी। पत्र में प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया था कि पीएम कार्यालय की तरफ से एक ऐसा फंड बनाया जाए, जिसमें उनकी तरह से ही उत्पीड़न और बदले की कार्रवाई के शिकार अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई में होने वाले खर्च और मुआवजे का भुगतान किया जा सके।

पुरस्कार राशि भी जमा कराई थी : आइएफएस संजीव चतुर्वेदी बताते हैं कि उन्होंने इससे पहले सितंबर 2015 में मैग्सेसे पुरस्कार से मिली करीब 20 लाख की रकम भी राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कर दी थी। वहीं, मध्यस्थता के रूप मिली ढाई लाख की धनराशि इस साल फरवरी में पुलवामा के आतंकी हमले के शहीदों के परिवारों को दान की थी। यह धनराशि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई थी।

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में प्लास्टिक व पॉलीथिन प्रतिबंधित

राज्य ब्यूरो, देहरादून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने को चल रही मुहिम का असर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस चुनाव में प्लास्टिक व पॉलीथिन से बनी प्रचार सामग्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव में प्लास्टिक व पॉलीथिन से निर्मित सामग्री का उपयोग किसी भी दशा में न होने पाए।

सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पहल की गई है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कदम बढ़ाए हैं। असल में, हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में आगामी पांच अक्टूबर, 11 अक्टूबर व 16 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। आयोग ने इन चुनावों में प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी प्रचार सामग्री को प्रतिबंधित कर दिया है। यानी न तो कोई प्रत्याशी इसका उपयोग प्रचार में करेगा और न मशीनरी ही प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी वस्तुओं का कोई प्रयोग करेगी।

12 जिलों के जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश : राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने सभी 12 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्लास्टिक-पॉलीथिन से बने बैनर, पोस्टर, झंडियां जैसी चुनाव सामग्री को प्रतिबंधित करने को प्रभावी कदम उठाए जाएं। यदि कोई प्लास्टिक-पॉलीथिन से बनी सामग्री का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।

प्रिंटिंग प्रेस का नाम-पता अनिवार्य : राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि पंचायत चुनाव में प्रचार-प्रसार की सामग्री हैंडबिल, पंफलेट आदि पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता अनिवार्य रूप से अंकित हो। प्रिंटेड सामग्री की संख्या भी इसमें दर्ज होनी चाहिए।

भवन स्वामी का प्रमाणपत्र जरूरी

चुनाव प्रचार के दौरान किसी भवन की दीवार, चहारदीवारी को प्रचार के लिए इस्तेमाल करने पर इसके लिए संबंधित भवन स्वामी से स्वीकृति का प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक स्वीकृति पत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

व्यवस्था

राज्य को विरासत में मिला है नियम, विधायकों को खुद करनी पड़ती है अपनी व्यवस्था, हाल ही में उप्र सरकार ने इस नियम में किया है बदलाव

छग में भी सरकार जमा करती है सीएम और मंत्रियों का आयकर

संजीत कुमार, रायपुर

छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का आयकर राज्य सरकार जमा करती है। विधायकों को अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नियमों में इसका प्रावधान है। नियमानुसार जीएडी पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों की आयकर की फाइल मेंटेन करती है। सीधे मंत्रिमंडल का मामला होने की वजह से उनके आयकर के रूप में जमा की जाने वाली राशि को लेकर अफसर कुछ भी बताने से बचते हैं। बता दें कि हाल ही में उप्र की योगी सरकार में इस नियम को बदला गया है।

जीएडी के अफसर कहते हैं कि यह नियम छत्तीसगढ़ को विरासत में मिला है। हम उसका अब तक पालन कर रहे हैं। राज्य में विधायकों का वेतन 20 हजार है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को क्रमशः 30 और 28 हजार रुपये मिलता है। वहीं, मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा 35 हजार रुपये हर महीने वेतन मिलता है। अब इसमें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, दैनिक भत्ता, मेडिकल, टेलीफोन आदि शामिल कर दिया जाए तो यह आंकड़ा लाख रुपये के पार पहुंच जाता है। राज्य में विधायकों को कुल एक लाख 10 हजार, कैबिनेट मंत्री को एक लाख 60 हजार, राज्य मंत्री को एक लाख 58 हजार और मुख्यमंत्री को एक लाख 65 हजार रुपये हर महीने मिलता है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फाइल

वेतन-भत्ता के साथ कई सुविधाएं : मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के बाकी सहयोगियों को तो सरकार बंगला गाड़ी समेत कई सुविधा देती हैं। विधायकों को भी कुछ कम सुविधाएं नहीं मिलती। सभी विधायकों को राजधानी में आवास की सुविधा दी जाती है। बसों में मुफ्त के साथ हर वर्ष चार लाख रुपये तक ही हवाई और रेल यात्रा की सुविधा भी दी जाती है।

दो करोड़ हुई विधायक निधि : छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष विधायक निधि की राशि को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया गया है। इस निधि का उपयोग केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, व्यक्तिगत नहीं। प्रायः इस राशि का उपयोग उन सार्वजनिक हित के कार्यों में किया जाता है तो सरकार की किसी योजना में नहीं आ पाती है।

एक बार बने माननीय तो बाकी जिंदगी कटती है आराम से : एक बार विधायक चुनकर माननीय बन गए तो बाकी पूरी जिंदगी आराम से कटती है। विधायकी खत्म होने के बाद पहले पहले पांच वर्ष के लिए 20 हजार मासिक पेंशन है। इसके बाद छह से 10 वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष का तीन सौ, 11 से 15 साल के लिए प्रत्येक वर्ष का चार सौ और 16 या उससे अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ मासिक अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। चिकित्सा सुविधा के साथ बसों में मुफ्त सफर, दो लाख रुपये तक हवाई और रेल यात्रा हर वर्ष करने की छूट रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई सुविधाएं भी मिलती हैं।

फिलहाल राज्य मंत्री और संसदीय सचिव नहीं

राज्य सरकार में फिलहाल राज्य मंत्री और संसदीय सचिव नहीं हैं। नियमानुसार इन पदों के लिए वेतन तय कर रखा गया है। संसदीय सचिव को एक लाख 51 हजार रुपये मासिक देने का प्रावधान है। पूववर्ती सरकार में करीब एक दर्जन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था।

किसे कितना मिलता है वेतन और भत्ता

1 लाख 65 हजार	मुख्यमंत्री
1 लाख 60 हजार	कैबिनेट मंत्री
1 लाख 58 हजार	राज्य मंत्री
1 लाख 51 हजार	संसदीय सचिव
1 लाख 10 हजार	विधायक

मप्र सरकार के मंत्री ने कहा-मंत्रियों का आयकर क्यों भरे सरकार

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा है कि मंत्रियों को मिलने वाले वेतन-भत्ते का टैक्स सरकार क्यों भरे। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने जब वेतन-भत्ते बढ़ाए थे, तब भी मैंने इसका विरोध किया था। मंत्रियों को अपना टैक्स स्वयं ही भरना चाहिए। मालूम हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि मंत्रियों का आयकर अब सरकार नहीं भरेगी। इसके बाद ही सिंह ने यह बयान दिया है।

दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार 'नईदुनिया' से विशेष चर्चा में डॉ. सिंह ने कहा कि वैसे यह बात भी सही है कि विधायक-मंत्री बनने के बाद जनप्रतिनिधि का खर्च भी बढ़ जाता है। पूरे क्षेत्र में घूमने और जनसंपर्क का भी खर्च कम नहीं रहता। आयकर अधिनियम के तहत मंत्रियों के भत्तों पर छूट भी है, लेकिन वेतन पर जो टैक्स बनता है, वह मंत्री को खुद ही भरना चाहिए। वहीं, लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का मानना है कि जिस प्रदेश में जैसी परिस्थितियां हों, मुख्यमंत्री को वैसा निर्णय लेना चाहिए।

बड़े नेताओं के निर्देशों का पालन होगा

चिकित्सा, शिक्षा और संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि उप्र की योगी सरकार ने क्या निर्णय लिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे बड़े नेता जो दिशा-निर्देश देंगे, उनका पालन होगा। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कहा कि योगी सरकार ने क्या निर्णय लिया, मुझे कोई जानकारी नह

40 वर्षों से कांच खा रहे हैं मध्य प्रदेश के 55 वर्षीय अधिवक्ता दयाराम साहू। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के शहपुरा निवासी दयाराम बल्ब और बोतलों के टुकड़ों को आसानी से चबाकर निगल जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में सैलानियों से भरी नाव गोदावरी नदी में पलटी, 12 की मौत

बड़ा हादसा ▶ नाव में कुल 60 लोग सवार थे, स्थानीय लोगों ने 17 लोगों को बचा लिया

मुख्यमंत्री जगन ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के देवीपटनम में नाव हादसे के बाद बचाव कार्य में जुटी नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) की टीम। एएनआइ

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक बड़े नाव हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग लापता हैं। 60 सैलानियों और चालक दल के नौ सदस्यों से भरी नाव उफनती गोदावरी नदी में पलट गई। स्थानीय लोगों ने 17 लोगों को बचा लिया। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। तेलंगाना के सीएम ने भी पांच-पांच लाख रुपये देने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री रेड्डी ने नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ), नौसेना और ओएनजीसी से युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाने को कहा है। बचाव कार्य में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने जिले में मौजूद सभी मंत्रियों को भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

पीएम और रक्षा मंत्री ने जताया दुख : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'आंध्र प्रदेश पूर्वी गोदावरी में नाव के डूबने से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।'

राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक नाव के पलटने से बहुमूल्य जान माल की हानि से बहुत दुखी हूं। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं।'

नौका विहार सेवाओं के लाइसेंस निलंबित : मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूर्वी गोदावरी जिले के अधिकारियों ने क्षेत्र में सभी नौका विहार सेवाओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। नावों के लाइसेंस की जांच भी शुरू कर दी गई है।

उफान पर थी गोदावरी नदी

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक नदी में पिछले कुछ दिनों से बाढ़ आई हुई है। जिस समय यह हादसा हुआ नदी उफान पर थी। आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित नाव पर 22 सैलानी तेलंगाना के थे, जो हैदराबाद निवासी थे।

कच्चुलुरु के पास हुआ हादसा

नाव देवीपटनम के पास गांडी पोचम्मा मंदिर से पर्यटन स्थल पापीकोंडालु के लिए निकली थी। नाव प्राइवेट ऑपरेटर की थी। कच्चुलुरु के पास ही वह हादसे का शिकार हो गई।

आइआइटी धनबाद के निदेशक को जारी होगा कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, कानपुर : आइआइटी कानपुर के एयरोस्पेस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुब्रमण्यम सडरेला की शिकायत पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने आइआइटी धनबाद के निदेशक प्रो. राजीव शेखर पर अपनी निगाहें टेढ़ी कर दी हैं। बाहरी जांच समिति ने एक ओर डॉ. सडरेला की डिग्री रद नहीं करने पर मुहर लगा दी तो एमएचआरडी ने आइआइटी धनबाद के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कहा है। इस संबंध में एमएचआरडी ने आइआइटी कानपुर को पत्र लिखा है। डॉ. सडरेला ने डॉ. राजीव शेखर समेत चार प्रोफेसरों पर जाति आधारित उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।

डॉ. राजीव शेखर के खिलाफ एक ईमेल की वजह से यह कार्रवाई की जा रही है जिसमें उन्होंने डॉ. सडरेला की नियुक्ति पर टिप्पणी की थी। उसके बाद डॉ. सडरेला ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कई जांच समितियां बनाई गईं। हाल ही में 23 अगस्त को एमएचआरडी ने आइआइटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर को पत्र भेजकर प्रो. शेखर के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। हालांकि नोटिस पर फैसले की प्रक्रिया काफी लंबी है।

संघ संस्थापक के स्मारक पर पहुंचे उद्योगपति राहुल बजाज

प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नागपुर मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने संस्थापक सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एएनआइ

नागपुर, प्रेट्र : मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक 'हेडगेवार स्मृति मंदिर' का शिष्टाचार दौरा किया। यह स्मारक महाराष्ट्र के नागपुर के रेशिमबाग में स्थित है। हालांकि, वह पास ही में महल इलाके में स्थित संघ मुख्यालय नहीं गए। उल्लेखनीय है कि अपनी राय बेबाकी के साथ रखने वाले बजाज ने साल की शुरुआत में संघ मुख्यालय की तरफ से संघ नेतृत्व के दौरे के लिए दिए गए आमंत्रण को ठुकरा दिया था।

संघ के एक पदाधिकारी ने बताया, बजाज शनिवार को नागपुर के महानगर संघचालक राजेश लोया व अन्य पदाधिकारियों के साथ यहां आए थे। उन्होंने हेडगेवार स्मृति मंदिर में फूल चढ़ाए। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, 'यह एक शिष्टाचार दौरा था। मैंने बजाज को स्मारक के दौरे के लिए आमंत्रित किया था। कहा था कि जब कभी वह नागपुर के आसपास हों तो यहां आएं। चूंकि वह पड़ोसी वर्धा जिले में थे तो यहां भी आए। यह एक अनौपचारिक निमंत्रण था।'

डॉ. हेडगेवार ने संघ की स्थापना विजयादशमी (दशहरा) के मौके पर वर्ष 1925 में की थी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से संगठित करना था।

बालीचौकी में 300 साल पुराना देव श्री मतलोड़ा का मंदिर राख

बालीचौकी के सोमगाड़ स्थित प्राचीन मंदिर जो जल कर राख हो गया। जागरण

जागरण संवाददाता, बालीचौकी (मंडी)

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बालीचौकी तहसील के दुर्गम सोमगाड़ में देव श्री मतलोड़ा का करीब 300 साल पुराना मंदिर जलकर राख हो गया है। काष्ठकुणी शैली में निर्मित देवता के प्राचीन मंदिर में विद्यमान प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां भी आग की भेंट चढ़ गई। अग्निकांड में करीब 30 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

देवता के पुजारी परिवार से संबंधित एवं सराज इंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात को स्थानीय लोगों ने देव श्री मतलोड़ा मंदिर में आग की लपटें उठती देखी। लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। मंदिर के साथ बहते नाले से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन प्रचंड लपटों के आगे उनकी यह कोशिश नाकाम रही। देवता का मंदिर इस इलाके के गांवों से काफी दूर एक घने जंगल में था। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मंदिर श्री मतलोड़ा के चोहठ के बाद दूसरे सबसे प्रमुख मंदिरों में शुमार था। सेवक धर्मदास ने बताया कि आग से मंदिर में सदियों से स्थापित देवता की पत्थर की मूर्तियां भी नष्ट हो गई हैं। रविवार को पुलिस टीम ने राजस्व विभाग की टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और पूछताछ की।

कॉलेज में बुर्का-टोपी का विरोध करने पर छात्र नेताओं पर मुकदमा

जासं, अलीगढ़ : डॉ. आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएस कॉलेज में बुर्का-टोपी पहनने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं का विरोध करना हिंदूवादी छात्र नेताओं को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीन छात्र नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। बरौली से भाजपा विधायक दलवीर सिंह ने कार्रवाई को गलत बताया है। छात्र नेता आदित्य पंडित, अमित गोस्वामी व सोनू ठाकुर ने 11 सितंबर को प्रॉक्टर को ज्ञापन देकर सवाल किया था कि कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है तो कुछ मुस्लिम छात्र-छात्राएं बुर्का-टोपी पहनकर क्यों आ रहे हैं? चेतावनी दी थी कि कॉलेज प्रशासन ने तीन दिन में इस पर रोक नहीं लगाई तो हिंदू छात्र-छात्राएं भी भगवा वस्त्र पहनकर आएंगे। ऐसा न होने पर छात्राओं की टीम बुर्का व छात्रों की टीम टोपी उतारेगी। इस मामले में पुलिस ने चार दिन बाद शनिवार को मुकदमा दर्ज किया है।

मुकदमा वापस न होने पर होगा आंदोलन : अमित गोस्वामी का कहना है कि कार्रवाई एएमयू छात्रों के इशारे पर की गई लगती है। हिंदू छात्र ड्रेस कोड का पालन कर सकते हैं तो अन्य क्यों नहीं? सोमवार को एसएसपी से मिलेंगे। मुकदमा वापस न हुआ तो मंगलवार से आंदोलन करेंगे।

स्वामी चिन्मयानंद और छात्रा के मित्र का कराया गया आमना-सामना

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर लगे दुष्कर्म के आरोप की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने रविवार को उन्हें फिर पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार उनका सामना छात्रा के दोस्त संजय सिंह से कराया गया। दोनों को आमने-सामने बैठाकर सवाल किए गए। इसके साथ ही चिन्मयानंद के कॉलेज के दोनों प्राचार्यों, कार चालक से भी पूछताछ की गई।

रविवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे स्वामी चिन्मयानंद व उनके ड्राइवर साकेत को एसआइटी ने पुलिस लाइंस स्थित अस्थाई कार्यालय बुलाया। कार चालक से पूछा गया कि वह छात्रा के बारे में क्या जानता है। चिन्मयानंद से उसकी जान पहचान कैसे हुई, कब से वह नौकरी कर रहा है।

इसके बाद करीब एक बजे एसएस परास्नातक कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अवनीश मिश्र, एसएस लॉ कालेज के प्राचार्य डॉ. संजय बरनवाल व एक क्लर्क को बुलाया। तीनों लोगों के पास कई अभिलेख भी थे। एसआइटी ने चिन्मयानंद व साकेत की मौजूदगी में उन तीनों से भी पूछताछ की। दोपहर करीब ढाई बजे छात्रा के दोस्त संजय सिंह व संजय के तहेरे भाई दुर्गेश व मौसेरे भाई सचिन सेंगर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। तीन बजे दोनों प्राचार्य व बाबू तो बाहर निकल जाए, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद, साकेत व तीनों युवक अंदर ही रहे, जहां उनसे देर शाम तक पूछताछ जारी थी। बताया जा रहा कि उन्हें आमने-सामने बैठाकर सवाल किए गए। इससे पहले 12 सितंबर को भी चिन्मयानंद से लंबी पूछताछ की गई थी।

चिन्मयानंद प्रकरण

- रविवार देर शाम तक जांच अधिकारी दोनों से करते रहे पूछताछ
- चिन्मयानंद के कॉलेज के प्राचार्यों और चालक से भी किए गए सवाल-जवाब

हृश. ष्टड्डश्चह्लद्बश्ठ्ठ

कौन है संजय

संजय सिंह खुद को छात्रा का दोस्त बताते हैं। कह चुके हैं कि चिन्मयानंद छात्रा का शोषण करते थे। पता चला तो उसे न्याय दिलाने के लिए उसका साथ दिया। 24 अगस्त को आपबीती का वीडियो वायरल कर लापता हुई छात्रा जब 30 अगस्त को राजस्थान के दौसा जिले के एक होटल में पुलिस को मिली तो संजय भी साथ थे। बाद में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें संजय कुछ लड़कों से बात कर रहे। उसे रंगदारी प्रकरण से जोड़ा गया। इस वीडियो में संजय के तहेरे भाई दुर्गेश व मौसेरे भाई सचिन सेंगर भी बताए जा रहे हैं। इसीलिए एसआइटी संजय से भी पूछताछ कर रही है।

दो मामलों की एक साथ हो रही जांच : छात्रा का आरोप है कि उससे दुष्कर्म किया गया, जिसकी शिकायत दिल्ली के लोधी रोड थाने में दर्ज करा चुकी है। वहीं चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पांच करोड़ की रंगदारी न देने पर चिन्मयानंद व कॉलेज की छवि खराब की जा रही। उन्होंने चौक कोतवाली में इसका मुकदमा दर्ज कराया था।

किसने वायरल किए वीडियो, कोर्ट में करूंगा शिकायत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद और दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली छात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पिता ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत न्यायालय में करेंगे। साथ ही जांच की मांग करेंगे ताकि वीडियो वायरल कर हमें बदनाम करने वालों पर कार्रवाई हो सके। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को कुछ वीडियो फुटेज वायरल हुई थी। जिन्हें स्वामी चिन्मयानंद व छात्रा से जुड़ा बताया जा रहा था। बाद में कुछ फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। छात्रा के पिता ने जागरण को बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग खुराफात के तहत ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। उन लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग करेंगे। चूंकि हाई कोर्ट अब पूरे प्रकरण की निगरानी कर रहा है, इसलिए जल्द ही वहां शिकायत करने जाएंगे।

14 सितंबर को सौंपे थे सुबूत : छात्रा के पिता ने 14 सितंबर को एसआइटी (विशेष जांच दल) को एक पेन ड्राइव सौंपी थी, जिसमें 43 वीडियो बताए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही कुछ वीडियो दस सितंबर को वायरल हो गए थे।

बिहार में पिता को ही बच्चा चोर समझ पुलिस को सौंपा

जागरण संवाददाता, सारण : बिहार के सारण में ग्रामीणों ने पिता को ही बच्चा चोर समझ कर पुलिस को हवाले कर दिया। युवक पत्नी से झगड़कर अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। रविवार सुबह स्थानीय बाजार में लोगों ने एक युवक को गोद में बच्चे को लिए सड़क किनारे खड़े देखा। लोग कुछ पूछते इसके पूर्व ही वह बच्चे समेत गाड़ी में सवार होने लगा। साथ में किसी महिला को नहीं देख ग्रामीण उसे बच्चा चोर समझा और घेर लिया। भीड़ जुटने लगी एवं उसकी गतिविधि को देख लोग संदेह करने लगे। जबकि वह बच्चे को पुत्र बता रहा था।

ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना को दी। थानाध्यक्ष उसे थाने ले गए। पूछताछ में पता चला कि वह पत्नी से झगड़कर बच्चे को ले जा रहा था। थानाध्यक्ष ने पत्नी को बुलाकर बच्चे को सौंप दिया। वहीं अररिया में बच्चा चोर होने की आशंका पर कुछ ग्रामीणों ने एक युवक को रात भर खूंटे से बांधकर रखा। सूचना मिलने पर पुलिस ने रविवार की सुबह उसे ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उल्लेखनीय है कि बिहार समेत देश के कई राज्यों में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह जोरों पर है। इसी के चलते कई बेकसूर लोग भीड़ का निशाना बन रहे हैं।

पूरे सेवाकाल में वेतन न पाने वाला शिक्षक कोर्ट में जीता

- शीर्ष अदालत ने प्रबंधन से कहा, नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक का वेतन दें
- बिहार के संस्कृत कॉलेज में 1980 में नियुक्त हुए थे गोपाल कृष्ण गोखले

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को बड़ी राहत दी है। गोपाल कृष्ण गोखले नामक इस शिक्षक को नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक कभी वेतन ही नहीं मिला था। अब शीर्ष अदालत ने उनके पूरे वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश दिया है। बिहार के सलेमपुर स्थित भरत मिश्रा संस्कृत कॉलेज में जुलाई 1980 में गोखले की नियुक्ति हुई थी और वह जुलाई 2013 में रिटायर हो गए थे। 72 वर्षीय गोखले के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेज प्रबंधन उनके बकाए भुगतान को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है। उनके एक अन्य वकील ने बताया कि एक अन्य प्रवक्ता से कानूनी लड़ाई के चलते गोखले के बकाए का भुगतान नहीं हो सका है।

दरअसल, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध इस कॉलेज में 31 जुलाई, 1980 को गोखले के साथ ही प्रेम कुमारी की नियुक्ति भी प्रवक्ता पद पर हुई थी। विज्ञापन एक पद इतिहास के प्रवक्ता के लिए निकला था। प्रेम कुमारी की नियुक्ति इतिहास के प्रवक्ता के पद पर हुई थी। उसी दिन कॉलेज की प्रबंधन समिति ने गोखले की नियुक्ति भी कर दी थी। प्रेम कुमारी का कहना था कि गोखले अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे, जिसका विज्ञापन ही नहीं निकला था। उनका यह भी कहना था कि विश्वविद्यालय से गोखले की नियुक्ति को कभी मंजूरी ही नहीं मिली। जबकि, गोखले ने प्रेम कुमारी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि नियुक्ति के समय वह पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं थी। बाद में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने गोखले की नियुक्ति को रद कर उसे अस्थायी कर दिया था। उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के आदेश पर जांच हुई, जिसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेम कुमारी की नियुक्ति को 2013 में रद कर उनसे वेतन की वसूली का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गोखले के साथ ही प्रेम कुमारी को भी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने प्रेम कुमारी को दोबारा नियुक्त करने और उन्हें बकाया वेतन समेत सभी तरह के लाभ भी देने का आदेश दिया है।

टाइगर डांस...

केरल में कलाकारों ने शनिवार को त्रिशूर जिले में ओणम महोत्सव के चौथे दिन शरीर को बाघ की तरह पेंट करके पुलिककली नृत्य किया। इसे टाइगर डांस भी कहा जाता है और यह स्थानीय मनोरंजक लोककला है। पुलिककली का शाब्दिक अर्थ 'बाघों का खेल' है। यह लोकनृत्य जंगल की शक्ति की भावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। एएनआइ

राजीव कुमार के लिए नवान्न पहुंची सीबीआइ की टीम

जागरण संवाददाता, कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ की टीम सरकारी अधिकारियों को कुछ पत्र सौंपने रविवार को राज्य सचिवालय नवान्न पहुंची। सचिवालय में मौजूद कर्मियों ने टीम को यह कहकर लौटा दिया कि छुट्टी का दिन होने के कारण मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्र ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। ये पत्र किस संबंध में थे, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, हालांकि सूत्रों की मानें तो ये कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के बारे में जानकारी जुटाने को लेकर हैं।

सीबीआइ की तीन सदस्यीय टीम रविवार शाम करीब 5.20 बजे नवान्न पहुंची। सीबीआइ अधिकारियों के पास कुल चार पत्र थे, जिसे वे राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सौंपना चाहते थे। इनमें से डीजीपी को संबोधित पत्र तो उन्होंने सौंप दिया लेकिन मुख्य व गृह सचिव को संबोधित पत्र रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण ग्रहण नहीं किया गया। सीबीआइ अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को आने को कहा गया। सीबीआइ की टीम के सोमवार को फिर नवान्न जाने की संभावना है। सूत्रों की मानें तो पत्रों के जरिए सीबीआइ कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार का पक्ष जानना चाहती है। पत्र में लिखा गया है कि राजीव कुमार को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने तुरंत हाजिर होना होगा। पत्र के जरिए यह भी पूछा गया है कि पत्नी की बीमारी के बहाने तो राजीव कुमार छुट्टी पर नहीं हैं? सूत्रों ने बताया कि चूंकि राजीव कुमार राज्य सरकार के तहत एडीजी (सीआइडी) के पद पर हैं, ऐसे में राज्य सरकार को उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।

ज्ञात हो, शनिवार शाम राजीव कुमार ने सीबीआइ को ईमेल कर पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए पेशी के लिए एक माह की मोहलत मांगी थी। सीबीआइ अब उनको और समय देने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआइ सोमवार को ही उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। वहीं, सूत्रों के मुताबिक, राजीव कुमार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अवकाश याचिका दायर कर सकते हैं।

हड़बड़ी

भारत ने 2015 के ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पर कर रखे हैं हस्ताक्षर, डब्लूएचओ के घोषणापत्र के अनुसार भारत को 2020 तक दुर्घटना मौतें करनी हैं आधी

सड़क हादसों में मौतें आधी करने की जल्दी में सिर्फ जुर्मानों पर जोर

संजय सिंह, नई दिल्ली

सड़क दुर्घटनाओं में मौत की डरावनी संख्या कम करने के लिए सरकार ने मोटर वाहन संशोधन एक्ट के जुर्माने वाले प्रावधानों को फटाफट लागू तो कर दिया, लेकिन यह भूल गई कि सिर्फ इतना नाकाफी है। खुद मोटर एक्ट में इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र है। यही वजह है कि तमाम नेकनीयती के बावजूद इस कानून को लागू करने में व्यावहारिक मुश्किलें पेश आ रही हैं और जनता ही नहीं राज्य सरकारें भी इसके खिलाफ गोलबंद हो गई हैं।

नवंबर, 2015 में ब्राजील में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओ द्वारा सड़क सुरक्षा पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें भारत समेत डब्लूएचओ के सदस्य देशों के 2200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में 2011-20 के दौरान सदस्य देशों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का रोडमैप पेश किया गया था। 'ब्राजीलिया डिक्लेरेशन' नाम से जारी सम्मेलन के घोषणापत्र पर भारत समेत तमाम देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें भारत को 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य दिया गया था।

चालान करते पुलिसकर्मी। प्रतीकात्मक फोटो

सम्मेलन के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणापत्र के लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया था। इसके लिए फरवरी, 2016 में राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में 18 राज्यों व 4 केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की सदस्यता वाले मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया गया। जीओएम को सड़क हादसे कम करने के साथ-साथ परिवहन व्यवस्था में सुधार के उपाय सुझाने थे। बाद में इसी जीओएम की रिपोर्ट के आधार पर मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2016 की रूपरेखा तैयार हुई, जिसे उसी वर्ष लोकसभा में पेश कर दिया गया था।

इस बिल में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्मानों की राशि में भारी बढ़ोतरी से पहले दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए जरूरी कई तकनीकी व प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता बताई गई थी। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक एन्फोर्समेंट, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रणाली में सुधार तथा दुर्घटना पीड़ितों के मददगार नागरिकों की सुरक्षा के कदम प्रमुख थे। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत (एक घंटे या गोल्डेन ऑवर के भीतर) अस्पताल पहुंचाने तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के प्रावधान भी किए गए थे।

लोकसभा से बिल को सांसद मुकुल राय की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति के सुपुर्द कर दिया गया था। चूंकि 31 सदस्यीय समिति ने, जिसमें राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 21 सदस्य थे, 8 फरवरी, 2017 को अपनी रिपोर्ट दी थी, लिहाजा विधेयक पुन पेश करने से पहले इसके नाम में 2017 जोड़ना पड़ा, परंतु राज्यसभा तक पहुंचते-पहुंचते 2019 के आम चुनावों का एलान हो गया। प्रचंड बहुमत से आई नई सरकार ने इसे मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2019 के नाम से पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पारित कराया।

राज्यों को तैयारी के लिए नहीं मिला समुचित समय : संशोधित मोटर कानून में भी स्थायी समिति के ज्यादातर सुझावों को समाहित कर लिया गया है, लेकिन जुर्माने वाले प्रावधानों को इसलिए तुरंत लागू किया गया ताकि सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों में जल्द से जल्द कमी लाकर डब्लूएचओ के लक्ष्य को यथासंभव पूरा किया जा सके। यह अलग बात है कि इस चक्कर में राज्यों को तैयारी के लिए समुचित समय नहीं मिला। पारित होने के 22 दिन के भीतर एक सितंबर से जुर्माने वाले सभी 63 उपबंध लागू कर दिए गए। इससे जनता में हाहाकार मच गया और राज्य सरकारों के कान खड़े हो गए।

... और कोई चारा नहीं था

जिस साल भारत ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, देश में सालाना साढ़े चार लाख सड़क दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोग मारे जा रहे थे। आज भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इसलिए सरकार के पास सख्ती के अलावा और कोई चारा नहीं था। सरकार का मानना था कि भारी जुर्मानों की बदौलत वह चार-छह माह में मौतों को आधे पर ला सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट, आइटी समाधानों व परिवहन सुधारों में समय लगेगा, लेकिन राज्यों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है।

75 प्रतिशत शूटिंग बिहार में करने पर फिल्म निर्माता को लागत की 25 फीसद सब्सिडी देगी नीतिश सरकार। हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में बनने वाली फिल्मों पर यह सब्सिडी दी जाएगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर 2019

चार-चार लाख के इनामी नक्सली ढेर

कांकेर, नईदुनिया : छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो इनामी नक्सलियों को मार गिराया। दोनो नक्सलियों पर चार-चार लाख रपये का इनाम घोषित था।

गढ़चिरौली में सी 60 कमांडो जंगलों की सर्चिंग के लिए निकले थे। रविवार सुबह ग्यारापत्ति थाना क्षेत्र के मरकसा के जंगल में सुरक्षाबल के जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों के हमले के बाद सी 60 के कमांडो ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। इसके बाद पुलिस के जवानों ने सर्चिंग की, जिसमें मुठभेड़ स्थल से दो माओवादियों के शव बरामद हुए। नक्सलियों के शवों को ग्यारपत्ति थाना लाया गया। जहां दोनों की शिनाख्त भी हो गई। मारे गए नक्सलियों ने एक की पहचान महिला नक्सली समिला के रूप में की गई, जो उत्तर बस्तर डिवीजन में सक्रिय थी और क्षेत्र के कई बड़े वारदातों में शामिल थी। जिस पर चार लाख का इनाम था। दूसरे नक्सली की शिनाख्त शांताराम देवराम गावड़े के रूप में हुई है। इस भी चार लाख का इनाम था।

जम्मू-कश्मीर में अस्पताल खोल सकते हैं कई बड़े ग्रुप

रोहित जंडियाल, जम्मू

- अनुच्छेद 370 के हटते ही स्वास्थ्य क्षेत्र में होने जा रहा बड़ा बदलाव
- कई बड़े निजी अस्पतालों की चल रही है ओपीडी

अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर हर क्षेत्र में पीछे चला गया था। मगर अब इसके हटने से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कई बड़े ग्रुप राज्य में अस्पताल खोलने को इच्छुक हैं। इनमें मेदांता और अपोलो ने यहां अस्पताल खोलने की इच्छा जताई है। हालांकि पहले से कुछ ग्रुप यहां अपनी ओपीडी चला रहे हैं। अलबत्ता, जम्मू-कश्मीर में नारायणा ग्रुप को छोड़ दें तो कोई बड़ा निजी अस्पताल नहीं है। नारायणा ग्रुप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर कटड़ा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चला रहा है। मेदांता द मेडिसिटी, फोर्टिज, एस्कार्ट और अपोलो जैसे बड़े ग्रुप पहले भी राज्य में अस्पताल बनाने की रुचि दिखा चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 हमेशा आड़े आया।

ये ग्रुप चला रहे ओपीडी : जम्मू में इस समय मेदांता द मेडिसिटी, अपोलो, एस्कार्ट, अमनदीप, हरदास, शैलबी अस्पताल, बीएलके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मैक्स अस्पताल की ओपीडी चल रही है। इनके अलावा भी और भी कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर यहां समय-समय पर आते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह। (फाइल)

आ सकते हैं और भी कई ग्रुप

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद मेदांता के डॉ. त्रेहन और अपोलो ग्रुप ने अपनी रुचि दिखाई है। पहले भी डॉ. त्रेहन के साथ बात हुई थी। लेकिन जगह के मालिकाना अधिकार को लेकर बात नहीं बन पाई थी। धीरे-धीरे कई और बड़े ग्रुप राज्य में अस्पताल खोलने को आगे आएंगे।

जम्मू में खुल रहा है अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट

अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे पहले जम्मू में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। हालांकि इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। इसका उद्घाटन इसी महीने होने की उम्मीद है।

जम्मू में प्रमुख निजी अस्पताल : इस समय जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चल रहा है। इसके अलावा आचार्य श्री चंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। जेके मेडिसिटी, बीएन जनरल अस्पताल और महर्षि दयानंद अस्पताल भी यहां मौजूद हैं।

सरकार की नीति : राज्य प्रशासनिक परिषद ने मार्च में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति-2019 को मंजूरी दी थी। इस नीति के पास होने से अब राज्य में कोई भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज स्थापित करता है तो उसे पूंजी निवेश में 30 फीसद की छूट दी जाएगी। यह छूट दस लाख की जनसंख्या से कम वाले शहरों में अधिकतम तीन करोड़ के निवेश तक और दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में अधिकतम पांच करोड़ तक निवेश करने पर ही मिलेगी। यही नहीं 15 लाख रुपये तक ऋण लेने पर ब्याज दर में भी पांच फीसद छूट दी जाएगी। यह छूट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अधिकतम पांच साल तक के लिए होगी।

चुनौतियों के बावजूद वादी में बढ़ रहा सेब खरीद का दायरा

- फसल की ग्रेडिंग और मंडी में इसे लेकर आना है बड़ी चुनौती
- इसके बावजूद सेब उत्पादकों को हो रहा सीधा फायदा

सेब कारोबारियों को राहत देने के लिए नैफेड के माध्यम से सेब खरीदे जा रहे हैं। (फाइल)

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सेब कारोबारियों को राहत देते हुए कश्मीर में नैफेड के माध्यम से सेब की खरीद जा रही है। नैफेड ने पूरे सीजन में जम्मू-कश्मीर बागवानी विभाग की मदद से करीब पांच हजार करोड़ के फल खरीदने का लक्ष्य रखा है। चूंकि नैफेड पहली बाद कश्मीर में सेब की खरीद कर रहा है और उसे तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला, बावजूद उसके टीम ने तत्परता से खरीद प्रक्रिया शुरू की। इससे फल उत्पादकों को सीधा फायदा मिला है। अब नैफेड के लिए चुनौती यह है कि दूरदराज के गांवों से किसान स्वयं अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचें या फिर नैफेड और बागवानी विभाग के अधिकारी उन गांवों में जाकर खरीद करें। वर्तमान हालात में यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है।

बागवानी विभाग ने फलों की ग्रेडिंग के अनुसार दाम तय कर दिए हैं। इससे पूर्व सेब का कारोबार निजी हाथों में किसान-डीलर-बाजार के चक्र में सीमित रहा है। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों द्वारा सेब निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने और बाहर से व्यापारियों के न आने से परेशान स्थानीय सेब उत्पादकों की मदद के लिए ही केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन के आग्रह पर इस योजना को मंजूरी दी थी। इससे किसानों को पर्याप्त दाम मिलेगा ही, तुरंत पैसा भी सीधे खाते में रिलीज किया जा रहा है।

नैफेड के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा कि कश्मीर में यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण है। उनके मुताबिक फसल की ग्रेडिंग बाजार में नहीं, बल्कि बागों में पेड़ों पर फल आते ही शुरू हो जाती है। इसके अलावा फसल के कुल उत्पादन और बाजार के रुझान को भी देखा जाता है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को श्रीनगर में नैफेड ने पहला कार्यालय खोला और उसके दो दिन बाद ही पूरे कश्मीर में उसने सेब को खरीदने का काम शुरू कर दिया गया। ढांचागत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार सहयोग कर रही है।

उन्होंने कहा हम जो दाम दे रहे हैं, वह सेब की ग्रेडिंग के आधार पर स्थानीय किसानों को बाजार में मिलने वाले दाम से ज्यादा हैं। सेब की जांच और ग्रेडिंग आसान काम नहीं है। इसके बावजूद तेजी से खरीद की जा रही है। नैफेड के प्रबंध निदेशक संजीव चड्ढा के मुताबिक, बागवानी योजना एवं विपणन निदेशालय जम्मू-कश्मीर ही किसानों से सेब खरीदकर हमें बेच रहा है और उसका तुरंत भुगतान यकीनी बना रहे हैं।

राज्य बागवानी विपणन विभाग में कार्यरत एयाज नतनु ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती किसानों का सत्यापन है। कौन सही है और कौन गलत, इसकी पहचान करनी है। इसके लिए हम आधार और केवाईसी का तरीका अपना रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रेडिंग मंडी के भीतर तय करना भी मुश्किल हो जाता है।

बारामुला फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ डार ने कह कि नैफेड को लाने की योजना हर किसान तक पहुंचे, यह जिम्मेदारी सरकार पूरी करे तभी फायदा होगा। डार के अनुसार वादी से हर साल 10 करोड़ से ज्यादा पेटी सेब देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। नैफेड अधिकारियों ने बताया कि पर्याप्त संचार सुविधाएं न होने के बावजूद वादी में काफी लोग हमारे पास आए हैं। वे सरकार द्वारा जारी बयान के आधार पर ही पहुंचे हैं। कई किसानों अपनी फसल की ग्रेडिंग नहीं, बल्कि एक मुश्त दाम मांग रहे हैं। फल व्यापारी मोहम्मद युसुफ डार ने कहा कि कश्मीर में डीलरों को बिक्री पर छह फीसद कमीशन मिलता था, दिल्ली में यह कमीशन दस फीसद है। नैफेड की योजना में हमारे लिए क्या है, यह तय नहीं है।

इस बीच, मंडी में मौजूद एक किसान ने कहा कि बहुत से लोगों के सामने अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाना भी चुनौती है क्योंकि आतंकियों ने धमकी दे रखी है। ट्रक नहीं मिल रहे हैं। उक्त किसान की बात सुनकर वहां मौजूद अधिकारियों ने कहा कि यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

सीमा पर गोलाबारी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी

सख्त रुख ▸ इस साल 2050 बार संघर्षविराम के उल्लंघन में मारे जा चुके हैं 21 लोग

भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बावजूद बाज नहीं आ रहा पाक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दुनिया के सामने न्यूक्लियर ब्लैक मेल की प्रधानमंत्री इमरान खान की कोशिशों के बीच भारत ने पाकिस्तान को संघर्षविराम उल्लंघन और सीमा पार से हो रही घुसपैठ को लेकर आगाह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिना किसी कारण के हो रही सीमा पार की गोलाबारी पर भारत गंभीर है। भारत ने पाकिस्तान को 2003 में संघर्षविराम को लेकर बनी सहमति का सम्मान करने, अंतरराष्ट्रीय सीमा व नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नहीं करने की नसीहत दी है।

दरअसल बार-बार भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार बिना किसी कारण के संघर्षविराम का उल्लंघन कर रहा है। रवीश कुमार के अनुसार अकेले इस साल पाकिस्तान ने बिना उकसावे के 1,050 बार संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। इसमें कुल 21 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं। यह अलग बात है कि भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। शनिवार को ही पाकिस्तानी सेना के सफेद झंडे के साथ अपने दो जवानों के शव को ले जाने का वीडियो सामने आया है।

पाकिस्तान की नापाक हरकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी फौज भारतीय नागरिकों और बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाकर गोले दाग रही है। शनिवार को भी पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट में भीषण गोलाबारी की। इसके बाद नियंत्रण रेखा के पांच किलोमीटर के दायरे में स्कूल बंद करवा दिए गए। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में भी नियंत्रण रेखा से लगे हुए गांवों और अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार को मोर्टार से गोले दागे और भारी गोलीबारी करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में रिहायशी क्षेत्र में गिरे जिंदा मोर्टार शेल की जांच करते एक सैन्य अधिकारी। शनिवार को पाकिस्तान ने राजौर-पुंछ के पांच सेक्टरों में लगातार पांच घंटे तक गोलाबारी की थी। अभी भी कई जिंदा शेल सीमांत क्षेत्रों में गिरे हैं जिन्हें सेना निष्क्रिय कर रही है। गगन कोहली

- विना कारण सीमा पार की गोलाबारी गंभीर बात : रवीश कुमार
- नियंत्रण रेखा के पांच किलोमीटर के दायरे में बंद करने पड़े हैं स्कूल

भारत को मिली बिल्डिंग ब्लास्टर स्पाइस बम की पहली खेप

नई दिल्ली, एएनआइ : भारत की हवाई ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रक्रिया के तहत उसे बिल्डिंग ब्लास्टर स्पाइस-2000 बम मिलने शुरू हो गए हैं। ये उन बमों का उन्नत संस्करण हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए-मुहम्मद के आतंकी अड्डे पर बीती फरवरी में कहर बरपाया था। ये बम ग्वालियर स्थित वायुसेना के अड्डे को मिल रहे हैं। ग्वालियर अड्डा देश में मिराज-2000 लड़ाकू विमानों का मुख्य ठिकाना है। इसी विमान से इजरायली स्पाइस-2000 बम गिराए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने आपात खरीद प्रक्रिया के तहत जून में ही इजरायल की फर्म के साथ मार्क 84 वारहेड और बमों की खरीद का 250 करोड़ रुपये का सौदा किया था। इस सौदे के तहत 100 से ज्यादा स्पाइस-2000 बम खरीदे जाने हैं।

आपात खरीद की यह व्यवस्था मोदी सरकार ने शुरू की है। इसके तहत तीनों सेनाएं अपनी जरूरत के हथियार और गोला-बारूद लंबी प्रक्रिया में जाए बगैर कुछ महीनों में खरीद सकती हैं। बालाकोट हमले की सफलता के बाद वायुसेना ने इन बमों की बड़ी संख्या में जरूरत महसूस की।

नए आयातित बम बालाकोट हमले में प्रयुक्त बमों से ज्यादा शक्तिशाली हैं और बड़ी इमारत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाना बर्बाद किया था।

धर्म बदलने वाले आदिवासियों से छीना जाए जनजाति दर्जा

जागरण संवाददाता, रांची

- मुख्यमंत्री से मांग, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक जाति की श्रेणी में डालें, ग्राम सभा दे प्रमाण पत्र
- जनजातीय सुरक्षा मंच ने मोरहाबादी से राजभवन तक किया मार्च, पुलिसकर्मियों ने रोका

धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों का जनजाति का दर्ज खत्म किया जाए। उन्हें अल्पसंख्यक जाति की श्रेणी में डाला जाए। जनजातियों की पुरानी रीति-रिवाज, पूजा पद्धति व परंपरा को मानने वालों को ही ग्रामसभा के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस संबंध में आवाज बुलंद की है। रविवार को मंच की ओर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना थी। राजभवन के समीप पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मार्च में शामिल लोगों ने ईसाइयों को जाति प्रमाण पत्र देना बंद करो, राज्य सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए। इसके बाद मंच के लोगों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व मोरहाबादी मैदान में मंच की ओर से सभा का आयोजन भी किया गया। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. राजकिशोर हांसदा ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो आदिवासी धर्मांतरण कर चुके हैं, उनसे एसटी का दर्जा छीना जाए।

चर्च के माध्यम से चल रहा है धर्मांतरण का खेल : मंच के प्रांत संरक्षक डॉ. सुखी उरांव ने कहा कि चर्च के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आदिवासी भाई-बंधुओं का धर्मांतरण कराकर ईसाई बनाया जा रहा है। विदेशी धर्म अपनाते ही जनजाति समाज का रीति-रिवाज, पूजा, परंपरा व संस्कृति समाप्त हो जाती है। मंच के प्रांत संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि धर्मांतरित जनजातियों ने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। 45 वर्ष पूर्व स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने इसका विरोध किया था।

धर्मांतरण कर आदिवासियों की पहचान खत्म की जा रही

मंच ने कहा कि चर्चों की आड़ में जनजाति समाज का धर्मांतरण कर आदिवासियों की पहचान खत्म की जा रही है। आजादी के 72 वर्ष बाद भी जनजाति समाज की पहचान व अस्तित्व को मिटाने की साजिश की जा रही है। जनजाति समाज की लाखों एकड़ जमीन पर स्कूल व अस्पताल के नाम पर हजारों चर्च का निर्माण हो चुका है।

सेना के 'डच' को दी अंतिम विदाई :

कई मिल्ट्री ऑपरेशंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके सेना के 9 वर्षीय डॉग 'डच' को कोलकाता में रविवार को एक सैनिक की तरह अंतिम विदाई दी गई। उसकी 11 सितंबर को मृत्यु हो गई थी। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) की पहचान करने में 'डच' को खासतौर पर प्रशिक्षित किया गया था। उसने कई स्थानों पर बमों को पता लगाकर आतंकियों व नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। फिलहाल वह सेना की पूर्वी कमान में तैनात था। सेना की ईस्टर्न कमांड ने ट्वीट करके 'डच' की असमय मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एएनआइ

मध्य प्रदेश में मदरसे में जंजीर से बंधा मासूम बेंच लेकर डेढ़ किमी भागा

भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि

मध्य प्रदेश के भोपाल में अशोका गार्डन क्षेत्र के निजी मदरसे में दस वर्षीय बच्चे को जंजीर से बांधकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। दुकान के सामने सो रहे बच्चों को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मदरसा संचालक की प्रताड़ना से मासूम इतना तंग आ गया था कि रविवार तड़के वह जंजीर से बंधी टेबल लेकर ही मदरसे से भाग गया। उसके साथ सात साल का एक और बच्चा था। मदरसा संचालक और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अशोका गार्डन थाना प्रभारी उमेश यादव के मुताबिक प्रभात चौराहा अशोका गार्डन में दो बच्चों के बारे में जानकारी मिली थी। बताया गया था कि एक बालक के पैर में जंजीर ताले से बंधी है, जिसका दूसरा सिरा लोहे की छोटी बेंच से बंधा है। सूचना मिलते ही पुलिस दोनों बच्चों को थाने लेकर आई और जंजीर काटकर बच्चों को मुक्त कराया। चाइल्ड हेल्प लाइन की कांउसलर अनिता मिश्रा ने दोनों बच्चों की कांउसलिंग की गई। बच्चों से पूछताछ के आधार पर जकरिया मस्जिद अशोका गार्डन के मुफ्ती मोहम्मद साद (32) और हाफिज सलमान (19) के खिलाफ बच्चों से मारपीट और पैर में लोहे की जंजीर बांधकर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज किया गया है।

अमानवीयता

- एक दुकान के सामने बच्चों को सोता देख लोगों ने पुलिस को दी खबर
- मदरसा संचालक और शिक्षक गिरफ्तार

जंजीर से बांधा जाता था, मुक्के व पाइप से मारते थे मौलवी : चाइल्ड लाइन की काउंसिलिंग में बच्चों ने बताया कि गुरुवार से ही हम दोनों को जंजीर से बांध रखा था। रविवार को मदरसा खाली रहता है, जिससे मौका देखकर हम भाग गए। पढ़ाई के लिए मौलवी पीठ पर इतनी जोर से मुक्का मारते थे कि रात भर दर्द होता था। पाइप से भी पिटाई की जाती थी। लगभग सभी बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता है। मरदसे में खाना भी अच्छा नहीं मिलता था। पतली दाल व खराब चावल दिया जाता था। कभी-कभी सब्जी मिलती थी। जब हमारे अम्मी-अब्बू (माता-पिता) आते थे तो पिटाई होने की बात बताने पर मौलवी उनके जाने के बाद और अधिक पीटते थे। 10 साल के बच्चे के शरीर पर कई स्थानों पर मेडिकल के दौरान डॉक्टर को घाव मिले हैं। हालांकि पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि यह मारपीट के हैं या बीमारी के हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

थाने में बैठा बच्चा। नईदुनिया

देशभक्ति

पाकिस्तान के बालाकोट इलाके के आतंकी शिविरों पर हुए सर्जिकल एयर स्ट्राइक की तर्ज पर कोलकाता में बन रहा पंडाल।

दुर्गापूजा में दिखेगा वायुसेना का पराक्रम

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

26 फरवरी, 2019...यह वह दिन था, जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी करतूतों का करारा जवाब दिया था। उस दिन पौ फटने से पहले ही भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर वहां चल रहे आतंकी शिविरों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर उन्हें नेस्तानाबूद कर दिया था। वह ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई अब आंखों के सामने घटित होती नजर आएगी। लोग दांतों तले अंगुली दबाकर भारतीय वायुसेना का पराक्रम देखेंगे। कोलकाता की एक दुर्गापूजा कमेटी उसका पुनः सृजन करने जा रही है।

मध्य कोलकाता के यंग ब्वायज क्लब ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष पर इसे ही अपना थीम बनाया है। सर्जिकल एयर स्ट्राइक के बीच भारतीय वायुसेना के जाबांज विंग कमांडर अभिनंदन भी नजर आएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया था।

क्लब के यूथ विंग के अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि यह हमारी ओर से पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि और उसके बाद सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाले वायु वीरों को सलामी है। इसके साथ ही हम विंग कमांडर अभिनंदन के सम्मान में उनकी एक प्रतिकृति को भी दर्शाएंगे।

150 कारीगर तैयार कर रहे 65 मॉडल : इस थीम को मूर्त रूप देने के लिए कोलकाता से दूर पूर्व मेदिनीपुर जिले में वायुसेना के जवानों और आतंकियों के 65 मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इस काम में 150 कारीगर दिन-रात जुटे हुए हैं। पंडाल में वायुसेना के जाबांज आतंकियों पर कहर बरपाते नजर आएंगे। बीच में विंग कमांडर अभिनंदन का बड़ा सा पुतला होगा। पूर्व मेदिनीपुर के जाने-माने थीम आर्टिस्ट देव शंकर महेश इसे मूर्त रूप दे रहे हैं। घटना को जीवंत करने के लिए आलोक सच्जा व साउंड इफेक्ट पर खास काम किया जाएगा। पंडाल की ऊंचाई 40 फुट होगी।

धागे से बन रही माता की प्रतिमा

यहां की दुर्गा प्रतिमा भी उतनी ही अद्भुत होगी। प्रतिमा को रेशम जैसे धागे से तैयार किया जा रहा है। इस खास धागे का नाम मलाई कट है। कुल 600 किलो धागे का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रतिमा ऑफ व्हाइट रंग की होगी। इसके निर्माण में मिट्टी का कम से कम इस्तेमाल किया जा रहा है। मिट्टी उतनी ही होगी, जिससे ढांचे को मजबूती दी जा सके। दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई करीब 15 फुट होगी।

पंडाल के अंदर होगी शांति

पंडाल के बाहर एयर स्ट्राइक का नजारा होगा लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह शांत होगा। वहां अद्भुत नक्काशी देखने को मिलेगी, जो कल्पना पर आधारित होगी और दिमाग को शांत करेगी। पिछले एक महीने से पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है। महालया से पहले इसके तैयार हो जाने की उम्मीद है।

सेना के अधिकारी से उद्घाटन कराने की योजना :

क्लब के अधिकारियों ने बताया कि पंडाल का उद्घाटन सेना के ही किसी अधिकारी से कराने की योजना है। इस बाबत सेना के पूर्वी कमान से संपर्क किया जा रहा है।

तैयार किए जा रहे मॉडल। जागरण

कश्मीर के साप्ताहिक बाजार खरीदारों से रहे गुलजार

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- प्रमुख बाजार बंद होने से रविवार को उमड़ी भीड़
- रेहड़ी वालों को कोई परेशान न करे, प्रशासन ने किए इंतजाम

कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले रविवार बाजारों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने जरूरत का सामान खरीदा। दरअसल, कश्मीर में लगातार 42वें दिन भी ज्यादातर प्रमुख बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इसलिए लोगों के लिए खरीदारी का एक प्रमुख स्थान रविवार का बाजार ही है। ऐसे में यह बाजार खरीदारों से खूब गुलजार हो रहे हैं।

श्रीनगर के टीआरसी चौक और पोलो व्यू के आसपास रविवार को कई जगहों पर रेहड़ियां लगी थीं। इस स्थान पर कई सालों से हर रविवार को बाजार सजता है। लोग इनमें खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए थे। इन रेहड़ी वालों को कोई असामाजिक तत्व तंग न करे, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। इस दौरान कश्मीर में निजी वाहनों की आवाजाही पर कोई भी रोक नहीं थी। कुछ अंतर जिला कैब भी सड़कों पर नजर आ रही थीं।

हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में ही चालू हैं मोबाइल सेवाएं

कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। लैंडलाइन सेवा पूरे कश्मीर में बहाल कर दी गई है। वहीं, मोबाइल वॉयस काल की सुविधा सिर्फ उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जिलों में ही बहाल है। कश्मीर के कई क्षेत्रों में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन सुरक्षाबल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सजग हैं। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद से ही प्रतिबंध लगाए गए थे। इन सभी प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है।

04 फीसद ज्यादा बारिश दर्ज की गई है देश में इस साल अब तक। क्षेत्रवार बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में यह आंकड़ा 10 फीसद ज्यादा है। मध्य भारत में 23 फीसद ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है।

ऑनर किलिंग ▸ गोलियां मारीं, कार से रौंदा और फिर धारदार हथियारों से किए कई वार

प्रेम विवाह से खफा चचेरे भाइयों ने बहन और उसके पति को मार डाला

एक साल पहले हुआ था विवाह, गुरुद्वारे से माथा टेककर लौट रहे थे दंपती

जागरण संवाददाता, तरनतारन

प्रेम विवाह करने वाले अमनदीप सिंह अमन व अमनप्रीत कौरा की फाइल फोटो।

पंजाब के तरनतारन जिले में करीब एक साल पहले प्रेम विवाह करने वाले दंपती की रविवार दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। युवती के चचेरे भाइयों ने गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुड्ढा साहिब से माथा टेककर लौट रहे बाइक सवार दंपती को भैणी रोड पर राजा ताल गांव के पास रोका। कार सवार हमलावरों ने पहले दोनों को गोलियां मारीं। इसके बाद दोनों को अपनी कार में डालकर कर बहन की ससुराल नौशहरा ढाला ले गए। वहां दोनों को चौराहे पर फेंका और कार से रौंदा। इसके बाद फिर गोलियां मारीं। बर्बरता यहीं नहीं थमी। हमलावरों ने दोनों पर धारदार हथियार से भी कर वार किए।

नौशहरा ढाला निवासी अमनदीप सिंह अमन (24) ने गहरी गांव निवासी अमनप्रीत कौर प्रीत (21) से करीब एक साल पहले प्रेम विवाह किया था। इस बात से अमनप्रीत के घर वाले बेहद नाराज थे। रविवार को अमनप्रीत अपने पति के साथ बाइक से गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने गई थी। इस बात की जानकारी अमन के भाईयों को हो गई और उन्होंने वारदात को अंजाम देने का फैसला कर लिया। बहन-बहनोई के गुरुद्वारे से वापसी के दौरान भैणी रोड पर राजा ताल गांव के पास भाइयों ने अपनी कार से बाइक में टक्कर मारी, जिससे अमन और उसकी पत्नी गिर पड़े। इसके बाद कार से उतरे लोगों ने दंपती पर कई गोलियां दाग दीं। इसके बाद दोनों को लहूलुहान हालत में अपनी कार में डाला और नौशहरा ढाला ले गए। गांव के चौराहे पर हमलावरों ने दोनों घायलों को कार से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद कार से रौंदने के बाद फिर गोलियां मारी। हमलावर इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने मरणासन्न दंपती पर धारदार हथियारों से भी कई वार किए। अमनदीप सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अमनप्रीत कौर करीब 15 मिनट सड़क पर तड़पती रही। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े सड़क पर दो लोगों के कत्ल की जानकारी मिलते ही एसएसपी ध्रुव दहिया, डीएसपी कमलजीत सिंह औलख, थाना प्रभारी करनजीत सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी हासिल की। पुलिस ने मौके से गोलियों के खोल बरामद किए हैं। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सभी आरोपित फरार हैं। युवा दंपती की हत्या के बाद क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल है।

घटनास्थल पर पहुंचे युवती के माता पिता हिरासत में : हत्या के कुछ समय बाद अमनप्रीत कौर के माता पिता अमरजीत सिंह और हरजिंदर कौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि इस हत्याकांड से उनका कोई वास्ता नहीं। उनके भतीजों ने ही मिलकर यह हत्याएं की हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है।

पिता और भाई समेत नौ लोगों पर केस दर्ज : डीएसपी कमलजीत सिंह औलख ने कहा कि थाना सराय अमानत खां में अमनप्रीत कौर के पिता अमरजीत सिंह, भाई मंजीत सिंह, उसके चचेरे भाइयों गुरभिंदर सिंह व सुरजीत सिंह के अलावा हरविंदर सिंह और चार अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए छापामारी की जा रही है।

एयर इंडिया के फ्लाइट क्रू के लिए अब कम फैट वाला खाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयर इंडिया ने उड़ानों के दौरान चालक दल के सदस्यों (फ्लाइट क्रू) के लिए अपने मेन्यू में बदलाव किया है। अब उन्हें खास कम फैट वाला खाना मिलेगा, जिसमें पालक मटर भुर्जी, टिंडा मसाला, चुकंदर आलू की टिक्की और मसूर की दाल शामिल है। एयर इंडिया ने ऐसा चालक दल के सदस्यों की सेहत सुधारने के लिए किया है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी मेन्यू में बदलाव केवल दिल्ली-मुंबई फ्लाइट में किया गया है। यह पहल एयर इंडिया के खर्च के लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि उस पर करीब 58000 करोड़ रुपये का कर्ज है।

एयर इंडिया द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि मेन्यू में बदलाव 15 सितंबर से प्रभावी कर दिया गया है। यह बदलाव और कॉकपिट और केबिन क्रू के लिए लागू किया गया है। फ्लाइट के दौरान कम फैट वाली खाद्य सामग्री तैयार की जाएगी। अरहर की दाल, पुदीना रायता, चपाती, मुर्ग धनिया, ताजा हरा सलाद, दाल कबीला, बूंदी रायता और पालक-मक्के की टिक्की भी मेन्यू में होगी। एयर इंडिया ने अपने फ्लाइट स्टॉफ से कहा है कि चालक दल के सदस्यों के स्वास्थ्य का पहलू ध्यान में रखते हुए फ्लाइट के भीतर के मेन्यू में परिवर्तन की पहल निदेशक (ऑपरेशंस) की ओर से की गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार एयरइंडिया की सेवाओं में बेहतरी के साथ ही उसे विश्वस्तरीय विमानन कंपनियों के मुकाबले के लिए तैयार करने में जुटी है। इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।

बालिका गृह कांड की पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, बेतिया (प. चंपारण)

10 घंटे आइसीयू में रहने के बाद स्थिति में सुधार, आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस

13 सितंबर की रात में घर के पास से अगवा की गई थी पीड़िता, 14 सितंबर को थाने पहुंची

बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता के बयान पर चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच का जिम्मा महिला थाने की प्रभारी को दिया गया है। घटना के बाद गंभीर हालत में पीड़िता दस घंटे तक आइसीयू में रही। रविवार को हालत थोड़ी सुधरी तो पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 13 सितंबर की रात बोलेरो से उसे अगवा किया गया। करीब दो घंटे तक बोलेरो शहर के अलग-अलग मोहल्लों में भ्रमण करती रही। इसी दौरान चार युवकों ने दुष्कर्म किया।

घर में अकेली थी : बालिका ने बताया कि 13 सितंबर की वह रात घर में अकेली थी। मां बड़ी बेटी के घर गई थी। पिता बाहर रहते हैं। इसलिए बगल के मोहल्ले में रिश्ते की भाभी के घर सोने जा रही थी। वह अपने घर से निकली कि नजदीक से एक बोलेरो गुजरी। फिल्मी अंदाज में दो युवक नीचे उतरे और जबरन खींच कर गाड़ी में बैठा लिया। सभी गमछा से मुंह बांधे थे। गाड़ी में चारों ने दुष्कर्म किया।

जान से मारने की धमकी : पीड़िता ने बताया कि दो घंटे तक बोलेरो में दुष्कर्म किया। इसके बाद घर के पास लाकर छोड़ दिया। जाते-जाते घटना का जिक्र करने पर जान मारने की भी धमकी दी। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई। घर जाकर भाभी को मोबाइल पर सूचना दी। रात में ही पीड़िता की भाभी पहुंची। 14 सितंबर की सुबह पीड़िता नगर थाने पहुंची और मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। ज्ञात हो, बिहार में अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है।

मोकामा शेल्टर होम से घर आई थी पीड़िता

मुजफ्फरपुर बालिका गृह से मुक्त होने के बाद युवती को मोकामा में शिफ्ट कराया गया था। जानकारी मिलने के बाद परिजन वहां पहुंचे और घर लाया था। पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा भी मिला है।

पीड़िता के बयान पर चार लोगों के खिलाफ कांड दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

-पूनम कुमारी, थानाध्यक्ष, महिला थाना, बेतिया (प. चंपारण)

बच्चों में बौनापन मापने के मापदंड की समीक्षा कर रही सरकार

▸ **ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट-2018 के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा 4.66 करोड़ बच्चे बौनेपन का शिकार**

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार बच्चों में बौनापन मापने के मापदंड की समीक्षा कर रही है। साथ ही भारतीय मानव विज्ञान के अनुसार इसके भारतीयकरण के तरीके का पता भी लगा रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

पर्याप्त पोषण न मिलने, बार-बार संक्रमण आदि के कारण बच्चों की लंबाई प्रभावित होती है। इसे बौनापन कहा जाता है। फिलहाल बौनेपन का निर्धारण बच्चे की लंबाई के आधार पर किया जाता है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट-2018 के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा 4.66 करोड़ बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। इसके बाद नाइजीरिया व पाकिस्तान का नंबर आता है, जहां क्रमशः 1.39 व 1.07 करोड़ बच्चों में बौनेपन की समस्या है। भारत में 2.55 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं, जबकि नाइजीरिया व इंडोनेशिया में इनकी संख्या क्रमशः 34 व 33 लाख है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4) के अनुसार, भारत में पांच साल से कम उम्र के 38.4 फीसद बच्चों में बौनापन है। यानी, उनकी लंबाई उम्र के मुकाबले कम है। दूसरी तरफ, 21 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में पांच साल से कम उम्र के 48.3 फीसद बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बच्चों का मानव संरचना विज्ञान बदलता है। विविधतापूर्ण देश में बच्चों में बौनापन मापने का एक ही मापदंड सही नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सरकार हार्वर्ड टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से यह जानने का प्रयास कर रही है कि बौनेपन को मापने वाले अंतरराष्ट्रीय मापदंड का भारतीयकरण कैसे किया जाए। केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के कुपोषित बच्चों की भोजन की जरूरतों को समझते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खाद्य पदार्थों का अध्ययन भी करा रही है, जो पोषणयुक्त होने के साथ-साथ सस्ते और पारंपरिक रूप से स्वीकार्य हों। सरकार बच्चों व उनके परिजनों को भी पोषण के बारे में जागरूक कर रही है।

मैदानी इलाकों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मानसून अभी भी सक्रिय है। मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आइएमडी के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक देश में सामान्य से चार फीसद ज्यादा बारिश हुई है।

सामान्य तौर पर एक सितंबर के बाद से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मानसून की सक्रियता कम होने लगती है। 15 सितंबर तक राजस्थान के कुछ अन्य इलाकों, गुजरात के कछ और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में भी मानसून की बारिश बंद हो जाती है। लेकिन इस साल पश्चिमी राजस्थान में अभी भी मानसून सक्रिय है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख के. सती देवी के मुताबिक मौजूदा समय में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे अच्छी बरसात हो रही है। इसके चलते पूरवइया हवा में नमी बनी हुई है। उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा उमस बनी हुई है, जो सितंबर के महीने में प्रायः देखने को नहीं मिलती। कम दबाव क्षेत्र के चलते हवा में नमी है जो तापमान के साथ मिलकर उमस पैदा कर रही है। आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि वैसे तो कम दबाव की तीव्रता में सोमवार कमी आने लगेगी, लेकिन उसका प्रभाव अगले पांच दिनों तक बना रहेगा। उसके बाद ही मानसून के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

अभी तक देश में सामान्य से चार फीसद ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। दक्षिणी क्षेत्र में यह 10 फीसद ज्यादा है, जबकि मध्य भारत में 23 फीसद ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और उत्तर भारत में क्रमशः 18 और आठ फीसद कम बरसात हुई है। वैसे देश के मौसम संबंधी 36 उप क्षेत्रों में से दो तिहाई से ज्यादा क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक बारिश हुई है। इनमें 16 उप क्षेत्रों में सामान्य और 11 उप क्षेत्रों में अधिक बारिश दर्ज की गई है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान में बाढ़ के हालात की समीक्षा, मदद के निर्देश

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने रविवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ के चलते पैदा हुए हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को तत्काल सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि समिति को बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। राज्य सरकारें हालात पर लगातार नजर रख रही हैं। किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और सेना की पर्याप्त टीमों को लगाया गया है।

राजस्थान के कई शहरों में रविवार को भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। कोटा शहर में कई फीट पानी भर गया। ऐसे में ट्यूब की मदद से एक शख्स ने बाढ़ में घिरे दो बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यहां बारिश ने करीब 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एएनआइ

एसआइटी को नहीं मिलीं सिख विरोधी दंगे की फाइलें

जागरण संवाददाता, कानपुर : कानपुर में हुए सिख विरोधी दंगा मामले की दोबारा जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआइटी) को अब तक गंभीर अपराधों से संबंधित फाइलें नहीं मिल सकी हैं। 35 साल पुराना मामला होने के कारण रिकार्ड रूम के कर्मचारी भी पत्रावलियां नहीं खोज पा रहे। अब एसआइटी ने जिला प्रशासन के साथ कोर्ट से मदद मांगी है क्योंकि मुआवजे से संबंधित पत्रावलियां प्रशासन और मुकदमा संबंधित अभिलेख अदालत के पास भी हैं।

1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नजीराबाद, फजलगंज, नौबस्ता आदि क्षेत्रों में दंगे के दौरान करीब 127 लोगों की मौत हुई थी। कई जगह लूटपाट व आगजनी भी हुई थी। शहर के विभिन्न थानों में इस संबंध में मुकदमे लिखे गए थे। इसमें से 38 मुकदमे हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े थे।

एसआइटी सूत्रों ने बताया कि इन 38 मुकदमों में से 12 मुकदमों में चार्जशीट और बाकी में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई थी। शासन के निर्देश पर सबसे पहले उन्हीं मामलों की जांच की जानी है लेकिन अब तक फाइलें नहीं मिली हैं। खास बात यह है कि एफआइआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिल सकी है।

दर्ज हुए 1254 मुकदमे, 1101 मामलों में लगी एफआर: सिख विरोधी दंगों के दौरान विभिन्न थानों में 1254 मुकदमे दर्ज हुए थे। नजीराबाद थाने में 135, नौबस्ता में 227, गोविंदनगर में 374, सीसामऊ में 72, कल्याणपुर में 47, पनकी में 46 और किदवईनगर में 52 के अलावा अन्य थानों में भी मुकदमे लिखे गए थे। इनमें से पुलिस ने 1101 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट और 153 में चार्जशीट लगाई थी।

हत्या, डकैती जैसे गंभीर प्रकृति के 38 मुकदमों की फाइलें अभी नहीं मिल सकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआइआर की कॉपी लेने के लिए मुकदमों के वादी से भी संपर्क किया जा रहा है लेकिन वह भी नहीं आ रहे हैं।

बालेंदु भूषण, एसपी एसआइटी

नाकामी छिपाने के लिए उत्तर भारतीयों को बताया अयोग्य : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर भारतीयों की योग्यता पर सवाल उठाने संबंधी श्रम मंत्री संतोष गंगवार के बयान पर कांग्रेस ने बेहद तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री से तुरंत माफी की मांग की है। पार्टी ने कहा कि सरकार रोजगार के मोर्चे पर अपनी नाकामी छिपाना चाहती है और गंगवार ने लोगों को अपमानित कर मंत्रिपरिषद में रहने का हक खो दिया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के जरिये सरकार को आड़े हाथ लिया। प्रियंका के ट्वीट के बाद पार्टी प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने कहा, गंगवार का बयान उत्तर भारत के लोगों का अपमान है। यह शर्मनाक, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अपनी कमियों को छिपाने वाला बयान है। केंद्र सरकार के मंत्री योग्यता पर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर भारत से ही चुनाव लड़ते हैं और इस पैमाने पर तो वह भी योग्य नहीं हुए। श्रम मंत्री भी उत्तर भारत से हैं तो खुद वह भी योग्य नहीं हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एएमयू के साथ पूरब के ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए तिवारी ने कहा कि इनके होते हुए भी श्रम मंत्री को उत्तर भारत के युवा अयोग्य लगते हैं। इससे साफ है कि श्रम मंत्री के बयान में मोदी सरकार का अहंकार बोल रहा है।

ई-फ्लो की मौजूदा संरचना में बदलाव की जरूरत नहीं

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सभी मौजूदा परियोजनाओं की संरचना में निर्धारित ई-फ्लो के हिसाब से पानी छोड़ने की सुविधा है और उनकी संरचना में किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद कई परियोजनाएं व्यवसायिक हितों के चलते ई-फ्लो नियमों के अनुसार पानी नहीं छोड़ रही हैं। यही वजह है कि एनएमसीजी ने मौजूदा परियोजनाओं को दी गई तीन साल की मोहलत को घटाकर 15 दिसंबर 2019 करने का फैसला किया।

सूत्रों के मुताबिक, सीडब्लूसी ने इस साल अप्रैल से जून के दौरान ऊपरी गंगा नदी बेसिन में ई-फ्लो की निगरानी की तो पता चला कि चार परियोजनाओं ने अधिकांश समय पर ई-फ्लो के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया। पालन न करने वाली परियोजनाओं में मानेरीभाली फेज-2, विष्णुप्रयाग एचईपी और श्रीनगर एचईपी शामिल हैं। वहीं मानेरीभाली फेज-1 और पशुलोक बैराज आंशिक रूप से ई-फ्लो नियमों का पालन कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि टिहरी, भीमगौड़ा बैराज और कानपुर बैराज से तय फॉरमेट में ई-फ्लो का डाटा नहीं मिल रहा है। अप्रैल से जून की अवधि में टिहरी और भीमगौड़ा परियोजनाओं से ई-फ्लो के आंकड़े घंटे के आधार पर नहीं मिले।

क्या हैं ई-फ्लो नियम : ई-फ्लो नियमों के मुताबिक, ऊपरी गंगा नदी बेसिन में देवप्रयाग से हरिद्वार तक नवंबर से मार्च के दौरान औसत मासिक प्रवाह का कम से कम 20 फीसद, अक्टूबर से अप्रैल-मई के दौरान 25 और जून से सितंबर तक 30 फीसद प्रवाह तय किया जाना है। वहीं हरिद्वार से उन्नाव के बीच अक्टूबर से मई, जून से सितंबर की अवधि के लिए अलग-अलग ई-फ्लो तय किए गए। मसलन, हरिद्वार के निकट भीमगौड़ा बैराज से आगे अक्टूबर से मई के दौरान 36 क्यूमेक (घनमीटर प्रति सेकेंड) और जून से सितंबर के दौरान 57 क्यूमेक जल गंगा की धारा में बनाए रखना होगा। बिजनौर, नरौरा और कानपुर में अक्टूबर से मई के दौरान कम से कम 24 क्यूमेक और जून से सितंबर के दौरान 48 क्यूमेक जल गंगा नदी में बनाए रखना होगा।

कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान को तैयार विमान पर मधुमक्खियों का हमला

जागरण संवाददाता, कोलकाता

नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआइ) हवाई अड्डे पर रविवार सुबह उस समय लोग हैरत में पड़ गए, जब उड़ान के लिए रन वे पर दौड़ रहे एयर इंडिया केविमान पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। उस समय विमान में बांग्लादेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हसन ममूद व बांग्लादेश के उच्चायोग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी सवार थे। बाद में अग्निशमन विभाग के कर्मियों की मदद से मधुमक्खियों को हटाया गया और दो घंटे से अधिक विलंब के बाद विमान अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर सका।

जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह एयर इंडिया का विमान (बोइंग एआइ-743) सुबह सुबह 9.50 बजे अगरतल्ला के लिए उड़ान भरने को तैयार था। पायलट विमान को टैक्सी वे से रन वे पर भी ले गया, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। विमान के सामने और बगल के हिस्से को घेर लिया, जिससे पायलट को दिक्कतें आने लगी। काफी जद्दोजहद के बाद भी जब पायलट मधुमक्खियों का हटा नहीं सके, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद विमान को मोड़ कर वापस टैक्सी वे पर लाया गया। वहां से कुछ देर बाद पायलटों ने दोबारा से उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। इससे विमान में सवार बांग्लादेश के मंत्री हसन ममूद के साथ ही उसमें सवार अन्य यात्रियों को भी काफी दिक्कतें हुई। वहीं, एयर इंडिया के कर्मचारी भी काफी परेशान हुए। बार-बार मधुमक्खियों से हमले से परेशान होकर उनसे छुटकारा पाने के लिए अग्निशमन विभाग की मदद ली गई। अग्निशमन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद मधुमक्खियों के झुंड को विमान से हटाया। उसके बाद सुबह 12 बजे के करीब विमान अगरतल्ला से लिए उड़ान भर सका।

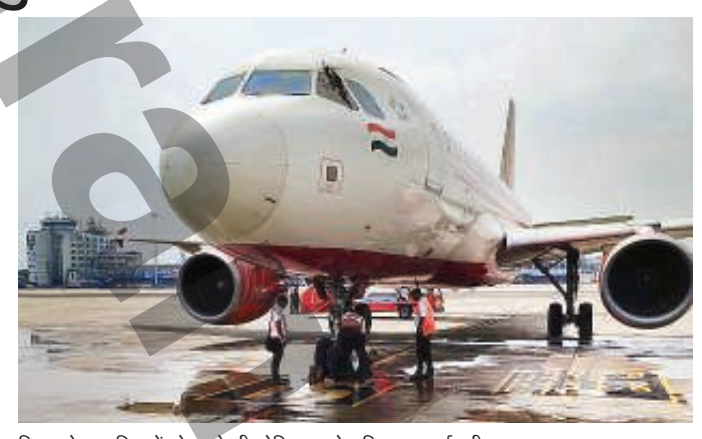

विमान से मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश करते अग्निशमन कर्मचारी। जागरण

सरकार की गलती

वेतन निर्धारण में अधिकारियों की चूक से सरकारी खजाने को लग रही चपत. अब तक अध्यापकों के खाते में दो हजार करोड़ से ज्यादा का हो गया भुगतान

अध्यापकों को हर माह 50 करोड़ का ज्यादा वेतन भुगतान

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में आए कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में सरकार की एक गलती से अध्यापकों को हर महीने लगभग 50 करोड़ रुपए का ज्यादा वेतन भुगतान हो रहा है। सरकार के एक आदेश से लगभग सवा लाख क्रमोन्नत अध्यापकों को ज्यादा वेतन देने की गलती हो गई।

दरअसल, 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मी 2010 में क्रमोन्नत होकर अध्यापक बने, लेकिन वेतनमान की गणना आदेश में उसे अध्यापक का वेतनमान देने के लिए सेवा अवधि गणना 2007 से कर दी, तब वह सहायक अध्यापक थे। ऐसी ही गलती 2001 और 2003 में नियुक्त संविदा शिक्षकों की क्रमोन्नति में हुई है। इन कर्मियों को क्रमशः 2013 व 2015 में क्रमोन्नत वेतनमान दिया गया, लेकिन वित्तीय लाभ देने के लिए सेवा अवधि की गणना 2007 की तारीख से कर दी। इस आदेश में क्रमोन्नत और पदोन्नत अध्यापकों का वेतन निर्धारित करने की तारीख में गड़बड़ी हुई। इस तकनीकी त्रुटि के कारण 1998, 2001 और 2003 में नियुक्तसभी कर्मियों का वेतन निर्धारण एक जैसा हो गया। ज्यादा भुगतान के आंकड़े का विश्लेषण किया जाए तो वर्ष 2016 से अब तक राज्य सरकार दो हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान अध्यापकों को कर चुकी है।

एक जनवरी 2016 से छठा वेतनमान स्वीकृत : राज्य सरकार ने अध्यापक संवर्ग को एक जनवरी 2016 से छठा वेतनमान स्वीकृत किया था। छठे वेतनमान में निर्धारण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पहला आदेश 31 मई 2016 को निकाला, पर तकनीकी त्रुटि के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय निकाय विभाग द्वारा दो-तीन बार आदेश निकाले गए, लेकिन हर बार किसी चूक के चलते उन्हें रद्द करना पड़ा। अंत में 7 जुलाई 2017 के आदेश के तहत अध्यापक संवर्ग को छठा वेतनमान दिया गया।

वेतन निर्धारण में हुई चूक : वर्ष 1998, 2001 और 2003 में लगभग सवा लाख शिक्षाकर्मी नियुक्त हुए थे। सरकार ने इन्हें 12 साल की अवधि पर क्रमोन्नत और पदोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया, लेकिन इनके वेतन निर्धारण की तारीख में चूक हो गई। मसलन 1998 में जो शिक्षाकर्मी बने थे, उन्हें 2010 की तारीख से पदोन्नत कर अध्यापक बनाया गया। साथ ही 2001 और 2003 वाले भी क्रमोन्नत कर दिए गए, पर अलग-अलग वर्षों में नियुक्तइन अध्यापकों को क्रमोन्नत वेतनमान की गणना 12 साल की अवधि पूरी करने के बाद से जाना थी, लेकिन सरकार ने सभी सेवा अवधि की गणना 1 अप्रैल 2007 की तारीख से मान ली और उसी आधार पर वेतनमान दे दिया। जबकि अध्यापकों की पदोन्नक्त क्रमशः 2010, 2013 और 2015 में हुई। यानी उन्हें तब 1 अप्रैल 2007 की तारीख से क्रमोन्नत मान लिया, जब उनका सिर्फ विलयन अध्यापक संवर्ग मे हुआ था। उस तारीख पर वे क्रमोन्नत नहीं हुए थे। क्रमोन्नति का वर्ष तो 2010, 2013 और 2015 है, क्रमोन्नत वेतनमान की गणना के लिए सेवा अवधि की गणना इन वर्ष से की जाना थी।

ऐसे समझें इस गलती को

जो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में 1998 में नियुक्त हुए वे 2010 में क्रमोन्नत होकर अध्यापक बने। 2001 और 2003 वाले वर्ग 3 के संविदा शिक्षक 2013 और 2015 में अध्यापक बने। इन तीनों की सेवा अवधि सरकार ने 1 अप्रैल 2007 मानकर अध्यापक के लिए वेतन निर्धारण कर दिया, जबकि उस तारीख में वे सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे थे।

▸ **मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी से शिक्षक बनाए गए तकरीबन सवा लाख लोगों के वेतनमान के निर्धारण में हुई गलती**

इस वेतन विसंगति का हम परीक्षण कराएंगे। वेतन निर्धारण में यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो ठीक करवाएंगे। जो भी ज्यादा भुगतान हुआ है, उसका समायोजन किया जाएगा।

- तरण भनोत, वित्त मंत्री, मप्र शासन

हिंदी पर थम नहीं रहा घमासान, कर्नाटक से केरल तक विरोध

▸ **हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपना आरएसएस का एजेंडा : येचुरी**

▸ **एक राष्ट्र और एक भाषा कभी हकीकत नहीं बन सकती : जयराम रमेश**

नई दिल्ली, एजेंसियां : हिंदी को घर-घर की भाषा बनाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद मचा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटक से लेकर केरल तक अमित शाह के बयान का विरोध जारी है। कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसे केंद्र सरकार का हिडेन एजेंडा बताया है।

माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि संघ की एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति की विचारधारा स्वीकार्य नहीं है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बेंगलुरु में कहा कि हिंदी को देश की आम भाषा बनाने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र और एक कर भले ही संभव हो सका है, लेकिन एक राष्ट्र और एक भाषा कभी हकीकत नहीं बन सकती।

तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि देश के सामने मौजूदा समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नियोजित तरीके से हिंदी भाषा को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने हिंदी को देश की भाषा बनाने की पैरवी को गैर हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ युद्ध घोष बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर संघ परिवार आंदोलन का एक और मंच तैयार कर रहा है।

वहीं, केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने गृहमंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि भाषा लोगों को प्रेरित और एकजुट करती है। हिंदी के जरिए देश की एकता भी मजबूत होगी। ज्ञात हो, नई शिक्षा नीति में भी सरकार ने हिंदी की अनिवार्यता की बात कही थी, लेकिन बाद में विरोध होने पर इससे कदम पीछे खींच लिए थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर 2019

दैनिक जागरण

प्रेम की शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है

हिंदी विरोध की आदत

हिंदी की महत्ता का उल्लेख करते ही किस तरह कुछ हिंदी विरोधी लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने में जुट जाते हैं, यह एक बार फिर तब स्पष्ट हुआ जब हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से व्यक्त किए गए इस विचार का विरोध शुरू हो गया कि हिंदी देश को जोड़ने का काम कर सकती है। उनके इस कथन में ऐसा कुछ भी नहीं कि उसका विरोध किया जाए या फिर यह मनमाना निष्कर्ष निकाला जाए कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। क्या यह यथार्थ नहीं कि यदि कोई भाषा देश की संपर्क भाषा बन सकती है तो वह हिंदी ही है? सच तो यह है कि वह संपर्क भाषा के रूप में काम भी कर रही है और प्रभावी भी सिद्ध हो रही है। गैर हिंदी भाषी राज्यों के जो नेता अमित शाह के कथन पर कोलाहल कर रहे हैं वे यह देख पाएं तो बेहतर कि उनके यहां भी हिंदी का चलन और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। उन्हें इस सत्य से भी परिचित होना चाहिए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पैरवी उनके अपने लोगों ने की थी। इसका कारण यही था कि वे हिंदी की सामर्थ्य से भली-भांति अवगत थे। बिना विचारे हिंदी विरोध की ध्वजा उठाने को तत्पर नेताओं को इसका भान होना चाहिए कि उनके आचरण से सभी भारतीय भाषाओं का अहित होता है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर उन लोगों को सक्रिय होने का अवसर मिल जाता है जो इस मिथ्या धारणा से ग्रस्त हैं कि ज्ञान की भाषा तो अंग्रेजी ही है। ध्यान रहे कि जापान, जर्मनी, इजरायल, चीन आदि इसके ही उदाहरण हैं कि अपनी भाषा में कहीं अच्छे से उन्नति की जा सकती है।

देश की सभी भाषाओं का विकास और विस्तार होना चाहिए, क्योंकि भाषा संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसी के साथ यह भी समझना होगा कि हिंदी का किसी से बैर नहीं और वह हर भाषा को साथ लेकर चलने की हामी है। वास्तव में इसी कारण हिंदी की उपयोगिता बढ़ी है। इस सबके बाद भी केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि एक लोकप्रिय संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अपनी पहचान बनाने में समर्थ है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर विज्ञान, तकनीक और अन्य अनेक विषयों की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? एक प्रश्न यह भी है कि न्यायपालिका और साथ ही सरकारी तंत्र के उच्च स्तर पर हिंदी का उपयोग क्यों नहीं हो हो पा रहा है? निश्चित रूप से इसका उत्तर हिंदी विरोध की संकीर्ण राजनीति में भी छिपा है।

बीएड माफिया पर सख्ती

आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जितने घोटाले बिहार में हुए हैं, उतने शायद ही किसी अन्य क्षेत्र में हुए हों। बिहार में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक भ्रष्टाचार शिष्टाचार सा बन गया था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की गड़बड़ियां तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बटोर चुकी हैं। स्कूल भवनों के निर्माण में पहले ठेकेदार और शिक्षा विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार करते थे, फिर प्रधानाध्यापक करने लगे। नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद, अयोग्य लोगों की नियुक्ति, मोटी तनख्वाह लेना और नहीं पढ़ाना, जाली सर्टिफिकेट बांटना, कदाचार को बढ़ावा देना जैसी बातें हर कोई जानता है। एक समय था जब किताबें, भत्ते, मध्याह्न भोजन की गड़बड़ियां आम बात थीं। हालांकि पिछले एक दशक में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की गंभीर कोशिशें हुई हैं। व्यवस्था बदली भी है। निगरानी सख्त हुई है। कुलाधिपति कार्यालय से लेकर पंचायतों तक को शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर रोक के लिए सक्रिय किया गया है। इसका असर भी हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। राजभवन की सक्रियता से विश्वविद्यालयों की व्यवस्था पटरी पर लौट रही, लेकिन शायद सब कुछ अभी ठीक होने में देर है। अब राज्य के निजी बीएड कॉलेजों में नियमों को ताक पर रख नामांकन में विश्वविद्यालयों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यालयों में नई पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करना है, वही इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते रहे हैं। बीएड नामांकन से परीक्षा तक की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन उसमें भी छेद हो गए हैं। अवैध नामांकन की भनक मिलने पर कुलपतियों की बैठक में नामांकित अभ्यर्थियों की जांच नालंदा खुला विश्वविद्यालय से कराने की सलाह कुलाधिपति ने दी थी। लेकिन इस पर अमल केवल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने ही किया। आरोप है कि 700 छात्रों का नामांकन गलत तरीके से लिया गया है। यह भी आरोप है कि एडमिशन फीस के अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन, फॉर्म और हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के नाम पर कॉलेज प्रबंधन ने अवैध वसूली की है। यह गंभीर विषय है। शिक्षक नियोजन के दौरान हजारों फर्जी प्रमाणपत्र के मामले सामने आए थे। फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति शिक्षक नहीं कहे जा सकते। ऐसे लोग बच्चों को सदाचार का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? यह सच है कि आज बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के नाम पर फर्जीवाड़ा की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती।

इसलिए जरूरी है समान नागरिक संहिता

हृदयनारायण दीक्षित

देश में एक ही विषय पर दो कानूनी विकल्पों का कोई औचित्य नहीं। एकताबद्ध राष्ट्र में 'निजी कानून' निरर्थक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है

'हम भारत के लोग' भारतीय राष्ट्र राज्य की मूल इकाई हैं। संविधान की उद्देशिका 'हम भारत के लोग' से ही प्रारंभ होती है। इसके अनुसार भारत के लोगों ने ही अपना संविधान गढ़ा है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक को समान मौलिक अधिकार दिए हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। राष्ट्र राज्य को भी अनेक कर्तव्य सौंपे गए हैं। वे संविधान के भाग-चार में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में वर्णित हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। इनमें व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा को ही सूचीबद्ध किया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने ठीक लिखा है कि 'राज्य की सकारात्मक बाध्यताओं की रचना करके संविधान सभा ने भारत की भावी सरकारों को उत्तरदायित्व सौंपे हैं।' कुछ निदेशक तत्वों पर सकारात्मक काम हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए अपरिहार्य 'एक समान नागरिक संहिता' (अनुच्छेद 44) के प्रवर्तन में कोई प्रगति नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायपीठ ने तीखी टिप्पणी की है कि 'समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ है।' न्यायालय ने इसके पहले 2003, 1995 और 1985 में भी संहिता पर जोर दिया था।

संविधान और विधि के प्रति निष्ठा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। समान नागरिक संहिता संविधान का भाग है। संविधान का आदर्श भी है। बावजूद इसके सांप्रदायिक कारण से इसका प्रवर्तन राष्ट्र की मुख्य चुनौती है। सर्वोच्च न्यायालय ने चौथी बार ध्यानाकर्षण किया है। उसने गोवा की प्रशंसा की है। गोवा में पंथिक विश्वास के परे समान नागरिक संहिता है। बेशक निदेशक तत्वों के प्रवर्तन में न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, लेकिन जीवन स्तर उन्नत करने संबंधी निदेशक तत्व (अनुच्छेद 47) पर अच्छा काम हुआ है। मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर आशातीत प्रगति की है। कुटीर उद्योगों के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43) पर बड़ा काम हुआ है। ग्राम पंचायतें भी इसी सूची (अनुच्छेद 40) में हैं। इसे लेकर तमाम अधिनियम बने हैं। संविधान में संशोधन भी हुआ है। गरीबों में भूमि वितरण (अनुच्छेद 39ख) पर भी बात आगे बढ़ी है। अन्य निदेशक तत्वों पर भी प्रगति हुई है, लेकिन 'समान नागरिक संहिता' दूर की कौड़ी है। मूलभूत प्रश्न है कि आखिरकार एक राष्ट्र, एक विधि और एक समान नागरिक संहिता का स्वाभाविक सिद्धांत लागू क्यों नहीं हो सकता?

समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे। संविधान सभा में इस पर जोरदार बहस हुई थी। संप्रदाय विशेष के सदस्य संहिता को अपने निजी मजहबी कानूनों में हस्तक्षेप मानते थे। वैसे संहिता का प्रवर्तन कोई हस्तक्षेप नहीं था। कानून निजी नहीं होते। दुनिया के सारे कानून राज और समाज की संवैधानिक संस्थाओं से जन्म लेते हैं और उन्हीं पर लागू होते हैं, लेकिन सभा के कुछ सदस्य राष्ट्रीय विधि के निर्माण में निजी कानूनों को ऊपर बता रहे थे। एक सदस्य मोहम्मद इस्माइल ने कहा, 'यह उचित नहीं कि लोगों को उनके निजी कानून छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए।' महबूब अली ने कहा कि 'साढ़े तेरह सौ साल से मुसलमान इसी कानून पर चलते रहे हैं। हम अन्य प्रणाली मानने से इन्कार कर देंगे।' बी पोकर ने कहा कि 'अंग्रेजों ने निजी कानूनों को मानने की अनुमति दी थी।' इस बात को काटते हुए अल्लादि स्वामी अय्यर ने कहा 'अंग्रेजों ने पूरे देश में एक ही आपराधिक कानून लागू किया। क्या उसे लेकर मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया?'

पंथिक विश्वास नितांत निजी आस्था है, लेकिन संविधान सभा में पंथिक विश्वास को निजी कानून की शक्ल में पेश किया गया। कहा गया कि 'समान नागरिक संहिता अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अन्याय है। केएम मुंशी ने कहा कि किसी भी उन्नत देश में अल्पसंख्यक समुदाय के निजी कानून को अटल नहीं माना गया कि व्यवहार संहिता बनाने का निषेध हो।' उन्होंने तुर्की और मिस्र के उदाहरण दिए कि 'इन देशों में अल्पसंख्यकों को ऐसे अधिकार नहीं मिले। हमारी महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकता है। हम वास्तव में एक राष्ट्र हैं। मुस्लिम मित्र समझ लें कि जितना जल्दी हम अलगाववादी भावना को भूलते हैं, उतना ही देश के लिए अच्छा होगा।' डॉ. आंबेडकर ने कहा, 'मैं इस कथन को चुनौती देता हूं कि मुसलमानों का निजी कानून, सारे भारत में अटल तथा एकविधि था। 1935 तक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में शरीयत कानून लागू नहीं था। उत्तराधिकार तथा अन्य विषयों में वहां हिंदू कानून मान्य थे। उसके अलावा 1937 तक संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बंबई जैसे अन्य प्रांतों में उत्तराधिकार के विषय में काफी हद तक मुसलमानों पर हिंदू कानून लागू था। मैं असंख्य उदाहरण दे सकता हूं। इस देश में लगभग एक ही व्यवहार संहिता है, एकविधि है। इस अनुच्छेद को विधान का भाग बनाने की इच्छा सुधार की है। यह पूछने का समय बीत चुका है कि क्या हम ऐसा कर सकते है?' इसके बाद मतदान हुआ। संहिता का प्रस्ताव जीत गया। संहिता संविधान का हिस्सा बनी।

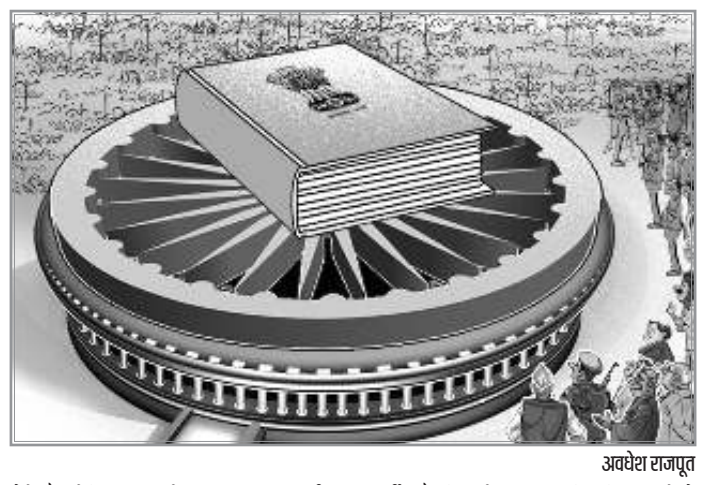

अवधेश राजपूत

समूचा भारत समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। आंबेडकर के अलावा डॉ. राममनोहर लोहिया भी इसके समर्थक थे। पर्सनल लॉ की बातें कालवाह्य हो रही हैं। समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए ही 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया था। बोर्ड राष्ट्र सर्वोपरिता में विश्वास नहीं करता। वह विधि सर्वोच्चता का सिद्धांत भी नहीं मानता। इसका विश्वास 'पर्सनल लॉ' में है, लेकिन बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण इसका प्रभाव नगण्य हो चुका है। कुछेक दल वोट लोभ में संहिता के विरोधी हैं। वे चर्चित शाहबानो मामले में अदालती फैसले के खिलाफ थे। तब उस फैसले को निष्प्रभावी बनाने वाला कानून बना। ऐसे दल राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की तुलना में थोक वोट बैंक को ज्यादा तरजीह देते हैं। वे एक देश में दो तरह के कानूनों के पक्षधर हैं।

भारत बदल रहा है। तीन तलाक पर कानून बन गया है। अनुच्छेद 370 अब अतीत बन चुका है। राष्ट्र सर्वोपरि अस्मिता है। संविधान भारत का राजधर्म है और भारतीय संस्कृति भारत का राष्ट्रधर्म। प्रत्येक भारतवासी संविधान और विधि के प्रति निष्ठावान हैं। अपने विश्वास और उपासना में रमते हुए संविधान का पालन साझा जिम्मेदारी है। एक देश में एक ही विषय पर दो कानूनी विकल्पों का कोई औचित्य नहीं। आखिरकार एकताबद्ध राष्ट्र में 'निजी कानून' का मतलब क्या है। संप्रति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आशा और उमंग का माहौल है। राष्ट्रवादी संगठन पहले से ही भारत में ऐसी संहिता के पक्षधर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ध्यानाकर्षण से संहिता पर फिर से विमर्श का अवसर आया है। दलतंत्र राष्ट्रीय अभिलाषा पर ध्यान दें। निजी कानून के आग्रही मित्र देश और काल का आह्वान सुनें। संविधान निर्माताओं की इच्छा का सम्मान करें।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

जीरो बजट खेती के अंदेशे

एनके सिंह

जीरो बजट खेती को लेकर उठी आशंकाओं को दूर किए बिना इसे अपनाना सही नही होगा। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए

अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और फिर बीते सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-प्रतिरोधी कन्वेंशन' में शामिल देशों के 14वें सम्मेलन में भारत की 'जीरो बजट' खेती की योजना का संकल्प दोहराया, लेकिन देश के दर्जनों कृषि वैज्ञानिकों इससे उत्साहित नहीं हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पंजाब सिंह के नेतृत्व में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद एवं भारतीय कृषि शोध परिषद (आइसीएआर) महानिदेशक तिरलोचन महापात्र की मौजूदगी में एक गोष्ठी में न केवल इस विचार को खारिज किया गया, बल्कि इस पर अमल से अनाज उत्पादन और उत्पादकता के भारी नुकसान की चेतावनी भी दी है। 'वापस मूल की ओर' के सिद्धांत के तहत जीरो बजट खेती की योजना इस वर्ष के आम बजट में घोषित की गई, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस खेती में जो पद्धति अपनाने की योजना है उसके बारे में न तो कोई प्रामाणिक आंकड़ा है, न ही उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसा गया है। दरअसल इसके पीछे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का दबाव है। यह योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नाइट्रोजन, कार्बन डाईऑक्साइड, धूप और पानी प्रकृति मुफ्त में देती है। केवल उसे हासिल करने का तरीका मालूम होना चाहिए। शेष दो प्रतिशत पोषण जीवाणु को जड़ों के भीतर सक्रिय करने से मिल सकता है, जो गाय के मूत्र, गोबर, गुड़ और दाल आदि के घोल के छिड़काव से मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन जरूर है, पर यह मुफ्त में उपलब्ध नहीं है। पौधे उसे लेकर एमिनो एसिड में बदल कर अपने लिए तब तक भोजन नहीं बना सकते हैं, जब तक उन्हें अमोनिया या यूरिया का सहारा न दिया जाए, यानी रासायनिक खाद न मिले।

भारत में जीरो बजट खेती की अवधारणा का जनक महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर को माना जाता है। उनके अनुसार जीरो बजट खेती के सफल होने की एक और शर्त यह है कि इसमें प्रयुक्त होने वाला गोबर और मूत्र केवल काली कपिला गाय का होना चाहिए। क्या देश में खेती की नीति काली कपिला गाय के गोबर और मूत्र के आधार पर बनाना और उसे पूरी दुनिया को बताना भरतीय नेतृत्व की तर्क-क्षमता और वैज्ञानिक सोच पर प्रश्न-चिन्ह नहीं खड़ा करेगा? देश में विरले नेता हुए हैं, जिनका दिमाग इतना जरखेज (उपजाऊ) रहा है जितना

मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन योजनाओं को वैज्ञानिक और व्यावहारिक पुष्टि के बिना घोषित करना नुकसान पहुंचा सकता है। मोदी सरकार का पहला पांच साल का कार्यकाल हो या दूसरे कार्यकाल के पिछले सौ से अधिक दिन, कुल गणना करें तो हर हफ्ते एक योजना, या विचार-संदेश देश को अपने सबसे मकबूल नेता से मिलता रहा है। एक देश, जिसमें नए-नए विचार न हों, वह धीरे-धीरे जड़वत होता जाता है। लिहाजा इस समाज को हर रोज चैतन्य रखना मोदी सरकार की अच्छी उपलब्धि है, लेकिन ऐसी चैतन्यता का भाव वास्तव में जीवन गुणवत्ता में कितना बदलाव लाता है, इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करने का समय आ गया है।

मोदी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में कृषि को लेकर एक नया भाव पैदा हुआ है जो शायद 'वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और बार-बार दोहराने' के दबाव के कारण है। शायद मोदी सरकार को यह मालूम है कि किसानों की आय कम रहने का सबसे बड़ा कारण उत्पादकता न बढ़ना है। भारत में जहां अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जमीन की उत्पादकता लगातार घटती जा रही है। इसके मूल में खेती की जमीन पर जनसंख्या का दबाव, किसानों का रासायनिक खादों तथा जल का अविवेकपूर्ण उपयोग और बाजार की सुविधा का अभाव है। लिहाजा सरकार अब 200-400 साल पुरानी खेती यानी देसी बीज, देसी खाद और देसी बाजार आधारित परंपरागत खेती की ओर उन्मुख होने का इरादा बना रही है। इसके संकेत सरकार द्वारा जुलाई में जारी आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने से और प्रधानमंत्री मोदी के हाल के तमाम भाषणों से मिलता है। सर्वेक्षण के कृषि अध्याय (पेज 172) का प्रारंभ वेस जैक्सन के इस कथन से होता है कि प्रकृति में सर्वाधिक संधारणीय (सस्टेनेबल) पारिस्थितिकी विद्यमान है। और चूंकि अंततोगत्वा कृषि प्रकृति से ही जन्म लेती है, अतः एक धारणीय पृथ्वी के लिए हमारा मानक स्वयं प्रकृति की पारिस्थितिकी ही होनी चाहिए। स्वयं इस सर्वेक्षण में भी यह पाया गया है कि रासायनिक खाद के दुरुपयोग के कारण अब खेतों को दीर्घकालिक नुकसान हो रहा है। साथ ही अगले ग्राफ में बताया गया है कि सिंचाई के पानी का भी अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तमाम राज्य कर रहे हैं। ऐसे में बेहतर तो यह होता कि सरकार 'स्वच्छ भारत', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'प्लास्टिक मुक्त भारत' की तरह ही रासायनिक खाद खासकर नाइट्रोजन वाले खाद के खिलाफ 'वैज्ञानिक खेती' का नारा देती तो एक बेहतर परिणाम मिल सकता था। धान और गन्ना उत्पादन के लिए इजरायली तकनीकी का प्रयोग करना सार्थक प्रयास था, जो देश में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का 60 प्रतिशत खपत करते हैं। गन्ने की खेती के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र पानी का भयंकर दोहन कर रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक रूप से बदलाव लाया जाना चाहिए। ऐसी खेती के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जहां सिंचाई के लिए जल उपलब्धता सबसे अच्छी है। इससे किसानों की आय बढ़ाने का कारगर उपाय हो सकता है।

जीरो बजट खेती के प्रति ऐसी शंका व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक न तो वामपंथी विचारधारा वाले हैं और न ही 'देश-विरोधी', बल्कि इनमें से कई मोदी काल में ही कृषि विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। पंजाब सिंह वाजपेयी काल में सरकार की सबसे बड़ी संस्था भारतीय कृषि शोध परिषद के महानिदेशक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। सरकार को व्यापक चर्चा के बाद ही देश में 'जीरो बजट' खेती को जमीन पर लाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके प्रवर्तन से पहले सभी पहलुओं पर गौर करना होगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विचार-औषधि

मानव मस्तिष्क एक पवित्र देवालय की तरह है तथा विचार उसमें प्रतिस्थापित देव-मूर्तियों की तरह। विचारों की श्रेष्ठता ही मानव हृदय में आनंद एवं विषाद अथवा सुख-दुख को जन्म देती है। असली आनंद की अनुभूति वही कर सकता है, जिसका मस्तिष्क सदैव अच्छे विचारों से भरा रहता है। हृदय के तालाब में आनंद एवं खुशी की पवित्र लहरें तभी उठ सकती हैं, जब श्रेष्ठ विचारों के कैलोरीनुमा रसायन से समय-समय पर उसकी सफाई की जाए। यह कैलोरीनुमा रसायन महापुरुषों के सत्संग, प्रभु नाम-स्मरण तथा भगवत-चर्चा से ही प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क एक नव-निर्मित आलीशान हवेली की तरह है, जिसे विचार के स्वच्छ झाड़ू से नित्यप्रति बुहारने की आवश्यकता है। जब तक आलीशान भवन को वैचारिक गंदगी जकड़े रहेगी, तब तक खुशी, आनंद एवं प्रसन्नता के परिवेश का वहां चाहकर भी निर्माण संभव नहीं है। एक छोटे से कुविचार का कण हमारे मस्तिष्करूपी तालाब के संपूर्ण पवित्र विचाररूपी जल को प्रदूषित कर डालता है। यदि हमारे मस्तिष्क में श्रेष्ठ विचारों की दृढ़ता का कवच हो तो ऐसे क्षुद्र विचार वहां प्रवेश करने का साहस भी नहीं जुटा सकते। श्रेष्ठ विचार मस्तिष्क के आनंद भवन को चिर-प्रसन्न रखने की रामबाण औषधि है।

अवसाद के क्षणों में महापुरुषों का एक श्रेष्ठ विचार हमें न केवल उस पीड़ा से उबार सकता है, बल्कि हममें उत्साह एवं नव चेतना भर कर हमारे मन को खुशियों से प्रफुल्लित भी कर देता है। श्रेष्ठ विचार एवं उससे उत्पन्न रचनात्मक सोच ऐसी संजीवनीयुक्त औषधि है, जिसके आगमन मात्र से जीवन से दुख, भय, संताप एवं विषाद के घने बादल पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि दुख एवं आनंद ईश्वर के दिए वरदान या अभिशाप नहीं, बल्कि हमारे श्रेष्ठ एवं निकृष्ट विचारों का प्रतिफल मात्र हैं। मानसिक शक्तियों का विकास तथा जीवन-दुखों से मुक्ति केवल प्रभुकृपा, सकारात्मक सोच एवं श्रेष्ठ विचारों से ही संभव है। अतः अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें तथा सुखद भविष्य की नींव रखें।

डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल

अमृत कुमार

भारत को ज्ञान-विज्ञान और शोध का केंद्र बनाना है तो सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता देनी होगी

टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) की ओर से जारी दुनिया के 300 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी को जगह नहीं मिलना भारत की उच्च शिक्षा की बदहाल तस्वीर पेश करती है। 2012 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले साल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु ने टॉप 300 की सूची में जगह बनाई थी, पर इस बार वह इससे बाहर है। इस सूची में इंग्लैंड स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है तो वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दूसरा स्थान मिला है। इंग्लैंड का ही कैंब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गया है। इस सूची में चीन के दो विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। इनमें सिंघुआ यूनिवर्सिटी को 23वीं रैंकिंग मिली है तो वहीं पीकिंग विश्वविद्यालय को 24वीं रैंकिंग मिली है।

इस सूची को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोध का माहौल, रिसर्च पेपर्स का वैश्विक स्तर पर उद्धृत किया जाना, पढ़ाई का माहौल और उसकी गुणवत्ता, पेटेंट आदि से औद्योगिक आय जैसे पैमानों पर ध्यान दिया गया है। इससे साफ है कि हमारे विश्वविद्यालयों में मौलिकता और सृजनशीलता जैसी जरूरी चीज पर कम ध्यान दिया जा रहा है। तथा हमारा सामाजिक माहौल भी अभी मौलिक शोध करने के पक्ष में नहीं है।

इस सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा करने वाले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आर्थिक प्रगति को वहां की उच्च शिक्षा से जोड़कर देखा-समझा जा सकता है। इन देशों में शोध एवं अनुसंधान पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत भारत में शोध एवं अध्ययन की गुणवत्ता किसी प्रकार से डिग्री हासिल करने तक ही सीमित है। आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों में केवल भारत ही ऐसा देश है, जहां शोध पर कुल जीडीपी का मात्र 0.9 फीसद खर्च किया जाता है। दूसरी ओर चीन में यह 1.9 फीसद, रूस में 1.5 फीसद, ब्राजील में 1.3 फीसद तथा दक्षिणी अफ्रीका में एक फीसद खर्च होता है। सरकार को समझना होगा कि देश में बड़ी संख्या में अच्छे संस्थान और विश्वविद्यालय होंगे तभी नई पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हम दे पाएंगे और उन्हें बाजार की मांग के मुताबिक बना पाएंगे।

हालांकि पिछले कुछ समय में देश में उच्च शिक्षा के कई नए संस्थान खुले हैं। निजी शिक्षा संस्थाओं में भी वृद्धि हुई है। कई नए कार्यक्रम विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी के साथ शुरू हुए हैं। विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की दरकार है। दुनिया के महानतम शिक्षण संस्थान अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र में खास स्थान इसलिए बना पाए हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता मिली है। वे अपने फैसले खुद लेते हैं और अपने खर्चे के लिए सरकार पर आश्रित नहीं रहते हैं। भारत को भी ज्ञान का केंद्र बनाना है तो उच्च शिक्षा संस्थानों को ऐसी छूट देनी होगी। सरकार को उच्च शिक्षा का ढांचा शिक्षाविदों को ही गढ़ने देना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कैसे टूटे सुस्ती का चक्र

आर्थिक सुस्ती दूर करने की चुनौती शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने आर्थिक सुस्ती पर कांग्रेस को ओछी राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। कांग्रेस ने देश पर लंबे समय तक राज किया है, अगर इसने शुरू से ही देश में आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज देश में आर्थिक भ्रष्टाचार की बीमारी न फैली होती और न ही मोदी सरकार को आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए नोटबंदी का कठोर फैसला लेना पड़ता और न ही नोटबंदी आज आर्थिक सुस्ती का कारण बनती। खैर बीता समय वापस तो नहीं आ सकता। लेखक ने यह तो ठीक कहा है कि कांग्रेस को आर्थिक सुस्ती के लिए मोदी सरकार को घेरने के लिए धरना-प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी सलाह देनी चाहिए, जिससे इस पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मंदी से पार पाने के लिए जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, गांवों में खपत बढ़ाने, कृषि में और सुधार लाने, पूंजी निर्माण में तेजी लाने, नौकरी बढ़ाने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने और अमेरिका-चीन में चल रहे ट्रेड वॉर में नए निर्यात बाजारों को तलाशने की जो सलाह दी है उस पर मोदी सरकार कितना अमल कर रही है? यदि सरकार इन सलाहों पर अमल करे तो देश में आर्थिक सुस्ती के चक्र को तोड़ा जा सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

प्लास्टिक एक गंभीर समस्या

प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। सुबह जिस अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर उठते हैं उसका निर्माण इसी से होता है। मोबाइल फोन का बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का बना होता है। बाथरूम का ज्यादातर सामान भी इसी का होता है। घर में खाने पीने के सामान प्लास्टिक कंटेनर में रखे होते हैं। कंप्यूटर के ज्यादातर पार्ट इसी के बने होते हैं। कार की एसेसरी भी प्लास्टिक की मिलेगी। ये सभी चीजें जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन इसका जरा सा हिस्सा भी शरीर में चला जाए तो बीमार बना देगा। प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनरो में नमक आदि रखा जाता है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकता है। प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। समुद्र भी इसके प्रकोप से नहीं बचा है। दुनिया भर के महासागरों में इसके बड़े-बड़े ढेर बन चुके हैं। भारत में प्लास्टिक से लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इसका असर बहुत कम देखने को मिला है। भारत के 14 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं रुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित कॉप-14 सम्मेलन में कहा कि प्लास्टिक की वजह से हो रहे मरुस्थलीकरण को अगर नहीं रोका गया तो भूक्षरण का नया स्वरूप सामने आएगा। देश के एक जागरूक नागरिक होने के कारण हमको खुद इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा कि जल्द से जल्द प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग त्याग दें और ज्यादा से ज्यादा कागज और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें।

satyamrai276304@gmail.com

दिल्ली में ऑड-इवेन

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक बार फिर से ऑड - इवेन लागू करने जा रही है। ऑड-इवेन नंबर की गाड़ियों के लिए अलग दिन होने से कारें सड़कों पर आधी रह जाती हैं। लोग सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण कम हो जाता है। इससे हार्ट के रोगियों को काफी फायदा होता है। आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। यह फॉर्मूला काफी प्रभावी रहेगा।

kunalpratapsingh94@gmail.com

किसानों को पेंशन

वर्तमान सरकार ने किसानों को आर्थिक एवं सामा

0.6 प्रतिशत ही रही देश में विनिर्माण की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह वृद्धि दर 12.1 फीसद थी।

आजकल

आर्थिक माहौल को बदलने में जुटी सरकार

राहुल लाल
आर्थिक मामलों के जानकार

भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है। उद्योगों के बहुत से सेक्टर में विकास दर बीते कई वर्षों के मुकाबले निचले स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 2016-17 में जीडीपी विकास दर 8.2 प्रतिशत थी, जो 2017-18 में घटकर 7.2 प्रतिशत रह गई और 2018-19 में जीडीपी की विकास दर 6.8 प्रतिशत रह गई। हालांकि देश के आठ कोर यानी मुख्य उद्योगों का उत्पादन जुलाई में 2.1 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पिछले साल जुलाई में इन उद्योगों ने 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की थी। ये आठ उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट व बिजली। जून में इन मुख्य उद्योगों की वृद्धि दर महज 0.2 फीसद रही थी जिससे आर्थिक मोर्चे पर चिंता बढ़ गई थी

ताजा अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी वृद्धि दर पांच प्रतिशत रह गई है। विकास दर का यह स्तर छह साल में न्यूनतम है। ज्ञात हो कि जीडीपी विकास दर पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 5.8 फीसद थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विनिर्माण की वृद्धि दर मात्र 0.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में यह 12.1 प्रतिशत थी। जीडीपी की विकास दर घटने से लोगों की आमदनी, खपत और निवेश, सब पर असर पड़ रहा है। जिन सेक्टरों पर इस मंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वहां पर नौकरियां घटाने के ऐलान हो रहे हैं।

एक दौर में प्रभावशाली निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज आज बंद हो चुकी है। एयर इंडिया काफी घाटे में चल रही है। बीएसएनएल आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने हाल में बाजार से एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर कर्मचारियों को वेतन दिया। भारतीय डाक सेवा का वार्षिक घाटा 15 हजार करोड़ हो चुका है। देश की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी ओएनजीसी का अतिरिक्त कैश रिजर्व घट रहा है। सरकार द्वारा गैर जरूरी अधिग्रहण के चलते आज यह कंपनी एक बड़े कर्ज के दबाव में आ गई है।

खपत में गिरावट : विकास दर घटने से लोगों की आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है। बाजार की एक बड़ी शोधकर्ता कंपनी की रिपोर्ट कहती है कि तेजी से खपत वाले सामान एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री की विकास दर इस साल जनवरी से मार्च के बीच 9.9 प्रतिशत थी, लेकिन इसी साल अप्रैल से जून की तिमाही में ये घटकर 6.2 फीसदी रह गई। एफएमसीजी के उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि लोग अब अनिवार्य आवश्यकताओं में भी कटौती कर रहे हैं।

ग्राहकों की खरीदारी के उत्साह में कमी का बड़ा असर ऑटो उद्योग पर पड़ा है। इस सेक्टर में बिक्री घटी है और नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी की जुलाई में पिछले साल के मुकाबले कारों की बिक्री में 36 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस कारण टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों को गाड़ियों के निर्माण में कटौती करनी पड़ी है। नतीजन कल-पुर्जे और दूसरे तरीके से ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए लोगों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। उदाहरण के लिए जमशेदपुर का टाटा मोटर्स का प्लांट दो माह से 30 दिनों में केवल 15 दिन ही चलाया जा रहा है। इससे जमशेदपुर और आस-पास के इलाकों में 1,100 से ज्यादा कंपनियां बंदी के कगार पर खड़ी हैं, जो टाटा मोटर्स को कई चीजों की सप्लाई कर रही थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी करीब 50 फीसद है।

निर्यात में लगातार गिरावट : आमतौर पर जब घरेलू बाजार में खपत कम हो जाती है तो भारतीय उद्योगपति अपना सामान निर्यात करते हैं और विदेश में बाजार तलाशते हैं। अभी स्थिति यह है कि विदेशी बाजार में भी भारतीय सामान के खरीदार का विकल्प बहुत सीमित है। पिछले दो सालों से जीडीपी विकास दर में निर्यात का योगदान घट रहा है। मई माह में निर्यात की विकास दर 3.9 प्रतिशत थी, लेकिन इस साल जून में निर्यात में 9.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। ये 41 महीनों में सबसे कम निर्यात दर है। चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर का विस्तार भारत के साथ भी हो रहा है। ऐसे में निर्यात वृद्धि के लिए विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए चीन में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ने से एक रिक्तता पैदा हुई है, ऐसे में भारत लगभग 57 प्रकार के उत्पादों को चीन में बेच सकता है, जो चीन के साथ हमारे एकपक्षीय व्यापार में संतुलन बना सकता है। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह ट्रेड वॉर के संकट को वियतनाम और बांग्लादेश ने अपने लिए अवसर में बदला। जब चीन ने टेक्सटाइल सेक्टर को छोड़कर अधिक मूल्य वाले उत्पादों पर जोर दिया तो उस जगह को भरने के लिए बांग्लादेश और वियतनाम तेजी से आए, वहीं भारतीय टेक्सटाइल इसका लाभ नहीं उठा सका। इसी तरह वियतनाम ने ट्रेड वॉर का लाभ 'मोबाइल निर्माण' क्षेत्र में भी लिया। दुनिया भर में स्मार्टफोन का कारोबार 300 बिलियन डॉलर का है। इसका 60 प्रतिशत हिस्सा चीन के पास है। ट्रेड वॉर के बाद चीन के मोबाइल विनिर्माता कम जोखिम वाले क्षेत्र की तलाश में थे। वियतनाम ने इसके लिए पूर्व तैयारी की थी। अंततः अब स्मार्टफोन के ग्लोबल निर्यात में वियतनाम की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो गई है, जबकि भारत की हिस्सेदारी नगण्य है।

बचत में गिरावट : अर्थव्यवस्था का विकास धीमा होने का रीयल इस्टेट सेक्टर पर भी बुरा असर पड़ा है। एक आकलन के अनुसार इस वक्त देश के 30 बड़े शहरों में 12.76 लाख मकान बिकने को पड़े हुए हैं। कोच्चि में मकानों की उपलब्धता 80 महीनों के उच्चतम स्तर पर है, जयपुर में 59 महीनों, लखनऊ में 55 महीनों और चेन्नई में ये 75 महीनों के अधिकतम स्तर पर है। इसका ये मतलब है कि इन शहरों में जो मकान बिकने को तैयार हैं, उनके बिकने में पांच-छह वर्ष लग रहे हैं। आमदनी बढ़ नहीं रही है और बचत की रकम बिना बिके मकानों में फंसी हुई है। वित्त वर्ष 2011-12 में घरेलू बचत, जीडीपी का 34.6 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह बचत दर जीडीपी के अनुपात में घटकर 30 प्रतिशत पर आ गई है, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे कम है। घरेलू बचत की जो रकम बैंकों के पास जमा होती है, उसे ही बैंक कारोबारियों को कर्ज के तौर पर देते हैं। जब भी बचत में गिरावट आती है, बैंकों के कर्ज देने में भी कमी आती है। जबकि कंपनियों के विकास और नए रोजगार के लिए कर्ज का अहम रोल है। बैंकों के कर्ज देने की विकास दर भी घट गई है। इस वर्ष अप्रैल में कर्ज देने की विकास दर 13 प्रतिशत थी, जो मई में गिरकर 12.5 फीसद ही रह गई।

विदेशी निवेश प्रभावित : अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल हों, तो इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। अप्रैल 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 7.3 अरब डॉलर था, लेकिन मई माह में यह घटकर 5.1 अरब डॉलर ही रह गया। रिजर्व बैंक ने जो अंतरिम आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक देश में आ रहा कुल विदेशी निवेश, जो शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में निवेश किया जाता है, वह अप्रैल में तीन अरब डॉलर था। लेकिन मई में यह घटकर 2.8 अरब डॉलर ही रह गया था।

हालांकि विगत माह भारत में सऊदी अरब की कंपनी 'अरैमको' ने 15 अरब डॉलर के निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह कंपनी आरआइएल की ऑइल-टू-केमिकल का 20 प्रतिशत शेयर खरीदेगी। इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश बताया जा रहा है। इससे पहले एस्सार की तेल व गैस कंपनी में रूस की रॉसनेफ्ट कंपनी ने 12 अरब डॉलर का निवेश किया था। एक तरह से इस डील को प्रमुख तेल उत्पादक सऊदी अरब और प्रमुख तेल उपभोक्ता भारत के विशिष्ट डील के रूप में देखा जा रहा है। यह मंदी के बीच एक खुशखबरी है।

कृषि विकास दर की चुनौती : पिछले पांच वर्षों में औसत कृषि विकास दर 2.7 प्रतिशत रही। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। इसके लिए नीति आयोग के तत्वावधान में अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया, जिसने कृषि आय दर को दोगुना करने के लिए कृषि विकास दर को 12 प्रतिशत तक पहुंचाने की सिफारिश की। परंतु कृषि विकास दर 12 प्रतिशत के स्थान पर ताजा तिमाही आंकड़ों में केवल दो प्रतिशत है। मालूम हो कि कृषि क्षेत्र देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में घरेलू मांग पैदा करने के लिए इस सेक्टर का विकास अहम है।

उपायों की घोषणा से बढ़ी तेजी की उम्मीद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को आर्थिक मंदी के बीच अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए '32 सूत्रीय' उपायों की घोषणा की थी। इसमें सर्वप्रथम कदम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआइ) और घरेलू इक्विटी इन्वेस्टर्स पर बढ़ाए गए 'सुपर रिच सरचार्ज' को वापस लेना था। माना जा रहा था कि पांच जुलाई को घोषित बजट में सुपररिच सरचार्ज को लगाने से अधिकतम 1,400 करोड़ की आमदनी होती, परंतु सरकार के इस निर्णय से भारत से करीब 25 हजार करोड़ रुपये निवेश की राशि दूसरे देशों की तरफ चली गई, जबकि इस अफरातफरी में मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार ने इस क्षेत्र में बजट के प्रमुख भूल में सुधार कर लिया, अन्यथा इससे और भी अधिक नुकसान हो सकता था।

इसके अतिरिक्त सरकार ने बैंक लोन और रेपो रेट को जोड़ने की भी घोषणा की। पिछले दिसंबर से अब तक रेपो रेट में चार बार कटौती की गई है, लेकिन स्वयं आरबीआइ का कहना है कि यह कटौती उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे में यह घोषणा भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सबसे अहम घोषणा यह थी जिसमें कहा गया कि पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) का लंबित वस्तु एवं सेवा कर बकाया 30 दिन की तय अवधि में निपटाया जाएगा। सरकार ने वाहन उद्योग को राहत देने के लिए उच्च पंजीयन शुल्क को टाल दिया गया है तथा गाड़ियों के सरकारी खरीद पर रोक अब हटा दी गई है। इसके साथ ही सरकार अब नई पॉलिसी लाने वाली है, ताकि गाड़ियों की मांग को बढ़ाया जा सके।

इस बीच शनिवार को वित्त मंत्री ने निर्यात और हाउसिंग सेक्टर के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का बड़ा पैकेज घोषित किया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष पहली जनवरी से एक नई स्कीम- रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑर टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट (आरओडीटीईपी) शुरू करने और दुनिया भर में विख्यात दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर देश में चार 'मेगा शॉपिंग फेस्टिवल' आयोजित करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हाउसिंग क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का नया फंड बनाने का निर्णय लिया है, जिसका प्रयोग अधूरे फ्लैट्स को शीघ्र पूरा करने के लिए किया जाएगा। इससे लगभग 3.5 लाख फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार के ये उपाय दर्शाते हैं कि अब सरकार संकट को नकारने के दौर से बाहर आ चुकी है और यह मान रही है कि अर्थव्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस स्थिति में कई बिजनेस कंपनियां नौकरी जाने का भय दिखाकर बड़ी रियायतें वसूलने में लगी हैं, ऐसे में सरकार कंपनियों को राहत देने के स्थान पर स्वयं बाजार में मांग उत्पन्न करने का प्रयास करे। इसके लिए कृषि क्षेत्र में किसानों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम काफी अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग पैदा होगी। इसी तरह आधारभूत संरचना और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के व्यय में वृद्धि करने से भी लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

खरी-खरी

हांफता राहगीर, बढ़ता चालान

समीक्षा तैलंग

वो राहगीर था। गिर-गिरकर चलना ही उसकी नियति हो गई थी। बस, समय के साथ उसके गिरने का कॉन्सेप्ट बदलता गया। पहले वह पैदल चलते-चलते गिरता था, क्योंकि स्कूटर, टेंपो की गति और उसके चलने की गति में कछुआ-खरगोश का अंतर था। उनकी गति के बीच में उस पैदल का आना, मतलब व्यवधान। इसलिए उसके पैरों को कुचलकर, चालक आगे बढ़ते हुए अपनी शौर्य गाथा का बखान करते। वे उसके गिर-पड़ने पर भी वहां न रुककर, ट्रैफिक हवलदार की सीटी और हाथों के इशारों पर रुक जाते।

राहगीर जब बच्चा था, तब उसने स्कूली किताबों में यातायात के नियम पढ़े। उसके दिमाग में नियम फिट न बैठते। तब भी उसने नंबरों की खातिर नियमों को घोट लिया। मगर जब वह बड़ा हुआ और उसका सामना असली सड़क से हुआ, तो उसे न तो फुटपाथ दिखे, न ही जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग से जेब्रा घोड़े की तरह गाड़ियां दौड़ाते 'गधे' जरूर दिखे। बेचारा वो, असली व किताबी सड़क के नियमों के बीच हादसे का शिकार हो गया।

राहगीर अब चलते-चलते वर्तमान में पहुंच चुका है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या ने अपने 'फुट' पर चलने वाले उस बेचारे को फुटबॉल बना दिया है। हर वाहन चालक मानो मैसी है, पैदल वाले बेचारे की ऐसी-तैसी है। न फुटपाथिए दुकानदारों का चालान कटता है, न यमराजों का। इनकी कमाई हवलदार की जेब का आधार-कार्ड है।

हर चौराहे पर ऊपर लटकती आंखें अधकचरी अंधी हैं। वे रिकॉर्ड सब करती हैं, बोलती कुछ नहीं। वो शिवजी की आंख नहीं जो तांडव मचाए, शिवराम हवलदार की आंख है, जो हवलदार दिखाना चाहता है, वही दिखाए। वह केवल कट मारने वालों को रिकॉर्ड करती है, ताकि उनकी जेब पर कट मारा जा सके। वे आंखें चालाक हैं, सिर्फ चालान पर उनकी दृष्टि है।

बढ़ते चालान का राहगीर की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। ओवरस्पीडिंग या ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले नए कायदों से बचने की अगली प्लानिंग में बिजी हैं। वे अपने 'अधिकारों' की रक्षा के प्रति अचानक सजग हो गए हैं कि कैसे हवलदार को चकमा दे सकें। हवलदार और उसकी सिटी आज भी बाबा आदम के जमाने के हैं। जब तक हवलदार चालान काटने खड़ा रहेगा, चालाक तीसरी आंख की व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं होने वाली।

ट्वीट-ट्वीट

आखिर नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ऐसे बयान ही क्यों देते हैं कि उन्हें बाद में उस पर सफाई देनी पड़े? निश्चित रूप से इससे आर्थिक सुस्ती को लेकर बनी धारणा दूर नहीं होगी। उनकी बातें असंवेदनशीलता और जमीनी हकीकत से अनभिज्ञता को ही दर्शाती हैं।

मारिया शकील@maryashakil

भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए समस्याएं खुद खड़ी की हैं। यहां निवेशक विरोधी, वेल्थ क्रिएटर-विरोधी, सफलता विरोधी और उपलब्धियों का मखौल उड़ाने वाले माहौल ने ही बेड़ा गर्क किया है।

सदानंद धूमे @dhume

लोकतंत्र प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव संपन्न कराने से कहीं बढ़कर है। हम चुनावों को लोकतंत्र के उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन दो चुनावों के बीच की अवधि को लेकर शायद ही कोई फिक्र करते हैं। हमें इसके बारे में भी गंभीरता से आत्मचिंतन करना होगा।

एस इरफान हबीब@irfhabib

राज्यनामा

उत्तर प्रदेश

दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है

बाबा जी ने पत्ते फेंटे तो सत्ता के गलियारे में एक चर्चा आम हो गई कि फलां मंत्री जी की बाजी तो बिल्कुल पिट गई। कुछ दिन खामोशी रही, नेताजी भी उदास रहे, लेकिन फिर वक्त का फेर शायद समझ आ ही गया। मगर ढाई साल तक इलाज वालों के सिरमौर रहे माननीय उसी झोले में से अपने लिए भी तसल्ली की एक 'मीठी गोली' निकाल लाए। अब खुद खाकर बैठ जाएं तो चर्चा कौन सी थम जाती। लिहाजा मंत्री जी वही अपनी वाली डोज दफ्तर में आने वालों को भी दे रहे हैं। कहते हैं कि सरकार को सूबे का धंधा-कारोबार बढ़ाना है। इसके लिए काबिल हाथों की जरूरत थी, सो मुझे जिम्मा सौंपा है। चूंकि कारोबार वाला विभाग दो मंत्रियों में बंटा है तो यहां भी अपनी अहमियत साबित करनी है सो माननीय राग अलापे जा रहे हैं कि समझने की कोशिश कीजिए, 'नाथ' तो हम ही हैं, दूसरे वाले कामचलाऊ रहेंगे। मंत्री जी की बात तो सब तसल्ली से सुन लेते हैं, फिर बाहर आकर गुनगुनाए जा रहे हैं- 'हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।'

चंदा मामा दूर के : चंदा मामा दूर के ही रह गए और विक्रम उनसे संपर्क नहीं कर पाया। सूबे में अल्पसंख्यकों के कल्याण वाले महकमे के जूनियर मंत्री जी का दर्द आंसुओं के साथ यूं छलका की चर्चा का विषय बन गया। फफक-फफक कर उनके रोने के वीडियो वायरल हुए और मंत्री जी सुर्खियों में आ गए। विरोधी बोले, भैया अभी तक उनके पास विज्ञान वाला ही विभाग था, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध से लगाव तो हो ही गया होगा। फिर विभाग भी बदला है, ऐसे में ऊपर तक यह भी तो दिखाना है कि वह भी वैज्ञानिकों के लिए अभी भी हमदर्दी रखते हैं। क्रिकेट के तेज गेंदबाज रहे हैं, इसलिए पता है कि कब पार्टी लाइन पर गेंद इन स्विंग होगी और कब आउट स्विंग। फिलहाल सुर्खियों में आकर मंत्री जी ने अपने नंबर तो बढ़ा ही लिए।

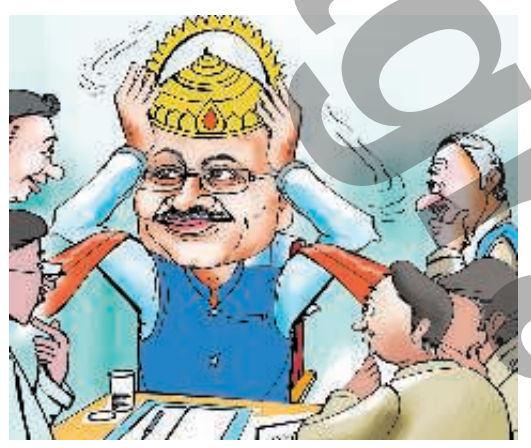

न रहेगा बांस और... : साइकिल वालों और चाभी वालों में कुछ ऐसी ठनी है कि दोनों एक दूजे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। हाथी वालों से मात खाकर खिसियाए साइकिल वालों की नजर में चाचा को मिला बंगला खटक रहा है। सो नित नए हथकंडे आजमाते हैं जिससे चाचा को मिली बंगले की चाभी किसी काम की न रहे। चाचा को आलीशान बंगला सरकार ने विधायक होने के नाते आवंटित किया है। असल दर्द यह भी है कि चाचा को जो बंगला मिला उसके पास कभी साइकिल वाली पार्टी का दफ्तर हुआ करता था जिसे सरकार ने खाली करा लिया। तब से साइकिल वालों को चाचा का बंगला और मुंह चिढ़ाता नजर आता है। चाचा का बंगला खाली कराने के लिए साइकिल वालों ने आखिरी दांव भी चल दिया। चाचा की विधायकी समाप्त कराने को याचिका दाखिल कर दी ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बंगला खाली होने की आस लगाए साइकिल वालों को चाचा के समर्थक पुराने दिनों की याद दिलाना नहीं भूलते हैं। उनका कहना है कि जब साइकिल वालों के राज में पीस पार्टी के बागियों की सदस्यता नहीं जा सकी थी तो अब चाचा की क्यों जाएगी?

समय होत बलवान : साइकिल वाली पार्टी छोड़कर देश के उच्च सदन वाले एक माननीय बीते दिनों कमल वाली पार्टी में शामिल हुए तो उनकी शान में खूब कसीदे पढ़े गए। उन्हें तपस्वी तक बताया गया। उनका जलवा-जलाल इतना कि भगवा दल ने उन्हें उच्च सदन का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया और उनका निर्विरोध निर्वाचन भी तय माना जा रहा है। सियासी गलियारों में ऐसे ही मौकों पर पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। समाजवादियों की सरकार में तपस्वी महोदय को विधानमंडल के उच्च सदन में भेजने के लिए साइकिल वाले मुखिया जोर लगाये थे तो महामहिम ने उनकी हसरत पर ब्रेक लगा दिया था। महामहिम ने श्रीमान को इस योग्य नहीं समझा था कि वह सूबे के उच्च सदन की शोभा बन सकें। अब महामहिम के रिटायर होने के बाद भगवा दल श्रीमान का जिस तरह महिमा मंडन कर रहा है, उससे लोग यह तो कहने को विवश हो ही गए हैं कि मनुज बलि नहीं होत है, समय होत बलवान।

सबसे बड़े मैनेजर हम : मंत्रियों को राजकाज की कुशल नीतियां बनाने के गुर सिखाने और उनका प्रबंध कौशल निखारने के लिए सरकार के मुखिया का उन्हें प्रबंधन के प्रतिष्ठित गुरुकुल में दीक्षा दिलाने की पहल की सराहना हो रही है। यह बात और है कि अंदरखाने कई मंत्रियों को यह पाठशाला रास नहीं आ रही है। मुखिया की पहल के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ कहने की वे जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा है कि दबी जुबां संगी-साथियों के बीच उन्हें यह कहते सुना गया है कि मैनेजमेंट के गुरुजन उनका ज्ञान भले न बढ़ा पाएं अलबत्ता वे उन्हें जरूर इस विधा में कारगर टिप्स दे सकते हैं। आखिरकार हर पांच साल में जनता के बीच जाकर तमाम समीकरणों को साधकर चैंपियन बनकर लौटना कोई आसान काम थोड़े ही है। वह भी एक मर्तबा नहीं, बल्कि कई-कई बार। वे उलाहना दे रहे हैं हुकूमत चलाने वाले कई आइएएस अफसरों को जो विदेशी विश्वविद्यालयों से मैनेजमेंट सीखने और रणनीति बुनने की डिग्रियां लेकर लौटे, लेकिन चुनाव में जनता जनार्दन की कसौटी पर फेल हो गए।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाना चाहिए?

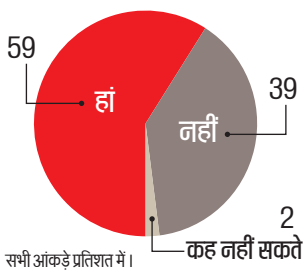

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या हाउसिंग व निर्यात सेक्टर के लिए सरकारी प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ओसामा के पूत भी गए हूर के पास,
चार गोलियां जो पड़ीं बने खुदा के खास।
बने खुदा के खास खायं जन्नत का पेड़ा,
इनका यही इलाज खत्म हो गया बखेड़ा।
गया खुदा के पास मोर्चा जिसने थामा,
हैं ये सब विषबेल बो गया जो ओसामा।

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

भयावह समस्या पैदा करता कचरा

ज्ञानेंद्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद्

देश भर में कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह प्रयास में जुटी है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है

आज देश में कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसके निपटान के लिए किए जाने वाले तमाम प्रयास नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। देश में इसी मकसद से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने 1,041 शहरों-कस्बों को कूड़े-कचरे से मुक्त करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के तहत कूड़े-कचरे के निस्तारण की चरणबद्ध मुहिम शुरू करने की घोषणा की। इसमें देश के शहरी इलाके की तकरीबन 40 करोड़ आबादी हिस्सेदार बनी। राज्यों की राजधानियों समेत एक लाख से ज्यादा आबादी वाले 500 शहरों और उससे कम आबादी वाले 3,541 छोटे शहरों-कस्बों को इसमें शामिल किया गया था। यह एक अच्छा कदम था। लेकिन हुआ क्या। कुछेक शहरों को छोड़ दें, तो देश के बाकी शहरों, कस्बों की हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इस सबके बावजूद असलियत यह है कि देश के शहरों में अब भी सालाना 6.2 करोड़ टन ठोस कचरा निकलता है। सरकार की मानें तो देश में प्रति वर्ष कचरे की मात्रा में 1.3 फीसद की दर से बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते देश में कचरे की समस्या ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया है।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र की यह योजना दिल्ली के अलावा पटना, गया, पुणे, इंदौर, गंगटोक और वाराणसी सहित देश के 20 शहरों में एकसाथ शुरू होनी थी। इसमें शामिल सभी एजेंसियों को केंद्रीय निगरानी तंत्र के सहयोग से समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने हेतु अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। इसके तहत 2018 से पूर्व कचरे का शत प्रतिशत निस्तारण होना था। आज 2019 के भी आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात में खास बदलाव नहीं दिखाई देता। दरअसल इस बाबत हमारी सरकारें दूसरे देशों से कुछ सीखना नहीं चाहतीं। इंडोनेशिया का उदाहरण जरूर हमें देखना चाहिए। इंडोनेशिया में ताड़ के पेड़ों से घिरा रहने वाला बाली का समुद्री तट समुद्र में सर्फिंग और तट पर धूप सेंकने के शौकीन पर्यटकों के लिए लंबे समय से आकर्षण का केंद्र रहा है। सत्रह हजार से अधिक द्वीपों का यह द्वीपसमूह समुद्री कचरा पैदा करने वाले देशों में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां पर सालाना 12.9 लाख टन कचरा पैदा होता है। 2017 में इससे वहां यह समस्या इतनी विकराल हो गई कि बाली में जिमबारन, कुटा और सेमियांक जैसे लोकप्रिय विख्यात समुद्री तटों सहित तकरीबन छह किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर फैले कचरे के कारण प्रशासन को आपात स्थिति की घोषणा करने को बाध्य होना पड़ा। बाली की घटना से साफ जाहिर है कि कचरे की समस्या व्यवस्था से जुड़ी है। जरूरी है इसके प्रति सरकार की संवेदनशीलता और इसके निपटारे के लिए प्रबल इच्छाशक्ति। यह किसी भी समस्या के निदान की दिशा में बेहद जरूरी है।

इसमें दो राय नहीं कि कूड़े-कचरे की समस्या विकराल है। यह स्थिति तब है जब देश में कूड़े-कचरे के निस्तारण के लिए व्यवस्थित रूप से एक सरकारी विभाग है, हजारों कार्यालय हैं, हजारों-लाखों की तादाद में पूरे लाव-लश्कर और तामझाम के साथ कर्मचारी-अधिकारी तैनात हैं। उस हालत में कूड़ा कैसे भीषण समस्या बन गया, यह विचारणीय है। दरअसल कूड़े का जन्म ही अव्यवस्था से होता है। यदि कूड़े के निस्तारण की समुचित व्यवस्था हो जाए तो समस्या विकराल ही न हो। इससे जाहिर होता है कि कूड़े की समस्या की विकरालता के पीछे इसके निस्तारण की व्यवस्था के लिए नियुक्त विभाग का नाकारापन पूरी तरह जिम्मेदार है। यह भी कि कूड़े के जन्मदाता हम ही हैं। कूड़े को हम अपने जीवन से अलग भी नहीं कर सकते। न हम इससे बच ही सकते हैं। यह जीवन की एक वास्तविकता है।

चिकित्सकों की मानें तो जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको कूड़े से सबसे अधिक परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आंखों में जलन की समस्या आम बात है। ब्रोंकाइटिस, दमे की संभावना बनी रहती है। अधिक समय तक कूड़े के संपर्क में रहने की वजह से टीबी जैसी बीमारी होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। अक्सर सड़कों पर कूड़े के ढेर रहने और उसके फैले रहने से डायरिया जैसी बीमारियों का हमेशा अंदेशा बना रहता है। कई बार तो कई दिनों, हफ्तों और महीनों सड़क पर कूड़े के ढेर पड़े रहने से प्लेग की आशंका को झुठलाया नहीं जा सकता। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पांच साल तक के बच्चों को उठाना पड़ता है।

प्रतीकात्मक फोटो

देखा जाए तो कूड़े के मामले में हमारे विकल्प बहुत ही सीमित हैं। ऐसी स्थिति में कूड़ा-कचरा निपटान बहुत बड़ी समस्या है। देश में एक साल में कुल 44 लाख टन कूड़ा-कचरा हर साल निकलता है। इसमें 22 फीसद अकेले घरेलू गंदगी होती है और 50 फीसद से अधिक कागज, पुट्ठा या लकड़ी आदि होती है। सरकार मानती है कि देश के कुल कूड़े-कचरे का केवल पांच फीसद का ही वह निपटान करने में सक्षम है। इतनी बड़ी तादाद में कूड़े-कचरे को एक जगह इकट्ठा करना व उसे दूसरी जगह ढोकर ले जाना दुरुह काम है। राजधानी दिल्ली में ही रोजाना तकरीब सात हजार मीट्रिक टन कूड़ा-कचरा निकल रहा है। जबकि इसमें से अधिकांशतः प्लास्टिक, कागज, गत्ते के टुकड़े, धातु आदि को कचरा बीनने वाले निकालकर बेच देते हैं। शेष करीब तीस फीसद कूड़े-कचरे का निपटान कर पाने में दिल्ली के तीन-तीन निगमों के पसीने छूट रहे हैं। कहने को दिल्ली में पॉलीथिन पर बंदिश है। लेकिन आज भी 585 टन के करीब प्लास्टिक कचरा रोजाना निकल रहा है। इसमें मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रदूषण में और जहर घोल रहा है। पानी को प्रदूषित करने में इसकी अहम भूमिका है।

यह तय है अलग-अलग तरीकों से कचरा पैदा करने में समाज की बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके निपटान की व्यवस्था का दायित्व तो सरकार पर ही है। वर्ष 2021 तक दिल्ली के कूड़े की मात्रा 16 हजार मीट्रिक टन हो जाएगी। यह अकेले देश की राजधानी की बदहाल तस्वीर है, पूरे देश की हालत क्या होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

26 लाख लोगों की दुनियाभर में जान चली जाती है हर साल मेडिकल गलतियों के कारण। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, बीमारी की सही पहचान न होना, दवा व इलाज में त्रुटियां और दवाओं का अनुचित सेवन इन मौतों के तीन मुख्य कारण हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर 2019

डाटागीरी

देश के पूर्वोत्तर राज्यों में है सबसे घने जंगलों का विस्तार

24.49 फीसद भूभाग देश का वनों से आच्छादित है

6.79 फीसद के साथ हरियाणा में सबसे कम वृक्षों का आवरण है

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के भौगोलिक भूभाग का एक चौथाई भाग (24.49 फीसद) वनों से आच्छादित है। यह आकलन फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 2017 में आई थी। इसके आंकड़े इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आइएसएफआर) में प्रकाशित किए गए।

देश में सबसे कम वृक्षों का आवरण हरियाणा में है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.79 फीसद है। पंजाब 6.87 फीसद के साथ हरियाणा से ऊपर है। राजस्थान में वृक्षों का आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.26 फीसद है, जबकि मध्यप्रदेश का 27.73 फीसद है। गोवा और केरल में 50 फीसद से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन हैं।

लक्षद्वीप शीर्ष पर कायम : 97 फीसद के साथ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शीर्ष पर कायम है। हालांकि, इसका भौगोलिक क्षेत्र मात्र 30 वर्ग किमी है। उच्चतम वन और वृक्षों के आवरण वाले छह राज्यों में चार पूर्वोत्तर के हैं- मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वृक्ष और वन आवरण है। यहां 85,487 वर्ग किमी भूभाग वनाच्छादित है।

वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में : वनों की मौजूदगी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ऐसा तब है जब बाकी के नौ देशों में जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है और भारत में यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। विश्व के कुल वनाच्छादित भूभाग का 2.4 हिस्सा भारत में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रों की प्रगति वाले दुनिया के 10 देशों में भारत आठवें नंबर पर है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- देश का 40 फीसद वनाच्छादित क्षेत्र 10 हजार वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक के नौ बड़े क्षेत्रों के रूप में मौजूद है।
- 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कच्छ वनस्पति का क्षेत्र 4921 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कुल 181 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई।
- कच्छ वनस्पति वाले सभी 12 राज्यों में कच्छ वनस्पति क्षेत्र में पिछले आकलन की तुलना में सकारात्मक बदलाव देखे गए।

वनों से आच्छादित शीर्ष छह राज्य

राज्य	वन क्षेत्र (% में)
लक्ष्यद्वीप	97
मिजोरम	88.48
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	82.16
अरुणाचल प्रदेश	80.93
मेघालय	79.37
मणिपुर	78.68

सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य

राज्य	वन क्षेत्र (% में)
हरियाणा	6.79
पंजाब	6.87
राजस्थान	7.26
उत्तर प्रदेश	9.18
बिहार	10.15
गुजरात	11.61

पेशेंट पोर्टल के जरिये कोलंबिया से होगा इलाज

तलाशी राह ▸ झारखंड के देवेश की पहल पर कोलंबिया के माउंट सिनाई अस्पताल के डॉक्टर देंगे मुफ्त में परामर्श

देश के लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में सुविधा देने के लिए तैयार किया मोबाइल एप

धनंजय मिश्रा, साहिबगंज

झारखंड के साहिबगंज के देवेश मिश्र कोलंबिया (अमेरिका राज्य दक्षिणी कैरोलिना की राजधानी) के माउंट सेनाई अस्पताल के हेल्थकेयर विभाग में आइटी विशेषज्ञ हैं। परदेस में बसने के बाद भी अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें कायम रहा। इस चाहत को मुकाम देने के लिए उन्होंने पेशेंट पोर्टल नाम का एक मोबाइल एप तैयार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मोबाइल एप के जरिये भारत के मरीजों के लिए कोलंबिया के माउंट सेनाई अस्पताल के डॉक्टरों से मुफ्त चिकित्सकीय परामर्श का भी इंतजाम करा दिया। बीमारी कोई भी हो एप के जरिये बेहतर इलाज के लिए कोलंबिया के डॉक्टर अपना सुझाव देने को तैयार रहते हैं।

स्वस्थ समाज

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) से एमसीए करने वाले देवेश ने हैदराबाद की जेमटेक्ट कंपनी में नौकरी शुरू की। बाद में कंपनी ने काम के सिलसिले में उनको अमेरिका भेजा। इस बीच कोलंबिया विश्वविद्यालय से देवेश ने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद माउंट कोलंबिया के सेनाई अस्पताल के हेल्थकेयर विभाग में आइटी विशेषज्ञ के नाते काम करने का मौका मिल गया।

चिकित्सकों को भी मिल सकती है मदद : अपने देश के लोगों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा करने की ललक पैदा हुई तो देवेश ने माउंट सेनाई अस्पताल के प्रबंधन से बातचीत की। उनके समक्ष भारत के मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकीय परामर्श देने का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव स्वीकार होते ही पेशेंट पोर्टल एप बनाया। अगर इमरजेंसी वार्ड में कोई मरीज भर्ती है तो यहां चल रहे इलाज एवं चिकित्सकीय जांच की रिपोर्ट एप में अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट अपलोड होते ही कोलंबिया के डॉक्टर उसे देख लेंगे। क्या बेहतर इलाज हो सकता है? वे इसी पर परामर्श भी दे देंगे। मरीज के परिजन बीमारी के लक्षण बताकर इलाज संबंधी सुझाव भी ले सकते हैं। खास बात यह है कि भारतीय डॉक्टरों को ऐसे परामर्श से मरीज का इलाज करने में और सहूलियत होगी। एप में मरीज की चिकित्सा जांच और इलाज की सारी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। छोटे कस्बों तक पोर्टल पहुंच होने से गरीब गांववालों को बड़ा फायदा होगा। देवेश के पिता दिनेश्वर मिश्र ने बताया कि परदेस में रहने के बाद भी बेटा देश के लोगों से जुड़ा है और यहां के लोगों के लिए लगातार कुछ करना चाहता है।

मुखिया ने बताई रिश्तेदार की समस्या तो मिला सुझाव : साहिबगंज के छोटा लोहंडा की ग्राम प्रधान सुकुरमुनी दिनेश्वर मिश्र के घर गई थीं। अपने संबंधी के बीमार होने की बात बताई। दिनेश्वर ने अपने मोबाइल से एप के माध्यम से उनको कोलंबिया के चिकित्सक का परामर्श दिलाया। रोग के लक्षण सुन बीमारी के बारे में बताया गया। किस विशेषज्ञ से इलाज कराएं यह भी बताया।

ग्राम प्रधान सुकुरमुनी को पोर्टल के बारे में बताकर उनको चिकित्सक से परामर्श दिलाते दिनेश्वर। जागरण

देवेश मिश्रा जागरण

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

कैंसर पीड़ितों के परिजनों के लिए उम्मीद की किरण हैं बनारस के बबलू

रवि पांडेय, वाराणसी

मिसाल

पेशे से ड्राइवर सिगरा के रहने वाले राजू पर एक पुत्र और तीन पुत्रियों के साथ ही संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी थी। जब उन्हें कैंसर हुआ तो सरकारी मदद से इलाज के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में सहायक के रूप में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बबलू कुमार बिंद ने भागदौड़ कर इनको तीन लाख रुपये बीएचयू में सरकारी मदद के रूप में दिलाए, जिससे काफी राहत मिली। ये एक मामला नहीं है। कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए बबलू लंबे समय से उनके साथ खड़े हो रहे हैं।

आमतौर पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आया सामान्य परिवार हर तरह से टूट जाता है। सरकार की कुछ योजनाएं हैं, लेकिन लोगों को उसका पता ही नहीं है। ऐसे में बनारस के महमूरगंज के रहने वाले बबलू उनकी मदद को आगे आते हैं और न केवल सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, बल्कि उसके लिए जरूरी भागदौड़ भी वह स्वयं करते हैं। दरअसल, बबलू के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन कैंसर के कारण मां को खोने के बाद वह टूट गए। इसी के बाद उन्होंने ठाना कि जो उन्होंने सहा वह कोई और न सहे। तभी से यह सिलसिला शुरू हो गया। अब तक वह अपने खर्चे और भागदौड़ करके 250 से अधिक परिवारों को सरकारी मदद दिला चुके हैं और साथ ही उनको इस बीमारी से लड़ने की राह भी दिखाई है।

...और लिया संकल्प : अपने दर्द को साझा करते हुए बबलू बताते हैं कि मां को कैंसर से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चार वर्ष पहले हार गया। बीमारी में खर्च से बिल्कुल टूट गया और अंत में तो स्थिति ऐसी हो गई कि कब घर के एक-एक कर गहने बिक गए, पता ही नहीं चला। मां को खोने के गम को कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद करने की ठान ली।

ऐसे पूरा करते हैं संकल्प : बबलू ने बताया कि मां के इलाज के दौरान मिलीं ठोकरों को याद करके संकल्प लिया कि अब जितना हो सकेगा, वह लोगों को इस लड़ाई से लड़ने में मदद करेंगे। तब से कोई पीड़ित उनसे संपर्क करता है या किसी के बारे में बबलू को पता चलता है तो वह उसकी मदद करते हैं।

कैंसर पीड़ितों का मददगार बबलू। जागरण

> अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उनकी मदद के लिए खून-पसीना बहाते हैं, जिनसे उनका खून का रिश्ता तक नहीं होता। कुछ ऐसी ही कहानी है वाराणसी के रहने वाले बबूल कुमार बिंद की, जो कैंसर पीड़ितों और उनके परिवार के साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं। वह अब तक 250 से ज्यादा लोगों को सरकारी सहायता दिला चुके हैं, ताकि इस बीमारी का सामना करने में उन्हें कुछ मदद मिल सके...

कम लागत में उगाइए, हर सीजन में हरा साग खाइए

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी

बारिश में ताल-तलैया व अन्य मौसम में ग्रामीणों के खेत-खलिहान में दिखने वाला हरा साग अब व्यावसायिक खेती के लिए तैयार है। पूर्वांचल के जिलों में 'करेमुआ' के नाम से ख्यात इस कलंबी या कलमी साग पर शोध हो रहा है। शोधित हरा कलमी साग पोषण का खजाना है। लौह तत्व की पूर्ति करता है, विटामिन सी, कैरोटिन और अन्य कई विटामिन्स व खनिज तत्व का भी बढ़िया स्रोत है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (वाराणसी) पोषण सुरक्षा की दिशा में इस पर पहली बार शोध कर रहा। 'वीआरडब्ल्यूएस-1' प्रजाति के हरे साग संग अल्पदोहित एवं भविष्य की सब्जियों के प्रोजेक्ट के तहत कलमी साग के 25 से अधिक प्रारूप पर रिसर्च जारी है। इसे एक बार लगाने के बाद चौराई के जैसे वर्षभर खाएं। इसमें लागत न के बराबर व मुनाफा खूब है।

ऐसे बोएं कलमी साग : 10-15 सेमी लंबी व 4-8 पर्व वाली कलमें तैयार की जाती हैं। एक हेक्टेयर के लिए 25,000-30,000 कलमों की जरूरत होती है। कलमों को लगाकर नालियों में 15-20 सेमी गहराई तक पानी भरते हैं।

मात्र 35-40 दिन में ही तैयार : पौधे लगाने के 35-40 दिन बाद तैयार होते हैं। हरी पत्तियों व टहनियों को जमीन की सतह से काटते हैं। इससे पार्श्व शाखाएं निकलती हैं व बढ़वार तेज होती है।

हवा में झूलते हुए की शादी...

कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं। इस कहावत को अलग अंदाज में सही साबित किया जर्मनी के ब्रिआच में दूल्हे स्वेन लिर और दुल्हन एना ट्रैबर ने। इन्होंने हवा में लटकते हुए शादी की। इस अनोखी शादी के लिए शहर के चौक पर लोहे के तारों की लाइन बिछाई गई। इस पर लटकते हुए एक झूले पर दूल्हा-दुल्हन बैठे तो शादी की रस्में पूरी करने के लिए रजिस्ट्रार व मेयर को भी झूले पर बैठना पड़ा। इन झूलों को मोटरसाइकिलों से चौक के बीचों-बीच पहुंचाया गया। दुल्हन बनी एना जर्मनी के एक प्रसिद्ध कलाकार घराने से ताल्लुक रखती हैं। एपी

चमोली में बिखरेगी कस्तूरी, फेन व नील कमल की चमक

संरक्षण

केदार दत्त, देहरादून

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बाद अब इसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों कस्तूरी, फेन व नील कमल पुष्प भी नर्सरी में उगेंगे। वन विभाग की अनुसंधान विंग ने इसके लिए देश के अंतिम गांव माणा (चमोली) की वन पंचायत की नर्सरी में कसरत शुरू कर दी है। इस कड़ी में उच्च हिमालयी क्षेत्र के नंदी कुंड से इन प्रजातियों के राइजोम (कंद) एकत्रित किए जा रहे हैं। वन संरक्षक अनुसंधान वृत्त संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक, कोशिश है कि ब्रह्मकमल परिवार की ये तीनों प्रजातियां अगले साल नर्सरी में उग जाएं। इस पहल के पीछे इन कमल पुष्प प्रजातियों के संरक्षण की मंशा है।

समुद्रतल से 3800 से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का धार्मिक और औषधीय महत्व है। केदारनाथ में रक्षाबंधन के मौके पर ब्रह्मकमल से बाबा केदार की पूजा की जाती है। इसके अलावा हर साल नंदादेवी लोकजात के समापन पर नंदाष्टमी को बेदनी व बालपाटा बुग्याल में इसी पुष्प से नंदादेवी की पूजा होती है। यह दुर्लभ पुष्प तिब्बतन चिकित्सा पद्धति में विभिन्न रोगों के उपचार में लाया जाता है।

ब्रह्मकमल के संरक्षण के मद्देनजर वन विभाग की अनुसंधान विंग ने पिछले साल प्रयास शुरू किए। इसके तहत माणा वन पंचायत की नर्सरी में ब्रह्मकमल के कंद लगाने के साथ ही बीज भी बोए गए। अनुसंधान वृत्त के वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के अनुसार, कंद से जो पौधे लगाए गए थे, उनमें इस वर्ष जून में फूल खिले। अलबत्ता, बीज से पौधे तो उगे हैं, उनके खिलने का इंतजार है।

संजीव चतुर्वेदी के अनुसार, इस साल ब्रह्मकमल परिवार के तीन अन्य सदस्यों कस्तूरी कमल, फेन कमल व नील कमल को भी उगाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मकमल की तरह यह तीनों कमल भी औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कस्तूरी कमल 3700 से 5700 मीटर और फेन व नील कमल 4000 से 5600 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इन तीनों पुष्प प्रजातियों के रोपण के मद्देनजर इनके कंद एकत्रित करने का वन क्षेत्राधिकारी की अगुआई में एक दल चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र के नंदीकुंड क्षेत्र में भेजा गया है। कंद एकत्रित होने के बाद इन्हें भी माणा वन पंचायत की नर्सरी में रोपा जाएगा।

संरक्षण की है आवश्यकता : वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तेजी से तमाम वनस्पतियां व पुष्प प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, उसे देखते हुए इनका संरक्षण आवश्यक है। इसी क्रम में ब्रह्मकमल के साथ ही इसके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को संरक्षण देने की मुहिम शुरू की गई है। इसके पीछे मंशा यही है कि यदि ये कहीं विलुप्त भी हो गए तो सैंपल सुरक्षित रहने पर उन्हें वहां फिर से उगाया जा सकेगा।

उत्तराखंड में चार प्रजातियां : संजीव चतुर्वेदी बताते हैं कि ब्रह्मकमल परिवार की विश्वभर में 61 प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी औषधीय गुणों से लबरेज हैं। इनमें से उत्तराखंड में ब्रह्मकमल, कस्तूरी कमल, नील कमल व फेन कमल ही मिलती हैं।

नील कमल

कस्तूरी कमल

फेन कमल सभी फाइल फोटो

- राज्य पुष्प ब्रह्मकमल के बाद अब इसके परिवार के तीन अन्य कमल भी उगेंगे नर्सरी में
- वन विभाग की अनुसंधान विंग ने इसके लिए माणा नर्सरी में शुरू कर दी हैं तैयारियां

जानें संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पर किस राज्य का है क्या रुख

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों से भारी-भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने इसमें छूट की घोषणा की है तो कई ने इसे लागू न करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं किस राज्य में क्या है स्थिति...

उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार ने गत बुधवार को संशोधित अधिनियम को जुर्माने में कटौती के साथ अपनाने का फैसला किया। राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति वाहन चलाते पकड़ा जाए तो उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि केंद्र ने 5,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया था। इसी तरह, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने या नाबालिग द्वारा सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो केंद्र द्वारा प्रस्तावित 5,000 रुपये से कम है। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है और वह सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो उस पर केंद्र द्वारा प्रस्तावित 10,000 रुपये के बजाय 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने पर केंद्र सरकार ने 5,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया, लेकिन उत्तराखंड ने इसे घटाकर 1,000 रुपये तक काटने का फैसला किया। वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के मानकों के उल्लंघन के लिए केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है, लेकिन राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इस तरह के अपराध पर पहली बार 2,500 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना बीमा के वाहन चलाने पर केंद्र ने पहली बार के लिए 2,000 रुपये और दूसरी और उसके बाद के लिए 4,000 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार ने इस कम करते हुए दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए पहली बार 1,000 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 2,000 रुपये कर दिया है। इन श्रेणी के वाहनों के लिए दूसरी और उसके बाद के लिए जुर्माना दोगुना करने का फैसला किया है।

झारखंड : झारखंड सरकार ने नए कानून के तहत भारी भरकम जुर्माने से तीन माह तक राहत देने का फैसला किया है। इस दौरान पुराने कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। गत शुक्रवार को हुई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीन माह तक यातायात नियमों को लेकर लोगों के बीच सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस अवधि में लोगों को अपनी गाड़ियों के कागजात अपडेट कराने का भी समय मिल जाएगा।

नए नियमों के तहत बड़े जुर्माने का असर देशभर में देखा जा रहा है। फाइल

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में चालान के दो सिस्टम चलेंगे। राज्य के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की पुरानी दरें ही लागू हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नई दरों से चालान न करें। हालांकि, मौके पर चालक जुर्माना न भरकर कोर्ट जाता है तो वहां नई दर से शुल्क वसूला जाएगा।

कर्नाटक : राज्य के परिवहन मंत्री लक्ष्मण सावदी के मुताबिक, संशोधित अधिनियम तीन सितंबर को लागू हो गया। हालांकि, राज्य सरकार जुर्माने को कम करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। सरकार इस बारे में गुजरात सरकार से भी परामर्श करेगी। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि जुर्माने की राशि आम लोगों पर भारी न पड़े। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ चर्चा करने के बाद गुजरात की तरह जुर्माना राशि कम करने की घोषणा की जाएगी।

गुजरात : राज्य सरकार ने अधिनियम के तहत 15 मामलों में जुर्माना राशि में कटौती की है। अधिकांश मामलों में केंद्र द्वारा प्रस्तावित जुर्माने की राशि 50 फीसद कम की गई है तो कुछ में 70 फीसद तक की कमी की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने साफ कहा कि सरकार कठोर जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करना नहीं चाहती है। हमारी प्राथमिकता मानव जीवन की सुरक्षा है।

महाराष्ट्र : फिलहाल यहां संशोधित अधिनियम लागू नहीं किया गया है। पिछले हफ्ते परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने कहा कि उनके विभाग ने एक प्रशासनिक निर्णय लिया है, लेकिन संशोधित जुर्माना राशि की घोषणा करने से पहले यह कानून विभाग की राय का इंतजार कर रहा है।

ओडिशा : राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में कई जगहों पर पुलिस और जनता के बीच विवाद को देखते हुए संशोधित अधिनियम का क्रियान्वयन तीन महीने के लिए रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने परिवहन विभाग को लोगों को इस कानून के बारे में बताने के लिए कहा है, ताकि इसे आसानी से लागू किया जा सके।

मध्य प्रदेश : राज्य ने संशोधित अधिनियम के क्रियान्वयन को यह कहते हुए रोक दिया गया है कि जुर्माना बहुत ज्यादा है। कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि हम अन्य राज्यों में इसके क्रियान्वयन का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जुर्माने की राशि कम की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के पास ऐसा करने का अधिकार है।

छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ ने भी पुरानी नीति को ही लागू रखा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हम यह पता कर रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं।

पंजाब : पंजाब ने संशोधित नियमों को लागू नहीं किया है। परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने कहा कि फिलहाल संशोधित अधिनियम के प्रावधान राज्य में लागू नहीं होंगे। जब तक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के क्रियान्वयन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक पुराना नियम ही लागू रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि परिवहन राज्य सरकार का विषय है इसलिए पंजाब सरकार संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी।

हरियाणा : राज्य ने केंद्र सरकार के नई नीति को लागू कर दिया है। हालांकि, राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में तीन दिन का जागरूकता अभियान चलाया गया।

बिहार : सरकार ने एक सितंबर को आदेश पारित कर कहा है कि केंद्र द्वारा निर्धारित जुर्माना राज्य में लागू किया जाएगा।

केरल : केरल में नए नियमों के तहत पहले तीन दिन जुर्माना किया गया। इसके बाद जनता और ट्रेड यूनियनों के विरोध के बाद इस पर रोक लगा दी है। परिवहन मंत्री एके ससींद्रन ने कहा कि फिलहाल हमने संशोधित जुर्माना नहीं वसूलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वह गुजरात सरकार के फैसलों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद फैसला होगा।

पश्चिम बंगाल : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार संशोधित अधिनियम को लागू नहीं करेगी क्योंकि इससे लोगों पर बोझ पड़ेगा। राज्य में मौजूदा पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियम, 1989 जारी रहेगा। उनका साफ कहना है कि राज्य सरकार ने अपने यातायात सुरक्षा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया है और पुलिस और अन्य विभाग दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

राजस्थान : राज्य ने नियमों को आंशिक रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। तीन सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि 17 तरह के मामलों में जुर्माना राशि कम रखी जाएगी ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए खुद प्रेरित हों। हालांकि, 16 गंभीर मामलों में जुर्माना संशोधन अधिनियम के तहत ही लगाया जाएगा।

त्रिपुरा : परिवहन मंत्री प्रणजीत सिंघा रॉय का कहना है कि कहा ये अच्छे संशोधन हैं। इसका कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। हम इसे वैसे ही लागू करेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है।

14 फीसद ज्यादा होगी कपास की पैदावार इस साल देश में। वहीं, धान की पैदावार में 13 फीसद की कमी की आशंका है। मौसम एजेंसी स्काईमेट ने एक जून से 15 अगस्त की बारिश के आधार पर यह अनुमान लगाया है।

दिलजीतपाल ने कनाडा के लोगों का जीता दिल

इनसे मिलिए

अपने देश में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बने दिलजीतपाल का मन जब यहां नहीं रमा तो वह कनाडा चले गए। पहले भंगड़ा अकादमी खोली, जिसने उन्हें पहचान दिलाई और फिर कदम रखे राजनीति के क्षेत्र में। बीते सप्ताह वह कनाडा के विनिपेग में चुनाव जीतकर विधायक बने। आइए जानते हैं पंजाब से निकलकर कनाडावासियों के दिलों में जगह बनाने के उनके सफर के बारे में...

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का...। इसको सच साबित किया है पंजाब के मुक्तसर के गांव भंगचड़ी में किसान परिवार के दिलजीतपाल सिंह बराड़ ने। वह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी करने लगे, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। कुछ बड़ा करने की चाह लिए कनाडा चले गए। वहां उन्होंने भंगड़ा डांस अकादमी खोली। भंगड़े ने उन्हें कनाडा में प्रसिद्धि दिलाई और फिर मन हुआ राजनीति में उतरने का। इसके बाद कनाडा के मैनीटोबा प्रांतीय चुनाव में विनिपेग के ब्रोअ सीट से एनडीपी की टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। बीते सप्ताह जब यह खुशखबरी उनके गांव भंगचड़ी में पहुंची तब से यहां खुशी का माहौल है। उनके माता-पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे।

दिलजीतपाल सिंह

पिता मंगल सिंह बताते हैं कि बेटा शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा आज्ञाकारी था, लेकिन वह इस तरह विदेश में नाम रोशन करेगा इसकी कल्पना नहीं की थी। वह बताते हैं, 'दिलजीतपाल ने छठी कक्षा तक गांव भंगचड़ी में ही पढ़ाई की थी। सातवीं कक्षा जीटीबी मलोट से की। इसके बाद वह गांव रुपाणा के सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल मे दाखिल हुआ।' माता अमरजीत कौर सरकारी मिडिल स्कूल में ही पढ़ाती थीं। दिलजीतपाल ने डीएवी चंडीगढ़ से प्लस टू की व पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में चले गए। जहां से उन्होंने बीएससी व एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लुधियाना में ही शुरू कर दी। वह नौकरी के दौरान गुरदासपुर, फतेहगढ़ साहिब व लुधियाना में रहे। लुधियाना में ही भूविज्ञानी नवनीत कौर के साथ शादी की। इसके बाद 2010 में नौकरी छोड़कर कनाडा चले गए। पहले सरी गए, लेकिन बाद में विनिपेग के मैनीटोबा में रहने लगे। वहां एक डांस अकादमी बुल्ला आर्ट्स इंस्टीट्यूट (बाई) खोला। इससे लोग उनसे जुड़ते गए। वह बाई के नाम से मशहूर हो गए थे। लोगों के कहने पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा और 416 वोट से जीत हासिल की। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। दिलजीतपाल के दादा गांव के सरपंच थे।

पिता मंगल सिंह बताते हैं कि कनाडा में एक यूनिवर्सिटी को बाबा नानक स्कॉलरशिप शुरू करने के लिए 25 हजार डॉलर चाहिए थे। यह राशि दिलजीतपाल ने भंगड़े के शो लगाकर इकट्ठी की थी।

दिलजीतपाल के शिक्षक जगन्नाथ खुराना ने बताया कि वह साइंस में भी अव्वल रहते थे। जगन्नाथ कहते हैं, 'उसने कई बार राज्यस्तर की प्रदर्शनी में भाग लिया था। उसे साइंस का शौक था। वह बचपन से ही पढ़ाई व खेलों की ओर प्रेरित था। उसने बचपन में कभी किसी शिक्षक की बात से इन्कार नहीं किया। वह रात को देर से सोता था और सुबह जल्द ही जागकर मॉडल तैयार करने में जुट जाता था। उसमें जीत का जुनून था। इसी जुनून के चलते उसने नाम रोशन किया है।'

अब तो नया बोर्ड लगाना पड़ेगा : पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर व पंजाबी साहित्य अकादमी के पूर्व प्रधान गुरभजन गिल कहते हैं, 'दिलजीतपाल शुरू से ही होनहार था। उसने यूनिवर्सिटी का बहुत मान बढ़ाया है।' वह हंसकर कहते हैं, 'अब तो यूनिवर्सिटी में नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। इसमें लिखा जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा लायक बच्चा भी था, जिसने यूनिवर्सिटी का नाम विदेश में रोशन किया है।'

खेल का जुनून : पीएयू में दिलजीतपाल के क्लासमेट रहे नरेंद्र पाल सिंह बताते हैं कि हॉस्टल में तीन गुणा चार के कमरे में दिलजीतपाल रहता था। उसको खेल का जुनून था। कमरे में ही हॉकी का अभ्यास करने लगता था। कनाडा जाने के बाद उसने वहां कल्चरल ग्रुप बनाया और रचनात्मक कार्यों में लगा रहा।

कनाडा में किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं : दिलजीतपाल

दिलजीतपाल ने फोन पर दैनिक जागरण को बताया कि वे पंजाब में भी पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, लेकिन पंजाब में सीधे पॉलिटिक्स में आना मुश्किल है। कनाडा में किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है। कनाडा में मैं लोगों के साथ जुड़ा, अपने दम पर पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ा।

नानक नगरी में देखिए गुरु जी का 99 शहरों का सफर

पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में बन रही है मूल मंत्र इमारत, हर मंजिल पर चित्रित होंगी सिख धर्म से जुड़ी अमूल्य जानकारियां

जागरण विशेष

हरनेक सिंह जैनपुरी, कपूरथला

'इक ओंकार सतनाम, करता पुरखु निरभउ। निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसादि।।' यह सिख धर्म का मूल मंत्र है। गुरु नानक देव जी ने पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में पवित्र काली बेई के किनारे सिख धर्म के इस मूल मंत्र का उच्चारण कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बुनियाद रखी थी। अब यहीं पर सिख धर्म से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। गुरु जी की 99 शहरों की यात्रा हो या सिख धर्म से जुड़ी कोई भी जानकारी... सब कुछ यहां मिलेगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) इस स्थान पर चार मंजिला मूल मंत्र इमारत का निर्माण करा रही है। इसकी अलग-अलग मंजिलों पर सिख धर्म से जुड़ी जानकारियां होंगी। यहां विविध तरीके के खोज कार्य भी होंगे।

गौरतलब है कि श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 14 साल 9 महीने 13 दिन का समय सुल्तानपुर लोधी में व्यतीत किया। यहां की धरती पर उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण किया और विश्व कल्याण के लिए दुनिया का भ्रमण शुरू किया था।

पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में बन रही 'मूल मंत्र' इमारत का मॉडल। जागरण

पूरी दुनिया में फैलेगा गुरबाणी का ज्ञान : करीब 20 करोड़ की लागत से बन रही मूल मंत्र इमारत से गुरबाणी के ज्ञान का प्रकाश दुनिया भर में फैलेगा। यहां गुरबाणी को लेकर खोज कार्य होंगे। बाणी सिद्धांत और फलसफे को प्रचारित किया जाएगा, ताकि लोगों में मानव हित के लिए कार्य करने की भावना भरी जा सके। इमारत की पहली मंजिल गुरु नानक देव जी की पहली उदासी को समर्पित होगी। गुरु जी ने 1500 ई. में सुल्तानपुर लोधी से पहली उदासी शुरू की। इसके तहत गोईंदवाल, अमृतसर से एमनाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, कासूर से पिहोवा, करनाल, हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा, गुवाहाटी आदि करीब 99 शहरों से होकर 1505 ई. को सुल्तानपुर लोधी वापस आए थे। गुरु जी के इस सारे सफर को चित्रों के जरिये दर्शाया जाएगा। श्रद्धालु एक क्लिक पर डिजिटल रूप में पूरे सिख इतिहास से रूबरू हो सकेंगे।

13 फीट होगी ऊंचाई : कारसेवा की देखरेख कर रहे भाई सतनाम सिंह ने बताया कि इमारत की नींव 20 फीट गहरी है। इसे गोलाकार आकृति में बनाया रहा है। हर मंजिल की ऊंचाई 13 फीट होगी। इमारत के अंदर 20 फीट घेरे में 13-13 फीट चौड़ी जगह में पानी का प्रवाह होगा, जिसका निकास पवित्र काली बेई में होगा। इस स्थान पर कुल 13 गैलरियां बनेंगी। मध्य वाले हिस्से को ऊपरी मंजिल तक बिल्कुल खाली रखा जाएगा। ऊपर से नीचे को शानदार लाइटों से खूबसूरत रूप प्रदान किया जाएगा। लगभग 65 फीट ऊंची इस इमारत में सबसे ऊपर गुंबद बनेगा। इसका डिजाइन इंजीनियर बाबा महिंदर सिंह यूके वालों ने तैयार किया है। भाई इंद्रजीत सिंह बिट्टू ने बताया कि इमारत पूरी तरह डिजिटलाइज होगी। टच स्क्रीन के जरिये श्री इतिहास के बारे में जान सकेंगे। चित्रों के जरिये भी सिख इतिहास को दर्शाया जाएगा। भाई सतनाम का अनुमान है कि प्रकाशोत्सव तक इमारत का ढांचा तैयार हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह तैयार होने में वर्ष 2020 की बैसाखी तक का समय लग जाएगा।

दो मंजिल तैयार, तीसरी का लेंटर डाला

इमारत का निर्माण कार्य 18 अक्टूबर 2018 को आरंभ हुआ है। इसकी दो मंजिल तैयार हो चुकी हैं। तीसरी मंजिल का लेंटर डाला गया है। इमारत के लिए एसजीपीसी ने सिर्फ स्थान उपलब्ध कराया है। निर्माण कार्य श्रद्धालुओं के सहयोग से चल रहा है। इसकी सेवा निष्काम सेवक जत्था यूके के भाई महिंदर सिंह, किला आनंदगढ़, आनंदपुर साहिब के संत बाबा लाभ सिंह और बाबा हरभजन सिंह भलवान निभा रहे हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

रेल व मेट्रो के जरिये पहुंचाएंगे गुरु नानक देव के संदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर उनके संदेशों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीसीजीपीसी) रेलवे और मेट्रो की मदद लेगी। भारतीय रेलवे की लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ दिल्ली, मुंबई और जयपुर रूट की मेट्रो कोच के ऊपर और नीचे के पैनलों पर विज्ञापन के जरिये उनकी शिक्षा और संदेशों के प्रति समाज को जागरूक करेंगे।

डीएसजीपीसी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए समिति ने दिल्ली से मुंबई के बीच राजधानी, दिल्ली से लखनऊ तथा दिल्ली से अमृतसर के बीच शताब्दी सहित दस लंबी दूरी की प्रीमियम रेलगाड़ियों सहित दिल्ली, मुंबई व जयपुर मेट्रो के कोच में डिस्प्ले पैनलों पर चित्र, प्रिंट सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्मार्ट पोस्टर, होलोग्राफिक प्रतिमाओं आदि के माध्यम से गुरु नानक देव के संदेशों को प्रचारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिकारियों से इस बारे में बातचीत अंतिम दौर में है। इस माह ही लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में गुरु नानक देव के संदेश रेलवे के कोच के अंदरूनी पैनलों पर प्रिंट कर दिए जाएंगे। कमेटी ने दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेवा पर एक मेट्रो ट्रेन को चुना है। द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी व वैशाली मेट्रो लाइन के कोच में विज्ञापन लगाए जाएंगे।

दौड़ने लायक नहीं रहा 162 साल पुराना इंजन

- तीन महीने से खराब पड़ा है ऐतिहासिक स्टीम इंजन जेडबी-66
- लंदन की एक प्राइवेट कंपनी ने 1857 में बनाया था इंजन

विनोद कुमार, पठानकोट

हिमाचल की हसीन वादियों में फिर से छुक-छुक की आवाज सुनने के लिए पर्यटकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कारण यह है कि तीन महीने से बैजनाथ की वर्कशॉप में खड़ा 162 साल पुराना जेडबी-66 स्टीम इंजन ट्रैक पर दौड़ने लायक नहीं रहा है। इस वजह से इस इंजन में नई जान डालने के लिए अमृतसर लोको भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों की ओर से पठानकोट-जोगिंद्रनगर नैरोगेज रेल सेक्शन पर स्टीम इंजन को चलाने की मांग के बाद पठानकोट रेलवे ने प्रतापगढ़ (गुजरात) से स्टीम इंजन की मांग की थी। इस पर रेलवे ने लंदन की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा 1857 में बनाए गए जेड बी- 66 स्टीम इंजन को पठानकोट की वर्कशॉप में भेजा था। पठानकोट लोको में पहुंचे स्टीम इंजन को ठीक करके मार्च 2003 में रेलवे अधिकारियों की देख -रेख में पठानकोट से ज्वालामुखी रोड तक लगभग 30 किलोमीटर तक ट्रायल लिया गया। ट्रायल तो कामयाब रहा, परंतु इंजन के ब्वायलर में समस्या आ गई। इस कारण पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं की डिमांड पूरी नहीं हो पाई। वर्ष 2004 में बॉलीवुड के एक फिल्म निदेशक व विदेशी पर्यटकों ने दोबारा इंजन की मांग कर दी। इंजन का दूसरी बार डल्हौजी रोड स्टेशन तक दस किलोमीटर का ट्रायल हुआ, लेकिन दोबारा वही समस्या आ गई। इसके बाद 2007 में लखनऊ से आए अधिकारियों ने इसे ठीक किया, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आखिरकार विभाग ने समस्या को हायर अथॉरिटी के समक्ष रखा। इसके बाद नवंबर 2008 में स्टीम इंजन को अमृतसर लोको भेजा गया था। यहां से वह दोबारा नए कलपुर्जों के साथ 2017 में पठानकोट लोको में पहुंचा था।

बैजनाथ की वर्कशॉप में खड़ा 162 साल पुराना जेडबी-66 स्टीम इंजन। जागरण

विदेशी पर्यटकों ने किया था जेडबी-66 के साथ सफर: जानकारी के अनुसार, 2017 में अमृतसर की लोको से पावरफुल होकर पठानकोट पहुंचे जेडबी-66 इंजन की विशेष तौर पर बुकिंग करवाई थी। इसके बाद ब्रिटेन के 11 सैलानियों ने पालमपुर से बैजनाथ तक के लिए दो स्पेशल डिब्बे बुक करवाकर हसीन वादियों का नजारा लिया था। पर्यटकों ने दो दिनों तक अपनी सुविधा अनुसार करीब 22 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पहाड़ियों के बीच फोटोग्राफी भी करवाई थी। टूर सफल होने के बाद विदेशी पर्यटकों ने फिर से भारत भ्रमण के दौरान स्टीम इंजन की बुकिंग करने की बात कही थी, लेकिन इंजन जबाव दे गया है।

तीन महीने पहले हो गया था खराब : विभागीय अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष विदेशी पर्यटकों को हिमाचल की हसीन वादियों का भ्रमण करवाने के बाद स्टीम इंजन को चालू रखने के लिए प्रत्येक रविवार स्कूली बच्चों को घुमाने का कार्यक्रम तय किया गया था। इसी दौरान करीब तीन महीने पहले पालमपुर से बैजनाथ के बीच जब इंजन चलाया जा रहा था तब वह रुक गया। इंजन को बैजनाथ लोको पहुंचाया गया। इस दौरान इंजन को ठीक करने की कोशिश की गई, परंतु रेलवे अधिकारी सफल नहीं हो पाए। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि स्टीम इंजन को ठीक करने वाला अधिकतर स्टाफ रिटायर हो चुका है। नए स्टाफ के लिए इसे अपने स्तर पर ठीक कर पाना मुश्किल है। इसी को देखते हुए पठानकोट रेलवे ने स्टीम इंजन को फिर से अमृतसर भेजे जाने का फैसला किया है। उधर, इस संदर्भ में जब पठानकोट लोको के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (लोको) देस राज से बात की तो उनका कहना था कि जेडबी-66 को फिर से ट्रैक पर चलाने को नए कलपुर्जे डालने के लिए अमृतसर की लोको भेजा जाएगा। वर्तमान में स्टीम इंजन बैजनाथ की लोको में खड़ा है। यहां से उसे बहुत जल्द पठानकोट लाया जाएगा और फिर अमृतसर भेजा जाएगा।

नक्सल क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिले तो सीआरपीएफ अफसर ने उठाई चॉक

नईदुनिया, जगदलपुर

- तीन माह से नौवीं, 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहे गणित और विज्ञान

छत्तीसगढ़ का ग्राम कोलेंग घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली व संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित इस गांव में एक हाईस्कूल तो है पर लंबे समय से वहां गणित व विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं हैं। क्षेत्र में सर्च आपरेशन में जाने वाले सीआरपीएफ 80 बटालियन के युवा असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी बटालियन के कमांड अफसर को दी। सीओ अमिताभ कुमार के प्रोत्साहन व अनुमति के बाद उन्होंने दो कक्षाओं के बच्चों को गणित व विज्ञान विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। वह तीन माह से इस कार्य में लगे हुए हैं।

इलाहाबाद से प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी की डिग्री लेने वाले राजेश इतने रोचक ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं कि छात्र उनसे साल भर पढ़ाने की जिद कर बैठे हैं। बहरहाल वह बीते तीन माह से अपनी ड्यूटी से समय निकालकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दरभा इलाके में सीआरपीएफ 80 बटालियन की कंपनियां काफी दिनों से तैनात हैं। बल की ओर से ग्रामीण इलाकों में खेलकूद समेत सिविक एक्शन कार्यक्रम समय-समय पर चलाए जाते रहे हैं, लेकिन साल भर पहले ही बटालियन में तैनात एक युवा अफसर राजेश सिंह ने एक अनूठा प्रयास किया। सिंह ने बताया कि कोलेंग में सर्च ऑपरेशन के दौरान वे जुलाई माह में वह हाईस्कूल के बच्चों से मिलने पहुंच गए।

बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को पढ़ाते राजेश कुमार सिंह। नईदुनिया

इस दौरान उन्हें यह बताया गया कि लंबे अरसे से यहां विज्ञान व गणित विषय के अध्यापक नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि यह दूर दराज का नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसके चलते यहां आने वाले शिक्षक अपनी पोस्टिंग कहीं और करा लेते हैं। युवा अफसर राजेश को इस बात से काफी पीड़ा पहुंची कि बच्चों में शिक्षा के प्रति नकारात्मक माहौल बन रहा है। वह इस विषय को वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाए। बटालियन के सीओ अमिताभ कुमार ने फौरन ही सिंह को कहा कि आप अपनी योग्यता का सही उपयोग कर बच्चों को तालीम दें। इसके लिए उन्होंने ड्यूटी के दौरान उन्हें स्कूल में कक्षा नौवीं व 10वीं के बच्चों को गणित व विज्ञान पढ़ाने की विशेष अनुमति दी। इसके बाद राजेश सिंह ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बताते हैं कि शुरुआत में तो बच्चे कुछ झिझक रहे थे, लेकिन बाल मनोविज्ञान के टिप्स अपनाते हुए वह पहले बच्चों के करीब आए। इसके बाद पढ़ाई शुरू करवाई। इसका काफी सकारात्मक नतीजा निकला। नौवीं के कुल 39 व 10वीं के 49 छात्र-छात्राएं अब उनसे बेझिझक अपनी जिज्ञासाएं शांत करते हैं।

> बल के युवा अफसर ने जब हमें कोलेंग के हाईस्कूल में शिक्षक की कमी बताई तो हमने उनका उत्साह बढ़ाते हुए बच्चों को पढ़ाने को कहा, ताकि स्कूल का परिणाम बेहतर आए।
> – अमिताभ कुमार, सीओ, सीआरपीएफ 80 बटालियन

76 साल बाद फिर गुनगुनाया जाएगा आजाद हिंद फौज का गाना

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम ने आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बनी बांग्ला फिल्म 'गुमनामी' के लिए एक गाना गाया है। यह गाना आजाद हिंद फौज के उस गाने पर आधारित है, जो उसके सैनिकों ने नेताजी के सिंगापुर पहुंचने पर उनके स्वागत में गाया था। 76 वर्षों बाद इस गाने को नए सिरे से गाया जा रहा है। इस गाने को दूसरे विश्व युद्ध के बाद रिकार्ड किया गया था। गाने के बोल हैं... सुभाषजी, सुभाष वो जान ए हिंद आ गए..। फिल्म में बाबुल सुप्रियो ने भी एक गाना गाया है। बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी नेताजी की भूमिका निभा रहे हैं। दो अक्टूबर को प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त बांग्ला फिल्म निर्देशक श्रीजीत बोस ने किया है। श्रीजीत ने बताया, 'सोनू निगम इस गीत में भरे जोश को दर्शकों के पास ले जाएंगे। हम इस तरह देश के महान नेतृत्वकर्ता को श्रद्धांजलि देंगे। फिल्म में आजाद हिंद फौज द्वारा तैयार किए गए ओरिजिनल साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया है।'

सोनू निगम

अब प्रसव के दौरान नहीं होता है पीड़ा का अहसास

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ईजाद किया गया एक नया फॉर्मूला
- प्रसव पीड़ा के समय नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का देते हैं मिश्रण

कोलकाता मेडिकल कॉलेज में पहली बार लाफिंग गैस (नाइट्रस ऑक्साइड) और ऑक्सीजन को 50-50 प्रतिशत मिलाकर एक गैस का मिश्रण तैयार किया गया है, जिसके जरिये बिना दर्द के महिलाओं की डिलीवरी करवाई जा रही है। इस तकनीक का उपयोग कर 25 महिलाओं की डिलीवरी कराई जा चुकी है। इस दौरान एक भी प्रसूता को प्रसव पीड़ा का अहसास नहीं हुआ। बंगाल के सरकारी अस्पताल में ऐसा पहली बार हुआ है। करीब एक साल पहले कोलकाता मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग के प्रमुख डॉ. पार्थ मुखोपाध्याय ने इस मामले में फैसला लिया था। उन्होंने इस बारे में कॉलेज के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के लिए आवेदन भेजा। साथ ही इस बाबत एक से अधिक बार इस विषय में चिकित्सक और विशेषज्ञों को लेकर सेमिनार का आयोजन भी किया गया। इस नई तकनीक में नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन को समान मात्रा में मिलाकर गैस तैयार की जाती है। प्रसव पीड़ा के समय मास्क के जरिये महिलाएं इसका उपयोग करती हैं।

नुकसानदेह नहीं है यह तकनीक : डॉ. पार्थ

डॉ. पार्थ ने बताया कि गैस के उपयोग से जच्चा और बच्चा को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अभी तक हम एक महीने में इस तरीके का इस्तेमाल कर कुल 25 डिलीवरी करवा चुके हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की इस सफलता के बाद अब शहर का हर मेडिकल कॉलेज इसकी शुरुआत करना चाहता है।

ऐसे होता है गैस का उपयोग : डॉ. पार्थ मुखोपाध्याय ने बताया कि प्रसव पीड़ा जब शुरू होती है तब हम इस मास्क को गर्भवती महिलाओं के मुंह में लगा देते हैं। एक निश्चित समयसीमा तक इसको लगाकर रखते हैं। इससे प्रसव पीड़ा कम हो जाती है। ऐसे में बिना किसी दर्द के ही डिलीवरी हो जाती है।

एनजीटी की सख्ती पर सीईटीपी से कनेक्शन मांगने लगीं कंपनियां

मनीस पांडेय, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) : कंपनियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को स्वच्छ बनाने के लिए लगाई गई सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती के बाद प्रभाव में आने जा रही है। अभी तक उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) की करीब 200 से ज्यादा कंपनियों ने इसका कनेक्शन नहीं लिया था। एनजीटी ने जब ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद करने के आदेश दिए, तब जाकर ईटीपी प्लांट चलाने वाली कंपनियां भी सीईटीपी से कनेक्शन मांग रही हैं। एनजीटी के अनुसार, पंतनगर स्थित सीईटीपी में पानी साफ करने की क्षमता चार एमएलडी यानी चार हजार किलोलीटर प्रतिदिन की है। इसके बाद भी मात्र सवा एमएलडी केमिकल युक्त गंदा पानी ही सीईटीपी को मिल रहा है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसे संवेदनशील मान एनजीटी ने आदेश में कहा कि सिडकुल पंतनगर की सभी 520 कंपनियां सीईटीपी में अपना पानी भेजें। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि जलशोधक कुंड में पानी भेजना आवश्यक है, जिससे पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसा न करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद किए जाएंगे। टाटा वेंडर्स के एक अधिकारी ने बताया कि एनजीटी की सख्ती देख सीईटीपी से कनेक्शन मांगा गया है, जिसमें प्रक्रिया चल रही है। एनजीटी के आदेश के बाद दर्जनों कंपनियां सीईटीपी से जुड़ चुकी हैं। जल शोधन प्लांट के प्रॉसेस मैनेजर रमन ने बताया कि सीईटीपी सितारगंज में करीब 90 फीसद कंपनियों का पानी सीईटीपी में भेजा जा रहा है, जबकि सिडकुल पंतनगर में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत ही है।

> सीईटीपी में जल शोधन के निर्देश कंपनियों को दिए गए हैं। एनजीटी के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में पाइपलाइन की समस्या है, जिसके लिए देहरादून मुख्यालय में पाइपलाइन का प्रोजेक्ट भेजा गया है।
> – पारितोष वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, सिडकुल, रुद्रपुर

उत्सव

वर्ष 1962 से पूर्व भारत-तिब्बत व्यापार का सीजन समाप्त होने पर आयोजित होता था यह उत्सव, उन्हीं यादों को जिंदा रखने के लिए आज भी चला आ रहा यह सिलसिला, होती है सोमेश्वर देवता की पूजा

भारत-तिब्बत व्यापार की यादों को संजोए हुए है सेल्कू मेला

शैलेंद्र गोदियाल, उत्तरकाशी

उत्तराखंड के जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 85 किमी दूर मां गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखवा में हर वर्ष मनाया जाने वाला दो-दिवसीय सेल्कू मेला सबसे निराला उत्सव है, जो हर वर्ष 16-17 सितंबर को आयोजित होता है। इस बार भी 15 दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई थीं। इस दिन ग्रामीण उच्च हिमालयी क्षेत्र से पूजा के लिए ब्रह्मकमल समेत कई तरह के फूल लाते हैं और चीड़ व देवदार की लकड़ियों के छिल्लों से भैलो तैयार किए जाते हैं।

उत्सव का इतिहास : सेल्कू मेला भारत-तिब्बत व्यापार से जुड़ा हुआ है। गंगा घाटी की संस्कृति एवं सभ्यता पर पुस्तक लिख चुके स्थानीय इतिहासकार उमा रमण सेमवाल बताते हैं कि 1962 के भारत-चीन युद्ध से पहले गंगा घाटी तिब्बत और भारत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। तब वर्ष में 15 अप्रैल से लेकर 15 सितंबर तक यह व्यापार चलता था और व्यापार सीजन की समाप्ति पर सेल्कू उत्सव मनाया जाता था। उन्हीं यादों को जिंदा रखने के लिए यह सिलसिला आज भी चला आ रहा है। सेल्कू का अर्थ है 'सोएगा कौन'। इस त्योहार का स्वरूप भी दीपावली जैसा ही है। त्योहार में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दीपावली में चीड़ व देवदार की लकड़ियों के छिल्लों से बना भैलो खेला जाता है। रातभर लोग जागकर उत्सव मनाते हैं और परंपरागत नृत्य करते हैं। इसमें शामिल होने के लिए आस-पास के लोग भी आते हैं।

उत्तरकाशी जिले के मुखवा गांव में सेल्कू उत्सव के दौरान नृत्य करते ग्रामीण। फाइल फोटो

ऐसे मनाया जाता है उत्सव

मुखवा गांव निवासी राजेश सेमवाल बताते हैं कि सेल्कू उत्सव पर ग्रामीण अपने घरों में मक्की के आटे व गुड़ को मिलाकर घूड़ा, स्वाले, पकौड़े आदि पकवान बनाते हैं। मुखवा स्थित गंगा मंदिर परिसर में ग्रामीण चीड़ व देवदार की लकड़ी के छिल्लों से बने भैलो खेलते हैं। इसके बाद ब्रह्मकमल, जयाण, केदार पत्ती व गंगा तुलसी से सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। ग्रामीण पूरी रात रांसो व तांदी नृत्य की छटा बिखेरते हैं।

इस तरह से होता था व्यापार : भारत-चीन युद्ध से पहले इस गांव के ग्रामीण तिब्बत के दोरजी (तिब्बती व्यापारी) के साथ व्यापार करते थे। नमक, ऊनी कपड़े, चमड़े के जूते आदि सामान तिब्बती व्यापारी यहां के लोगों से खरीदते थे और बदले में तिब्बती व्यापारियों को झंगोरा, धान, गेहूं, मंडुवा, फाफर, कुट्टू आदि अनाज बेचे जाते थे। इस व्यापार के लिए मुखवा के निकट नागणी, नेलांग व सुमला में मंडियां लगती थीं। शीतकाल में तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे (हिमालयी मार्ग) बर्फ से बंद हो जाते थे। इसलिए व्यापार सीजन समाप्त होने पर दो दिन का उत्सव मनाया जाता था।

यहां लगता था बाजार : इतिहासकार सेमवाल बताते हैं कि मुखवा गांव के निकट नागणी नामक स्थान है, जहां बाजार लगा करता था। गढ़वाल के प्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी के एक गीत में इस नागणी बाजार का जिक्र हुआ है। पहले इसी स्थान पर यह सेल्कू उत्सव मनाया जाता था, लेकिन अब यह उत्सव गांव में मनाया जाता है और इस दौरान सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है।

नए व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म की तैयारी में सेबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए सेबी नई व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म लाने जा रहा है। मार्केट रेगुलेटर इस नई व्यवस्था से ऑडिटर और अन्य जिम्मेदार लोगों को किसी अनुचित गतिविधि की रिपोर्ट करने की सुविधा देगा। इसमें सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इनसाइड ट्रेडिंग को छोड़कर वित्तीय अनियमितताओं और हर तरह के फ्रॉड को इसके दायरे में लाया जाएगा।

सरकार ने रियल एस्टेट की हालत सुधारने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। हालांकि इन कदमों को अभी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए रियल एस्टेट को अधिक सहायता की जरूरत है।
— जक्षय शाह, चेयरमैन, क्रेडाई

त्योहारी मौसम से हो सकती है अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार की शुरुआत

इंटरव्यू देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ के चेयरमैन **रजनीश कुमार** का कहना है कि मौजूदा मंदी के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वैश्विक वजहों से लेकर घरेलू मांग में कमी आने से मंदी ने जड़ें जमाई हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से मंदी दूर करने के लिए कदम उठाने में कोई देरी नहीं हो रही है। लेह में **दैनिक जागरण** के विशेष संवाददाता **जयप्रकाश रंजन** के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने उम्मीद जताई कि इस त्योहारी सीजन से हालात में सकारात्मक बदलाव होंगे।

● सरकारी क्षेत्र के दस बैंकों को मिला कर चार बड़े बैंक बनाने का एलान किया गया है। इससे बैंकिंग सेक्टर पर और एसबीआइ पर किस तरह का असर पड़ेगा?

-सरकारी क्षेत्र में बैंकों के विलय की जरूरत काफी दिनों से महसूस की जा रही थी। यह वक्त की मांग थी, जिसे पूरा किया गया है। जिस तरह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बैंकिंग सेक्टर का चेहरा बदल रहा है, उसे देखते हुए छोटे बैंकों के लिए अब काफी मुश्किल होगी। हर बैंक को तकनीक पर बहुत खर्च करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह खर्च और बढ़ेगा। छोटे बैंक इस लागत को नहीं उठा सकेंगे। आप यह भी देखिए कि इतने सारे सरकारी बैंकों में प्रमुख इक्विटी होल्डर तो केंद्र सरकार ही है। वह इन सभी बैंकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी तो उसके दूसरे सामाजिक दायित्वों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस फैसले को जमीनी तौर पर किस तरह से लागू किया जाता है। सरकार ने विलय के साथ गवर्नेंस को सुधारने की कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्हें लागू करना बहुत जरूरी है।

● एनपीए की समस्या अब भी बहुत विकराल है। क्या विलय के फैसले से बैंकिंग सेक्टर में एनपीए पर कोई असर होगा?

-एनपीए की स्थिति में सुधार सिर्फ विलय के फैसले से नहीं होगा। निश्चित तौर पर बड़े आकार के बैंक अब एनपीए को लेकर ज्यादा तर्कसंगत नीति बना सकेंगे या उसके झटके को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल सकेंगे। एनपीए के लिए कई ऐसे कारक जिम्मेदार होते हैं जो सीधे तौर पर बैंक के कामकाज से जुड़े होते हैं। मसलन, उच्च स्तर की गवर्नेंस, कर्ज देने की बेहद ठोस और जिम्मेदार नीति आदि। जिन बैंकों में इनका अभाव था, अगर उनका विलय बेहतर गवर्नेंस वाले बैंकों में किया जाए तो उसका सकारात्मक असर एनपीए पर भी दिखाई देगा। हां, एनपीए की समस्या के लिए कई दूसरे ऐसे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जिनको लेकर बैंक कुछ नहीं कर सकते, जैसे अर्थव्यवस्था की माली हालात का खराब होना आदि। ये फैक्टर तो आगे भी रहेंगे और सभी तरह के बैंकों पर एक जैसा असर डालेंगे।

● इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) बने हुए ढाई साल हो गए। क्या एनपीए संभालने को लेकर इसकी प्रगति से आप संतुष्ट हैं?

-देखिए इस कानून से काफी उम्मीदें थीं और अभी तक के परिणाम पूरी तरह से उम्मीदों के अनुकूल नहीं रहे हैं। लेकिन आप यह भी देखिए कि पहली बार इस तरह का कानून बना है। एनपीए समस्या के लिए अभी तक जो कानून था, वह कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों या ग्राहकों की संपत्तियों को बेचने पर ध्यान देता था। अब अगर पांच फीसद भी उम्मीद है तो एनपीए घोषित हो चुकी कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ कर्ज रिकवरी पर ध्यान नहीं दे रहे बल्कि कंपनी को चलाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही सरकार की मंशा बेहद स्पष्ट है और वह तुरंत कदम भी उठा रही है। आइबीसी कानून में कई बार संशोधन किया जाना इसका उदाहरण है। कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन दो चीजों पर इसकी भावी सफलता तय होगी। पहला कि कर्ज देने वालों के स्तर पर भी तेजी से फैसला हो और दूसरा कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी हो। निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम दिखाई देंगे।

● अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है और आप हालात में कब तक सुधार होता देख रहे हैं?

-अभी हम जो मंदी देख रहे हैं उसके लिए कई वजहें जिम्मेदार हैं। पहला प्रभाव तो वैश्विक हालात का है। दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। इसके अलावा पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जीएसटी, आइबीसी जैसे बड़े कदमों का भी असर हुआ। ये बड़े कदम थे और इनका असर आने में वक्त लगता है। इसी बीच एनबीएफसी की समस्या सामने आ गई जिसने काफी असर डाला। आर्थिक विकास दर का एक चक्र भी होता है, यानी कुछ वर्षों बाद मंदी का एक दौर आता है। एक बैंकर के तौर पर मेरा अनुभव कहता है और मेरी रिसर्च टीम के शोध की मानें तो मांग में सुधार होने की तस्वीर बन रही है। यह त्योहारी सीजन काफी महत्वपूर्ण होगा। सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए काफी कदम उठाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। बैंकों की तरफ से कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। फंड की कोई समस्या नहीं है। मानसून भी बढ़िया रहा है, जिसका अच्छा असर होगा। उम्मीद है कि इन त्योहारों से हालात बेहतर होंगे। हमें साफ दिख रहा है कि मांग बढ़ने वाली है।

● यह कहा जाने लगा है कि आने वाले दिनों में बैंक तकनीकी कंपनियों में बदल जाएंगे। क्या एसबीआइ इसके लिए तैयार है?

-बैंकों में तकनीक का महत्व काफी बढ़ जाएगा लेकिन बैंक तकनीकी कंपनी तो नहीं बनेंगे। कम से कम भारत में तो यह नहीं होने जा रहा है। जहां तक एसबीआइ की बात है तो हम देश के सबसे मजबूत व अग्रिम तकनीक आधारित बैंक बनने की तरफ अग्रसर हैं। आप यह देखिए एसबीआइ अब ज्यादा बैंक खाते योनो एप के जरिये खोल रहा है। रोजाना 40-50 हजार नए ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। 1.25 करोड़ ग्राहक योनो के जरिये जुड़े हैं। अगले स्तर पर हम योनो के जरिये कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रहे है। प्रवासी भारतीयों के लिए भी योनो एप आधारित नई सेवा लांच करने जा रहे हैं। हम तकनीकी क्षेत्र में लीडर बने रहेंगे।

जागरूकता के दम पर बढ़ाया जाएगा निर्यात

उम्मीद ▸ एफटीए यूटिलाइजेशन मिशन से एमएसएमई क्षेत्र को होगा फायदा

व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली रियायतों को लेकर बढ़ेगी जागरूकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों के बेहतर इस्तेमाल से भारतीय निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। निर्यातकों का मानना है कि केंद्र सरकार ने इन समझौतों के तहत मिलने वाली रियायतों का लाभ लेने के लिए जो सिस्टम बनाने का एलान किया है, उससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। निर्यात संगठनों के फेडरेशन फियो का कहना है एफटीए यूटिलाइजेशन मिशन के गठन से निर्यातकों में विभिन्न समझौतों के तहत मिल रही शुल्क रियायतों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के प्रयासों के तहत शनिवार को निर्यातकों के लिए एक व्यापक पैकेज का एलान किया। इसके तहत अन्य घोषणाओं के साथ-साथ एक एफटीए यूटिलाइजेशन मिशन स्थापित किया जाना भी तय हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में स्थापित होने वाला मिशन फियो और अन्य निर्यात संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। इसका मुख्य ध्येय निर्यातकों खासतौर पर छोटे और मझोले मैन्यूफैक्चरर निर्यातकों के बीच शुल्क रियायतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना होगा।

दरअसल अभी तक छोटे और मझोले निर्यातक अनभिज्ञता के चलते विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। किस देश के साथ किस समझौते में किन उत्पादों पर किस तरह की रियायतें उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी नहीं होना अक्सर नुकसान का कारण बनता है। रियायतों का लाभ नहीं उठा पाने की वजह से भारतीय निर्यातक उन देशों के बाजार में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। फियो के प्रेसिडेंट शरद कुमार सराफ ने बताया कि फियो लंबे समय से ऐसी व्यवस्था बनाए जाने की मांग कर रहा था। निर्यातक और आयातक दोनों एफटीए के नियमों के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। इस सिस्टम के जरिये निर्यातकों को प्रत्येक एफटीए में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिलेगी, जिससे अंततः भारतीय निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फियो ने सरकार की तरफ से उठाए गए अन्य कदमों का स्वागत करते हुए कहा है कि एमईआइएस स्कीम को बदलने वाली नई स्कीम काफी आकर्षक है। इससे निर्यात उत्पादों पर लगने वाले सभी तरह के शुल्क का बोझ उठाने से निर्यातकों को राहत मिलेगी। साथ ही आइटीसी के इलेक्ट्रॉनिक रिफंड की व्यवस्था कायम हो जाने से निर्यातकों की वर्किंग कैपिटल की समस्या भी दूर होगी।

सराफ का मानना है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए जारी संशोधित प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के दिशानिर्देश निर्यातकों के लिए 36,000 करोड़ रुपये से 68,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी उपलब्ध कराएंगे। इससे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की स्थिति में सुधार होगा। फियो अध्यक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से ये राहत उस वक्त आई है, जब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ रहा है। इन स्थितियों में व्यापार समुदाय के लिए मध्यम से लेकर दीर्घकालिक उपायों की दरकार बन गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार के इन कदमों से निर्यात क्षेत्र को राहत मिलेगी।

एफटीए में मिली रियायतों की जानकारी नहीं होने से पिछड़ जाते हैं निर्यातक। प्रतीकात्मक फोटो

दिवाली से पहले वीवो लांच करेगी यू सीरीज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : त्योहारी सीजन में मोबाइल हैंडसेट बाजार में नए मॉडल लांच करने की होड़ मची है। रीयल मी के बाद वीवो ने भी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए नए मॉडल लांच करने की तैयारी कर ली है। कंपनी इस सीजन में अपनी यू सीरीज लांच करने जा रही है। इसके अलावा अगले सप्ताह कंपनी अपना वी17 प्रो भी लांच कर रही है।

भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए वीवो मोबाइल इंडिया ने व्यापक रणनीति तैयार की है। कंपनी के डायरेक्टर ब्रांड स्ट्रेटजी निपुण मार्या ने बताया कि अपने बजट फोन की श्रृंखला में कंपनी इस त्योहारी सीजन में एकदम नई यू सीरीज के हैंडसेट बाजार में उतारने जा रही है। इनकी कीमत 12000 रुपये से नीचे होगी। इस सीरीज को ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया जाएगा। खास बात यह है कि कंपनी के भारतीय बाजार में लांच होने वाले सभी मॉडल घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों में ही निर्मित हैं।

यू सीरीज के अतिरिक्त अगले सप्ताह कंपनी वी17 प्रो भी बाजार में उतार देगी। इसी महीने की शुरुआत में कंपनी वीवो जेड1एक्स भी बाजार में पेश कर चुकी है। इसकी कीमत 16999 रुपये से शुरू होती है। कुल मिलाकर कंपनी इस त्योहारी सीजन में करीब आधा दर्जन फोन उतारने की तैयारी में है। कंपनी मैन्यूफैक्चरिंग का विस्तार कर रही है। विस्तार के बाद उत्पादन क्षमता पांच करोड़ फोन बनाने की हो जाएगी।

एयर इंडिया को 4,600 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग लॉस

- बीते वित्त वर्ष में कच्चे तेल की ज्यादा कीमतों के कारण कंपनी को हुआ घाटा
- 2019-20 में कंपनी को 700 से 800 करोड़ रुपये के प्रॉफिट की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 4,600 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें कर्ज में डूबी विमानन कंपनी के घाटे की बड़ी वजह रहीं। हालांकि चालू वित्त वर्ष में कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट में आने की उम्मीद कर रही है।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 2018-19 में कंपनी का कुल राजस्व 26,400 करोड़ रुपये पर रहा। इस दौरान कंपनी का कुल घाटा करीब 8,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक अन्य अधिकारी का कहना है कि हाल के दिनों में तेल की कीमतों में स्थिरता के दम पर वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी को 700 से 800 करोड़ रुपये के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की उम्मीद है। रुपये में ज्यादा उठापटक नहीं होने से भी कंपनी को संभलने में मदद मिलेगी। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। अप्रैल से जून की अवधि में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस 175 से 200 करोड़ रुपये के करीब रहा। पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने से बढ़ी लागत के चलते कंपनी को यह घाटा उठाना पड़ा।

एयर इंडिया के विमान फिलहाल 41 अंतरराष्ट्रीय एवं 72 घरेलू रूट पर उड़ान भरते हैं। अधिकारी के मुताबिक, एयर इंडिया के लोड फैक्टर और यील्ड में सुधार हो रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति में इसलिए भी सुधार की उम्मीद है, क्योंकि कुछ महीनों में एयर इंडिया के बेड़े में फिर बड़े विमान शामिल होने वाले हैं। अभी एयर इंडिया ने अपने कई बड़े विमान (वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट) को मैंटेनेंस के लिए ग्राउंड किया हुआ है। इनमें से कई विमान फिर से उड़ान में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कंपनी दो नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने की तैयारी में है। 27 सितंबर को टोरंटो के लिए उड़ान शुरू की जाएगी, जबकि नवंबर में नैरोबी के लिए उड़ान की शुरुआत होगी। कंपनी पर 58,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। कर्ज चुकाना कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इस मद में कंपनी की सालाना देनदारी 4,000 रुपये से ज्यादा की बनती है। सरकार एयर इंडिया के विनिवेश की कोशिश में भी लगी है। एविएशन कंसल्टेंसी सीएपीए साउथ एशिया के सीईओ व डायरेक्टर कपिल कौल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। प्रदर्शन में सुधार से कंपनी के विनिवेश में भी मदद मिलेगी।

पीई निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है इन्फ्रास्ट्रक्चर

- रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर भी निवेशकों की नजर
- प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश में आए ढाई लाख करोड़ रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशकों के लिए देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पहली पसंद के रूप में उभर कर आया है। 2019 के पहले आठ महीने के पीई व वीसी निवेश के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में सर्वाधिक निवेश इसी सेक्टर में प्राप्त हुआ है। वैसे इन आठ महीनों में देश में पीई व वीसी निवेश ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है।

प्राइवेट इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल (वीसी) निवेश पर ईवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त की समाप्ति तक इन निवेशकों ने देश में 36.7 अरब डॉलर (करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये) का निवेश किया है। इनकी तरफ से भारत में होने वाले निवेश के मामले में यह अब तक का सर्वाधिक है। 2018 के पहले आठ महीने में इन निवेशकों ने 36.5 अरब डॉलर (करीब 2.59 लाख करोड़ रुपये) का निवेश किया था। 2019 के अंत तक निवेश 48 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह के निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आया है। पहले आठ महीने में आए कुल निवेश का 35 फीसद हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की परियोजनाओं को मिला है। रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पर पेंशन और सॉवरेन फंडों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर आकर्षण का केंद्र है और इसके फिलहाल आगे भी बने रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अगस्त के महीने में देश में पीई और वीसी निवेश के 4.4 अरब डॉलर (करीब 31,250 करोड़ रुपये) के 82 एग्रीमेंट हुए। पिछले साल के मुकाबले निवेश के लिहाज से यह 39 परसेंट अधिक है। 2018 के अगस्त में 3.9 अरब डॉलर (करीब 27,700 करोड़ रुपये) के 59 एग्रीमेंट हुए थे।

अगस्त में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 80.3 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) का निवेश हुआ। इसके बाद 76.4 करोड़ डॉलर (करीब 5,425 करोड़ रुपये) का निवेश रियल एस्टेट सेक्टर को मिला। तीसरे स्थान पर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर रहा जिसके हिस्से 73.4 करोड़ डॉलर (करीब 5,210 करोड़ रुपये) का निवेश आया।

बिजली वितरक फर्मों पर 73 हजार करोड़ रुपये का बकाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष में बिजली वितरक कंपनियों (डिस्कॉम्स) के कर्ज में बड़ा इजाफा हुआ है। जुलाई में यह 57 परसेंट की दर से बढ़कर 73,748 करोड़ रुपये हो गया है। 'प्राप्ति' पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने में बिजली उत्पादकों पर वितरकों का कुल बकाया 46,779 करोड़ रुपये था।

प्राप्ति पोर्टल मई, 2018 में लांच किया गया था। इसका मकसद बिजली खरीद और वितरण में पारदर्शिता लाना था। इस वर्ष 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलने के बाद भी उत्पादकों को उनका बकाया नहीं लौटाया गया है। ग्रेस पीरियड में बकाया नहीं चुकाने पर ज्यादातर मामलों में उत्पादक इस पर दंडात्मक ब्याज वसूलते हैं। इससे पहले सरकार ने पहली अगस्त से बिजली उत्पादकों को राहत देते हुए एक पेमेंट सेक्यूरिटी मैकेनिज्म लागू किया था। इसके मुताबिक बिजली वितरकों को बिजली सप्लाई बरकरार रखने हेतु जरूरी क्रेडिट प्राप्त करने के लिए ओपन लेटर देना था। पोर्टल के मुताबिक राजस्थान, बिहार, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बिजली वितरकों पर बिजली उत्पादकों का सबसे ज्यादा बकाया है।

जोखिम के दौर में आइपीओ मार्केट में कदम रखने से बच रही हैं कंपनियां

10300 करोड़ रुपये जुटाए हैं आइपीओ से 2019 में अब तक 11 कंपनियों ने

68000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आइपीओ लाई थीं 2017 में कुल 36 कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस वर्ष अब तक आइपीओ मार्केट में सूखे का दौर रहा है। साल खत्म होने में सिर्फ तीन महीने बाकी हैं और अब तक कुल 11 कंपनियां ही कैपिटल मार्केट में आइपीओ (इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग) लेकर आई हैं। इन 11 कंपनियों ने करीब 10,300 करोड़ रुपये शुरुआती शेयरों की बिक्री से हासिल किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है। पिछले साल कुल 24 कंपनियों ने शेयर मार्केट में कदम रखा था और आइपीओ से 30,959 करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे पहले 2017 में 36 कंपनियां आइपीओ मार्केट में उतरी थीं और रिकॉर्ड 68,000 करोड़ रुपये जुटाए थे।

जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में बाजार जोखिम को देखते हुए आइपीओ बाजार सूना रहने के आसार हैं। रिलायंस सेक्यूरिटीज में रिसर्च प्रमुख नवीन कुलकर्णी के मुताबिक, मिड और स्माल कैप स्टॉक के मूल्य निर्धारण में तेज बदलाव के चलते प्राइमरी मार्केट सकते में है। इसकी वजह से आगे भी आइपीओ बाजार में सुस्ती का दौर जारी रहेगा।

मोतीलाल ओसवाल इंवेस्टमेंट के ईडी मुकुंद रंगनाथन कहते हैं कि आइपीओ मार्केट के सुस्त होने के पीछे कई कारण हैं। पिछले 12 से 18 महीनों में शेयर मार्केट में निवेशकों की रुचि कम हुई है। इसका असर आइपीओ पर भी पड़ा है। इसके अलावा पिछले वर्ष 90 से अधिक कंपनियों ने आइपीओ के लिए आवेदन किया था, जिसमें से बहुत कम कंपनियों को आइपीओ के लिए मंजूरी मिली थी। इस वजह से कंपनियां आइपीओ की जगह पर दूसरे तरीकों से फंड जुटाने में अधिक भरोसा दिखा रही हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

जनरल इंश्योरेंस के लिए एसबीआइ नहीं लाएगा आइपीओ

लेह, प्रेट्र : एसबीआइ ने कहा है कि वह अपने जनरल इंश्योरेंस के लिए आइपीओ नहीं लाएगी। इससे पहले कंपनी ने आइपीओ लाने की बात कही थी। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि कंपनी को अतिरिक्त फंड की जरूरत नहीं है। एसबीआइ कार्ड में निवेशकों की रुचि बनी हुई है और मार्च में इसकी लिस्टिंग की जाएगी। इससे पहले बैंक ने कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में अपने जनरल इंश्योरेंस के लिए आइपीओ के जरिये फंड जुटाएगा। एसबीआइ ने जनरल इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। मौजूदा समय में कंपनी की वैल्यू 12,000 करोड़ रुपये है।

कोल मंत्रालय में संयुक्त सचिव संग वार्ता विफल

जागरण संवाददाता, धनबाद : कोल मंत्रालय में श्रम संगठनों की ओर से 24 मई को प्रस्तावित हड़ताल को टालने की कोशिश विफल हो गई है। हड़ताल टालने के लिए नई दिल्ली स्थित कोल इंडिया स्कोप भवन में कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष उपाध्याय के साथ पांच श्रम संगठनों के साथ उच्चस्तरीय वार्ता रखी गई थी। हालांकि वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकल सका।

वार्ता विफल होते ही बैठक में शामिल रहे श्रम संगठनों इंटक, एचएमएस, सीटू, एटक व एक्टू ने कार्यकर्ताओं से 24 सितंबर को कोल सेक्टर में प्रस्तावित हड़ताल की तैयारी में जुट जाने की अपील की। श्रम संगठनों ने कहा कि समय आ गया है कि मजदूर अब सरकार को अपनी एकता का परिचय कराएं। मजदूरों की ताकत का एहसास होने के बाद ही सरकार उनकी मांगों के सामने झुकेगी।

बैठक में कोल मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती, कोल इंडिया के डीपी आरपी श्रीवास्तव, बीसीसीएल के डीपी आरएस महापात्रा, ईसीएल डीपी विनय रंजन, श्रम संगठनों में एटक से रमेंद्र कुमार, एचएमएस से नाथू लाल पांडेय, सीटू से डीडी रामानंदन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शेयर समीक्षा

सऊदी अरब द्वारा तेल उत्पादन में कटौती से एनर्जी स्टॉक को हो सकता है नुकसान, निर्यात को बढ़ावा देने और हाउसिंग सेक्टर की मदद का होगा सकारात्मक असर

वैश्विक गतिविधियों पर बनी रहेगी निवेशकों की निगाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह इक्विटी मार्केट पर ग्लोबल डेवलपमेंट और थोक मंहगाई के आंकड़ों का असर दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा इकोनॉमी को गति देने के लिए तीसरी बार की गई घोषणाओं का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की थी। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी 30,000 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की गई है। सरकार लगातार सुधार की घोषणाओं से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह इकोनॉमी को गति देने के लिए प्रयासरत है। हाउसिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर की मदद से बड़े स्तर पर रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाले सेक्टरों में शामिल हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने अधूरे पड़े फ्लैट्स के लिए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा को सराहनीय कदम बताया है। ग्लोबल फ्रंट पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से भारतीय बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं। यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के तेल प्लांट पर हुए हमले से अरब का तेल उत्पादन घटकर लगभग आधा रह गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के आसार हैं। इससे भारत का एनर्जी सेक्टर भी प्रभावित होगा। इस समय कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर कुछ नए डेवलपमेंट होने हैं। सोमवार को थोक मंहगाई के आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम कहते हैं कि इस सप्ताह हमारे पास काफी चीजें है जिन पर निवेशकों की नजर रहेगी। इनमें थोक मंहगाई के आंकड़े, ट्रेड वार, ऑयल मार्केट शामिल हैं। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी बाजार को प्रभावित करेगी।

एफपीआइ ने भारतीय बाजारों में दिखाई रुचि : अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार में नरमी और सरकार की ओर से सुधार के प्रयासों का असर पूंजी बाजार पर दिखने लगा है। इस महीने के पहले हाफ में एफपीआइ ने पूंजी बाजार में 1,841 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे पहले पिछले दो महीने से एफपीआइ नेट सेलर बने हुए थे।

ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के मुताबिक एफपीआइ ने तीन से 13 सितंबर के बीच इक्विटी मार्केट से कुल 2,031.02 करोड़ रुपये निकाले, जबकि डेट सेग्मेंट में 3,872.19 करोड़ रुपये निवेश किए। इस तरह से पूंजी बाजार में कुल 1,841.17 करोड़ रुपये का इनफ्लो दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पिछले महीने में एफपीआइ ने पूंजी बाजार से कुल 5,920.02 करोड़ रुपये निकाले थे। जुलाई में विदेशी निवेशकों ने 2,985.88 करोड़ रुपये खींच लिए थे। ग्रॉव के सीओओ हर्ष जैन के मुताबिक अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वार खत्म होने के संकेतों का बाजार पर सकारात्मक असर रहा।

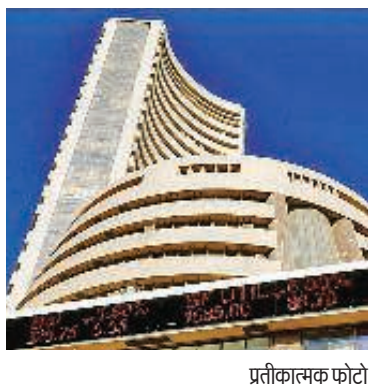

प्रतीकात्मक फोटो

छह बड़ी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में इजाफा

पिछले सप्ताह सेंसेक्स की टॉप 10 में से छह कंपनियों ने सम्मिलित रूप से अपने बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 50,580 .35 करोड़ रुपये का इजाफा किया। इसमें बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियां एसबीआइ और आइसीआइसीआइ सबसे ऊपर रहीं।

इस दौरान जिन कंपनियों के मार्केट कैप में इजाफा हुआ उनमें आरआइएल, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। दूसरी ओर टीसीएस, इन्फोसिस और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई। पिछले सप्ताह सरकारी क्षेत्र के बैंक एसबीआइ के बाजार पूंजीकरण में 15,841 .19 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। एसबीआइ का कुल बाजार पूंजीकरण 2,60,330 .92 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा।

स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की हालत सुधारेगी सरकार

- कर्ज के भुगतान की अवधि बढ़ाने पर विचार, कंपनी को वित्तीय मदद भी दे सकती है सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार सार्वजनिक उपक्रम स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) की माली हालत सुधारने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार कंपनी को वित्तीय मदद भी उपलब्ध करा सकती है।

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एसटीसी को मदद देने के लिए एक विकल्प उसके कर्जों के भुगतान में रियायत देना भी शामिल है। एक अधिकारी के मुताबिक, एसटीसी को बैंकों का कर्ज चुकाने की अवधि को बढ़ाए जाने की छूट देने के साथ-साथ उसे संपत्तियां बेचने का अधिकार देने संबंधी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एसटीसी को अपने 500 करोड़ रुपये के कर्ज की अदायगी के लिए पांच वर्ष का वक्त मिल सकता है। ऐसा करने के साथ-साथ बैंकों से एसटीसी पर एनसीएलटी में दायर मुकदमा वापिस लेने को भी कहा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2018-19 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सभी लेनदार बैंकों ने खातों को एनपीए घोषित कर दिया है। कंपनी अपने कर्जों पर ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पा रही है। इसके चलते कंपनी को लिक्विडिटी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कंपनी के पास किसी भी प्रकार की बैंक लिमिट नहीं है।

2018-19 में एसटीसी को 881 करोड़ का घाटा हुआ है

44 शव मिले हैं मेक्सिको के जलिस्को प्रांत में एक कुएं से। शवों को टुकड़ों में काटकर बोरों में बंद किया गया था। बीबीसी में आई रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों की सूचना पर इसी महीने प्रशासन ने इन शवों को बरामद किया था।

2047 के बाद हांगकांग का भविष्य!

हांगकांग में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन एक विवादित प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ शुरू हुए थे। धीरे-धीरे इस विरोध ने लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की शक्ल ले ली। कुछ दिन पहले वहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रगान गाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप से चीनी सत्ता से मुक्ति दिलाने की गुहार भी लगाई है। ऐसे में आजादी के लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के मन में एक आशंका यह भी उमड़-घुमड़ रही है कि 2047 के बाद स्वायत्तता खोने पर इस क्षेत्र का भविष्य क्या होगा? पूरे मामले पर एक नजर:

ब्रिटेन-चीन समझौता

1984 में ब्रिटेन-चीन समझौते के तहत ब्रिटेन ने एक देश, दो प्रणाली के तहत 1997 में चीन को हांगकांग सौंपा था। इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हांगकांग 50 वर्षों यानी साल 2047 तक विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत्तता का आनंद लेगा।

खत्म होगी स्वायत्तता: दोनों देशों के बीच हुए समझौते के समय ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई गई, जिससे स्वायत्तता को बचाया जा सके। इसका मतलब 70 लाख आबादी वाला हांगकांग विशेष स्वायत्त क्षेत्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता अगले 28 साल बाद खो देगा। तब हांगकांग के भाग्य का फैसला चीनी कम्युनिस्ट सरकार के पास चला जाएगा।

चीन का रुख

2017 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यक्रम में यह संकेत दिया था कि हांगकांग में एक देश, दो प्रणाली का सिद्धांत कभी बदला नहीं जाएगा।

कारोबार के लिहाजा से फायदेमंद

हांगकांग के विशिष्ट प्रशासन ने इसे चीन में विदेशी निवेश का प्राथमिक प्रवेश द्वार बनाने में मदद की, क्योंकि कई वैश्विक कंपनियां भूमि के नियामकों और कानूनी प्रणाली पर भरोसा नहीं करती हैं। व्यापार के उद्देश्य से अमेरिका हांगकांग को शेष चीन से खास मानता है। इसलिए चीनी वस्तुओं पर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से हांगकांग अछूता है। दोनों प्रमुख दलों के अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि अगर चीन हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करता है तो वे हांगकांग की विशेष स्थिति पर पुनर्विचार करेंगे।

अन्य विकल्प क्या हैं

स्वायत्तता खत्म होने के बाद : हांगकांग औपचारिक रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल हो सकता है और चीन के शेनजेन जैसे कुछ क्षेत्रों को मिले विशेष अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। हालांकि, उन क्षेत्रों के विशेषाधिकार लोकतांत्रिक शासन या स्वतंत्र न्यायपालिका के बजाय व्यापार और कारोबार से संबंधित हैं।

2047 तक स्वायत्ता पर संशय: जोनाथन रॉबिसन ने सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक लेख में लिखा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो चीन के लिए कई तरह से काम करती है, जिसमें एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में हांगकांग की स्थिति को कम करना भी शामिल है। चीन यह व्यवस्था बनाये रखना चाहता है क्योंकि इसे ताइवान के एकीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में भी देखा जाता है। उनका तर्क है कि एक देश, दो प्रणाली को उदार लोकतंत्र के लिए एक ढांचे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

जनता का रुख

चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। कई साल से वहां की जनता आंदोलनों के जरिये चीनी सत्ता से आजादी की मांग कर रही है।

अमेरिका ने ढेर किए तालिबान के 90 आतंकी

काबुल, एएनआइ : अमेरिका ने शांति वार्ता रद करने के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। उसने अफगान बलों के साथ संयुक्त अभियान में तालिबान के करीब 90 आतंकियों को ढेर कर दिया। 20 आतंकियों के घायल होने की भी खबर है।

अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांत पकतीका में रविवार को तालिबान के खिलाफ संयुक्त आतंक रोधी अभियान चलाया गया था। इस अभियान में अमेरिका ने हवाई हमले से अफगान बलों की मदद की थी। अफगान नेशनल आर्मी कॉर्प के प्रवक्ता ने बताया कि संयुक्त अभियान के दौरान 90 आतंकी मारे गए और 20 घायल हुए। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की 23बाइक, एक ट्रैक्टर और कई हथियार भी तबाह कर दिए।

सऊदी तेल संयंत्रों पर हमले से तनाव

ठकराव के आसार ▸ अमेरिका ने हमले के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार

जवाब में तेहरान ने चेताया, अमेरिकी सैन्य अड्डे और पोत हमारे निशाने पर

दुबई, रायटर : सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको के दो संयंत्रों पर ड्रोन हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर ईरान के विशिष्ट सुरक्षा बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक शीर्ष कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका मुल्क युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका के सैन्य अड्डे और विमानवाहक पोत ईरानी मिसाइलों की जद में हैं। सऊदी अरब के तेल प्लांट पर शनिवार को हुए हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने ली थी।

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने रविवार को रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर एयरोस्पेस फोर्स के प्रमुख अमीरली हाजीजादेह के हवाले से कहा, 'हर कोई जानता है कि ईरान के दो हजार किलोमीटर के दायरे में अमेरिकी सैन्य अड्डे और उनके विमानवाहक पोत हैं। इसलिए वे हमारी मिसाइलों की जद में हैं। जब चाहेंगे, उन्हें मार गिराएंगे। तेहरान युद्ध के लिए हमेशा तैयार है।' इसके पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने सऊदी तेल संयंत्रों पर हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया था।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

हसन रुहानी। फाइल

परमाणु करार टूटने से शुरू हुआ तनाव : पिछले साल मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने का एलान किया था। इसके बाद उस पर कई सख्त प्रतिबंध थोप दिए थे। तब से दोनों देशों में तनाव गहराता जा रहा है।

अरैमको ने भारत में आपूर्ति प्रभावित नहीं होने का भरोसा दिलाया

रियाद, रायटर : यमन के हाउती विद्रोहियों के ड्रोन हमले का शिकार हुई सऊदी अरब की तेल कंपनी अरैमको ने भारत में तेल आपूर्ति प्रभावित नहीं होने का भरोसा दिलाया है। सूत्रों के अनुसार, अरैमको ने एक भारतीय रिफाइनरी को बताया कि हमले के कारण तेल आपूर्ति पर तत्काल कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरैमको की अबकैक स्थित ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी और खुरैश स्थित बड़ी ऑयल फील्ड को शनिवार को ईरान समर्थित यमन के हाउती विद्रोहियों ने ड्रोन से निशाना बनाया था। अबकैक फैसिलिटी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। बताया जा रहा है कि इस हमले से अरैमको की उत्पादन क्षमता आधी रह गई है। कंपनी को नुकसान की भरपाई में समय लगेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने इस हमले की निंदा करते हुए आशंका जताई कि इससे वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। जानकारों का मानना है कि हमलों के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई के करीब छह फीसद हिस्से पर असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल अरैमको बाजार को यह भरोसा दिलाने की कोशिश में जुटी है कि हमलों के बावजूद कंपनी के तेल उत्पादन पर बहुत असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। अगर कंपनी यह भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि वह हमले से हुए नुकसान की भरपाई जल्द कर लेगी, तो तेल की कीमतों में वृद्धि पर अंकुश लग सकता है। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि सऊदी के पास ग्राहकों की मांग के अनुरूप पर्याप्त तेल जमा है, इसलिए आपूर्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ने देगी। फिलहाल सऊदी सरकार ने पत्रकारों को हमले वाली जगह पर जाने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण से वास्तविक स्थिति साफ नहीं हो पाई है।

पश्चिम एशिया में तैनात किए विमानवाहक पोत : अमेरिका ने ईरान की ओर से होने वाले किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए पश्चिम एशिया में अपने विमानवाहक पोत और कई युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। इस क्षेत्र में उसने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। अमेरिका ने बमवर्षक विमान भी तैनात कर रखे हैं।

हांगकांग में फिर बवाल, चले आंसू गैस के गोले और पेट्रोल बम

▸ आमने-सामने हैं लोकतंत्र समर्थक और पुलिस, प्रशासन ने दी चेतावनी

▸ विधानमंडल भवन और केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने किया घुसने का प्रयास

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में रविवार को लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर टकराव हुआ। स्वायत्त क्षेत्र के विधानमंडल भवन और केंद्रीय कार्यालय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो टकराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठी-डंडों के साथ आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार छोड़ी तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और पेट्रोल बम चलाए। सूचना है कि कुछ पेट्रोल बम कार्यालय परिसर के भीतर भी गिरे। इस बीच आंदोलनकारियों ने लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन में ब्रिटेन से मदद मांगी है। उल्लेखनीय है कि 1997 में समझौते के तहत हांगकांग ब्रिटेन से चीन को मिला है।

कुछ प्रदर्शनकारी हांगकांग स्थित चीनी सेना के अड्डे के नजदीक पहुंच गए, वहां उन्होंने पेट्रोल बम फेंके। उस लाल बैनर को नीचे गिराकर आग लगा दी जिसमें एक अक्टूबर को चीन गणराज्य की 70 वीं वर्षगांठ पर समारोह मनाने की सूचना लिखी थी। एक स्थान पर नीले पानी की बौछार कर रही वाटर मशीन पर फेंके गए पेट्रोल बम से आग लग गई, इसके बाद वहां मौजूद फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। रविवार को कई स्थानों पर भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अपनी गैरकानूनी गतिविधियां बंद करने की चेतावनी दी है। एकजुट लोकतंत्र समर्थकों की गतिविधियों को रोकने के लिए रविवार को चीन समर्थक गुट नहीं दिखे। हांगकांग में चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि करने के प्रस्ताव के विरोध में तीन महीने पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद उसके साथ चार अन्य मांगें भी जुड़ गईं। इनमें सबसे प्रमुख मांग हांगकांग में लोकतंत्र की मांग है जिसके तहत स्वायत्त क्षेत्र में हांगकांग का ही निवासी चुनाव लड़कर शासन करेगा। चीन इस मांग को अपने मूलभूत ढांचे पर प्रहार मानता है और इसके लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के आंदोलनकारियों के समर्थन को जिम्मेदार मानता है।

हजारों लोकतंत्र समर्थकों ने ब्रिटेन का सहयोग चाहने के लिए रविवार को हांगकांग स्थित ब्रिटिश दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी चीन से आजादी की मांग पर अडिग हैं। एएफपी

पीआइए के विमान की आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइए) के विमान के एक इंजन में उड़ान भरते ही आग लग गई, लेकिन गनीमत रही कि पायलट ने हालात को काबू करते हुए विमान को सुरक्षित तरीके से उतार दिया। इस दौरान विमान में सवार लगभग दो सौ यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। विमान लाहौर से जेद्दा जा रहा था। उसने रविवार की सुबह लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी टेकऑफ किया ही था कि उसके एक इंजन में आग लग गई। एक अधिकारी के मुताबिक पायलट ने स्थिति से कंट्रोल रूम को अवगत कराया और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। बाद में वह विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराने में सफल रहा। इस दौरान किसी यात्री को चोट नहीं आई। यात्रियों को एक दूसरे विमान से दोपहर जेद्दा भेजा गया। पीआइए के प्रवक्ता मसूद तजवर ने हालांकि दावा किया कि विमान में आग नहीं लगी थी। उन्होंने कहा कि एक तकनीकी खराबी के चलते विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। कुछ सप्ताह पहले पीआइए को पक्षी के टकरा जाने के कारण लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी।

हल्क से तुलना कर जॉनसन बोले, पूरा करेंगे ब्रेक्जिट

▸ पीएम बोरिस ने किया बड़ी सफलता मिलने का दावा

▸ कहा- बिना समझौते के ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से लाएंगे बाहर

लंदन, रायटर : ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कॉमिक बुक हीरो हल्क से खुद की तुलना करते हुए कहा कि वह सब कुछ ठीक करते हुए 31 अक्टूबर को ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर लाएंगे। उन्होंने ब्रेक्जिट मामले में बड़ी सफलता मिलने का दावा भी किया।

द मेल को दिए साक्षात्कार में जॉनसन ने कहा कि ब्रेक्जिट को टालने के हाल के संसद के आदेश को दरकिनार करते हुए वह बिना समझौते के ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर लाएंगे। जिस तरह से हल्क हर मुश्किलों से बचते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी तरह से वह हर बाधा को पार करते हुए 31 अक्टूबर को ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा करेंगे। संसद ने जॉनसन की पूर्ववर्ती टेरीजा मे के पेश किए समझौते के तीन प्रस्तावों को खारिज किया था। इसके बाद सत्ता संभालने वाले जॉनसन ने संसद को दरकिनार करते हुए बिना शर्त ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरी करने की रणनीति बनाई। इसी सिलसिले में संसद को करीब एक महीने के लिए निलंबित किया गया। लेकिन निलंबन शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष के 21 सांसदों के साथ मिलकर बिना शर्त ब्रेक्जिट पर रोक लगाने का कानून बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जॉनसन अभी भी 31 अक्टूबर को ही ब्रेक्जिट के अपने एलान पर डटे हुए हैं, भले ही वह बिना शर्त हो। जॉनसन ने ब्रेक्जिट से पहले देश में चुनाव कराने की कोशिश की थी लेकिन विपक्ष ने उनके प्रस्ताव का विरोध कर उसे खारिज कर दिया था। संसद में बहुमत खो चुके जॉनसन 31 अक्टूबर को ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरी कर हीरो हल्क की तरह चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में हैं।

बोरिस जॉनसन। फाइल

शर्तों का मसौदा तैयार कर रही सरकार : जॉनसन सरकार में गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा है कि सरकार 31 अक्टूबर को ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरी करने के लिए शर्तों का मसौदा तैयार कर रही है। यह मसौदा मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद लागू किया जा सकता है।

भारत-पाक तनाव से 'तापी' पर नहीं होगा असर

▸ पाकिस्तान ने इस संबंध में तुर्कमेनिस्तान को दिया आश्वासन

▸ दस अरब डॉलर के प्रोजेक्ट से हर दिन 1.3 अरब घन फीट गैस मिलेगी

इस्लामाबाद, आइएएनएस : पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि कश्मीर को लेकर भारत-पाक के बीच बढ़े तनाव का असर तापी (तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत) और अन्य गैस पाइपलाइन परियोजनाओं पर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस संबंध में तुर्कमेनिस्तान को आश्वासन दिया है। दस अरब डॉलर की तापी परियोजना से भारत और पाकिस्तान को प्रतिदिन 1.3 अरब घन फीट गैस मिलेगी।

पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाकिस्तान के एक अफसर के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान को तापी और अन्य बड़ी परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ने का भरोसा दिलाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कितना भी तनाव बढ़ जाए लेकिन तापी पाइपलाइन परियोजना पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। इस बीच, तापी गैस पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी ने भूमिगत गैस भंडारण की भी योजना बनाई है। ताकि लोड मैनेजमेंट के जरिए ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स (आइएसजीएस) कंपनी तापी समेत नार्थ-साउथ पाइपलाइन और ऑफशोर गैस पाइपलाइन जैसी कुछ बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है। तापी परियोजना के जरिए मध्य और दक्षिण एशिया को जोड़ा जा सकेगा। यह पाइपलाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक पहुंचेगी। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली यह पाइपलाइन क्षेत्र में शांति और स्थिरता को सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना के जरिए दोनों क्षेत्रों को सड़क, रेल और फाइबर केबिल के जरिए जोड़ा जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि इस गैस पाइपलाइन के लिए तुर्कमेनिस्तान में निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। तुर्कमेन-अफगान सीमा से लेकर हेरत क्षेत्र तक जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान में इससे संबंधित निर्माण कार्य वर्ष 2020 की पहली तिमाही में शुरू होगा। अधिकारी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि तापी कंपनी का प्रतिनिधिमंडल अगले महीने परियोजना के कार्यों पर प्रगति देखने के लिए आएगा और निर्माण की योजना को अंतिम रूप देगा।

इमरान खान। फाइल

पाक की यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई नहीं करेंगे छात्र-छात्राएं

इस्लामाबाद, प्रेट्र : बार-बार मानवाधिकार की दुहाई देने वाले नापाक पड़ोसी पाकिस्तान का लिंगभेद विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय ने कक्षा में छात्र-छात्राओं के एक साथ बैठने पर पाबंदी लगा दी है। यहां तक कि शैक्षणिक समूह में भी छात्र-छात्राओं को एक साथ रखने पर रोक लगा दी गई है।

जियो न्यूज के अनुसार, बाहरिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव की तरफ से जारी अधिसूचना में विवि के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि छात्र-छात्राओं की छुट्टी का समय अलग-अलग रखें। अधिसूचना में विवि के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, 'यह सुनिश्चित करें कि छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय के एक भवन से दूसरे भवन में कम से कम आना-जाना करें।'

विश्वविद्यालय ने कक्षाओं के दौरान दिए जाने वाले ब्रेक को भी खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि बाहरिया विश्वविद्यालय का यह आदेश पूरे पाकिस्तान में स्थित इसके सभी कैंपसों पर लागू होगा या यह किसी खास कैंपस या शहर के लिए जारी किया गया है।

नवाज को मुकेश के गीतों का संग्रह उपलब्ध कराए सरकार : राशिद

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने कहा कि सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक टेप रिकार्डर और भारत के दिवंगत गायक मुकेश के गीतों का संग्रह उपलब्ध कराए। पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल कैद की सजा हुई है और अभी वह लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं।

69 वर्षीय शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल मामले में दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा पेपर्स मामले में सात साल जेल की सजा सुनाई थी। 24 दिसंबर 2018 से वह अपनी सजा भुगत रहे हैं। जुलाई में अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी डायसपोरा से कहा था कि वह पाकिस्तान लौटने के बाद सुनिश्चित करेंगे की शरीफ को जेल में एयर कंडीशन या टीवी मुहैया नहीं कराया जाए।

शरीफ को एयरकंडीशन मुहैया कराने के सवाल के जवाब में राशिद ने कहा, 'मैं नवाज और किसी अन्य से एयर कंडीशनर वापस लेने के समर्थन में नहीं हूं। मैं तो नवाज और अन्य कैदियों को मुकेश के गाने और रिकॉर्डर उपलब्ध कराने के पक्ष में हूं।'

जासूसी की आशंका में अमेरिका के निशाने पर चीनी ट्रेन निर्माता कंपनी

न्यूयॉर्क टाइम्स से

शिकागो : अमेरिका में अपना संयंत्र लगाने वाली चीन की ट्रेन निर्माण कंपनी जासूसी के शक के दायरे में आ गई है। इसके चलते अमेरिका में उसके कारोबार पर आशंका के बादल मंडराने लगे हैं। जासूसी की आशंका को लेकर अमेरिकी संसद से एक ऐसा बिल पारित कराने की तैयारी चल रही है, जिससे इस कंपनी को अमेरिका में ट्रेन निर्माण का कोई नया कांट्रैक्ट नहीं मिल सकेगा।

अमेरिकी संसद से यह बिल जल्द ही पारित होने की संभावना जताई जा रही है। बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं का हवाला दिया गया है। यह माना जा रहा है कि इस प्रयास को राष्ट्रपति भवन ह्वाइट हाउस का समर्थन प्राप्त है। इस बिल के पारित होने से चीन की सरकारी ट्रेन निर्माता कंपनी सीआरआरपी कॉर्प के लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो जाएगा। यह माना जा रहा है कि ऐसा होने से अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी जंग और तेज हो सकती है।

अमेरिकी संसद में जल्द पेश किया जाएगा बिल। फाइल

▸ सीआरआरपी कॉर्प को कांट्रैक्ट पाने से रोकने के लिए संसद से बिल पारित कराने की तैयारी

सांसदों ने जताई आशंका

संसद में बिल पेश करने वाले टैमी बाल्डविन और दूसरे सांसदों ने यह आशंका जताई है कि ट्रेन निर्माण के जरिये चीन के लिए अमेरिकियों की जासूसी करना आसान हो सकता है।

चीनी कंपनी ने शिकागो में लगाया प्लांट

सीआरआरपी कॉर्प की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन निर्माता कंपनियों में होती है। इस चीनी कंपनी ने इसी साल शिकागो में दस करोड़ डॉलर (करीब सात सौ करोड़ रुपये) की लागत से अपना प्लांट स्थापित किया है। उसे उम्मीद है कि अमेरिका के शिकागो और वाशिंगटन के लिए सबवे कार और यात्री ट्रेन बनाने का कांट्रैक्ट मिलेगा।

हुआवे पर लगाया प्रतिबंध : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी उत्पादों के प्रति पहले से ही सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगा रखा है। ट्रंप प्रशासन चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे पर संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकी पाने पर रोक भी लगा चुका है।

भारतवंशी दंपती के दान से अमेरिका में खुला मेडिकल कॉलेज

फ्लोरिडा, आइएएनएस : भारतवंशी चिकित्सक दंपती किरन सी पटेल व पल्लवी पटेल के रिकॉर्ड 25 करोड़ डॉलर (करीब 1775 करोड़ रुपये) के दान से अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में तैयार मेडिकल कॉलेज की विधिवत शुरुआत शनिवार को हो गई। किसी भारतवंशी द्वारा अमेरिका में दिया गया यह अभी तक का सबसे बड़ा दान है। शनिवार को नोवा साउथ-ईस्टर्न यूनिवर्सिटी (एनएसयू) के तंपा बे स्थित नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन डॉक्टर दंपती के हाथों किया गया। जांबिया में जन्मे व भारत में पढ़ाई किए डॉक्टर किरन पटेल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। पत्नी डॉक्टर पल्लवी पटेल बाल रोग स्पेशलिस्ट हैं।

नया मेडिकल कॉलेज तीन लाख वर्ग फीट के कैंपस में बनाया गया है, जो एनएसयू के चार अन्य कॉलेजों का सेटेलाइट केंद्र भी बनेगा। इनमें दंपती के नाम पर बने डॉक्टर पल्लवी पटेल कॉलेज ऑफ हेल्थकेयर साइंसेज और डॉक्टर किरन सी पटेल कॉलेज ऑफ ओस्टियोपैथिक मेडिसिन शामिल हैं। इस मौके पर किरन पटेल ने कहा, 'दुनिया में इस तरीके से योगदान देने का अवसर प्राप्त होना निराला है। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने को सक्षम होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है।'

अमेरिकी डॉक्टर के घर से मिले दो हजार भ्रूण के अवशेष

▸ गर्भपात कराने वाले चिकित्सक के घर से इतनी बड़ी संख्या में भ्रूण मिलने से हर कोई हैरान

▸ जांच करने वाले अधिकारियों को डॉक्टर के घर पर गर्भपात किए जाने का नहीं मिला कोई प्रमाण

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका के इलिनोइस राज्य में गर्भपात कराने वाले एक डॉक्टर के घर से दो हजार से ज्यादा भ्रूण के अवशेष मिले हैं। इतनी बड़ी संख्या में भ्रूण मिलने से हर कोई हैरान है। जिस डॉक्टर के घर से यह बरामदगी हुई है, वह अब इस दुनिया में नहीं है।

इलिनोइस के विल काउंटी निवासी डॉक्टर उलरिच क्लोफर के घर से भ्रूण बरामद किए गए हैं। उनका गत तीन सितंबर को निधन हो गया। काउंटी के शेरिफ दफ्तर ने बताया कि घर में भ्रूण मिलने पर डॉक्टर उलरिच क्लोफर के पारिवारिक वकील ने अधिकारियों से संपर्क किया था। इसके बाद क्लोफर के घर पर पहुंचे अफसरों ने संरक्षित कर रखे गए 2,246 भ्रूण बरामद किए।

हालांकि उलरिच के घर पर गर्भपात किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इंडियाना राइट टू लाइफ संगठन के अध्यक्ष माइक फिशर ने कहा, 'क्लोफर के घर से इतनी बड़ी संख्या में भ्रूण मिलने से हम सहम गए हैं। इससे यह जाहिर होता है कि अमेरिका में गर्भपात उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि गर्भपात उलरिच के घर पर ही हुआ है तो यह और भी चिंताजनक स्थिति होगी।

क्लीनिक का रद किया गया था लाइसेंस : क्लोफर इंडियाना राज्य के साउथ बेंड में क्लीनिक चलाते था। प्रांतीय सरकार ने उसके क्लीनिक का लाइसेंस 2015 में रद कर दिया था। इसके चलते क्लीनिक बंद कर दिया गया था। इंडियाना के स्वास्थ्य विभाग को क्लीनिक के बारे में रोगियों के रजिस्ट्रेशन और गर्भपात संबंधी नीतियों में गड़बड़ी की कई शिकायतें मिली थीं।

कराए हजारों ऑपरेशन

साउथ बेंड ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, क्लोफर ने कई दशकों के दौरान अबॉर्शन (गर्भपात) के हजारों ऑपरेशन किए थे।

बेटी की शादी के दिन पिता ने विस्फोट कर उड़ा दिया घर

एजवुड, एपी : अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी वाले दिन ही विस्फोट कर अपना घर उड़ा दिया। इसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के नजरिये से देख रही है। घटना के समय घर के सभी लोग शादी में गए थे।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार, पिट्सबर्ग शहर के पास एजवुड इलाके में शनिवार को एक व्यक्ति ने अपने घर में विस्फोट कर दिया। इससे घर में आग लग गई। धमाके से पास के एक दूसरे घर को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मलबे से एक शव बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि धमाके के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था?

पिट्सबर्ग के पुलिस प्रमुख रॉबर्ट पायने ने कहा कि जिस समय धमाका किया गया, उस वक्त घर के सभी लोग शादी समारोह में गए थे। सिर्फ लड़की का पिता ही घर में था। जबकि पड़ोसियों ने बताया कि धमाके से कुछ समय पहले घर का मालिक बाहर टहल रहा था। थोड़ी देर बाद ही धमाके की आवाज सुनाई दी थी।

ये भी जानिए

यह लगातार दूसरी टी-20 सीरीज है जब बारिश ने खलल डाला है। इससे पहले भारतीय टीम जब कैरेबियाई दौरे पर थी तो भी वहां तीन मैचों की सीरीज का एक मुकाबला बारिश से रद हुआ था।

युवाओं को साबित करने के चार-पांच मौके काफी : कोहली

चेतावनी ▶ भारतीय कप्तान ने कहा, उन्हीं खिलाड़ियों को विश्व कप में मौका मिलेगा जो मौके का फायदा उठाएंगे

विराट बोले, जब मैं टीम में आया था तो ऐसा नहीं था कि मुझे 15 मौके मिले

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अगले साल ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने युवा खिलाड़ियों को सीधी चेतावनी दे दी है। कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ खास बातचीत में कहा कि विश्व कप में उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जो मौकों का फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी युवा खिलाड़ी को 15 मैच दिए जाएंगे।

टीम इंडिया के कप्तान ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मैं टीम में आया था तो ऐसा नहीं था कि मुझे 15 मौके मिले। आपको पांच मौके मिलेंगे और आपको उसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हम इसी स्तर पर खेल रहे हैं। जो खिलाड़ी मौके को लपकेंगे उन्हें मौके मिलेंगे। कोहली ने आगे कहा कि हमारे पास विश्व कप से पहले 30 टी-20 मैच हैं, ऐसे में हमें यह अनुमान लगाना है कि कितना समय किसी एक खिलाड़ी को दिया जा सकता है। मैं जब टीम में आया था तो मेरी सोच यह कभी नहीं थी कि मुझे 10-15 मैच मिलने चाहिए। मुझे लगता था कि शायद चार-पांच मैच मिलेंगे

विराट कोहली। फाइल फोटो

और उसी में कुछ करना पड़ेगा। टी-20 विश्व कप से पहले हम सभी लड़कों को मौका दे रहे हैं। हमारा उन खिलाड़ियों पर ध्यान है जो हमारी सोच को आगे ले जा सकते हैं। कोहली ने कहा कि टी-20 विश्व कप से पहले घरेलू सत्र बेहद ही अहम रहेगा। कोच रवि शास्त्री ने भी यही बात कही। शास्त्री ने कहा कि टी-20 विश्व कप से पहले घरेलू सत्र में अलग-अलग टीमों से खेलने में काफी फायदा होगा। विदेश में हमें अच्छा अनुभव मिला, अब यहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कई टीमें भारत आएंगी। घरेलू सत्र में भारत को छह टीमों से सीरीज खेलनी हैं।

दीर्घकालीन करार पर विचार कर रहा सीएसए

धर्मशाला, प्रेट्र : क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के शीर्ष अधिकारी कोरी वान जाइल ने कहा है कि बड़ी संख्या में क्रिकेटर राष्ट्रीय टीम की जगह काउंटी क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं, जिसे रोकने के लिए बोर्ड दीर्घकालीन करार लाने पर विचार कर रहा है।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज और अंतरिम कोच जाइल ने माना कि बोर्ड प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को लेकर गंभीर है जो कोलपैक करार के जरिये इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। जाइल सीएसए के क्रिकेट निदेशक भी हैं। कोलपैक करार के तहत यूरोपीय यूनियन के किसी भी सदस्य देश के साथ मुक्त व्यापार करार वाले देश के पेशेवर खिलाड़ी पेशेवर के तौर पर कहीं भी खेल सकते हैं। पिछले 15 साल में कोलपैक खिलाडियों में सबसे बड़ी संख्या दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की है। टीम को हाल के वर्षों में काइल एबोट (2017) और डुआने ओलिवर (2019) के जाने से नुकसान हुआ है। जाइल ने कहा, यह तो खिलाड़ी ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उन्होंने कोलपैक करार क्यों किया। मैं इस पर कोई कयास नहीं लगा सकता।

बारिश ने धोया पहला टी-20 मुकाबला

मुनीष गारिया, धर्मशाला

टी-20 विश्व कप 2020 की तैयारी को लेकर क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में सीरीज का पहला मैच खेलने की भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों की उम्मीदों पर मौसम ने पानी फेर दिया। अब दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को मोहाली में होगा।

धर्मशाला में रविवार दोपहर करीब एक बजे पानी बरसना शुरू हुआ, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी छा गई। हालांकि, करीब पौने तीन बजे बारिश थोड़ी थम सी गई। इस बीच एचपीसीए के ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को सुखाना शुरू किया ही था कि पांच मिनट बाद फिर बारिश शुरू हो गई, जो करीब पांच बजे तक लगातार जारी रही। करीब पांच बजे बारिश थोड़ी देर थमने के बाद फिर शुरू हो गई। साढ़े पांच बजे के बाद बारिश रुकी। इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने मैदान सुखाना शुरू कर दिया। करीब पांच घंटे तक रुक-रुक कर हुई बारिश ने दर्शकों के सब्र का खूब इम्तिहान लिया।

भारी बारिश के बीच में दर्शकों ने स्टेडियम नहीं छोड़ा और लगातार स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश जारी रहा। छह बजे तक 50 फीसदी से अधिक दर्शक स्टेडियम में पहुंच चुके थे। लगातार जारी रहे बारिश के दौर के चलते आठ बजे के बाद मैच रद कर दिया।

बारिश की वजह से ग्राउंड से पानी हटाने का प्रयास करते मैदान कर्मी। जागरण

ग्राउंड में पहुंच गए तीन दर्शक : पहले मैच को देखने पहुंचे क्रिकेट प्रेमी बारिश के बीच बेकाबू हो गए। बारिश के कारण सुरक्षा में थोड़ी सी ढील होते ही तीन क्रिकेट प्रेमियों ने स्टैंड को फांद कर ग्राउंड में छलांग लगा दी और ग्राउंड में प्रवेश कर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने बेकाबू हुए दर्शकों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया।

भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने फिर किया निराश

नूर-सुल्तान (कजाखिस्तान), प्रेट्र : रवि ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की ओर से पहली जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा जिससे रविवार को यहां देश के ग्रीको रोमन पहलवानों का खराब प्रदर्शन जारी रहा।

तीन वर्गों में ओलंपिक कोटा दांव पर लगे थे, लेकिन तीनों भारतीयों मनीष (67 किग्रा), सुनील कुमार (87 किग्रा) और रवि (97 किग्रा) कड़ी टक्कर देने में नाकाम रहे। पहले दिन चार पहलवान एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए, जबकि इनमें से तीन तो एक भी अंक नहीं जुटा पाए। रवि ने चीनी ताइपे के चेंग ह्याओ चेन को हराया। भारतीय पहलवान ने 5-0 से जीत दर्ज की। रवि को हालांकि चेक गणराज्य के आर्तुर ओमारोव के खिलाफ अगले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मैट से बाहर निकलने के कारण रवि ने दो अंक गंवा दिए और फिर अधिक रक्षात्मक खेल के लिए भी एक अंक उनके खिलाफ गया। ओमारोव ने इसके बाद स्कोर 7-0 किया और पहला राउंड खत्म होने से 27 सेकेंड पहले भारतीय खिलाड़ी को चित कर दिया। ओमारोव को इसके बाद क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के मिहाइल कजाइया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी जिससे रवि की पदक की उम्मीद खत्म हो गई। मनीष को बुल्गारिया के डेविड तिहोमिरोव दिमित्रोव के खिलाफ 1-10 से हार झेलनी पड़ी। बुल्गारिया का पहलवान इसके बाद डेनमार्क के होमक्विस्ट जेरहस के खिलाफ 0-6 से हार गया।

स्मिथ की मेहनत गई बेकार, इंग्लैंड ने ड्रॉ कराई एशेज सीरीज

लंदन, रायटर : सात पारियों में 774 रन। यह दिखता है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में किस तरह की जीवटता दिखाई, लेकिन अन्य बल्लेबाजों के नकारेपन का नतीजा यह हुआ कि स्मिथ के इस अद्भुत प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया टीम को एशेज सीरीज में 2-2 की बराबरी से मजबूर होना पड़ा। लंदन के द ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में पहली बार स्मिथ सीरीज में 50 रन से नीचे आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया ने मैच के चौथे दिन ही घुटने टेकते हुए 135 रनों से मुकाबला गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया का इसी के साथ 18 वर्ष बाद इंग्लैंड की धरती पर एशेज सीरीज जीतने का सपना टूट गया। हालांकि, पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के जीतने की वजह से एशेज मेहमानों के पास ही रहेगी।

ऑस्ट्रेलिया ने भोजनकाल के बाद तीन विकेट पर 68 रन से आगे खेलना शुरू किया। स्टीव स्मिथ ने 18 और मैथ्यू वेड ने अपनी पारी को 10 रन से आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया ने भोजनकाल के बाद 85 के स्कोर पर स्मिथ के रूप में अपना बेशकीमती विकेट खो दिया। दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज स्मिथ को ब्रॉड ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच कराया। स्मिथ इस सीरीज में पहली बार अर्धशतक लगाने से चूक गए। उन्होंने 53 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 23 रनों का योगदान दिया।

स्मिथ के आउट होने के बाद वेड ने मिशेल मार्श (24) के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। मार्श टीम के 148 के स्कोर पर पांचवें विकेट के रूप में आउट हुए। मार्श छह रन के अपने निजी स्कोर पर ही क्रिस वोक्स की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हो गए थे, लेकिन वोक्स की यह गेंद नो बॉल हो गई और मार्श को जीवनदान मिल गया। मार्श ने 67 गेंदों पर चार चौके लगाए।

मार्श के आउट होने के बाद वेड और पेन ने ऑस्ट्रेलिया को चायकाल तक और कोई झटका नहीं लगने दिया। इस बीच, वेड ने अपने करियर का पांचवां अर्धशतक पूरा किया। चायकाल के बाद कप्तान पेन 21 रन पर पवेलियन लौट गए। पेन के जाने के बाद पैट कमिंस नौ रन बनाकर चलते बने। इस बीच वेड ने शतक लगाया, लेकिन 117 रन के स्कोर पर रूट की गेंद पर स्टंप हो गए। कुछ देर बाद पूरी टीम 263 रन पर पवेलियन लौट गई। इंग्लैंड की ओर से ब्रॉड और लीच ने सबसे ज्यादा चार-चार विकेट लिए। इससे पहले, इंग्लैंड से मिले 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 29 रन तक अपने दोनों ओपनरों मार्कस हैरिस

दूसरी पारी में आउट होने के बाद निराशा के साथ लौटते स्टीव स्मिथ। एपी

टेस्ट

- पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड ने दर्ज की 135 रन से जीत
- 2-2 की बराबरी से ड्रॉ रही पांच मैचों की एशेज सीरीज

7 बार टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार आउट किया है जो रूट को पैट कमिंस ने। उन्होंने इस मामले में जोश हेजलवुड की बराबरी की

(09) और डेविड वार्नर (11) का विकेट गंवा दिया। दोनों बल्लेबाजों को ब्रॉड ने पवेलियन भेजा। वार्नर इस सीरीज में पूरी तरह से असफल रहे और उन्होंने 10 पारियों में केवल 95 रन बनाए। ब्रॉड ने इस सीरीज में 10 में से सात बार वार्नर को आउट किया।

इसके बाद स्मिथ और मार्नस लाबुशाने (14) के बीच तीसरे विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन, लाबुशाने भी टीम के 56 के स्कोर पर तीसरे बल्लेबाज के रूप में आउट हो गए। उन्हें जैक लीच ने विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों स्टंप कराया।

एक एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन

खिलाड़ी	देश	रन	वर्ष
डॉन ब्रैडमैन	ऑस्ट्रेलिया	974	1930
वॉली हैमंड	इंग्लैंड	905	1928
मार्क टेलर	ऑस्ट्रेलिया	839	1989
डॉन ब्रैडमैन	ऑस्ट्रेलिया	810	1936
स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	774	2019

टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बार 750 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी	देश	संख्या
डॉन ब्रैडमैन	ऑस्ट्रेलिया	4
ब्रायन लारा	वेस्टइंडीज	2
स्टीव स्मिथ	ऑस्ट्रेलिया	2

क्लासिक गोल्फ चैंपियनशिप में रोरी बने विजेता

गुरुग्राम, प्रेट्र : भारतीय गोल्फर राशिद खान को चौथे दौर के 15वें होल में बोगी करना महंगा पड़ा, जिससे वह क्लासिक गोल्फ एवं कंट्री क्लब अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में रविवार को खिताब जीतने से चूक गए। इंडोनेशिया के रोरी हिई चौथे दौर में 68 का कार्ड खेल कुल 21 अंडर 267 के स्कोर के साथ विजेता बने, जबकि 2014 में एशियाई टूर पर अपना पिछला खिताब जीतने वाले राशिद ने 69 का कार्ड खेला। वह कुल 19 अंडर 269 के स्कोर के साथ कोरिया के ब्यूंगजुन किम (67) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। राशिद के लिए 2016 में पैनासोनिक ओपन में दूसरे स्थान पर रहने के बाद यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस साल एशियाई टूर पर वह तीसरी बार शीर्ष-10 में रहे हैं। रोरी ने 10 साल पहले इसी क्लब में पहली बार भारत में खेला था और इस जीत के साथ उन्होंने लंबे समय के बाद कोई खिताब अपने नाम किया। राशिद खिताब जीतने से चूक गए लेकिन शीर्ष 10 में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। तालिका के शीर्ष-10 में चार, जबकि शीर्ष-20 में 10 भारतीय खिलाड़ी शामिल रहे। आदिल (66) ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 18 अंडर के स्कोर करके चौथा स्थान हासिल किया।

खराब फॉर्म के बावजूद डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा रहेंगे : पोंटिंग

लंदन, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का कहना है कि सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर यहां जारी एशेज सीरीज में खराब प्रदर्शन के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। वार्नर के लिए मौजूदा सीरीज बेहद खराब रही है और वह छह बार तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार हुए हैं। तीन बार तो वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए। पोंटिंग ने कहा कि वार्नर टीम में बने रहेंगे।

पोंटिंग ने कहा कि मार्नस लाबुशाने और स्टीव स्मिथ की जगह भी पक्की है। हालांकि, मध्य क्रम में मैथ्यू वेड और ट्रेविस हेड पर प्रश्न चिन्ह है। मार्कस हैरिस को इस सीरीज में बेहतरीन तेज गेंदबाजों की चुनौती का सामना करना पड़ा है। टिम पेन भी कप्तान बने रहेंगे, लेकिन बल्लेबाजी क्रम में कुछ ऐसी जगह हैं जिस पर पाकिस्तान सीरीज से पहले विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विल पुकोवस्की जैसे युवा खिलाड़ियों को घरेलू सीरीज में मौका दिया जाएगा। पोंटिंग ने कहा कि इतनी जगहें खाली हैं ऐसे में मैं पुकोवस्की जैसे खिलाड़ी को मौका मिलते हुए देखना चाहूंगा। सभी लंबे समय से उनके बारे में बात कर रहे हैं।

एशेज डायरी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग। फाइल

उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है, लेकिन वह एक बेहतरीन युवा बल्लेबाज हैं।

डीआरएस का इस्तेमाल नहीं करने से परेशान हैं पेन : ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन ने स्वीकार किया कि पांचवें एशेज टेस्ट में दो बार डीआरएस (अंपायरों की समीक्षा प्रणाली) का इस्तेमाल नहीं करना निराशाजनक है क्योंकि दोनों से ही उन्हें विकेट मिल सकते थे। इंग्लैंड की टीम सीरीज 2-2 से बराबर करने की कोशिश में है।

शनिवार को मैच के तीसरे दिन ओवल में पेन की गलतफहमी के कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम को नुकसान हुआ। जो डेनली जब 54 रन पर थे, तब वह मिशेल मार्श की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने नॉटआउट के फैसले की समीक्षा नहीं करने का विकल्प चुना और उन्होंने 94 रन बनाए। बाद में कप्तान और विकेटकीपर पेन ने जोस बटलर के एलबीडब्ल्यू की अपील पर नॉटआउट के फैसले की समीक्षा नहीं कराने का फैसला किया, जबकि रीप्ले में दिख रहा था कि नाथन लियोन की गेंद स्टंप हिट करती।

बटलर तब 19 रन पर थे और उन्होंने 47 रन बनाए। पेन ने कहा कि मैं फैसला नहीं कर पाया। पता नहीं और क्या कहूं। हमारे लिए यह दुःस्वप्न की तरह था। हमने गलत निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह मुश्किल काम है, मैंने पूरी सीरीज के दौरान यही कहा है।

पंकज का विश्व चैंपियनशिप में दबदबा कायम

मंडाले (म्यांमार), प्रेट्र : भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने रविवार को यहां 150 अप प्रारूप में लगातार चौथे आइबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के खिताब के साथ अपने करियर का 22वां विश्व खिताब जीता। बिलियर्ड्स के छोटे प्रारूप में यह 34 साल के आडवाणी का पिछले छह साल में पांचवां खिताब है। पिछले साल की तरह इस साल भी आडवाणी ने फाइनल में स्थानीय दावेदार नेम थ्वॉय ओ के खिलाफ 6-2 से आसान जीत दर्ज की।

आडवाणी ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और 145, 89 और 127 के ब्रेक के साथ जल्द ही 3-0 की बढ़त बना ली। थ्वॉय ओ ने 63 और 62 के ब्रेक के साथ अगला फ्रेम जीता। आडवाणी ने इसके बाद 150 के अटूट ब्रेक और 74 के ब्रेक के साथ आसानी से मुकाबला जीत लिया, जिससे थ्वॉय ओ को लगातार दूसरे साल रजत पदक से संतोष करना पड़ा। बेंगलुरु के आडवाणी से अधिक विश्व क्यू खिताब किसी खिलाड़ी ने नहीं जीते हैं।

आडवाणी ने कहा, 'प्रत्येक बार मैं जब भी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेता हूं तो एक चीज स्पष्ट होती है, मेरी प्रेरणा में कोई कमी नहीं होती। यह जीत इस बात का सबूत है कि मेरी भूख और मेरे अंदर की आग बरकरार है।' आडवाणी को 24 घंटे के भीतर स्नूकर में लय हासिल करनी होगी क्योंकि उन्हें आइबीएसएफ विश्व 6 रेड स्नूकर और विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। भारतीय खिलाड़ी ने 2014 के बाद से बिलियर्ड्स, स्नूकर दोनों में ही हर साल खिताब जीता है। उन्होंने कहा, 'यह एक अविश्वसनीय जीत है। लगातार चार साल तक खिताब जीतना और पिछले छह फाइनल में से पांच बार खिताब अपने नाम करना मेरे लिए यह एक बेहद खास उपलब्धि है।'

ट्रॉफी के साथ पंकज आडवाणी। ट्विटर

उपलब्धि

- भारतीय स्टार क्यू खिलाड़ी आडवाणी ने जीता 22वां विश्व खिताब
- फाइनल में नेम थ्वॉय ओ को आसानी से 6-2 से हराया

06 साल में भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी की यह विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की पांचवीं खिताबी ट्रॉफी है। इसके साथ ही उन्होंने लगातार चौथी बार यह खिताब जीता

34 वर्षीय पंकज ने एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक 2006 दोहा गेम्स और 2010 ग्वांग्झू गेम्स में जीते थे

रेबेका ने जीता पहला डब्ल्यूटीए खिताब

नानचांग, रायटर : जियांगशी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रविवार को स्वीडन की रेबेका पीटरसन ने कजाखस्तान की एलिना रिबाकिना को हराकर पहला डब्ल्यूटीए खिताब हासिल किया। नानचांग में खेले गए महिला सिंगल्स के फाइनल में रेबेका ने एलिना को 6-2, 6-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

इस मुकाबले के दौरान 24 वर्षीय रेबेका ने कजाखस्तानी खिलाड़ी की सर्विस को पांच बार तोड़ी और एक घंटे तक चले एकतरफा मुकाबले में कुल 13 विनर्स लगाए। रिबाकिना पर थकावट का असर साफ देखा जा सकता था जिन्हें क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में तीन सेट में जीत हासिल हुई थी। फाइनल में 20 साल की रिबाकिना ने कुल 11 असहज गलतियां कीं और केवल 40 फीसदी ही पहली सर्विस पर अंक हासिल कर सकीं। वहीं, रेबेका ने 83 फीसदी पहली सर्विस पर अंक हासिल किए। पहले सेट के पहले ही गेम में रिबाकिना ने डबल फॉल्ट करके स्वीडिश खिलाड़ी की ओर मुकाबले को मोड़ दिया। अंत में रेबेका ने लगातार नौ गेम्स अपने नाम करके खिताब पर कब्जा जमाया।

बैडमिंटन डायरी

भारतीय खिलाड़ी वर्मा ने फाइनल में चीन के सुन फेई शियांग को 21-12, 17-21, 21-14 से हराकर खिताब जीता

वियतनाम ओपन के चैंपियन बने सौरभ

हो ची मिन्ह सिटी, प्रेट्र : भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने रविवार को यहां वियतनाम ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में चीन के सुन फेई शियांग को हराकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी वरीय सौरभ ने एक घंटे 12 मिनट तक चले फाइनल मुकाबले को 21-12, 17-21, 21-14 से अपने नाम किया।

विश्व रैंकिंग में 38वें स्थान पर काबिज सौरभ अब 24 से 29 सितंबर तक खेले जाने वाले कोरिया ओपन में खेलेंगे। सौरभ ने पहले गेम में दबदबे के साथ शुरुआत करते हुए 4-0 की बढ़त बनाई और ब्रेक के समय वह 11-4 से आगे थे। ब्रेक के बाद भी उन्होंने लय बनाए रखी और स्कोर को 15-4 कर दिया। सुन ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने आसानी से पहला गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में सुन ने शानदार खेल दिखाया और 8-0 की बढ़त हासिल कर ली। ब्रेक के समय उनकी बढ़त 11-5 की थी। ब्रेक के बाद भी सौरभ संघर्ष करते दिखे, जिसका फायदा उठाते हुए सुन ने गेम अपने नाम कर लिया। निर्णायक गेम की शुरुआत में 26 साल के सौरभ 2-4 से पिछड़ रहे थे, लेकिन ब्रेक तक उन्होंने 11-7 की बढ़त कायम कर ली। चीन के खिलाड़ी ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। जब वह 17-14 से आगे थे तब उन्होंने लगातार चार अंक हासिल कर चीनी खिलाड़ी के मंसूबो पर पानी फेर दिया।

कौशल ने जीती म्यामांर की विजेता ट्रॉफी

यंगून, प्रेट्र : भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौशल धरमामेर ने रविवार को यहां पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंडोनेशिया के केरोनो को हराकर म्यामांर अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया। पिछले साल अक्टूबर में हेटजर अंतरराष्ट्रीय का खिताब जीतने वाले मुंबई के 23 साल के कौशल ने पहला गेम गंवाने के बाद एक घंटा चले मुकाबले में यहां केरोनो को 18-21, 21-14, 21-11 से हराया। लगभग दो साल से चोटों से परेशान कौशल की विश्व रैंकिंग 187 है।

चिराग-सत्विक की निगाहें लगातार अच्छे प्रदर्शन पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : चोट के बाद वापसी कर रहे चिराग शेट्टी और सत्विकसाईराज रेंकीरेड्डी की भारतीय शीर्ष डबल्स जोड़ी की निगाहें लगातार शानदार प्रदर्शन से शीर्ष-पांच में जगह बनाकर 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्थान पक्का करने पर लगी हैं। पिछले महीने थाइलैंड ओपन में बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी बनने के बाद उन्होंने शीर्ष-10 में जगह बनाई थी। हालांकि, चिराग और सत्विक दोनों टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए और उन्हें स्विट्जरलैंड के बासेल में प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप से हटना पड़ा। चिराग को पेट की मांसपेशियों में चोट लगी, जबकि सत्विक की कंधे की चोट गंभीर हो गई, जिससे उनकी रैंकिंग पर असर पड़ा और वे विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर खिसक गए। कड़े ट्रेनिंग कार्यक्रम के बाद पूर्ण फिटनेस हासिल कर चुकी इस भारतीय जोड़ी की निगाहें अब मंगलवार से शुरू होने वाले चीन ओपन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की है। चिराग ने कहा, 'हम अब पूरी तरह से फिट हैं। हम बेहतर खेल दिखाएंगे और उम्मीद है कि चीन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

2018 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने डच ओपन और कोरिया ओपन का खिताब जीता था

2019 में मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन सौरभ हैदराबाद ओपन और स्लोवेनियाई अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब भी जीत चुके हैं

वियतनाम ओपन का खिताब जीतने वाले सौरभ वर्मा। फाइल फोटो

ज्योफ्री कामवोरोर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड

कीनिया के धावक ने कोपेनहेगन हाफ मैराथन में 58 मिनट 01 सेकेंड के साथ पुरुष वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अब्राहम किपतुम के 58 मिनट 18 सेकेंड के रिकॉर्ड में 17 सेकेंड का सुधार किया। मैराथन में कीनियाई धावक हमेशा से ही बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। ज्योफ्री ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की है। ज्योफ्री से अगले वर्ष जापान में होने वाले ओलंपिक गेम्स में पदक की उम्मीद है।

फुटबॉल के खेल में आप हमेशा गलतियों से बच नहीं सकते।
– पेप गॉर्डियोला, मैनचेस्टर सिटी कोच

फुटबॉल डायरी ▸ ला लीगा में बार्सिलोना ने वेलेंसिया को 5–2 से हराया, 16 वर्षीय युवा सनसनी अंसू की सीनियर टीम में धमाकेदार शुरुआत

बार्सिलोना की बड़ी जीत में युवा फाती और सुआरेज चमके

सुआरेज ने दागे दो गोल, जबकि फाती, पिक और जोंग ने भी किए स्कोर

बार्सिलोना, रायटर : स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने ला लीगा में वेलेंसिया को 5-2 से करारी शिकस्त दी। इस दौरान बार्सिलोना के 16 वर्षीय युवा सनसनी अंसू फाती ने सीनियर टीम में अपने धमाकेदार शुरुआत के दौर को जारी रखा और एक गोल करने के अलावा गोल करने का एक मौका भी तैयार किया।

बार्सिलोना की ओर से स्ट्राइकर फाती (दूसरे मिनट), फ्रैंकी डि जोंग (सातवें मिनट) और जेरार्ड पिक (51वें मिनट) ने एक-एक गोल दागे, जबकि लुइस सुआरेज (61वें और 82वें मिनट) ने दो बार गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर मौजूदा सत्र में बार्सिलोना को दूसरी जीत दिलाई। वहीं, वेलेंसिया की ओर से केविन गोमेरियो (27वें मिनट) और मैक्सी गोमेज (90+2वें मिनट) ने स्कोर किए, लेकिन इसके बावजूद उसे पिछले तीन साल में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी।

पिछले सप्ताह बार्सिलोना की ओर से गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने फाती ने कैंप नाऊ में पहली बार स्कोर किया और डि जोंग के पास पर गोल करके बार्सिलोना को दूसरे ही मिनट में बढ़त दिलाई। इसके बाद उन्होंने डि जोंग के लिए गोल का मौका तैयार किया, जो बार्सिलोना की ओर से उनका पहला गोल था। इस मुकाबले में बार्सिलोना के चोटिल स्ट्राइकर लियोन मेसी नहीं उतरे जो स्टैंड में बैठककर मुकाबले का लुत्फ उठाते नजर आए। स्थानापन्न के तौर पर उतरकर दो गोल करने वाले सुआरेज को कैंप नाऊ के घरेलू प्रशंसकों ने जमकर स्वागत किया, लेकिन फाती के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा तालियां बजीं। दर्शक लगातार फाती का नाम पुकारते रहे। चार मुकाबलों में दो जीत, एक हार और एक ड्रॉ से सात अंक लेकर बार्सिलोना अंक तालिका में चौथे स्थान पर है।

हार के बावजूद एटलेटिको शीर्ष पर : इस बीच शनिवार को खेले गए एक अन्य मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिड को रीयल सोसिएदाद के हाथों 0-2 से हार झेलनी पड़ी। हालांकि, हार के बावजूद एटलेटिको ने अंक तालिका में नौ अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। रीयल मैड्रिड आठ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसने शनिवार को लेवांते को 3-2 से हराया।

गोल करने के बाद जश्न मनाते बार्सिलोना के खिलाड़ी। एपी

मेसी के बेटे ने बटोरी सुर्खियां

नई दिल्ली, एएनआइ : बार्सिलोना और अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी के बेटे मातियो अपने पिता की राह पर चल पड़े हैं। मेसी की पत्नी एंटोनेला रोकुजो ने मातियो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो खासा सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में मातियो पेनाल्टी किक पर गोल करने के बाद अपने पिता की तरह जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। रोकुजो ने वीडियो को पोस्ट करते हुए स्पेनिश में लिखा कि जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे प्यारे। मैं तुम्हारे जीवनभर खुश रहने और इसी तरह प्यारे बने रहने की कामना करती हूं।

माने और सलाह ने बरकरार रखा लिवरपूल का जलवा

फुटबॉल डायरी

- ईपीएल में लिवरपूल ने न्यूकैसल को 3-1 से हरा दर्ज की लगातार 14वीं जीत
- सादियो ने दागे दो गोल, सलाह ने भी किया स्कोर

लिवरपूल, प्रेट्र : सादियो माने और मुहम्मद सलाह ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के मौजूदा सत्र में लिवरपूल के शानदार सत्र को जारी रखते हुए एनफील्ड में अपनी टीम को शनिवार को न्यूकैसल युनाइटेड पर 3-1 की जीत दिलाई। यह लिवरपूल की ईपीएल में लगातार 14वीं जीत है।

यूरोपियन चैंपियन लिवरपूल का उसके मैनेजर जुर्जेन क्लोप की देखरेख में धीमी शुरुआत का इतिहास रहा है लेकिन इस मुकाबले में उसने न्यूकैसल के जेट्रो विलियम द्वारा सातवें मिनट में गोल खाने के बावजूद शानदार जीत दर्ज की। माने ने खेल के 28वें और 40वें मिनट में गोल करके लिवरपूल को हाफ टाइम से पहले बढ़त पर ला खड़ा किया। इसके बाद सलाह ने 72वें मिनट में रॉबर्टो फर्मिनो के बैक हिल पास पर गोल करके लिवरपूल को 3-1 से आगे कर दिया और यह स्कोर अंत तक बरकरार रहा। इस जीत के साथ लिवरपूल अंक तालिका में पांच मुकाबलों में पांच जीत के साथ 15 अंक लेकर शीर्ष पर बरकरार है।

निर्णायक बनी रशफोर्ड की पेनाल्टी किक : उधर ओल्ड ट्रैफर्ड के स्टैंफोर्ड ब्रिज स्टेडिमय में खेले गए ईपीएल के एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर युनाइटेड ने लीसेस्टर सिटी को 1-0 से हरा दिया जहां मुकाबले का इकलौता गोल मार्कश रशफोर्ड ने पेनाल्टी किक के जरिये दागा। इस जीत के साथ युनाइटेड अंक तालिका में आठ अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया जो अपने स्टार खिलाड़ी पॉल पोग्बा और एंथोनी मार्शल के बगैर खेल रहा था। उधर टॉटनहम ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से हरा दिया जहां उसके स्टार स्ट्राइकर सोन ह्यून मिन ने दो गोल दागे। वही साउथैंप्टन ने शेफील्ड युनाइटेड के खिलाफ 1-0 की जीत दर्ज की जहां मॉसा ड्जेनेपो ने इकलौता गोल दागा।

चेल्सी की जीत में अब्राहम की हैट्रिक : फॉर्म में चल रहे अपने स्ट्राइकर टैमी अब्राहम की शानदार हैट्रिक के दम पर चेल्सी ने वोल्वरहैंप्टन को 5-2 से करारी शिकस्त की और घरेलू टीम के मोलिन्यूक्स स्टेडियम की 130वीं वर्षगांठ के जश्न को खराब कर दिया। अब्राहम ने इस इस मुकाबले में एक आत्मघाती गोल भी किया। चेल्सी की ओर से फिकायो तोमोरी और मासोन माउंट ने भी गोल दागे। मैनचेस्टर सिटी को नॉर्विक सिटी के हाथों 2-3 से सनसनीखेज शिकस्त झेलनी पड़ी। नॉर्विक की ओर से केनी मैकलेन, टोड और टीमु पुक्की ने गोल दागे जबकि सिटी के सर्जियो अग्यूरो और रॉड्री द्वारा किए गए गोल के बादी भी पेप गॉर्डियोला को शिकस्त झेलनी पड़ी।

नेमार ने वापसी को बनाया यादगार

पेरिस : फ्रेंच लीग-1 में पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने स्ट्रासबर्ग को 1-0 से हरा दिया, जहां इंजुरी टाइम में नेमार ने मुकाबले का इकलौता गोल करके अपनी वापसी को यादगार बना दिया। चोट से उबरने और बार्सिलोना में वापसी की कोशिश में असफल रहने के बाद नेमार पहली बार पीएसजी की ओर से मैदान में उतरे जहां उन्हें कुछ प्रशंसकों ने चिढ़ाया लेकिन उनके द्वारा किए गए गोल के बाद दर्शकों ने उनका अभिवादन किया। इंजुरी टाइम के दूसरे मिनट में नेमार ने गोल दागा। इस जीत के बाद पीएसजी अंक तालिका में 12 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है।

रीयल की जीत में बेंजमा ने बिखेरी अपनी चमक

मैड्रिड : स्पेनिश लीग ला लीगा में रीयल मैड्रिड ने शनिवार को लेवांते को 3-2 से हरा दिया जहां उसके स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजमा ने दो गोल दागे। इस मुकाबले के जरिये रीयल के ईडन हैजार्ड ने ला लीगा में पदार्पण किया। बेंजमा (25वें और 31वें मिनट) के दो गोल के अलावा कासेमिरो (40वें मिनट) ने भी गोल करके रीयल को 3-0 से आगे कर दिया। हालांकि बोर्जा और मेलेरो ने गोल करके लेवांते को वापसी कराई लेकिन उनका प्रयास काम नहीं आया।

इटालियन लीग सीरी-ए में जुवेंटस को मायूसी

फ्लोरेंस (इटली) : इटालियन लीग सीरी-ए में शनिवार को जुवेंटस की टीम को फ्योरेंटिना से गोलरहित (0-0) ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इसके साथ ही जुवेंटस का मौजूदा सत्र में चला आ रहा जीत का क्रम भी टूट गया। इस मुकाबले से पहले जुवेंटस ने सत्र में अपने खेले पिछले दोनों मुकाबले जीते थे। वहीं इस ड्रॉ से फ्लोरेंटिना के जीत का इंतजार 17 मुकाबले तक पहुंच गया। फ्लोरेंटिना से हाल ही में जुड़े उसके स्टार फ्रैंक रेबरी ने गोल के कई मौके तैयार किए लेकिन उनकी टीम उन मौकों का फायदा नहीं उठा सकी।

कप्तानी का दबाव नहीं लेता : मनिंदर सिंह

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

उम्मीद

- पीकेएल में बंगाल वारियर्स की अगुआई कर रहे हैं सिंह
- कहा, लीग राउंड में शीर्ष दो में जगह बनाने की होगी कोशिश

मैं कप्तानी का दबाव नहीं लेता, बल्कि मैं तो खुद को कप्तान मानता ही नहीं। मैं हमेशा खुलकर खेलता हूं और साथी खिलाड़ियों को भी खुलकर खेलने को कहता हूं। बंगाल वारियर्स के नए कप्तान एवं स्टार रेडर मनिंदर सिंह ने खास बातचीत में ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि जब हमारी टीम मैदान में होती है तो सभी खिलाड़ी आपस में सलाह-मशविरा करके खेलते हैं। मैच की परिस्थितियों के मुताबिक हर कोई अपनी सलाह देता है। हम सभी की राय से चलते हैं, इसलिए उन पर कप्तानी का दबाव नहीं होता।

प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) में 650 से ज्यादा रेड प्वाइंट हासिल कर चुके मनिंदर ने कहा, 'हमारी नई टीम बढ़िया है। कई अच्छे रेडर आए हैं। सभी अच्छा खेल रहे हैं। पिछले सत्र में जैंग कुन ली को चोट लग जाने के कारण मैं अकेला मुख्य रेडर रह गया था, जिसकी वजह से सत्र मुश्किल हो गया था। इस बार हमारा टीम संयोजन काफी अच्छा है। हमारे पास के प्रपंजन और मुहम्मद इस्माइल नबीबख्श जैसे उम्दा रेडर हैं।' मनिंदर ने हालांकि बातों-बातों में पुराने साथी जैंग कुन ली की कमी खलने की बात भी जाहिर कर दी, जो इस सत्र में पटना पाइरेट्स का हिस्सा हैं। मनिंदर ने कहा, 'जैंग कुन ली दिल से खेलते हैं। वह मेरे बहुत अच्छे साथी थे। उम्मीद है कि अगले सत्र में हम फिर साथ में खेलेंगे।'

बंगाल वारियर्स के कप्तान मनिंदर सिंह। फाइल फोटो

नॉकआउट राउंड में हमेशा टीम के नाकाम रहने के बारे में पूछे जाने पर मनिंदर ने कहा, 'नॉकआउट राउंड में दबाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैच हारने का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना होता है। लीग राउंड में हमारी कोशिश शीर्ष दो टीमों में जगह बनाने की होगी। नॉकआउट राउंड में पहुंचने पर हम विरोधी टीम के मुताबिक खास रणनीति तैयार करेंगे। उम्मीद है कि हम इस बार टूर्नामेंट जीतेंगे।' होशियारपुर में जन्मे 29 साल के मनिंदर ने होम ग्राउंड के बारे में कहा, 'कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में खेलने में हमेशा ही मजा आता है। स्टेडियम में जब लोग हमारा नाम लेकर चिल्लाते हैं तो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है।' मनिंदर की निगाहें पीकेएल के बाद नेशनल गेम्स पर हैं। इससे पहले वह पुलिस गेम्स में भी शिरकत करेंगे।'

मुक्केबाज कविंदर प्री-क्वार्टर फाइनल में

एकातेरिनबर्ग (रूस), प्रेट्र : एशियाई रजत पदक विजेता कविंदर सिंह बिष्ट (57 किग्रा) ने रविवार को यहां विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में चीन के चिना झिहाओ को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ चीन के मुक्केबाज का चेहरा लहूलुहान हो गया। दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे पर कड़े प्रहार नहीं कर सके और जजों ने कविंदर के पक्ष में 3-2 से फैसला दिया।

भारतीय वायु सेना से जुड़े 26 साल के इस खिलाड़ी ने 2017 में हैम्बर्ग में हुई विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन इस बार वह पदक के दावेदारों में शामिल हैं।

इससे पहले दूसरी वरीयता प्राप्त और एशियाई चैंपियन अमित पंघाल (52 किग्रा) और कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता मनीष कौशिक (63 किग्रा) दमदार जीत के साथ प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। यह टूर्नामेंट टोक्यो 2020 ओलंपिक क्वालीफायर होना था, जिसमें पारंपरिक 10 भारवर्ग की बजाय संशोधित आठ भारवर्ग (52, 57, 63, 69, 74, 81, 91 और प्लस 91 किग्रा) रखे गए हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ (एआइबीए) में लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण इससे ओलंपिक क्वालीफायर का दर्जा छीन लिया। आइओसी ने इस खेल के ओलंपिक क्वालीफिकेशन को अपने हाथ में ले लिया है जो अगले साल फरवरी में एशियाई क्वालीफायर्स के साथ शुरू होगा।

कविंदर का शानदार प्रदर्शन जारी है। फाइल

विविध

टाइगर स्ट्राइक फोर्स गठित करेगी मध्य प्रदेश सरकार

मनोज तिवारी

- कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ में बाघों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही सरकार
- वन विभाग ने तैयार कर लिया है वनरक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव

भोपाल। नईदुनिया : बाघों की सुरक्षा को लेकर चिंतित राज्य सरकार ने आखिर टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन की तैयारी कर ली है। वन विभाग ने फोर्स के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जो मंजूरी के लिए कैबिनेट भेजा जा रहा है। पहले चरण में बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा की जिम्मेदारी फोर्स को सौंपी जाएगी। इसके लिए वनरक्षकों की भर्ती होगी, जो 40 साल की उम्र तक फोर्स में रहेंगे और फिर 62 साल की उम्र तक मैदानी अमले के रूप में विभाग में काम करेंगे। फोर्स को पॉवरफुल बनाने के लिए शस्त्र चलाने के अधिकार भी दिए जा रहे हैं।

आठ साल बाद प्रदेश 'टाइगर स्टेट' बना है। प्रदेश में पिछले साल हुई गिनती में 526 बाघ मिले हैं। इसके बाद सरकार की बाघों को लेकर चिंता और जिम्मेदारी बढ़ गई है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के वर्ष 2012 के प्रस्ताव पर अमल करते हुए राज्य सरकार टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन कर रही है। वैसे तो प्रदेश के सभी छह टाइगर रिजर्व में फोर्स गठित की जानी है, लेकिन पहले चरण में तीन टाइगर रिजर्व लिए जा रहे हैं। तीनों पार्क में एसीएफ के नेतृत्व में एक-एक कंपनी तैनात की जाएंगी। एक कंपनी में 112 लोग रहेंगे। इसमें तीन रेंजर, 22 उप वनपाल और 36 वनरक्षक रहेंगे। सरकार फोर्स में तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी, जबकि संसाधनों पर 6.60 करोड़ रुपए एक बार खर्च किए जाएंगे। फोर्स पार्क संचालक की निगरानी में काम करेगी।

विभाग करेगा वनरक्षकों की भर्ती: फोर्स का गठन रंगरूटों की नियुक्ति को लेकर अटका हुआ था। सात साल पहले भी वन विभाग ने फोर्स के गठन का प्रयास किया था, लेकिन तब रंगरूटों की नियुक्ति की मंजूरी नहीं मिली थी। पुलिस विभाग भी प्रतिनियुक्ति पर आरक्षक देने को तैयार नहीं हुआ। इस बार विभाग ने वनरक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग 18 से 25 साल के युवकों की भर्ती करेगा। उन्हें सेना के जवानों की तरह ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर पार्क में पदस्थ किया जाएगा, जो 40 साल की उम्र तक फोर्स में रहेंगे। इसके बाद वे विभाग में आकर नौकरी की अवधि पूरी करेंगे।

वन विभाग ने टाइगर स्ट्राइक फोर्स के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। फाइल

40 फीसद राशि राज्य सरकार देगी

फोर्स के गठन और संचालन पर खर्च होने वाली राशि में से 40 फीसद राशि राज्य सरकार खर्च करेगी, जबकि केंद्र सरकार 60 फीसदी राशि देगी। वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने सौ फीसद राशि देने का प्रस्ताव दिया था, तब राज्य सरकार ने प्रस्ताव नहीं माना, जबकि कर्नाटक सरकार ने केंद्र के निर्देश मानते हुए फोर्स का गठन किया था। इस के बाद कर्नाटक को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था।

शस्त्र चलाने की छूट रहेगी

प्रस्ताव में फोर्स को शस्त्र चलाने की छूट देने का प्रावधान भी किया जा रहा है। फोर्स जैसे अधिकार तो नहीं होंगे, लेकिन आत्मरक्षा की स्थिति में गोली चलाने और उससे किसी को नुकसान होने पर पहले जांच कराने का प्रावधान रहेगा। यदि जांच में वनरक्षक की ओर से परिस्थितियां निर्मित न होते हुए गोली चलाना पाया जाता है तो ही संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी।

करणी सेना ने महारैली निकाल कर की आरक्षण की मांग

नईदुनिया, इंदौर : आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में रविवार को हजारों राजपूत सड़कों पर उतरे। करणी सेना के बैनर तले निकली महारैली में बारिश के बावजूद देश के तीन राज्यों और प्रदेश के 52 जिलों से समाज के लोग शामिल हुए। दो और चार पहिया वाहनों के साथ हाथ में तख्तियां लिए करणी सेना के पदाधिकारी चल रहे थे। यात्रा में 'एससी-एसटी एक्ट हटाओ, देश बचाओ और एक देश, एक कानून लागू करो' जैसे नारे लगाए जा रहे थे। इस दौरान चुनिंदा मौकों पर हवाई फायर और तलवार भी लहराई गईं।

रैली की शुरुआत निरंजनपुर स्थित लोहा मंडी से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पहुंचने के बाद दोपहर 1 बजे हुई। इस दौरान यहां लगातार सुबह 8 बजे से देवास, शाजापुर, उज्जैन, देवास, खंडवा सहित प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं के काफिला जुटने का सिलसिला लगातार जारी था। रैली में लोग तख्तियों, दो-चार पहिया वाहनों पर करणी सेना के झंडे लेकर चल रहे थे। रैली में पंकज सिंह टोल, ऋषिराज सिंह सिसौदिया, दीपेंद्र सिंह सोलंकी, राम सिंह दीखित आदि मौजूद थे।

सीए छात्रों की अकादमिक व्यवस्था कानपुर के जिम्मे

- छात्रों के नए आवेदन, पढ़ाई से जुड़े कार्य लखनपुर रीजनल ऑफिस से
- नए सदस्य, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर भी यहीं बन रहा

अब देशभर के सीए छात्रों की व्यवस्था देखेगा कानपुर रीजन। फाइल

राजीव सक्सेना, कानपुर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) में कानपुर रीजन को दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हैं। अब देशभर में फैले आठ लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और उनसे जुड़ी अन्य जिम्मेदारी कानपुर को सौंप दी गई है। इसके साथ ही सीए सदस्यों की सदस्यता, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुंबई रीजन के बाद संस्थान में सबसे ज्यादा सक्रियता कानपुर की है।

कानपुर में सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल का मुख्यालय है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आते हैं। इन राज्यों के सदस्यों और छात्र-छात्राओं के बारे में कानपुर ऑफिस में डाटा रखा जाता है। यह जिम्मेदारी तो मुख्यालय होने की वजह से कानपुर को मिली है लेकिन अब आइसीएआइ ने छात्रों और सदस्यों के संबंध में जिम्मेदारी दी है। छात्र-छात्राओं की व्यवस्था के तहत नया आवेदन, फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक की पढ़ाई से जुड़े मसले, मोबाइल नंबर या पते में परिवर्तन, अन्य किसी क्षेत्र में पढ़ाई करनी है तो उसकी अनुमति संबंधी कार्य लखनपुर स्थित ऑफिस से होंगे। नया सदस्य बनने, सीए बनने के पांच वर्ष पूरा होने पर फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र कानपुर से ही मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर भी यहीं से जारी होगा। अगर प्रैक्टिस से जॉब में जाना है तो उससे जुड़े कार्य भी कानपुर से होंगे।

मुंबई रीजन पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, फर्म्स पर कार्य की जिम्मेदारी है। इसी तरह चेन्नई को हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे देश के सीए को हेल्प डेस्क से कोई जानकारी चाहिए तो उनकी मेल चेन्नई ही जाएगी और वहीं से जानकारी मिलेगी। इसी तरह कानपुर को पिछले माह देश भर के छात्रों की पढ़ाई, सदस्यता से जुड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये कार्य अब यहीं हो रहे हैं।

–मनु अग्रवाल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर

भाजपा तो मुझे हिंदू भी नहीं मानती : अखिलेश यादव

जासं, पीलीभीत

- सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा के राष्ट्रवाद से किसान, नौजवान परेशान

सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद व हिंदुत्व अलग तरीके का है। वह तो मुझे हिंदू तक नहीं मानती। हमें पिछड़ा वर्ग का भी नहीं मानती।

रविवार दोपहर वह बरेली से पीलीभीत के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे थे। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अलग तरीके का हिंदुत्व चला रहे हैं। आप ही बताइए कि हमारे वंशज कौन थे...खुद ही जवाब दिया कि कुछ दिन पहले ही पूरे देश ने जन्माष्टमी मनाई। इसके आगे भी हमें अपने हिंदू होने का कोई प्रमाण देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद यह है कि किसान परेशान है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने लोगों को शौचालय में फंसा दिया और विदेशी कंपनियों से समझौता कर देश का पैसा विदेश में भेजा जा रहा है। सपा प्रमुख ने राजनीतिक दलों के गठबंधन के अनुभव के बाबत कहा कि बड़े दलों के साथ चुनाव लड़ने का अनुभव अच्छा नहीं रहा। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लग चुके हैं। छोटे दलों से सहयोग की बात चल रही है।

आजम का बचाव, चिन्मयानंद पर निशाना : अखिलेश यादव शनिवार को रामपुर में थे। वहां से उसी रात बरेली आए और रविवार सुबह को पीलीभीत पहुंचे। कहा कि रामपुर में आजम खां का सिर्फ इतना कुसूर है कि उन्होंने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। उन पर 80 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।

नौ करोड़ के फर्जी ड्राफ्ट बनाए, पकड़े गए

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- बैंक अधिकारी की सतर्कता से गिरफ्तार हुए भोपाल के तीन बदमाश – मामले का मुख्य आरोपित राजेंद्र परमार फरार

फर्जी डिमांड ड्राफ्ट के जरिये बाराखंभा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेशनल बैंकिंग ब्रांच से करीब 10 करोड़ रुपये की ठगी का प्रयास करते तीन लोगों को बाराखंभा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान यश सक्सेना (42), देवेंद्र सिंह मालवीय (47) और राजीव उपाध्याय (43) के रूप में हुई। तीनों मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने 9.85 करोड़ रुपये का एक फर्जी डिमांड ड्राफ्ट, 20 लाख रुपये का साइन किया हुआ एक ब्लैंक चेक और परमार एंटरप्राइजेज के नाम की एक मुहर भी बरामद की गई है। इस मामले का मुख्य आरोपित राजेंद्र परमार अभी फरार है। आरोपितों के पास से मिला डिमांड ड्राफ्ट का पैसा राजेंद्र परमार के खाते में जमा किया जाना था।

यह ड्राफ्ट नेपाल से संचालित होने वाले पीएनबी के सब्सिडियरी बैंक एवरेस्ट बैंक लिमिटेड द्वारा 20 अगस्त को जारी किया गया था। इतनी बड़ी धनराशि का ड्राफ्ट देखकर बैंक अधिकारियों ने भुगतान से पहले जब जांच-पड़ताल की तो पता लगा कि एवरेस्ट बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किया गया ड्राफ्ट 43 हजार 350 रुपये का था। उसे इसी वर्ष जुलाई में चेन्नई से कैश भी कराया जा चुका है। असली डिमांड ड्राफ्ट के उसी नंबर का प्रयोग करते हुए आरोपितों ने फर्जी डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया और उसमे धनराशि आदि सब नए सिरे से भर दी थी।

नई दिल्ली के डीसीपी ईश सिंघल के मुताबिक, बृहस्पतिवार को बैंक के सीनियर मैनेजर अनिल कुमार जैन ने पुलिस से शिकायत की। जिसके बाद एसीपी रघुराज खटाना के निर्देशन में बाराखंभा रोड थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह यादव के नेतृत्व में एसआइ मंतोष चौहान, मुकेश खता, प्रवीण कुमार और संजय कुमार व कई अन्य पुलिसकर्मियों की टीम बैंक पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

फर्जी कागजों पर होटल खरीदने के लिए दिला चुके हैं लोन : पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि वे कमीशन पर जरूरतमंद लोगों को लोन दिलवाते थे और डायरेक्ट सेल्स असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। तीनों ने मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले राजीव उपाध्याय को होटल खरीदने के लिए फर्जी कागजों की मदद से एक करोड़ 20 लाख रुपये का लोन दिलाया था। इन तीनों ने राजेंद्र सिंह परमार नाम के एक व्यक्ति को साढ़े तीन करोड़ का लोन दिलाने में मदद की थी। इसके लिए तीनों ने कई फर्जी कागजों का प्रयोग भी किया था। राजेंद्र सिंह ने अपना एक और काम कराने के लिए इनसे मदद मांगी थी और बदले में 50 लाख का कमीशन देने का वादा किया था। एडवांस के रूप में उसने इन्हें 20 लाख रुपये का एक चेक भी दे दिया था। उसी काम को अंजाम देने के लिए ये लोग दिल्ली आए थे, लेकिन पकड़े गए।

मौसम विशेष

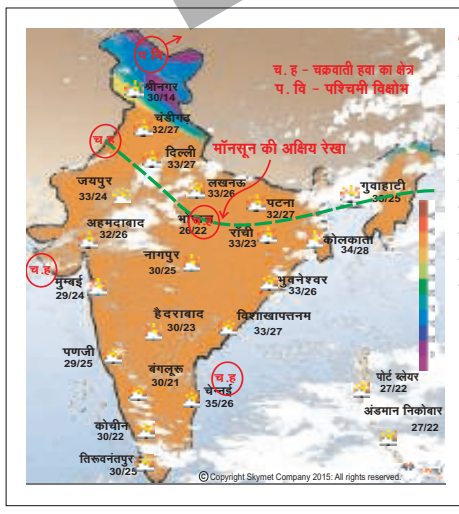

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में आंशिक बादलों के साथ मौसम गर्म रहेगा व कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होगी। पूर्वी राजस्थान में हल्की वर्षा होगी। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में मौसम गर्म रहेगा। इन राज्यों में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा संभव है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/25/व	अहमदाबाद	31/24/व
कोलकाता	33/27/व	बड़ौदा	29/25/आंबा
चेन्नई	34/25/व	नागपुर	27/23/आंबा
हैदराबाद	28/22/व	इन्दौर	26/21/आंबा
बंगलूरू	31/21/आंबा	रांची	32/24/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/25/व	पटना	35/30/व
गुवाहाटी	32/27/व	जमशेदपुर	35/26/व
गंगटोक	15/05/व	दुर्गा	25/23/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
सोमवार 16 सितंबर 2019
16
www.jagran.com

दुनिया के सामने आई फोटोकॉपी मशीन

1959 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक चेस्टर कार्लसन ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित एक लाइव टीवी शो में दुनिया की पहली सफल फोटोकॉपी मशीन जेरॉक्स 914 का प्रदर्शन किया। मशीन के काम करने के तरीके को देखकर लोग हैरान थे।

लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स का कॉपीराइट किया गया

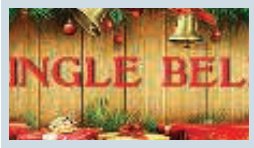

क्रिसमस के दिन गाये जाने वाले सबसे लोकप्रिय गीत जिंगल बेल्स को आज 1857 में कॉपीराइट किया गया था। इसे अमेरिकी गीतकार जेम्स लॉर्ड पियरपॉन्ट ने लिखा था। माना जाता है कि क्रिसमस के लिए इस गीत को नहीं लिखा गया था।

संगीत की लक्ष्मी थीं एमएस सुब्बालक्ष्मी

कर्नाटक संगीत की सबसे लोकप्रिय आवाज एमएस सुब्बालक्ष्मी का जन्म 1916 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। 11 साल की उम्र में पहली प्रस्तुति दी। उनकी ख्याति भक्ति संगीत और भजन को लेकर थी। मीरा के अधिकतर भजनों को उन्होंने ही आवाज दी। उन्होंने सेवासदन, सावित्री और शकुंतला जैसी तमिल फिल्मों में अभिनय भी किया। भारत रत्न और रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार बनीं। 11 दिसंबर, 2004 को उनका देहांत हो गया।

इधर-उधर की

हर दो घंटे में सब कुछ भूल जाती है यह महिला

वाशिंगटन,एजेंसी : दुनिया में लोगों को तरह-तरह की बीमारियां होती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। ऐसी ही एक बीमारी से ग्रसित अमेरिका के इलिनॉयस की रहने वाली रिले हॉर्नर भी हैं, जिससे वो बेहद परेशान हैं। डांस एक्ट के दौरान 16 साल की किशोरी रिले हॉर्नर के सिर में चोट लग गई, जिसके बाद वह कोई भी चीज दो घंटे से ज्यादा याद नहीं रख पाती हैं। हर दो घंटे के बाद वह उसके साथ होने वाली हर घटना भूल जाती हैं। न ही कोई चीज याद रहती है और न ही किसी के साथ हुई मुलाकात को याद रख पाती हैं। दरअसल, चोट लगते ही रिले को अस्पताल ले जाया गया लेकिन कई टेस्ट और स्कैन के बाद भी डॉक्टरों को उसकी बीमारी समझ नहीं आई। अब डॉक्टर कहते हैं कि जब उन्हें बीमारी का ही नहीं पता तो उसकी दवा कैसे देंगे।

शोध अनुसंधान

दिल की सेहत दुरुस्त रखने में दोपहर की झपकी मददगार

दिल की सेहत अच्छी रखने में दोपहर की झपकी की भी अहम भूमिका होती है। एक नए अध्ययन का दावा है कि दिन में झपकी लेने से ना सिर्फ तरोताजा रहा जा सकता है, बल्कि इससे हृदय को दुरुस्त भी रखा जा सकता है। जर्नल हार्ट में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 3,462 लोगों में झपकी की अवधि और हृदय रोग के बीच जुड़ाव पर गौर किया। 35 से 75 साल के इन प्रतिभागियों पर पांच साल तक अध्ययन किया गया था। इनसे दिन में कितने देर झपकी लेने के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। अध्ययन में पाया गया कि हफ्ते में एक या दो बार दिन में झपकी लेने वालों में हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने का 48 फीसद खतरा पाया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि यदि आपको अपने दिल की सेहत दुरुस्त रखनी है तो दिन में कुछ देर आराम जरूर करें। -एएनआइ

कीमोथेरेपी में बाल झड़ने से बचाव का तरीका किया ईजाद

वैज्ञानिकों को कीमोथेरपी में बाल झड़ने की रोकथाम करने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है, जिससे बालों को बचाया जा सकता है। कैंसर में आमतौर पर कीमोथेरेपी की जाती है। इसका एक प्रमुख दुष्प्रभाव बाल झड़ने के तौर पर सामने आता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन के नतीजों से जाहिर हुआ कि कैंसर के उपचार में काम आने वाली टैक्सनेस दवाओं से हमेशा के लिए बाल झड़ सकते हैं। इस समस्या की रोकथाम हो सकती है। ईएमबीओ मोलेक्यूलर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कैंसर रोधी दवा के तौर पर टैक्सनेस का आमतौर पर इस्तेमाल होता है। स्तन से लेकर फेफड़ों के कैंसर तक के उपचार में यह दवा उपयोगी होती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सीडीके4/6 इंहिबिटर वर्ग की नई दवाएं कोशिकाओं में विभाजन को रोकती हैं। इससे हेयर फॉलिकल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इन दवाओं को कैंसर के उपचार के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। -एएनआइ

कैंसर से लड़ सकते हैं शरीर के बुलबुले

नई तकनीक ▸ वैज्ञानिकों का दावा, कीमोथेरेपी से ज्यादा कारगर है एक्स्ट्रासेल्यूलर वेसिकल्स

दवाओं और जीन के मेल से ईवीएस कैंसर कोशिकाओं को बनाती हैं निशाना

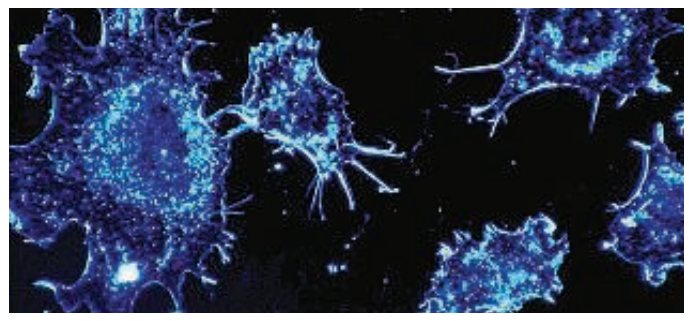

यह अध्ययन मॉलीक्यूलर कैंसर थेरैपिटिक्स में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : कैंसर किसी भी तरह का हो, लोगों के माथे पर शिकन जरूर ला देता है, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। कुछ मामलों में इलाज है भी तो वह बहुत खर्चीला होता है। अब इससे निपटने के लिए एक नई विधि ईजाद की है। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर में छोटे-छोटे बुलबुलों का पता लगाया है, जो कैंसर के इलाज में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बुलबुले कीमोथेरेपी के मुकाबले बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। इन्हें वाह्य कोशिकाएं या एक्स्ट्रासेल्यूलर वेसिकल्स(ईवीएस) भी कहा जाता है।

हमारे शरीर की कोशिकाएं बेहद छोटे-आकार के बुलबुलों का स्राव (रिलीज) करती हैं, जो आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए और आरएनए को अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरित करते हैं। यह आपका डीएनए ही है जो प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए आरएनए के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहीत करता है और सुनिश्चित करता है कि वे उसके अनुसार काम करते रहें। शोधकर्ताओं के मुताबिक, हमारी शरीर में पाए जाने वाले एक्स्ट्रासेल्यूलर वेसिकल्स दवाओं और जीन के मेल से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर उन्हें मार देती हैं। शोधकर्ताओं का यह अध्ययन मॉलीक्यूलर कैंसर थेरैपिटिक्स में प्रकाशित हुआ है, जो चूहों के स्तन की कैंसर की कोशिकाओं पर आधारित था। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर मैसमित्सु कनाडा ने कहा कि हमने जो किया है, वह शरीर में एंजाइम-उत्पादक जीन को वितरित करने का एक बेहतर तरीका साबित हो सकता है। यह कुछ दवाओं को विषाक्त एजेंटों में बदल कर ट्यूमर की कोशिकाओं को निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि ये दवाएं (प्रोड्रग) शुरुआत में निष्क्रिय यौगिक के रूप में रहती हैं, लेकिन शरीर के भीतर पहुंचते ही तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और कैंसर की कोशिकाओं से लड़ना शुरू कर देती हैं।

ऐसे किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एंजाइम-उत्पादक जीन को वितरित करने के लिए ईवीएस यानी एक्स्ट्रासेल्यूलर वेसिकल्स का इस्तेमाल किया, जो स्तन कैंसर की कोशिकाओं में गैनिक्लोविर और सीबी1954 नामक दवाओं के संयोजन के जरिये उन्हें सक्रिय कर सकता था। शोधकर्ताओं ने दो अलग-अलग जीन वैक्टर, मिनिकिरकल डीएनए और नियमित प्लास्मिड को वेसिकल्स लोड कर यह देखा कि क्या यह दवाओं को ट्यूमर की कोशिकाओं तक ले जाने में सक्षम है या नहीं। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि मिनिकिरकल डीएनए कैंसर की कोशिकाओं को मारने में अन्य के मुकाबले 14 गुना ज्यादा कारगर है। इसे प्रोड्रग थेरेपी के रूप में जाना जाता है।

कीमोथेरेपी नहीं कर पाती अंतर : कनाडा ने कहा कि परंपरागत कीमोथेरेपी ट्यूमर और सामान्य ऊतक के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह सभी पर हमला करता है, लेकिन ईवीएस के जरिये उपचार करने पर लक्षित हिस्सों को ही निशाना बनाता है। इससे अवांछित प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। कनाडा ने कहा कि अभी केवल चूहे पर इसका सफल प्रयोग किया गया है। यदि भविष्य में ईवीएस मनुष्यों में प्रभावी साबित होते हैं तो यह जीन वितरण के लिए एक आदर्श मंच सिद्ध होगा।

म्यूजिक चार्ट में पेड एडवरटाइजिंग व्यूज की गणना नहीं करेगा यूट्यूब

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : ऑनलाइन वीडियो दिखाने वाली दिग्गज कंपनी यूट्यूब अपने म्यूजिक चार्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दरअसल, कंपनी को पता चला है कि कलाकार और लेबल ग्रोथ हैक्स की मदद से वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या को घटा-बढ़ा कर लाभ कमा रहे हैं, जिससे कई लोगों को निश्चित तौर पर नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी हेरफेर को रोकने के लिए यूट्यूब ने यह कदम उठाने का फैसला किया है।

द वर्ज ने एक नए ब्लॉग के हवाले से बताया है कि अब यूट्यूब में 'एडवरटाइजिंग व्यूज' की गिनती म्यूजिक चार्ट में नहीं की जाएगी। सबसे ज्यादा देखे गए म्यूजिक वीडियो की रैंकिंग अब ऑर्गेनिक प्लेज के आधार पर की जाएगी। कंपनी ने ब्लॉग में लिखा है कि इंड्रस्ट्री में अधिक पारदर्शिता प्रदान करने और बिलबोर्ड और नीलसन जैसी आधिकारिक चार्टिंग कंपनियों की नीतियों के साथ पंक्ति बंद्ध होने के प्रयास में अब यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में 'पेड एडवरटाइजिंग व्यूज' की गणना नहीं करेगा। यूट्यूब ने कहा कि अब कलाकारों को ऑर्गेनिक प्लेज के व्यूज के आधार पर रैंक दी जाएगी।

दरअसल, कंपनी को पता चला है यूट्यूब के आर्टिस्ट (कलाकार) अपने व्यूज बढ़ाने के लिए दूसरे यूट्यूब चैनलों को पैसे देकर अपने वीडियो बतौर विज्ञापन चला रहे हैं। इससे 24 घंटे की टॉप वीडियोज के क्रम को बदला जा रहा था, जिस पर कंपनी ने अब लगाम लगा दी है।

स्पेक्ट्रम

▸ अब ऑर्गेनिक प्लेज के आधार पर होगी टॉप म्यूजिक वीडियो की रैंकिंग

ऑनलाइन वीडियो का बड़ा प्लेटफार्म है यूट्यूब।

2.5 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया में घूमते थे विशालकाय मारसूपियल

मेलबर्न, आइएएनएस : तमाम जीवों का आज कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन शोधकर्ता समय-समय पर मिलने वाले जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर इन जीवों की मौजूदगी और उनके विकास क्रम के बारे में नई नई जानकारियां देते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मारसूपियल (स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग जो अपने शिशुओं को पेट के पास बनी हुई थैली में रखकर चलते हैं) के बारे में नया दावा किया है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर कहा है कि आज से लगभग 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके मारसूपियल पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते थे। इस स्तनधारी जीव के समूह को पालोरकेस्टिड्स कहा जाता था। माना जाता है कि मारसूपियल का रहन-सहन अन्य प्राणियों से काफी भिन्न था और इनकी शारीरिक संरचना भी बड़ी विचित्र थी।

ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हेजल रिचर्ड और उनके सहयोगियों ने विभिन्न भूगर्भीय युगों के पालोरकेस्टिड्स के 60 से अधिक जीवाश्म के नमूनों की जांच की।

- इस स्तनधारी जीव के समूह को पालोरकेस्टिड्स कहा जाता है
- इनका रहन-सहन और शारीरिक संरचना बड़ी विचित्र होती है
- यह शोध पीएलओएस वन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है

मारसूपियल समूह का एक जीव। फाइल

शोधकर्ताओं के मुताबिक, उनके पास जितने जीवाश्म हैं, उनके अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सबसे बड़े पालोरकेस्टिड्स का वजन 1000 किग्रा से अधिक हो सकता है। इसके अलावा उसके अगले पैर बहुत ज्यादा मांसल रहे होंगे, जिससे ये जानवर पत्तियों और शाखाओं को आसानी से तोड़-मरोड़ कर खाते होंगे। यह अध्ययन पीएलओएस वन नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन के मुख्य लेखक हेजल रिचर्ड के मुताबिक, शायद स्तनधारी जीवों की दुनिया में मारसूपियल पहला जीव होगा जिसकी शारीरिक संरचना बड़ी विचित्र होगी। वर्तमान में कई ऐसे जीव क्लोन के जरिये तैयार किए जाते हैं।

क्या है मारसूपियस : मारसूपियल को धानीप्राणी भी कहा जाता है। यह स्तनधारी जानवरों की एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी (थैली) में रखकर चलते हैं। धानी प्राणियों में कंगारू, कोआला, पॉस्सम और वोम्बैट शामिल हैं। इनके नवजात शिशु अन्य स्तनधारियों के नवजात बच्चों की तुलना में अविकसित होते हैं और पैदा होने के बाद भी वे कई महीनों तक धानी में ही रह कर विकसित होते हैं।

'उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है गरीबी'

लंदन, आइएएनएस : हमारी जीवनशैली और पर्यावरण कहीं ना कहीं हम सभी को प्रभावित करता है। अब एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि युवावस्था में एक समय के बाद कम आय का असर लोगों के जीवन पर भी पड़ता है और इसकी वजह से उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। यानी ऐसे लोग समय से पहले ही ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं।

यूरोपियन जर्नल ऑफ एजिंग नामक प्रत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 5500 मध्यम आयु वर्ग के प्रतिभागियों को शामिल किया और 22 साल तक उनकी आमदनी और उनके शारीरिक बदलावों का अध्ययन किया।

इस अध्ययन के सह-लेखक और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिक्के ने कहा कि अध्ययन के दौरान हमने पाया है कि वित्तीय चुनौतियों और शुरुआती उम्र के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। यदि हमारी वित्तीय स्थिति कमजोर है तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे शरीर में भी देखने को मिलता है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ जिन प्रतिभागियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी वे अपनी उम्र से बड़े दिखने लगे थे।

ब्रिटेन के ब्लेनहेम पैलेस से सोने का शौचालय चोरी

लंदन, रायटर : ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर स्थित ब्लेनहेम पैलेस में चोरों ने सोने के एक शौचालय (टॉयलेट)पर ही हाथ साफ कर दिया है। 18 कैरेट सोने से बने और 50 लाख डॉलर (लगभग 35.5 करोड़ रुपये) से ज्यादा मूल्य के इस शौचालय को आर्ट प्रदर्शनी में रखा गया था। बता दें कि इस महल में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि इटली के कलाकार मौरीजियो कैटलान ने अपनी ऑर्ट प्रदर्शनी में इस शौचालय को रखा था। लंदन से पश्चिम में लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित इस पैलेस में लगी प्रदर्शनी को दो दिन पहले ही लोगों के लिए खोला गया था।

पुलिस को शनिवार की सुबह 4.57 बजे टॉयलेट चोरी होने की जानकारी मिली। पुलिस के एक बयान के मुताबिक घटना को अंजाम देकर चोर वहां से करीब 4.50 बजे फरार हो गए थे। मामले में 66 साल के एक व्यक्ति को चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।

इस टॉयलेट की कीमत करीब 35 .5 करोड़ रुपये है। एएफपी

पुलिस का कहना है कि चोरी गए टॉयलेट को अभी बरामद नहीं किया जा सका है, लेकिन इसे खोजने की और अपराधियों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस ने किसी भी गवाह को पुलिस से संपर्क करने की भी अपील की है।

'अमेरिका' के नाम से जाने जाने वाले इस टॉयलेट को सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में साल 2016 में गगेनहाइम में प्रदर्शित किया गया था। ब्लेनहाइम पैलेस में इस टॉयलेट को उस कमरे के पास लगाया गया था, जिसमें चर्चिल का जन्म हुआ था।

कला का अद्भुत प्रदर्शन

यूक्रेन की इस युवती केट ने अपने ब्रेक डांस के जरिये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड अर्बन गेम्स में सभी का मनमोह लिया। यह बी-बॉइंग डांस है, जिसे ब्रेक डांस भी कहा जाता है। ये स्ट्रीट डांस की एक सर्वाधिक चर्चित शैली है। दुनियाभर में युवाओं के बीच यह शैली काफी लोकप्रिय है। तीन दिवसीय अर्बन गेम्स में कई देशों के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट एथलिट प्रदर्शन करने यहां पहुंचते हैं। इसे सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। एएफपी

अफ्रीकी महिलाओं में साड़ी का क्रेज

भारतीय महिलाओं के प्रमुख परिधान साड़ी का क्रेज दक्षिण अफ्रीका तक जा पहुंचा है। डरबन के समुद्र तट पर 10 वें 'साड़ी स्ट्राल' के दौरान अफ्रीकी महिलाओं ने साड़ी पहनकर मार्च निकाला। साड़ी स्ट्राल का मकसद उम्र व देश की सीमाओं को लांघकर सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना है। साड़ी सदियों से भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक पोशाक का हिस्सा मानी जाती है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

करण जौहर ने शुरू की 'तख्त' की तैयारी!

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिल्म निर्माता करण जौहर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'तख्त' की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस मल्टी स्टारर फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अहम भूमिका निभाते दिखेंगे। दरअसल, आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म के सेशन का एक बूमरैंग वीडियो शेयर किया है, जिसमें 'तख्त' लिखा हुआ एक कॉफी मग रखा दिखता है। इसके बैकग्राउंड में करण जौहर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस में बनाया गया है। रणवीर और आलिया इससे पहले फिल्म 'गली ब्वॉय' में साथ नजर आ चुके हैं। फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने प्यार भी दिया था। अब 'तख्त' में भी दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, हालांकि फिल्म में उनके किरदारों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। बता दें कि करण जौहर की फिल्म 'तख्त' में रणवीर सिंह और आलिया के अलावा अनिल कपूर, करीना कपूर, भूमि पेडणेकर, विकी कौशल और जाह्नवी कपूर भी मुख्य भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं दूसरी ओर आलिया को संजय लीला भंसाली के ऑफिस भी अक्सर जाते हुए स्पॉट किया जाता है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि भंसाली फिल्म 'इंशाअल्लाह' की तैयारियां फिर से शुरू करने वाले हैं।

जैसी हैं, वैसी ही बनी रहना चाहती हैं सोनाक्षी

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का मानना है कि सेलिब्रिटीज को वास्तविक बने रहना चाहिए, क्योंकि लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। सोनाक्षी का कहना है कि वह इस बात का ध्यान रखती हैं। उन्होंने कहा, 'जब आप लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं तो आपको वास्तविक बने रहना चाहिए। बनावटीपन जिंदगी में काम नहीं आता है। फैंस के साथ मेरा सीधा कनेक्शन है। सोशल मीडिया में भी जब मैं फैंस से बात करती हूं या पोस्ट करती हूं, तब भी कोशिश करती हूं कि मैं जैसी हूं, वैसी ही बनी रहूं।' हालांकि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी ट्रोल भी होते हैं। इस पर वह कहती हैं, 'मैं हमेशा उस चीज पर ही कमेंट करती हूं, जिसे लेकर आश्वस्त होती हूं। अगर मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर बात नहीं करती। मेरा मानना है कि आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं सजग रहती हूं।'

शानदार सफर

साठ साल का हुआ दूरदर्शन, यादों में खोए लोग

महाभारत, रामायण, फौजी और मालगुड़ी डेज जैसे अत्यंत लोकप्रिय सीरियल प्रसारित करने वाले दूरदर्शन की सोशल मीडिया में हुई जमकर तारीफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी ब्राडकास्टर दूरदर्शन ने रविवार को साठ साल पूरे कर लिए और इस अवसर पर तमाम लोग पुरानी यादों में खो गए जब केवल यही माध्यम लोकप्रिय कार्यक्रमों का मंच हुआ करता था। दूरदर्शन के इस सफर पर तमाम लोगों ने ट्विटर पर अपने-अपने अनुभव शेयर किए। महाभारत, रामायण, फौजी और मालगुड़ी डेज जैसे अत्यंत लोकप्रिय सीरियल प्रसारित करने वाले दूरदर्शन की जमकर तारीफ भी हुई।

ट्विटर पर लोगों ने एक-दूसरे से यह सवाल भी किए कि उनका सबसे पसंदीदा सीरियल शो कौन सा था। कुछ ने दूरदर्शन के मशहूर लोगो को भी शेयर किया, जो अपनी चिर-परिचित धुन के साथ किसी भी शो के पहले टीवी पर नजर आता था। सोशल मीडिया में तमाम लोग इसके सहारे अपने बचपन की यादों में खो गए। आखिर हो भी क्यों न। निजी टेलीविजन चैनलों के आने के पहले पूरे देश के लिए दूरदर्शन ही मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम था। क्रिकेट मैचों के सजीव प्रसारण से लेकर फिल्मों और एंटरनेटमेंट शो घर-घर का हिस्सा हुआ करते थे।

प्रसार भारती से सीईओ शशि शेखर वेंपति ने कहा, आज का दिन यह समझने का दिन है कि केवल दूरदर्शन की उम्र ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इसने एक नया स्वरूप भी ग्रहण किया है। डिजिटल युग में रह रहे दर्शकों के लिए दूरदर्शन एक नए रूप में है। उन्होंने कहा, दूरदर्शन ही भारत में टेलीविजन का इतिहास है। छह दशक की हमारी कहानी कामयाबी का सफर है-टीवी इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर।

दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू ने कहा, यह माध्यम भारत का डीएनए है। हैपी बर्थडे दूरदर्शन, 60 शानदार साल। आप इसी तरह दर्शकों को रोमांचित करते रहें। साहू ने एक वीडियो में कहा, दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को एक प्रयोग के रूप में हुई थी, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे बड़े ब्राडकास्टरों में से एक के रूप में उभरा है। 1965 में दूरदर्शन ने एक सेवा का रूप लिया, जब उसने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में टेलीविजन सेटों तक अपने प्रसारण की शुरुआत की। 1972 तक यह सेवा मुंबई और अमृतसर तक पहुंच गई और फिर 1975 तक इसका दायरा सात अन्य शहरों तक फैल गया।

इस दौरान वह नेशनल ब्राडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो का एक सहयोगी रहा। एक अप्रैल 1976 से इसने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग के रूप में काम करना आरंभ कर दिया। अब दूरदर्शन 34 सेटेलाइट चैनलों का एक नेटवर्क बन चुका है। दूरदर्शन को अनेक स्टारों की लांचिंग का श्रेय भी जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं शाह रुख खान। शाह रुख सीरियल फौजी के जरिये घर-घर जाने-पहचाने जाने लगे थे।

▸ सोशल मीडिया में लोगों ने बताए अपने-अपने अनुभव, 15 सितंबर 1959 को एक प्रयोग के रूप में हुई थी दूरदर्शन की शुरुआत

रामायण ने दूरदर्शन को घर-घर तक पहुंचाया था।

सात सवाल

अब एक्शन फिल्में ही करूंगा : सिद्धार्थ आनंद

फिल्म 'बैंग बैंग' के करीब पांच साल बाद सिद्धार्थ आनंद ने एक्शन फिल्म 'वॉर' का निर्देशन किया है। रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत यह फिल्म दो अक्टूबर को रिलीज होगी। वह हॉलीवुड फिल्म 'रैंबो' की रीमेक बनाने की तैयारी में भी हैं। उनसे बातचीत :

एक फिल्म के लिए पांच साल का वक्त ज्यादा नहीं है?

-दो साल से मैं 'वॉर' पर काम कर रहा था। उससे पहले तीन वर्षों के दौरान मैंने कई स्क्रिप्ट लिखीं, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं था। अपनी फिल्मों को लेकर मैं कभी जल्दबाजी में नहीं रहा। यही वजह है कि 15 साल के अपने करियर में मैंने सिर्फ छह फिल्में बनाई हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हर साल एक फिल्म बनाऊं।

आपका झुकाव अब एक्शन फिल्मों की ओर हो गया है...?

- एक्शन फिल्मों की तरफ झुकाव डिस्कवर हो गया। इसका श्रेय फॉक्स स्टूडियो को जाता है। वह मेरे पास 'नाइट ऐंड डे' का रीमेक 'बैंग बैंग' लेकर आए। मैं अचरज में था कि उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं यह फिल्म कर पाऊंगा। अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक्शन फिल्में ही करूंगा।

'वॉर' के एक्शन सीन को डिजाइन करने में एक साल का वक्त लगा?

- जी। बच्चे और युवा सुपर हीरो वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं। दर्शक हमसे क्वालिटी फिल्मों की उम्मीद करते हैं। 'एवेंजर्स एंडगेम' ने भारत में बहुत अच्छा बिजनेस किया था। बॉलीवुड में दो दशकों में कम ही अच्छी एक्शन फिल्में आई हैं। मेरी कोशिश अच्छी एक्शन फिल्म बनाने की रही है।

वॉर की शुरुआत कैसे हुई?

- एक छोटी-सी कहानी से। हालांकि कहानी साधारण है, पर एक्शन बड़ा है। कहानी एक पेज से शुरू हुई। रितिक रोशन के बाद टाइगर श्रॉफ भी हमें मिल गए। एक साल से शूटिंग कर रहे हैं।

फिल्म में विदेशी एक्शन डायरेक्टर्स ने एक्शन सीन डिजाइन किए हैं?

- कार चेजिंग सीन के लिए मैं हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर पॉल जेनिंग्स को लाया। वह 'द डार्क नाइट' के लिए काम कर चुके हैं। दो इंटिमेट हैंड फाइट्स हैं, फिजिकल कोरियोग्राफी है, जिसके लिए मुझे कोरियन एक्शन डायरेक्टर चाहिए थे। एक बाइक पर चेज सीन है, उसके लिए पुर्तगाल में साउथ अफ्रीकी स्टंट टीम को बुलवाया। लोकल एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख ने देसी एक्शन स्टाइल किया।

एक्शन में पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव आया है?

- तब बॉलीवुड का एक्शन स्टाइल देसी था, अब फिनिशिंग आ गई है। अजय देवगन और अक्षय कुमार फिनिशिंग और क्वालिटी लेकर आ रहे हैं। स्मार्ट फोन के कारण हॉलीवुड फिल्में देखना आसान हो गया है। उनकी फिल्मों के बजट ज्यादा हैं, हम सीमित बजट में क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं।

अच्छी फिल्मों के लिए क्या बजट इतना मायने रखता है?

- अच्छी नहीं, बड़ी फिल्मों के लिए। फिल्म में यदि विजुअल स्पेक्टिकल देना है तो मैनपावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट में बहुत खर्च होता है। तमाम रिहर्सल होती हैं। इससे बजट बढ़ जाता है।

स्मिता श्रीवास्तव